राजस्थान विधान सभा की कार्रवाई का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का आठवां दिवस [संख्या: 03

सोमवार,

30 जनवरी 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्रद्धांजलि

शहीद दिवस के अवसर पर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज शहीद दिवस है। आप सबसे सानुरोध प्रार्थना है कि दो मिनट मौन के लिये अपने स्थान पर खड़े हों।

(30 जनवरी के शहीद दिवस के अवसर पर सदन द्वारा देश की सेवा करते शहीद हुए दिवंगतों के प्रति दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 44

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

मई गुर्जर व बरौलीछार (नदबई) में कृषि महाविद्यालय की स्थापना

45. **श्री जोगिन्दर सिंह अवाना** (नदबई): क्या तकनीकी शिक्षा (कृषि) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नदबई की तहसील मई गुर्जर (उच्चैन) व बरौलीछार (नदबई) मुख्यालय पर नवीन कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): वर्तमान में नदबई की तहसील

(कृषि मंत्री)

मई गुर्जर (उच्चैन) व बरौलीछार (नदबई) मुख्यालय पर नवीन कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भरतपुर जिले के कुम्हेर, भुसावर, नगर, कामां एवं भरतपुर जिला मुख्यालय पर पूर्व से ही कृषि महाविद्यालय संचालित हैं। क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नवीन कृषि महाविद्यालय खोले जाते हैं।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि नदबई और उच्चैन में, जो अभी 4 जगह बताई हैं जहां पर कृषि महाविद्यालय हैं, वहां से कुम्हेर 35 किलोमीटर है। भुसावर लगभग 25 किलोमीटर है। नगर लगभग 35 किलोमीटर है और कामां लगभग 50 किलोमीटर है। जो किसानों के बच्चे हैं वे ज्यादा दूरी पर नहीं जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों जगह, बरौलीछार (नदबई) में 15 बीघा जमीन हमारे पास है और मई गुर्जर में 25 बीघा जमीन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या माननीय मंत्री जी इस बजट में कृषि महाविद्यालय खोलने की कोई मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: जवाब दे चुके हैं। अगला प्रश्न।

श्री गोपी चन्द मीणा।

जहाजपुर में नवीन एनिकट का निर्माण

46. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में बांध एवं एनीकट कहां-कहां पर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बनास नदी पर (घाटारानी माताजी के पास) व आडियो खेड़ा से घाटारानी मार्ग पर एनीकट तथा रपट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

(3) क्या सरकार पूर्व में निर्मित जलस्रोत, बांध व एनीकट के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्ययोजना बनाकर बजट आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभाग के अधीन आने वाले बांधों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। विभाग द्वारा निर्मित व पंचायती राज विभाग को स्थानान्तरित बांधों एवं एनीकटों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में बनास नदी पर घाटारानी माताजी से आडियो खेडा के मध्य जीरो लेवल एनीकट (सब सरफेस बेरियर) निर्माण हेतु डी.एम.एफ.टी. योजना अन्तर्गत राशि रुपये 198.00 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। स्वीकृति उपरांत संसाधन उपलब्धतानुसार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। आडियो खेडा से घाटारानी के मध्य एनीकट-कम-रपट स्थल बीसलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। बीसलपुर बांध में पानी की कम आवक के कारण इसका निर्माण विचाराधीन नहीं है।

(3) जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा पूर्व निर्मित बांधों/एनीकटों के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यतानुसार विभिन्न योजनाओं यथा ड्रिप, आर. डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी., आर.आर.आर. एवं ई.आर.एम. अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार कर समय-समय पर स्वीकृति प्रदान कर कार्य करवाये जाते हैं। वर्तमान में बजट घोषणा वर्ष 2022-23 अन्तर्गत ई.आर.एम. योजना में 5 कार्यों के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त एक कार्य आर.आर.आर. योजना में स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है, जिसकी सूची परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(विवरण एवं सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर परियोजना के कैचमेंट एरिया में आता है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जीरो लेवल के एनीकट निर्माण हेतु मैंने प्रस्ताव दिये हैं, उनकी स्वीकृति जारी करें।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास में अगर जीरो लेवल एनीकट का प्रस्ताव आयेगा तो हम स्वीकृति के लिये कार्रवाई करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अविनाश।

जैतारण में जवाई बांध पेयजल परियोजना से लाभान्वित ग्राम

47. श्री अविनाश (जैतारण): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में जवाई बांध पेयजल परियोजना से कितने ग्रामों को लाभ मिल रहा है? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जवाई बांध पेयजल परियोजना से वंचित ग्रामों, ढाणियों व बेरों को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्ष 2022 में जवाई बांध में पर्याप्त मात्रा में पानी की आवक हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार शेष ग्रामों को जवाई बांध पेयजल परियोजना से लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सम्मिलित 216 आबाद राजस्व ग्रामों में से 125 ग्राम सतही जल स्रोत जवाई बांध आधारित स्वीकृत एवं प्रगतिरत जवाई पाइप लाइन क्लस्टर परियोजना-तृतीय में सम्मिलित किये जाकर, इनमें से 83 ग्रामों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। शेष रहे 42 ग्रामों में से 38 ग्रामों को उक्त परियोजना से माह मई, 2023 तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करना प्रस्तावित है तथा वन क्षेत्र में अवस्थित 04 ग्राम नॉन-फिजिबल होने के कारण इन्हें इस परियोजना से जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं है। उक्त परियोजना में सम्मिलित, लाभान्वित तथा शेष लाभान्वित किये जाने वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) प्रगतिरत जवाई पाइप लाइन क्लस्टर परियोजना-तृतीय में विधान सभा क्षेत्र जैतारण के उक्तानुसार वर्णित 121 आबाद राजस्व ग्रामों में से 118 ग्राम एवं इनकी 411 चिन्हित ढाणियों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल सम्बन्ध द्वारा जवाई बांध से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 61 अन्य जल योजनाओं की राशि रुपये 194.48 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर, इनका क्रियान्वयन चरणबद्ध रूप से माह दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जवाई बांध आधारित स्वीकृत परियोजनाओं में वर्तमान में प्रस्तावित/ लाभान्वित कस्बों एवं ग्रामों की जल मांग के अनुरूप आरक्षण होने एवं अतिरिक्त जल की मात्रा उपलब्ध नहीं होने के कारण, उक्त विधान सभा क्षेत्र के भू-जल आधारित जल योजनाओं से लाभान्वित 95 ग्राम एवं इनकी 163 ढाणियों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ा जाना विचाराधीन नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार। संभागीय आयुक्त, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 10.10.2022 को आयोजित जवाई बांध जल आरक्षण समिति की बैठक में विभाग द्वारा जवाई पाइप लाइन योजना पर आश्रित शहर एवं ग्रामों के लिये 01 वर्ष (अक्टूबर, 2022 से अक्टूबर, 2023 की अवधि) के लिये 3551.00 मिलियन घन फुट जल मांग आरक्षित करने के विरुद्ध, कमेटी द्वारा 3000.00 मिलियन घन फुट आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार, जवाई बांध से वर्तमान में जुड़े कस्बों एवं ग्रामों की जल मांग अनुसार जल आरक्षण कम होने एवं अतिरिक्त जल की मात्रा उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त विधान सभा क्षेत्र के शेष ग्राम एवं ढाणियों को वर्तमान में लाभान्वित करना विचाराधीन नहीं है।

बजट 2022-23 में पाली व सिरोही जिलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई नदी एवं साबरमती नदी पर जलाशयों का एक हजार 800 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाने तथा इन बांधों से जवाई बांध तक पानी लाने हेतु एक हजार 200 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे, बाबत घोषणा की गई थी। इस घोषणा की अनुपालना में बांधों के निर्माण से संबंधित भाग-प्रथम की परियोजना हेतु राशि रुपये 2,554.23 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 13.12.2022 को जारी की जा चुकी है तथा इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा निविदा संबंधी कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

भाग-प्रथम की उक्त परियोजना में सम्मिलित बांधों से जवाई बांध तक पानी लाने हेतु भाग द्वितीय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (अनुमानित राशि रुपये 1,943.71 करोड़) जल संसाधन विभाग के स्तर पर तकनीकी परीक्षण में विचाराधीन है तथा परीक्षण में सही पाये जाने के उपरान्त स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर पर प्रस्तावित की जा सकेगी।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उक्त वर्णित दोनों परियोजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण होने के उपरान्त, जवाई बांध में अतिरिक्त पानी उपलब्ध होने पर विधान सभा क्षेत्र जैतारण के उक्तानुसार शेष रहे ग्राम एवं ढाणियों को उक्त बांध से जोड़े जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैतारण विधान सभा क्षेत्र की उक्त महत्वपूर्ण जवाई जल परियोजना कब से स्वीकृत हुई? अभी तक इसमें कितना काम हो गया? कितनी राशि का काम था? कितनी राशि का भुगतान कर दिया और कितनी राशि का काम शेष है? एक क्वेश्चन मेरा यह है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, मैं यह कहूंगा कि जब परियोजना इतने लम्बे समय से चल रही है तो इसके लम्बित रहने का क्या कारण है? यह हमारी सरकार के समय शुरू हुई थी।आज आपके 4 साल पूरे होने के बाद भी जैतारण के 216 राजस्व ग्रामों में से 125 को जोड़ा जाना था, उसमें से ही मात्र, अभी आप उत्तर में बता रहे हैं कि 83 गांवों को ही जोड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री अविनाश (जैतारण): बाकी गांव कब तक जुड़ जायेंगे? यह मुझे बतायें डिटेल कि यह योजना कब स्वीकृत हुई थी, मई जो आप बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको भाषण देना है? प्रश्न पूछें न आप।

श्री अविनाश (जैतारण): प्रश्न ही पूछ रहा हूं कि यह योजना कब शुरू हुई थी? इसके इतने लम्बे समय तक लम्बित रहने के क्या कारण हैं? आज दिन तक इसके गांवों को क्यों नहीं जोड़ा गया?

श्री अध्यक्ष: फिर आप इस पर आ गये।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि शेष रहे 42 ग्रामों में से 38 ग्रामों को उक्त परियोजना से माह मई, 2023 तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करना प्रस्तावित है। वन क्षेत्र में अवस्थित 4 ग्राम नॉन फिजिबल होने के कारण उन्हें इस परियोजना से जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं है। आलरेडी यह इसके अंदर है और मई, 2023 तक इन 38 गांवों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से सवाल है।

श्री अध्यक्ष: डिले होने का कारण पूछ रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): नेक्स्ट।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, आप जवाब दे देंगे? (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जवाब दे रहे हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न में यह नहीं पूछा है इसलिए वे देखकर जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं। बैठे-बैठे बात करना, I will not allow it. I will not tolerate it. नो माननीय सदस्य, नो बाबूलाल जी, प्लीज।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अविनाश (जैतारण): आप मुझे बाद में सारा बता दें, जवाब नहीं देंगे तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी। यह बाद में बता दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, केवल प्रश्न पूछें। माननीय कटारियाजी। आप उत्तर भी चाहते हैं, प्रश्न भी चाहते हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। यह सब चीजें एक साथ नहीं हो सकतीं। माननीय मंत्रीजी, बैठें, एक मिनट। माननीय कटारियाजी जी पूछ रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटड़ा जो दो बांध बन रहे हैं, वहां से कितने लोगों को आप हटाएंगे? उनके लिए आपने अब तक क्या व्यवस्था की है? जो लोग वहां उन बांधों के कारण से डूब में आएंगे और वहां से उनको जगह बदलनी पड़ेगी, उसके लिए आपका एस्टिमेट उनको जो पैसा देने का है, क्या उसका निर्धारण हो गया? उनको कहां पर एडजस्ट करेंगे, उसका निर्धारण हो गया तो वह बता दें।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बांध के लिए पुनर्वास करने की जो व्यवस्था होती है वह डब्ल्यू आर डी ओ और राजस्थान सरकार मिलकर करेगी। उसका हमारे से सम्बन्ध नहीं है, हमारा सम्बन्ध पेयजल की सप्लाई करने से सम्बन्धित है, उसका जवाब लेकर मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष को दे दूंगा। आपने पूछा है, मैं इसका जवाब आपको भिजवा दूंगा।

प्रश्न संख्या 48

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामनिवास गावड़िया।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री बलवान पूनियां।

भादरा में खाद्य सुरक्षा योजना के लम्बित आवेदन

49. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन सही पाए जाने पर सरकार द्वारा खाद्यान्न कब तक उपलब्ध करवाया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र भादरा में खाद्य सुरक्षा के कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं तथा उनका निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार खाद्य सुरक्षा में संयुक्त खातेदारी जमीन की रिपोर्ट के बजाय हिस्से में आने वाली भूमि की सूचना को वैध मानकर खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत चयन किये गये लाभार्थियों हेतु खाद्यान्न का आबंटन पूर्वानुसार निर्धारित खाद्यान्न आबंटन प्रक्रिया अनुसार (अग्रिम माह का आबंटन) किये जाने के कारण उत्तरोत्तर माह से देय होगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र भादरा में 6,296 खाद्य सुरक्षा के आवेदन लम्बित हैं, जिनके शीघ्र निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है।

(3) जी हां। विभागीय पत्र दिनांक 03.09.2013 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, आपने कहा कि जिन लोगों का चयन हो गया, उनको आबंटन की प्रक्रिया उत्तरोत्तर माह से देय होगी तो 'उत्तरोत्तर' का मतलब क्या है?

खण्ड-2 में आप कह रहे हैं कि विधान सभा क्षेत्र भादरा के 6,296

(श्री बलवान पूनियां)

खाद्य सुरक्षा आवेदन लम्बित हैं। इनकी प्रक्रिया क्या चल रही है? लम्बित सुनते हुए हमें चार साल हो गए। नम्बर-3, आपने कहा कि जी हां। विभागीय पत्र दिनांक 03.09.2013 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इसमें नोशनल शेयर के बारे में बिलकुल स्पष्ट बात इंगित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): हां। नोशनल शेयर के बारे में मैं यही पूछ रहा हूं कि यह किस हिसाब से तय करते हैं? किसी व्यक्ति की जमीन की रिपोर्ट पटवारी करेगा, मैं मंत्री महोदय से इतना जानना चाहता हूं कि पटवारी जो रिपोर्ट करेगा, अगर उसकी जमीन खातेदारी की नाम नहीं है तो नोशनल शेयर के हिसाब से राजस्थान भर में कहीं कोई रिपोर्ट नोशनल शेयर के हिसाब से कर ही नहीं रहे।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): प्रश्न यही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने लम्बित की बात पूछी। आपको पता है कि पोर्टल खोला गया और पोर्टल खोलने के बाद पूरे राजस्थान में, मैं आपके भादरा विधान सभा क्षेत्र का भी बता दूंगा, क्योंकि यह पूरे राजस्थान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, 19,57,991 आवेदन पोर्टल पर आए थे उनमें से अप्रूव्ड 3,49,648 हो गए पूरे राजस्थान में। 28,071 रिजेक्ट हुए हैं और पेंडिंग 10,12,971 हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, क्वेश्चन में जो पूछा है, वह बताएं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां। माननीय सदस्य, भादरा विधान सभा क्षेत्र की टेली मैंने आपको दे दी है। आपके भादरा विधान सभा क्षेत्र की अपीलें 9,816 हैं। स्वीकृत अपीलें 2,118, निरस्त अपीलें 886, शेष लम्बित अपीलें 6,296 हैं। आप जो कह रहे हैं 'उत्तरोत्तर', अभी प्रक्रिया चल रही है और हम यह कोशिश कर रहे हैं, मैंने 22 जनवरी लास्ट डेट रखी थी। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो पात्र व्यक्ति हैं, पूरे राजस्थान में उनको मार्च तक गेहूं देना चालू कर दिया जाए। यह काम अधिकतर चालू करते जा रहे हैं, मार्च तक पूरा कर देंगे।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): नोशनल शेयर क्या है? नोशनल शेयर के बारे में पूछा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, ये जो दूसरा पार्ट है, किसी खातेदार की जमीन संयुक्त है, उस खातेदार को अलग करके जब तक नहीं करेंगे, तब तक उसका नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं आएगा। यह 2013 का सर्कुलेशन है, उस सर्कुलेशन के बाद सरकार कोई फैसला कर रही है क्या?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): खाद्य सुरक्षा में छोटे किसानों का जो मामला आ रहा है, हमने इसके आदेश जारी कर दिए हैं, सब जगह कह दिया गया है। आपके एरिया के अधिकारी भी आकर मिल लेंगे, पूरे राजस्थान में इसको ठीक कर रहे हैं, उनको जोड़ दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): मेरा निवेदन पुन: एक बार यह है कि यह पूरे राजस्थान का मसला है, एक मेरे एरिया का मसला नहीं है। नोशनल शेयर पर सरकार गाइडलाइन तय कर दे कि किसी भी खातेदार की जमीन अगर अलग-अलग तय नहीं हुई तो उसके शेयर के हिसाब से पटवारी रिपोर्ट कर दे। अगर वह लघु और सीमांत श्रेणी में आ जाता है तो जुड़ जाएगा, नहीं आता है तो टाल हो जाएगी। इसीलिए मेरा निवेदन है कि स्पष्ट 2013 का आदेश है, दस साल बाद अभी तक भी हम लिए बैठे हैं, स्पष्ट गाइडलाइन तय करें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने आदेश किया, यह आदेश जारी कर दिया गया और मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें किसी किसान को दिक्कत नहीं आएगी, वे सारे आदेश जारी कर दिए गए हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप सिंह।

वक्फ कमेटी, छबड़ा का गठन

50. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि छबड़ा में सरकार द्वारा वक्फ कमेटी का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) वक्फ कमेटी में नियुक्त किए गए सदस्य वक्फ अधिनियम,

(श्री प्रताप सिंह)

1995 की धारा 16 के अनुसार बोर्ड का सदस्य नियुक्त किए जाने या सदस्य बने रहने की निरर्हताएं रखते हैं? यदि हां, तो सभी सदस्यों के शपथ पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

वक्फ मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जी हां। छबड़ा में राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ द्वारा रिजोल्यूशन संख्या 21/2022 की अनुपालना में वक्फ कमेटी का गठन आदेश क्रमांक वक्फ/कमेटी/2022/4799-4805 दिनांक 19.09.2022 के द्वारा किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वक्फ कमेटी में सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 16 के तहत नहीं की जाती है।

वक्फ कमेटी का गठन बोर्ड द्वारा केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 18 के अंतर्गत किया जाता है, जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

वक्फ कमेटी, छबड़ा, जिला बारां की कमेटी के गठन की प्रक्रियान्तर्गत सदर, सचिव एवं कैशियर के शपथ पत्र प्रस्तुत हुए हैं, जिनकी छाया प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण एवं प्रति पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और असत्य शपथ पत्र देकर वे वक्फ कमेटी के सदस्य या नायब सदर बने हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं या नहीं रखते हैं? क्या नियमों में ऐसा प्रावधान है कि जिन व्यक्तियों पर हत्या के मामले हों, गबन और भ्रष्टाचार के मामले हों, दंगे के मामले हों, उनको सदस्य बनाया जा सकता है या नहीं?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 18 के अंदर पूरा स्पष्ट है। हालांकि इसमें जो शपथ पत्र लेने हैं, वक्फ एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी हम सदर, सचिव और कोषाध्यक्ष का शपथ पत्र लेते हैं। मान लो ऐसी कोई शिकायत आती है, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसमें किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होगी तो हम जांच कराएंगे।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने खुद शिकायत कर रहा हूं कि आपने जो नायब सदर बनाया है उसको..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप लिखकर भेज दें। आप लिखकर भेज दें और कार्रवाई नहीं हो तो प्रश्न पूछें। माननीय कटारियाजी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): नहीं, नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी रिक्वैस्ट है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने पढ़ लिया है, आपने बोल लिया।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, हत्या के मामले दर्ज हैं..

श्री अध्यक्ष: आपने शिकायत की है? प्लीज। रिकॉर्ड नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड नहीं होगा। आपने कोई शिकायत लिखकर भेजी? आपने कोई शिकायत लिखकर भेजी? भेजी ही नहीं तो कार्रवाई किस पर करें? आप लिखकर भेजें, कार्रवाई नहीं हो तो पूछें। माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 19.09.2022 का कार्यालय आदेश है, जिसके तहत इसका गठन हुआ और जिनको मेम्बर बनाया गया। इसी कार्यालय आदेश में आपके क्रमांक 10 पर दिया है, औहदेदारान द्वारा दिया गया शपथ पत्र असत्य पाए जाने पर होने वाले कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। यह आपने उसके साथ शर्त लगाई। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सात नम्बर पर जो व्यक्ति है अब्दुल सलीम पुत्र अब्दुल कय्यूम, यह 302 का मुलजिम 2015 से है या नहीं? दूसरा, इसी तरह से आपका मुश्ताक मोहम्मद पुत्र शफी मोहम्मद, यह गबन के आरोप में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन् 2000 में निलम्बित है या नहीं? यह जानकारी होने के बाद भी गलत शपथ पत्र देकर इन्होंने अपने बारे में बताया यह है– ''यह कि मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई फौजदारी मुकदमा नहीं है'', जबकि ये 2015 और 2002 के मुकदमे हैं। उसके बाद भी आपके पांच मेम्बर्स ऐसे हैं, जिन पर 2022 के मुकदमे हैं। एक नहीं सात-सात मुकदमे हैं। क्या इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखते हैं?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, वक्फ अधिनियम की धारा 64 में ये बोर्ड में हैं। हालांकि शपथ पत्र का प्रावधान एक्ट में नहीं है, फिर भी हम तीन व्यक्तियों

(श्री शाले मोहम्मद)

का तो शपथ पत्र लेते ही हैं। जैसे इस महीने हमने सदर साजिद खान का लिया है, सचिव मुश्ताक मोहम्मद का लिया है और कोषाध्यक्ष अब्दुल सलीम का लिया है। इन तीन व्यक्तियों ने अपना शपथ पत्र दिया है।

उसके अलावा, यदि हमें कोई ऐसी शिकायत प्राप्त होती है, हमारे लगभग 11 बिन्दु हैं, उन 11 बिन्दुओं में कोई भी ऐसी शिकायत पायी जाती है तो उसकी जांच करवाकर हम कार्रवाई करेंगे। जब तक कोई शिकायत ही नहीं आएगी तो हमें क्या पता चलेगा कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है अथवा नहीं। शपथ पत्र ले लिया, अब कोई शिकायत आएगी, तब ही तो हम अगली कार्रवाई करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय कटारिया जी ने रिकार्ड पर यह बात कही है, क्या आप इनकी जांच करवाकर इन पर कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): बिल्कुल सर, मैंने यही निवेदन किया है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्लीज बैठें। नीचे बैठें, प्लीज। मंत्री खड़े हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते। मंत्री जवाब दे रहे हैं। जो भी कटारिया जी ने बात रखी है, क्या मंत्री महोदय उसकी जांच करवाकर कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं? माननीय सदस्य भी यह लिखकर दें, उसमें यदि कुछ प्रूव होता है, तो मंत्री महोदय उस पर कार्रवाई करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: आप नहीं सुन रहे हैं। आपका नहीं लिखा जाएगा। रिकार्ड नहीं होगा। बैठें, प्लीज।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा है? एक बार कह दिया, फिर भी जिद कर रहे हैं अपनी। माननीय कटारिया जी, मैं समझता हूं, it is not desirable. You can't impose your condition in this House.

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप बैठें नीचे। I will name you. बैठें नीचे। सीनियर मेम्बर हैं आप। बैठें नीचे। आप समझ नहीं रहे, मैं खड़ा हूं। नीचे बैठें आप। आप अपने स्थान पर बैठें। I say, I will name you. बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): विषय हमने रख दिया। जो शिकायत है, वह हमारे प्रश्नों के माध्यम से भी आ गयी। उनकी जांच कराएं और उनके विरुद्ध कार्रवाई करें।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो नेता, प्रतिपक्ष फरमा रहे हैं, हमने कहा, शिकायत यदि कोई आएगी...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज बैठें। माननीय कटारिया जी जो चीज रिकार्ड पर लेकर आ गये हैं, उस रिकार्ड को आप चैक कर लें और यदि ये शपथ पत्र असत्य हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

नौगांवा (अलवर) में रीको के औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

51. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर में नवीन दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस हाईवे पर तहसील नौगांवा में सरकार द्वारा रीको का औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाना है? यदि हां, तो औद्योगिक क्षेत्र हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर भी अब तक उक्त क्षेत्र स्थापित क्यों नहीं हो सका? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्र को कब तक स्थापित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): (1) जिला अलवर में नवीन दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस हाईवे पर तहसील नौगांवा में रीको द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु तहसील-नौगांवा के ग्राम मूनपुर करमला एवं रसगन की 230.32 हैक्टेयर भूमि चिन्हित की गयी है, जो कि चरागाह एवं गैर-मुमकिन पहाड़ की किस्म में है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में किसी अन्य प्रकरण में दायर रिट याचिका संख्या 5132/2021 एवं 2856/2021 में चरागाह भूमि के आबंटन पर स्थगन प्रभावी होने के कारण

(उद्योग मंत्री)

वर्तमान में राजस्व विभाग द्वारा आबंटन/आरक्षण हेतु स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है। अत: जिला कलेक्टर, अलवर को चरागाह भूमि के अतिरिक्त अन्य उपयुक्त राजकीय भूमि के प्रस्ताव भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है। राजकीय भूमि के नवीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किया जाना सम्भव है।

(2) उपयुक्त राजकीय भूमि के नवीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी, अगर चरागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हो जाती है, क्या तब सम्भव है, या अलवर जिले में जैसे और भी बजट घोषणाएं हुई थीं, कठूमर, बानसूर में रीको एरिया की, एन.सी.जेड. एक कारण है कि वहां भी स्थापित नहीं हो पा रहे, क्या वह भी एक कारण है रामगढ़ में रीको का एस्टेब्लिश न होना?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): पहले यह प्रावधान था कि रीको अगर चरागाह भूमि आरक्षित करता है तो उसमें दूसरी क्षतिपूर्ति करके उसे कर सकता था, लेकिन अभी वर्तमान में दौसा से एक हाई कोर्ट में केस हुआ था रालावास का, उसके कारण इस पर स्टे लग गया है और पूरे राजस्थान में सभी जगहों पर क्षतिपूर्ति के बाद भी गोचर में किया जाना सम्भव नहीं है।

जो एन सी जेड का मैटर है, इसके लिए हमने समय-समय पर भारत सरकार को पत्र भी लिखा है। पहले मीटिंग भी हुई थी। पत्र 03.08.2021 को लिखा था। उसके बाद नवम्बर, 2021 में लिखा, फिर 2022 में लिखा। उसके बाद मैंने खुद ने भी भारत सरकार के मंत्री महोदय से फोन पर बात की और उनसे निवेदन किया कि बहुत सारी आपत्तियां आने के बाद भी अगर वे एन सी जेड से नहीं निकाल पा रहे हैं तो वे हमें अनुमति दे दें, जिससे कि हमारे उद्योग-धन्धे स्थापित हो सकें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर आगार के सेवानिवृत्त कार्मिकों का बकाया परिलाभ

52. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों व

(श्रीमती अनिता भदेल)

कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभ की कितनी राशि बकाया है? उक्त राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) अजमेर आगार में अप्रैल, 2013 से 13 जनवरी, 2023 तक कितने अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए व उनकी किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि बकाया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विगत पांच वर्षों की वित्तीय स्थिति का वर्षवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभ की इकाई स्तर पर जारी स्वीकृति के आधार पर कुल राशि रुपये 65.18 करोड़ के भुगतान बकाया हैं। निगम द्वारा उक्त राशि का भुगतान फंड की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

(2) निगम के अजमेर आगार में अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2022 तक 200 अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। उक्त में से जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभ बकाया हैं, उनका बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभों सहित विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विगत पांच वर्षों की वित्तीय स्थिति का वर्षवार विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से तीन सवाल पूछना चाहूंगी। प्रश्न का खण्ड-1, उसमें पूरे राजस्थान की जानकारी चाही थी। माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि 65.18 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। प्रश्न के खण्ड-2 में मैंने सिर्फ अजमेर आगार के बारे में पूछा है। अजमेर आगार, जिसके परिशिष्ट '1' की टेबल में आपने बकाया राशि वाले कर्मचारियों का बताया है, उसमें 16 कर्मचारियों का बकाया चल रहा है। यदि उसका टोटल काउंट करती हूं तो 89 करोड़ 69 हजार 687 रुपये बकाया हैं। जब सिर्फ और सिर्फ अजमेर आगार का 89 करोड़ बकाया है तो पूरे राजस्थान भर का 65 करोड़ बकाया है, इस पर मुझे संशय है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि मंत्री महोदय इसे क्लियर करें।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल है, जो 16 लोगों का मुझे परिशिष्ट दिया है, उसमें आप देखिएगा, पहले नम्बर पर है नरेन्द्र सिंह गौड़ (परिचालक), जो कि 31.01.2021 को रिटायर हुए, लेकिन इनकी स्वीकृति जारी न करके जो फरवरी में या दिसम्बर में रिटायर हुए हैं, उनकी स्वीकृतियां जारी कर दी गयी हैं। स्वीकृतियां जारी करने का क्या आधार है? जो पहले महीने में रिटायर हुआ है, उसे पहले स्वीकृति जारी करनी चाहिए या जो बारहवें महीने में रिटायर हुआ है, उसे स्वीकृति जारी करनी चाहिए?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से मेरा तीसरा प्रश्न पूछना चाहूंगी। जब मैं आय-व्यय की टेबल देखती हूं, परिशिष्ट '2', उसमें राज्य सरकार का जो अनुदान है, वह 2017-18 में 284 करोड़ है, 2018-19 में 383 करोड़ है, 2019-20 में 311 करोड़ है, 2020-21 में 556 करोड़ है, लेकिन पिछले दो वर्षों में यह 200 करोड़ पर अटक गया है। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि यह जो अनुदान है, उसे देने का क्या क्राइटेरिया है। कोई मापदण्ड तो होगा कि इतना परसेंट आपका घाटा होगा तो इसका इतना परसेंट देंगे? अनुदान देने का क्या क्राइटेरिया है? किस बेसिस पर हम यह अनुदान दे रहे हैं? मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, जिन 16 कर्मचारियों का आपने बकाया बताया है उसमें ज्यों ही कर्मचारी रिटायर होता है उसको अपने पेपर पूरे करने पड़ते हैं, नो-ड्यूज का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। उसके अलावा उसके कोई जांच बकाया नहीं होनी चाहिए। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि पहले रिटायर हो, उसका पहले बने और बाद में हो उसका बाद में बने। वह उसके पेपर देने पर और उसकी फाइल की पूर्ति करने पर ही निर्भर करता है।

दूसरा, जो मुझे विभाग ने दिया है, वह राजस्थान के सभी डिपो के बकाया का 65.18 करोड़ दिया है और अगर इसमें कहीं कोई गलती है तो इसकी जांच कराऊंगा तथा सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा।

तीसरा, जो आपने एक कर्मचारी गौड़ का पूछा है, मैं आपको सभी 16 कर्मचारियों का बता देता हूं। 4 कर्मचारी तो इसी दिसम्बर में रिटायर हुए हैं और उन्होंने अपनी फाइल की पूर्ति अभी तक नहीं की है। जिस गौड़ का आप बता रहे हैं तो हमारे पास एक तो टीकम चन्द हैं जो 28.02.2021 को रिटायर

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

हुए हैं। उसमें बकाया नहीं का प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं तथा कर्मचारी की मृत्यु हो गई और इसके परिवार को भी हमने लिख दिया, पर अभी तक उन्होंने कागजों की पूर्ति नहीं की है।

श्री अध्यक्ष: आप तो नरेन्द्र सिंह गौड़ का बता दो। नरेन्द्र सिंह गौड़ को पहले क्यों नहीं दिया, वह पूछ रहे हैं। नरेन्द्र सिंह गौड़, जो 31.01.2021 को रिटायर हो गये, उनका नहीं दिया और बाद वालों को दे दिया तो इन नरेन्द्र सिंह गौड़ की क्या प्रोब्लम है?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): उनके पेपर बकाया हैं, पेपर की पूर्ति नहीं की है। जहां तक अनुदान की बात है तो अनुदान का कोई निश्चित फार्मूला तय नहीं है। ज्यों ही रोडवेज राज्य सरकार से मांग करती है, हम कोशिश करते हैं क्योंकि यह उपक्रम ऐसा है जो पहले भी घाटे में था, अब भी घाटे में है, पर हमको हमारा सोशल आब्लिगेशन पूरा करने के लिए अच्छी बस सेवा पब्लिक को उपलब्ध हो, इसलिए हमें इसको चलाना पड़ता है। ज्यों ही रोडवेज राज्य सरकार से मांग करती है तो हम उस पर अनुदान जारी करवाते हैं। आपके समय में जितना अनुदान दिया गया था उससे ज्यादा इस कार्यकाल में सरकार ने अनुदान दिया है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खण्ड-2 'अजमेर आगार में अप्रैल, 2013 से जनवरी, 2023 तक कितने अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए?' इसमें आपने दिया कि 200 हुए। उनमें से जो बाकी बचे हुए हैं और यह जो आपका परिशिष्ट-1 है, जिसमें 16 लोग बताये हैं, इनका तो पेमेंट बाकी है, इनको पैसा नहीं मिला, पर इसमें दस लोग तो ऐसे हैं, जिनके बारे में आप लिख रहे हो कि ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश की स्वीकृति जारी नहीं हुई लेकिन ऊपर जिनकी आपने ग्रेच्युटी राशि 3 लाख 88 हजार 553 रुपया बता दिया कि यह इनकी ग्रेच्युटी है, पर यह इनको मिली नहीं है। 6 लोग तो ऐसे हैं जिनमें उनकी ग्रेच्युटी तय कर रखी है कि कितनी है, पर आपने पेमेंट नहीं किया और बाकी लोगों की कागज की पूर्ति नहीं होने के कारण से है तो दोनों का अन्तर समझाओ। जिनकी कागज की पूर्ति हो गई, ग्रेच्युटी तय हो गई, उनको आपने क्यों नहीं दिया?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैंने मेरे मूल प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया है कि फण्ड की उपलब्धता होने पर इनको करवा दिया जाएगा। हमारे पास देने को फण्ड नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, ये 16 जो व्यक्ति हैं, जिनकी ग्रेच्युटी आ चुकी है, प्राथमिकता के आधार पर उनका पेमेंट कराने का काम करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): प्राथमिकता के आधार पर उनका पेमेंट करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कान्ति प्रसाद।

थानागाजी में एकलव्य मॉडल विद्यालय की स्थापना

53. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में जनजातीय छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उत्थान हेतु निर्धारित प्रावधानानुसार बालिका छात्रावासों व एकलव्य मॉडल विद्यालय का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में करवाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील थानागाजी में एकलव्य मॉडल विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): जी हां। सरकार द्वारा जनजातीय छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उत्थान हेतु निर्धारित प्रावधानानुसार बालिका छात्रावासों व एकलव्य मॉडल विद्यालय का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में करवाया गया है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2018-19 में वर्ष 2022 तक जिन ब्लाकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.) खोलने की बजट घोषणा की गई थी, उन ब्लाकों में थानागाजी सम्मिलित नहीं है।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की घोषणा करती है, वह बात तो ठीक है, पर थानागाजी ब्लाक में भी 61 ग्राम माडा के हैं और बाकी बिखरी जनजाति क्षेत्र है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह ब्लाक भारत सरकार की सूची में कैसे जुड़े और यहां एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कैसे खुले? यह मुझे आप बता दें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की गाइडलाइन है कि सम्बन्धित ब्लाक में 50 प्रतिशत जनजाति की आबादी या उस ब्लाक में 20 हजार से अधिक। थानागाजी में 19 प्रतिशत ही आबादी है और भारत सरकार की गाइड-लाइन के अनुसार आगे कोई प्रावधान होगा तो उसमें मदद करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल शर्मा।

मांडलगढ़ उप खण्ड मुख्यालय में अधिशासी अभियंता कार्यालय की स्थापना

54. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में अधिशाषी अभियंता कार्यालय खोलने के क्या मापदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में उप-खण्ड मुख्यालय मांडलगढ़ पर अधिशाषी अभियंता कार्यालय नहीं होने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उप खण्ड मुख्यालय पर अधिशाषी अभियंता का कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) राज्य सरकार से प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत विद्युत वितरण निगमों में नवीन कार्यालय सृजित किये जाते हैं। प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों में नया अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय 90,000 विद्युत उपभोक्ताओं पर खोले जाने का प्रावधान है। ऊर्जा विभाग द्वारा जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगमों को जारी स्वीकृति आदेशों की प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट-अ, ब व स पर उपलब्ध हैं।

(2) वर्तमान में उप खण्ड मुख्यालय माण्डलगढ़ के उपभोक्ता खण्ड कार्यालय, भीलवाड़ा (ग्रामीण) के अधीन आते हैं। अतः माण्डलगढ विधान सभा क्षेत्र में उप खण्ड मुख्यालय माण्डलगढ़ पर नवीन अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, जिसके मापदण्डों के अनुरूप पाये जाने पर स्वीकृति सम्बन्धी कार्रवाई के उपरान्त उक्त अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया कि 90 हजार विद्युत उपभोक्ता होने पर खोले जाते हैं, परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो 90 हजार से बहुत ज्यादा हैं उसके बावजूद आपने अभी तक कार्यालय नहीं खोला है। दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मांडलगढ़ कस्बा भीलवाड़ा से 60 किलोमीटर दूर है, बिजौलिया ए.ईएन. कार्यालय 100 किलोमीटर दूर है और उसके बावजूद भी आपने वहां पर कार्यालय नहीं खोला है, जबकि भीलवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर उप खण्ड पर भी आपने अधिशाषी अभियंता कार्यालय खोल रखा है। इसलिए क्या कारण रहा कि मेरे मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में यह एक्स.ईएन. कार्यालय नहीं खोला और अब आप कब तक खोलने का आदेश करेंगे? यह बतायें आप।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया, विद्युत वितरण निगमों में नवीन कार्यालय सृजन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार से ऊर्जा विभाग के माध्यम से प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाती है। राज्य सरकार को प्रशासनिक व वित्तीय अनुमति के लिए भेजते हैं और वह अनुमति मिलने के बाद में नवीन कार्यालय खोला जाता है। उपरोक्त प्रश्न के सम्बन्ध में मांडलगढ़ अधिशाषी अभियंता कार्यालय का प्रस्ताव निर्धारित मापदण्डों व संसाधनों की उपलब्धता अनुसार परीक्षण अभी हम करवा रहे हैं, प्रक्रियाधीन है और जैसे ही वित्तीय स्वीकृति मिलेगी तो इसमें आगे कार्य बढ़ाया जाएगा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कब तक यह खुलेगा? यह प्रक्रिया तो आपकी कभी खतम होगी ही नहीं, पर संसाधन की उपलब्धता कब तक होगी, यह आपके डिपार्टमेंट का तो आपको पता ही होगा, इसलिए यह बताइये कि कब तक आप खोलेंगे?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा समय-समय पर ए.ईएन आफिस, एक्स.ईएन. आफिस विभाग के नोर्म्स के अनुसार भी और बजट घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्री महोदय करते हैं, उसमें भी नये एक्स.ईएन., ए.ईएन. आफिस खोले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि आपके नोर्म्स पूरे कर रहे हैं, नोर्म्स में कोई तकलीफ नहीं है। वे तो यह कह रहे हैं कि आपकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कब एक्सरसाइज करेंगे? क्या इस स्थिति में हैं कि जब भी नया अधिशाषी कार्यालय खुलेगा तो प्राथमिकता मांडलगढ़ को मिलेगी?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य के द्वारा प्रश्न उठाया गया है। जो 90 हजार का नोर्म्स है, निश्चित रूप से पहले मांडलगढ़ में 88 हजार थे, अभी उपभोक्ता बढ़े हैं, लगभग 90 हजार हो गये हैं। इसकी प्रक्रिया हम आगे बढ़ा रहे हैं और वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइनेंस में भिजवायेंगे। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद में यह कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: अगल प्रश्न। श्री सुभाष पूनिया।

सूरजगढ़ में संचालित होम्योपैथिक चिकित्सालय

55. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में किस स्तर के कितने होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं तथा विगत चार वर्षों में कितने नये चिकित्सालय प्रारम्भ किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में कितने पद स्वीकृत हैं? उनमें से कितने पद भरे हुए हैं व कितने पद रिक्त हैं? सरकार द्वारा रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (डा. सुभाष गर्ग): (1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पृथक से होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित नहीं है। 01 राजकीय ब्लाक आयुष चिकित्सालय, सूरजगढ़, झुंझुनूं में संचालित है, जिसमें होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। विगत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के तहत उक्त चिकित्सालय प्रारम्भ किया गया। (स्वीकृति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है)

(2). राजकीय ब्लाक आयुष चिकित्सालय, सूरजगढ़, झुंझुनूं में होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार है:-

क्रं.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	चिकित्साधिकारी	01	--	01
2.	नर्स/कम्पाउण्डर	01	--	01

उक्त चिकित्सालय में कुल स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

रिक्त पदों को भरने के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्षजी, किसी नये कार्य की घोषणा करने के उपरान्त भी उसकी क्रियान्विति की पहले व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? इसके क्या कारण हैं?

नम्बर 2, स्वीकृत पद खाली रहने के क्या कारण रहे हैं? इन्हें कब तक भर देंगे? आपने परिशिष्ट 'ब' पर खुद स्वीकार किया है कि 18 पद स्वीकृत हैं। उनमें से 3 भरे हुए हैं और 15 पद रिक्त हैं। इसके क्या कारण रहे हैं?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 2021 में आयुष पालिसी घोषित की गई थी। उसमें यह निर्णय लिया गया था, यह प्रस्तावित किया गया था कि जितने भी हमारे ब्लाक्स हैं, 392 ब्लाक्स हैं तो फेजेज के हिसाब से और वित्तीय उपलब्धता के अनुसार ब्लाक्स में आयुष के चिकित्सालय खोले जायेंगे। उसी के तहत 2020-21 में 58 ब्लॉक्स में और 2021-22 में 19 ब्लाक्स में ये चिकित्सालय प्रारम्भ किये गये हैं, जिनमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।

माननीय सदस्य ने बिलकुल सही कहा है कि सूरजगढ़ में खोला गया था, जिसमें 18 पद स्वीकृत हैं, 3 कार्यरत हैं और 15 पद रिक्त हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमको फाइनेंस से 639 आयुर्वेद चिकित्सकों की स्वीकृति मिल गई है। हमने होम्योपैथिक के 127 पदों के लिए प्रस्ताव भिजवाये हैं और 140 यूनानी चिकित्सकों की भर्ती के प्रस्ताव भी प्रक्रियाधीन हैं। जैसे ही भर्ती होगी, निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता है कि इंटीग्रेटेड ब्लाक्स हास्पिटल्स का जो कांसेप्ट लिया गया है, वहां पद भर दिये जाएं।

मैं बताना चाहूंगा कि गत 4 वर्षों में विभाग के अन्तर्गत कुल 1798 पदों पर भर्तियां की गई हैं, जिनमें आयुर्वेद में 1725, होम्योपैथिक में 9, यूनानी में 31, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय में 33 हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी ही इन पदों को भर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बहुत शर्म और अफसोस होता है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह का प्रश्न पूछा है। जब आपने सभी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराने का निर्णय 2021 में ले लिया, उसी के तहत आपने होम्योपैथिक हास्पिटल इनके क्षेत्र में भी खोल दिया। वहां दोनों पद रिक्त हैं। उस जगह 18 का स्टाफ है, उसमें से 3 लोग हैं, जिनमें से न होम्योपैथिक का कोई आदमी है, न मेडिकल का कोई आदमी है तो फिर आप

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्या सुविधा दे रहे हो? आज स्वीकृति मिली है, जब आप और मैं दोनों ही नहीं रहेंगे, तब ये पद भरोगे क्या?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं, वह बिलकुल सही है। आप भी जानते हैं कि कोई भी सरकार रही हो, इंस्टीट्यूशंस खुलते हैं और इंस्टीट्यूशंस खुलने के बाद सारी प्रक्रियाएं शुरू की जाती हैं। मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान और झुंझुनूं का भी, हमारे टोटल पदों का हंड्रेड परसेंट में से देखा जाए तो हमारे 71.63 परसेंट पद झुंझुनूं में भरे हुए हैं 28.37 परसेंट पद झुंझुनूं में रिक्त हैं। माननीय प्रतिपक्ष नेता जी, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो एक ही हास्पिटल का बता दें। आपने क्या किया है?

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी। माननीय मंत्रीजी, आप जो रिप्लाई दे रहे हैं, उसमें खाली आप यह ध्यान रखें कि 18 पद स्वीकृत हैं। उन 18 पदों में से यूनानी का जीरो, आज भी खाली पड़ा हुआ है। होम्योपैथिक का खाली पड़ा हुआ है, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का पद खाली पड़ा हुआ है। क्या सरकार जिन जगहों पर कम हैं, वहां पर रिप्लेस करके व्यवस्था करने का काम करेगी? आपके वहां न तो आयुर्वेद का काम हो रहा है, न यूनानी का काम हो रहा है, न होम्योपैथिक का काम हो रहा है तो सरकार जिन जिलों में ज्यादा है, उनमें से कुछ कम करके इधर कर दे तो सभी जगह व्यवस्था हो सकेगी। इतनी व्यवस्था करने की स्थिति में हैं क्या? भर्ती तो जब होगी, होती रहेगी लेकिन जो मैन पावर आपके पास अवेलेबल है, उसको डिप्लॉय करके हम ठीक कर सकते हैं। उसमें कोई प्रोब्लम है क्या?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल प्रोब्लम नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि पदों को भरने की जो प्रक्रिया है...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप फिर इस पर आ गये हैं। आप बैठिए। मैं पदों की नहीं कह रहा हूं। जो एग्जिस्टिंग मैन पावर अवेलेबल है, भर्ती तो बाद में होती रहेगी। जो आपकी अवेलेबल मैन पावर है, उस अवेलेबल मैन पावर को ही री-डिप्लॉय करके, जहां बिलकुल सुविधा नहीं है। जब आपने इंटीग्रेटेड व्यवस्था कर दी है और एक भी व्यवस्था नहीं है तो इंटीग्रेटेड करने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। उसे करने के लिए विभाग निश्चित तौर पर

(श्री अध्यक्ष)
एग्जामिन करे और री-डिप्लॉय करे, जिससे कम से कम वहां सुविधा तो स्टार्ट हो। एक जगह तो सभी सुविधाएं मिल रही हैं और दूसरी जगह बिलकुल भी सुविधा नहीं है तो उसको ठीक करने का काम करें।

प्रश्न संख्या 56

अगला प्रश्न। श्रीमती गंगा देवी।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

लम्पी वायरस से बचाव हेतु टीकाकरण

57. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) (श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) के स्थान पर):- क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2022 में कुल कितने मवेशी लम्पी वायरस से संक्रमित हुए एवं कितनों की मृत्यु हुई? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में दिसम्बर, 2022 तक लम्पी वायरस से बचाव हेतु कुल कितने गोवंश का टीकाकरण किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार लम्पी वायरस से जिन पशुपालकों के पशुधन काल कवलित हो गये उन्हें पशु क्रय हेतु आसान दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व कितने प्रतिशत ब्याज दर पर?

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) प्रदेश में लम्पी स्किन रोग से संक्रमित एवं मृत गोवंश पशुओं का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में लम्पी स्किन रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु गोवंशीय पशुओं में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार गोट-पॉक्स वैक्सीन से माह दिसम्बर, 2022 तक कुल 106.46 लाख चिन्हित गोवंशीय पशुओं में टीकाकरण किया गया है।

(3) प्रदेश में जिन पशुपालक के गोवंशीय पशु लम्पी स्किन रोग से मृत हुए हैं, उन्हें पशु क्रय हेतु आसान दरों पर ऋण दिया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से तीन प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। खण्ड-1 में लम्पी रोग से मृत पशुओं की संख्या 76 हजार 30 बताई गई है। क्या इन मृत पशुओं के पशुपालकों को सरकार के जन घोषणा पत्र में की गई घोषणा के अनुसार पशुधन बीमा योजना का लाभ मिलेगा या नहीं? अगर हां, तो कब तक?

दूसरा प्रश्न, खण्ड-2 में माह दिसम्बर, 2022 तक 1 करोड़ 6 लाख गोवंश के टीकाकरण का उल्लेख किया गया है। इस टीकाकरण में खर्च धनराशि में केन्द्र व राज्य सरकार का कितना-कितना अनुपात रहा है? अवगत करायें।

प्रश्न तीन, खण्ड-3 के उत्तर में कहा गया है कि लम्पी रोग से मृत पशुओं के लिए पशुपालकों को पशु क्रय किये जाने हेतु आसान दरों पर ऋण दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्या यह सही है कि सरकार की नीति जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 5 के पैरा 2 में किसानों को पशुधन के लिए आसान दर पर ऋण उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की गई थी? ये तीन प्रश्न हैं।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने पशुपालकों को मुआवजा देने की बात कही है, उसमें राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से 01 अक्टूबर, 2022 से बीमा योजना चालू कर दी गई है। दूसरा, आपने पूछा कि 1 करोड़ 6 लाख 86 हजार वाला, इसमें 60:40 का रेशो है, भारत सरकार व राज्य सरकार का। इसमें भारत सरकार से एस्केड के माध्यम से 3 करोड़ 67 लाख 85 हजार 70 रुपये प्राप्त हुए हैं। बाकी पैसा राज्य सरकार का लगा है और कुल राशि इसमें करीबन 6 करोड़ और कुछ लाख रुपये है। भारत सरकार ने 3 करोड़ 67 लाख 85 हजार 70 रुपये एस्केड के माध्यम से दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय सदस्यों से भी हमको राशि प्राप्त हुई है। चाहे वे लोक सभा के सदस्य हों, चाहे विधान सभा के सदस्य हों। उनका आंकड़ा भी मेरे पास है। विधायक कोष से 13 करोड़ 52 लाख रुपये और पांच सांसदों ने करीबन 80 लाख रुपये दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: किसका उत्तर नहीं आया?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पहले प्रश्न का मैंने पूछा, खण्ड-3 में लम्पी रोग से मृत पशुओं के लिए पशुपालकों को पशु क्रय किए जाने हेतु आसान दरों पर ऋण दिए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैंने पूछा कि क्या यह सही है कि सरकार की नीति जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 5...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, लम्पी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। लम्पी से घोषणा पत्र कहां लिंक कर रहे हैं आप? श्री कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने परिशिष्ट-1 लगाया है, थोड़ा इसको समझना चाहते हैं कि कुचामन सिटी में 36,521 कुल गोधन उससे प्रभावित हुआ, उसमें से 32,542 ठीक हुए और 3,979 मृत रहे, जबकि उदयपुर में 74 हजार लम्पी से प्रभावित हुए, लेकिन वहां उसमें डैथ 2,500 ही है। इस अन्तर का कारण क्या है? क्या वहां पर आप वैक्सीनेशन कर सके या नहीं कर सके? इतना अन्तर फिगर का क्यों आ रहा है कि एक ही जिले में इतने कम पशुओं पर भी इतनी ज्यादा डैथ हुई?

श्री अध्यक्ष: अलग-अलग समय पर लम्पी अलग-अलग फैला था, एक साथ नहीं फैला था। लम्पी का जो इम्पेक्ट है वह एक साथ पूरे राजस्थान में नहीं हुआ था। कुछ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ, फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ, इसलिये ये आंकड़ों में वैरिएशन आयेगा। पूरे स्टेट में एक साथ लम्पी शुरू नहीं हुआ था। मैं समझता हूं कि आपकी जो मंशा है कि वह कुचामन में...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकंड, पहला लम्पी केस अप्रैल, 2022 में आ चुका था।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 2022 में आ चुका था तो उसके बाद आप इन टीकों की संख्या 1 करोड़ 6 लाख बता रहे हो, ये टीके आपने उसके बाद लगाये हैं तो उन जिलों में जहां बीमार नहीं थे पशु, वहां लगाये हों तो उसके फिगर बता दो तो समझ में आ जायेगा कि कुचामन में क्या कारण रहा और उदयपुर में क्या कारण हुआ।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो बात आपने कही, वह सही है कि पहला जो केस हमारे को मिला, वह जैसलमेर जिले के हापुड़ गांव में अप्रैल, 2022 में मिला और जब इसके सैम्पल लिए गये और वह सैम्पल भारत सरकार के माध्यम से जो हिसार लैब थी उससे यह होकर

(श्री लालचन्द कटारिया)

आया कि यह लम्पी स्किन बीमारी है। उसके बाद में भारत सरकार के खुद जो मंत्री हैं रूपाला जी, वे 06 अगस्त, 2022 को जयपुर आये और भारत सरकार के पशुपालन के जो कमिश्नर हैं, वे उनके साथ थे। उसके बाद में यह तय हुआ कि जो गोट-पॉक्स दवा है, वह इसमें कारगर है जो दो कम्पनियां बनाती हैं। खुद रूपाला जी ने उस मीटिंग में टेलीफोन से हमारे सामने बात की और राजस्थान सरकार को आर्डर दिलवाये क्योंकि उनमें एक जो कम्पनी थी, वह पहले से ब्लैक लिस्टेड थी, जो आनाकानी कर रही थी वैक्सीन देने में, तो रूपाला जी ने पहल करके और वह गोट-पॉक्स वैक्सीन दिलाने का काम किया। उसके बाद में लगातार जो जिले, जिनमें लम्पी नहीं फैली, उन जिलों में तय किया गया कि पहले वहां टीकाकरण किया जाये तो जिन-जिन जिलों में यह डैथ रेट कम आ रही है उसका कारण यही है कि जैसे-जैसे हमारे को दवा उपलब्ध होती गई तो पहले हमने जहां फैल चुका था, वहां उन्होंने भी नोर्म्स के अनुसार मना कर दिया, पर जिन जिलों में कम लम्पी की बीमारी फैली, उन जिलों में हमने टीकाकरण पहले चालू किया और उसका असर यह रहा कि उस पर हम काबू कर पाये। बारां जिला एक जिला है जहां जीरो डैथ है तो जैसे -जैसे टीकाकरण की संख्या बढ़ती गई, आपकी बात भी ठीक है कि उदयपुर का जो आंकड़ा है वह यही दर्शाता है, उसका कारण भी यही है, पर उदयपुर में भी प्रभावशाली तरीके से हमारे पशुपालन विभाग ने काम किया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम।

नगरासर व खिदरत माइनरों का पानी टैल पर पहुंचाने की कार्ययोजना

58. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कोलायत लिफ्ट की नगरासर एवं खिदरत माइनर का पानी अंतिम छोर (टेल) तक नहीं पहुंच रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार टेल तक पानी पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

इन्दिरा गांधी नहर मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): जी नहीं। यह सही नही है। कोलायत लिफ्ट की नगरासर एवं खिदरत माईनर का पानी अंतिम छोर (टेल) तक समुचित मात्रा में पहुंचाया जा रहा है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा प्रश्न ही निवेदन कर लेता हूं।

(श्री पब्बाराम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण निवेदन कर लेता हूं, प्रश्न नहीं है। निवेदन यह है कि मेरे क्षेत्र में तीन लिफ्टें चल रही हैं एक नगरासर जो मैंने आपको प्रश्न पूछा, एक जम्बेश्वर लिफ्ट और एक पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय जय नारायण जी व्यास के नाम से है। दो जगह पानी आ रहा है, परन्तु पूर्व मुख्य मंत्री जय नारायण जी व्यास जो पोकरण लिफ्ट के नाम से जानी जाती है, उसमें तीस साल से एक बून्द भी पानी नहीं आया, इसका कारण क्या है? उसके अन्दर पानी दिलवाने का काम करें। यह आपके अधिकारी भी सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं। कम से कम पूर्व मुख्य मंत्री के नाम को सम्मान देने का ही आप काम करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-1 में जैसे अभी इन्होंने कहा कि पानी नहीं पहुंच रहा है, तो सात बारी पानी देना था, 5 बारी पानी पहुंच गया। इस बार हमने इन्दिरा गांधी नहर में लाइनिंग का काम बहुत शानदार तरीके से किया है पानी की दिक्कत नहीं है। जहां तक एक और सिंचाई की नहर के लिए कह रहे हैं, हमने 2023 की बजट घोषणा के अनुसार 123.15 करोड़ रुपये की स्वीकृति इसकी जारी कर दी और अगले एक सप्ताह में कार्य को प्रारम्भ कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामकेश। माननीय रामकेश जी, आप प्रश्न पूछ लें, उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया। प्रश्न पूछ लें आप।

चम्बल-गंगापुर-नादौती पेयजल परियोजना से लाभान्वित ग्राम

59. श्री रामकेश (गंगापुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चम्बल-गंगापुर-नादौती पेयजल योजना कब तक पूरी होगी तथा इस परियोजना से कितने ग्रामों को पानी मिल सकेगा एवं वर्तमान में उक्त योजना से कितने ग्राम व शहर लाभान्वित हो रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना से गंगापुर शहर को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) जिला सवाई माधोपुर एवं करौली की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु सतही

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

जल स्रोत चम्बल नदी (मण्डरायल) से चम्बल-सवाई माधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना के प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नवम्बर, 2004 में राशि रुपये 478.91 करोड़ की जारी की गई थी।

उक्त स्वीकृत परियोजना के प्रथम पैकेज के अंतर्गत मुख्य ट्रांसमिशन मैन पाइप लाइन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं सहित समग्र कार्य के कार्यादेश दिनांक 23.09.2005 को राशि रुपये 269.29 करोड़ के जारी किये गये। इस पैकेज का लगभग 74 प्रतिशत कार्य अब तक पूर्ण किया गया है तथा इसका कार्य माह दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

उक्त परियोजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 567.00 करोड़ की दिनांक 19.09.2013 को जारी स्वीकृति में, मुख्य ट्रांसमिशन लाइन के साथ-साथ सवाई माधोपुर शहर तथा सवाई माधोपुर एवं करौली जिले के 109 ग्रामों (तहसील नादौती, करौली एवं गंगापुरसिटी के क्रमश: 63 ग्राम, 15 ग्राम एवं 31 ग्राम) को पैकेज द्वितीय के अंतर्गत क्लस्टर पेयजल वितरण प्रणाली तंत्र से लाभान्वित करने हेतु दिनांक 23.09.2013 को राशि रुपये 234.90 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया। इस पैकेज का लगभग 90 प्रतिशत कार्य अब तक पूर्ण किया जाकर तहसील नादौती, करौली एवं गंगापुरसिटी के क्रमश: 63, 15 एवं 02, इस प्रकार कुल 80 ग्रामों को पेयजल आपूर्ति से जोड़ा जा चुका है। इस पैकेज का कार्य माह जून, 2023 तक पूर्ण कर शेष 29 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

गंगापुरसिटी एवं करौली कस्बे तथा पैकेज द्वितीय में सम्मिलित जिला सवाई माधोपुर एवं करौली के 109 ग्रामों को अस्थायी पम्पिंग व्यवस्था के तहत 16 एम.एल.डी. स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राशि रुपये 269.00 लाख की स्वीकृत योजना का कार्यादेश दिनांक 12.03.2018 को राशि रुपये 270.95 लाख का जारी किया गया। इस योजना का कार्य दिनांक 21.06.2018 को पूर्ण किया जाकर गंगापुरसिटी एवं करौली कस्बों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

उक्त परियोजना में सम्मिलित तथा पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित ग्रामों की वांछित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार, अस्थायी पम्पिंग व्यवस्था के तहत माह अगस्त, 2018 में पूर्ण की गई योजना से से गंगापुरसिटी को 3.00 मिलियन लीटर प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

आधारभूत संरचना कार्यों के उक्त वर्णित पैकेज प्रथम के अंतर्गत इन्टेक वैल, एप्रोच ब्रिज एवं फिल्टर प्लांट के कार्यों को उपरोक्तानुसार माह दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है तथा इन कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत गंगापुर कस्बे को निर्धारित मानक मात्रा अनुरूप स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी।

परियोजना के प्रथम पैकेज के पूर्ण क्रियान्वयन में अधिक समय लगने के कारण, गंगापुरसिटी एवं करौली कस्बों तथा पैकेज द्वितीय में सम्मिलित 109 ग्रामों में पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इन्टेक वेल से अतिरिक्त 60 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल उत्पादन बढ़ाने के लिये राशि रुपये 15.46 करोड़ के बनाये गये प्रस्तावों का प्रशासनिक अनुमोदन किया जाकर वित्तीय अनुमोदन हेतु प्रकरण वित्त विभाग में वर्तमान में विचाराधीन है।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि हमारे चम्बल-गंगापुर-सवाई माधोपुर पेयजल योजना वर्ष 2005 में एस.पी.एम.एल. कम्पनी को इसका ठेका दिया था और यह काम वर्ष 2008 में पूरा होना था। वर्ष 2008 से लेकर आज 2023 तक यह काम पूरा नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा? दूसरा, जो क्षेत्र अभी बच गए हैं, उनमें पानी पहुंचाने का क्या सरकार का इरादा है या नहीं है? तीसरी बात, मैं कहना चाहूंगा कि कम्पनी ने जितने का भी टेन्डर लिया था, करीब 478 करोड़ रुपये का और दो फेज में यह काम होना था। पहले फेज का जो काम था...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये फटाफट। प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्री रामकेश (गंगापुर): पहले फेज का काम 269 करोड़ का था, उसमें से 259 करोड़ रुपये कम्पनी ले चुकी है और काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इतने साल तक पेयजल की योजना पूरी नहीं हुई तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कब तक यह पूरा हो जायेगा?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि यह काम लेट हुआ, निश्चित रूप से लेट ही नहीं बहुत लेट हुआ। इसके जो कारण रहे उनमें पर्यावरणीय स्वीकृति भी एक कारण रही है। फर्म ने काम में विलम्ब किया, यह भी कारण रहा है और अब स्थिति यह है कि इस पूरी योजना के संवर्द्धन की आवश्यकता पड़

(डा. महेश जोशी)

गई, क्योंकि पानी की डिमाण्ड भी बढ़ गई है तो कम्पनी पर जो नियमानुसार दण्ड लगाना चाहिये वह हमने उनके ऊपर पेनल्टी भी लगायी है। इस योजना को हम पूरा करके गंगापुर और इस योजना से जितने इलाके जुड़े हुए हैं उनको पानी ठीक तरीके से और वर्तमान डिमाण्ड के हिसाब से पहुंच सके, इसलिये हमने इसकी संवर्द्धित योजना बनायी है और इस संवर्द्धित योजना को हमने एल एस सी सी में भी भेजा, लेकिन उसके मिनिट्स अभी जारी नहीं हुए हैं। कुछ क्वेरीज गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमसे की हैं। वह जैसे ही हम उनको संतुष्ट कर पायेंगे, उसके मिनिट्स जारी होंगे और योजना की स्वीकृति भी इसमें जारी की जा सकेगी। आप यह मानकर चलिये कि जो आपने कुछ अस्थायी व्यवस्था के लिए भी कहा है, उस अस्थायी व्यवस्था के तहत भी कार्य चल रहा है। 15 करोड़ से अधिक के हमने, जो आपने एक अस्थायी योजना के लिए कहा था, उसको हमने फाइनेंस में भेजा हुआ है और हमें उम्मीद है कि उसकी भी हमें जल्दी स्वीकृति मिल जायेगी। 31 लाख रुपये की एक योजना के लिए आपने और कहा है, उसके काम के हम टेन्डर जारी कर रहे हैं जिससे पानी की क्षमता बढ़ायी जा सके।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कम्पनी जिसने 2005 में टेन्डर लेकर के 2008 तक जिसको काम पूरा करना था वह पूरा नहीं किया, फिर सेकंड फेज का काम आपने 2013 में दिया, वह 2016 में पूरा होना था, वह काम उसने पूरा नहीं किया और पेमेन्ट लगभग पूरा ले चुकी है तो ऐसी कम्पनी के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की? मैं यह जानना चाहता हूं।

दूसरी बात, यह है कि मेरे क्षेत्र में पहले इन्दिरा लिफ्ट का जो काम था, वह सी डब्ल्यू सी से स्वीकृत होने के बाद में बन्द कर दिया सरकार ने। एस पी एम एल कम्पनी का यह काम है, यह पिछले 18 साल से बन्द पड़ा हुआ है। पांचना बांध 16 साल से बन्द पड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र एक-एक बून्द पानी के लिए तरस रहा है और यह सारी की सारी पेयजल की योजनाएं बन्द पड़ी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

(समय: 12.00 बजे)

श्री रामकेश (गंगापुर): मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ... (व्यवधान) पानी उपलब्ध करायेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। प्रश्न पूछिए।

श्री रामकेश (गंगापुर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री रामकेश (गंगापुर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) आई विल नोट अलाउ इट। मैं नोटिस कर रहा हूं, कौन क्या कर रहा है। यह लिबर्टी मैं आपको नहीं दूंगा कि आप इस तरह डिस्टर्ब करो। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछते हैं, आपकी समस्या ठीक है। माननीय मंत्री जी, आप कुछ जवाब देना चाहते हैं, प्रश्नकाल समाप्त होने की स्टेज पर है। आप घड़ी देखें। क्या कर रहे हैं?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी टेंडर किसी कम्पनी के खिलाफ जाता है तो जो कानूनी प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। कानून से ऊपर जाकर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जो भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, वह कार्रवाई की जा रही है और अगर और भी सख्त कार्रवाई करनी पड़ी तो वह कार्रवाई भी की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) प्रदेश में पाला, ओलावृष्टि एवं शीतलहर से बर्बाद फसलों का किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिलवाने विषयक स्थगन प्रस्ताव निम्नांकित माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए हैं:-

1. श्री गिरधारीलाल,
2. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल,
3. श्री राजेन्द्र राठौड़,
4. श्री नारायण बेनीवाल,

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री हमीर सिंह भायल,

6. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाये। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के विषय पर आज राज्य सरकार की ओर से सदन में वक्तव्य दिया जायेगा इसलिए इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से राज्य में बजरी लीजधारकों द्वारा आमजन से मनमानी वसूली करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में राज्य सरकार द्वारा संचालित रोजगारोन्मुखी विकास योजनाओं को प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में सुनियोजित नकल एवं पेपर लीक की घटनाएं होने से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र संगरिया में ग्राम सेवा सहकारी समिति हरदासवाली में विभागीय कर्मचारियों द्वारा किसानों के नाम से ऋण उठाकर किये गये गबन के संबंध में।

(6) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के माउन्ट आबू को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र' घोषित करने से विकास कार्यों पर लगे विराम से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से राजकीय महिला महाविद्यालय, गोविन्दगढ़ के भवन का निर्माण खेल स्टेडियम के पास करवाने के संबंध में।

(8) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में नव-संचालित अल्ट्राटेक सीमेन्ट उद्योग में स्थानीय योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन

(श्री अध्यक्ष)

में राजकीय महाविद्यालय में चल रहे रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंज मंडी में स्थित कोटा स्टोन कम्पनी ए.एस.आई. के वाहनों द्वारा कथित गैर-इरादतन हत्या करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश से निरन्तर हो रही गैंगवार, हत्या, डकैती इत्यादि घटनाओं से आमजन में व्याप्त भय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार सामग्री की गुणवत्ता सही नहीं होने, अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं श्री समाराम गरासिया को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री अमर सिंह, सदस्य की ओर से रुदावल कस्बे को नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में।

(2) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से यू.आई.टी., उदयपुर की परिसीमा क्षेत्र में समुचित विकास कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में मनरेगा की सामग्री एवं मेट/कारीगरों का समय पर फंड ट्रांसफर आर्डर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में किसानों की सिंचाई एवं पेयजल संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के संबंध में।

(5) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में

संचालित सीमेंट प्लान्ट्स द्वारा सी.एस.आर. बजट का जनहित की योजनाओं पर खर्च नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में नहरी परियोजनाओं के रिक्त पदों को नहीं भरने एवं पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में बिजली कटौती एवं पाले से खराब हुई फसलों पर किसानों को मुआवजा देने एवं विद्युत कटौती को तुरन्त बन्द करने के संबंध में।

(8) श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से सीकर जिले के लिए स्वीकृत कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करवाने के संबंध में।

(9) श्री प्रताप लाल भील (गमेती), सदस्य की ओर से विधान समा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति बड़गांव में प्रस्तावित सड़क निर्माण में प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में सीवरेज निकास की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री ओम प्रकाश हुड़ला, सदस्य की ओर से प्रदेश में सैनी समाज की आरक्षण की मांग पूर्ण करने एवं इस आंदोलन में युवाओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने के संबंध में।

(12) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर स्थित कोटड़ा आवासीय योजना एवं हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य में फेसिलिटी सेन्टर कम रूबाथ, गेस्ट हाउस आफ तेलंगाना स्टेट एवं अल्पसंख्यक छात्रावास हेतु आबंटित भूखण्ड को निरस्त करने के संबंध में।

(13) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में फसलों को शीतलहर से हुए नुकसान का फसल बीमा कम्पनियों द्वारा भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(15) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी की अनुसूचित जाति की छात्रा से हुए बलात्कार एवं पुलिस द्वारा बलात्कारियों को संरक्षण देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री धर्मेन्द्र कुमार।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

संगरिया की ग्राम सेवा सहकारी समिति हरदासवाली में विभागीय कर्मचारियों द्वारा ऋणों में गबन

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के प्रति किसानों का बड़ा लगाव है और विश्वास भी है। सहकारिता में किसान अपना सब कुछ जमा कराता है, अपनी कृषि संबंधी कार्यों की राशि काम में लेता है। हनुमानगढ़ जिले की 2-3 सहकारी समितियों पर काश्तकार धरने पर बैठे हैं। बार-बार ज्ञापन भी दे रहे हैं। वहां इतना गबन हो गया और काश्तकारों की कोई सुनने वाला नहीं है। संबंधित जिला कलेक्टर और संबंधित एस.डी.एम. को ज्ञापन देने के बाद भी वहां के कर्मचारियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, न ही गबन की हड़पी हुई राशि वसूल की जा रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सहकारिता एक स्वच्छ संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है एवं काश्तकारों के हित की संस्था है पर यदि इसमें इस प्रकार से गबन होते जायेंगे तो निश्चित ही काश्तकार इससे दूर हो जायेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि हरदासवाली, रावतसर और रतनपुरा, संगरिया में जिस प्रकार से गबन हुआ है, वह बहुत अलग ढंग से हुआ है और उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। मंत्री महोदय भी सुन रहे हैं। यदि सहकारिता को बचाना है और सहकारिता को आगे बढ़ावा देना है तो निश्चित ही जो कर्मचारी वहां काफी सालों से बैठे हैं, उनको इधर उधर किया जाये और प्रत्येक सहकारी समितियों की जांच कराई जाये। इसलिए मेरा निवेदन है कि हरदासवाली, रावतसर और रतनपुरा, संगरिया सहकारी समितियों के काश्तकारों को न्याय दिलायें और उनकी राशि वापस दिलायें। जय भारत, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री समाराम गरासिया।

माउन्ट आबू को पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र घोषित करने से विकास कार्यों पर लगा विराम

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि माउंट आबू रोड से जाने वाला रास्ता जो ईको सेंसेटिव जोन, 2020 में एक किलोमीटर बताया गया है, जबकि पहले 100 मीटर का दायरा किया था। उसमें माडर्न इंसुलेटर, ब्रह्मकुमारी जैसी संस्था बनी हुई है। अगर एक किलोमीटर किया जाता है तो ईको सेंसेटिव जोन में 15-16 पंचायतें आती हैं जिनमें मात्र खेतीबाड़ी की जा सकती है, अन्य निर्माण कार्यों की परमिशन लेने में आपत्ति आती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि जिस प्रकार से पहले जो 100 मीटर का दायरा किया था, उस दायरे को ही लिया जाये क्योंकि इसमें सरपचों का सारा अधिकार समाप्त हो जाता है और इससे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि कम से कम ईको सेंसेटिव जोन, 2020 के अधिनियम में 100 मीटर का दायरा दर्शाया गया है, उसको ही मान्य रखा जाये। यही मेरा आपसे निवेदन है।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष: श्री अमर सिंह (अनुपस्थित)। श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर यू.आई.टी., के परिसीमा क्षेत्र में विकास कार्यों का अभाव

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उदयपुर में यू डी ए के लिए एक प्रस्ताव आया था, जिसमें करीब 40 किमी. दूरी के गांव व पंचायतों को जोड़कर इस प्राधिकरण में लेने का प्रस्ताव दिया था, जो कतई सम्भव नहीं है क्योंकि वर्षों पहले उदयपुर में यू.आई.टी. पैरीफेरी में 130 गांवों को लिया था,

(श्री फूल सिंह मीणा)

जिसमें अनेक गांव आज भी ऐसे हैं, जहां एक नया पैसा डवलपमेंट में नहीं लगाया है। जैसे देई माता का राजस्व गांव होने के बावजूद भी विकास नहीं हुआ। ऐसे अनेक गांव हैं, जहां यू.आई.टी. की परमिशन बिना कोई भी सार्वजनिक सामुदायिक भवन है या रोड बनाना है, ऐसे कोई भी काम पंचायत द्वारा नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में शहर से लगी हुई पंचायत में ही विकास नहीं हो सका तो 40 किमी. दूरी के गांवों में विकास कैसे होगा?

(समय: 12.10 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

100 साल में भी इस पहाड़ी क्षेत्र में विकास की कोई संभावना नहीं है जबकि इन गांवों में जनजाति आदिवासी परिवार वर्षों से अपना जीवनयापन करने के लिए जमीन को मेहनत मजदूरी करके काश्त के लायक की है और अपना जीवनयापन कर रहे हैं। अगर इन पंचायतों को यू;डी.ए. में लेना है तो वर्षों से आबंटन रुका हुआ है, उसका अलाटमेन्ट करवाकर उनको खातेदारी का हक दिलावें, ताकि कम से कम उस जमीन में वह खेती कर सके या अनेक विकास कार्य करके अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके, क्योंकि वन विभाग से परेशान हैं। जो वन पट्टे भी अभी तक मिले हैं तथा यू.डी.ए. आने पर तो सारा विकास कार्य ठप हो जाएगा।

यू.आई.टी. पेरीफेरी में आज भी विकास के लिए गांव तरस रहे हैं। न साफ-सफाई है, न रोड है, न लाइट है, न शिक्षा के लिए भवन है, न पंचायत भवन बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में इनका ही विकास नहीं हुआ तो यह नई मुसीबत क्यों खड़ी कर रहे हैं? समय रहते हुए अगर इस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया तो इसके विरोध में भारी आंदोलन होगा व लोग सड़कों पर उतर कर सरकार को घेरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकरण की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

डूंगरपुर में मनरेगा की सामग्री एवं मेट/कारीगरों का समय पर फंड ट्रांसफर आर्डर

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं

(श्री राजकुमार रोत)

कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायतों का मनरेगा की सामग्री मद एवं मेट/कारीगरों का लम्बे समय से FTO नहीं होने से जिले की ग्राम पंचायतों की स्थिति खराब होने को लेकर सदन का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा।

डूंगरपुर जिले में मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों के द्वारा कच्चे-पक्के काम करवाये गये हैं और उनके सामग्री मद का भुगतान भी लम्बे समय से नहीं हुआ है, इस कारण जिले की सभी ग्राम पंचायतों के जन-प्रतिनिधियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सामग्री के FTO नहीं होने के कारण जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विकास में काफी बाधा उत्पन्न हो रही है। मनरेगा के मेट/कारीगरों का भुगतान भी 1-2 साल से नहीं हुआ है, जिससे इन मेट/ कारीगरों को घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है तथा ऊपर से सरकार ने ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम का भार भी इन्हीं पर डाल दिया है। अब ये मेट/ कारीगर महंगे एंड्रायड फोन कहां से लायें और कार्य कैसे करें? इस परिस्थिति में जिले की आम जनता से जुड़ी मनरेगा योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है और जिले के सरपंच से लेकर आम जनता सभी परेशान हैं।

अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि डूंगरपुर जिले में मनरेगा कार्यों के सामग्री का मद FTO जल्दी करवायें एवं साथ ही मेट/कारीगरों का FTO सामग्री मद से हटाकर श्रम भाग में जोड़ते हुए श्रमिकों के साथ ही मेटों/ कारीगरों का भुगतान किया जाए। डूंगरपुर जिले का FTO जल्द नहीं होता है तो जिले के जन-प्रतिनिधियों द्वारा मजबूर होकर आन्दोलन किया जाएगा और हमें भी इनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकार से विशेष अनुरोध है कि डूंगरपुर जिले का FTO अतिशीघ्र प्रदान किया जाए।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना में किसानों की सिंचाई एवं पेयजल की समस्याएं

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना की भौगोलिक स्थिति ऊबड़-खाबड़ एवं पठारी क्षेत्र में बसी हुई है, जिसके कारण किसानों को पेयजल एवं सिंचाई संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता

(श्री गोविन्द प्रसाद)

हूं कि जल है तो कल है एवं जल ही जीवन है। जब गरीब किसानों को स्वच्छ पानी पीने का एवं सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो स्वतः ही आर्थिक, शैक्षिकता में पिछड़ना स्वाभाविक है। विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में पलायन का मुख्य कारण भी सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होना एवं अन्य स्रोतों द्वारा आय नहीं होना ही है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में करीबन 300 गांव व ढांणियां पहाड़ी क्षेत्र में बसी हुई हैं, जिनके लिए मैंने पूर्व में भी सदन को अवगत कराया कि माइक्रो एवं मिनी डैम बनाये जायें, जिनका सर्वे भी कराया गया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा विशेष पैकेज नहीं देने के कारण कार्य प्रगति नहीं पकड़ पा रहे हैं एवं क्षेत्र की स्थिति जस की तस बनी हुई है। राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र में निवास करने वाली जातियां भील, मीणा, तंवर, गुर्जर, बंजारा, लोधा, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष पैकेज या दर्जा दिया जाकर उनकी मांग को ध्यान में रखकर नये माइक्रो डैम, मिनी डैम एवं कृषि विभाग के द्वारा कृषि संबंधी उपकरण जैसे फव्वारा सिंचाई, तारबंदी, पाइप लाइन पर विशेष ध्यान देकर क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाये एवं शिक्षा विभाग द्वारा भी रिक्त पदों को भरकर क्षेत्र का पिछड़ापन दूर किया जा सके।

श्री सभापति: श्री अविनाश गहलोत।

जैतारण में सीमेंट प्लान्ट्स द्वारा सी.एस.आर. बजट का जन हित की योजनाओं पर खर्च

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में संचालित चारों बड़े सीमेन्ट प्लान्ट, बांगड़ सीमेन्ट, रास; अम्बुजा सीमेन्ट, राबड़ियावास; नियोको सीमेन्ट प्लांट, निम्बोल; अल्ट्राटेक सीमेन्ट प्लांट, बलाड़ा टुकड़ा कुल मिलाकर 1185.39 हैक्टेयर भूमि में खनन कर रहे हैं। उक्त संयंत्रों के खनन से क्षेत्र में पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों एवं मानवीय जीवन पर प्रदूषण का कुप्रभाव पड़ रहा है। उक्त प्रदूषण से मनुष्य व पशुओं के फेफड़ों में सिलिकोसिस, टी.बी. तथा कैंसर जैसी कई बीमारियां हो रही हैं।

सभी प्लांट अपने सी.एस.आर. बजट को बिना किसी सक्षम अनुमोदन से मनमर्जी से अनावश्यक स्थानों पर खर्च कर रहे हैं। कुछ महीनों पूर्व प्रोफेसर नरेन्द्र बारहट व मेरे स्वयं के आग्रह पर अतिरिक्त निदेशक, उद्योग व

(श्री अविनाश)

वाणिज्य विभाग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 26.04.2022 द्वारा जिला कलेक्टर, पाली को निर्देशित किया कि प्रो. बारहट व स्थानीय विधायक, जैतारण दवारा प्रेषित परियोजनाओं पर जिला कमेटी में निर्णय करके प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। उक्त परियोजनाएं विधान सभा क्षेत्र जैतारण में माध्यमिक स्तर की समस्त कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड लगाना, प्रत्येक पंचायत से श्रेष्ठ दो विद्यार्थियों को IIT, JEE कोचिंग में छात्रवृत्ति देना, क्षेत्र की समस्त 25 से 65 वर्ष की महिलाओं का पैप मेडिकल टेस्ट करवाना तथा टेस्ट बाद पॉजिटिव पायी जाने वाली समस्त महिलाओं के IIPV टीकाकरण करना, गिर गाय नस्ल का लिंग चिन्हित (Sexed Semen) आयात करके जैतारण तहसील में कृत्रिम गर्भाधान करना, प्रत्येक राजकीय विद्यालय तथा प्रत्येक पंचायत भवन में जलग्रहण के लिए टांका तथा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना, महिला सशक्तीकरण हेतु ग्रामीण विकास चेतना संस्थान, बाड़मेर की विशेषज्ञ महिलाओं का जैतारण में प्रशिक्षण हेतु नियुक्त करना, सिलाई मशीनें देना व उनको तीन माह का प्रशिक्षण देना व अधिकतम पौधारोपण करना, जिससे एक एकड़ में 15 हजार व्यक्तियों के लिए आक्सीजन पैदा हो सकती है।

अतः राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि इन कम्पनियों को पाबन्द कर शत प्रतिशत CSR बजट जैतारण तहसील में प्रस्तावित जनहित की योजनाओं पर खर्च किया जाए।

श्री सभापति: श्री अमर सिंह।

रुदावल कस्बे का नगरपालिका में क्रमोन्नयन

श्री अमर सिंह (बयाना): महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना रूपवास की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का कस्बा रुदावल नगरपालिका के अभाव में मूलभूत सुविधाओं एवं विकास से वंचित होता आया है। रुदावल कस्बे की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। यह कस्बा क्षेत्रफल और भौगोलिक दृष्टि से नगरपालिका बनाये जाने के सारे आयाम पूर्ण करता है। यह कस्बा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस थाना, उप तहसील कार्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाएं, ग्रिड सब-स्टेशन, पशु चिकित्सालय, आयुर्वेद चिकित्सालय, अम्बेडकर छात्रावास, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च

(श्री अमर सिंह)

माध्यमिक विद्यालय, विभिन्न निजी संस्थान, कोचिंग आदि से परिपूर्ण हैं और यहां का बाजार काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां पर प्रसिद्ध ढंढार वाले हनुमान जी का मन्दिर स्थित है और नगरपालिका बनने के बाद यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कस्बा रुदावल नगरपालिका बनने के सारे नियम पूरे कर रहा है।

अतः मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि मेरे क्षेत्र की जनता का सम्मान रखते हुए इसी बजट सत्र में रुदावल कस्बा को नगरपालिका बनाने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

पचपदरा में नहरी परियोजनाओं में रिक्त पदों को भरा जाना एवं पेयजल व्यवस्था

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जनसंख्या 2011 के अनुसार 4 लाख 23 हजार लोगों एवं 2017 की पशु गणना के अनुसार 52 लाख पशुओं को पानी उपलब्ध करवाने के लिए मेरे क्षेत्र के 297 गांव पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना वृहद् पेयजल योजना, उम्मेदसागर परियोजना कैनाल से जुड़े हैं। इतने बड़े क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु परियोजना के दो खण्ड रेगुलर के एवं एक खण्ड में 7 सहायक अभियन्ता एवं 4 कनिष्ठ अभियन्ता के पद रिक्त हैं। साथ ही विभागीय मानदण्डानुसार आवश्यक तकनीकी स्टाफ के बदले महज 20 प्रतिशत कार्मिक ही कार्यरत हैं। नहरी परियोजना पोकरण-बालोतरा-सिवाना संतरा भाखरी से सिवाना के काठाडी और पायलाकला तक की लगभग 187 किमी लम्बाई में पाइप लाइनों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण हेतु महज एक अधिशाषी अभियन्ता ही वर्तमान में कार्यरत है। ऐसी स्थिति में काम कैसे होगा? जमीनी पानी खतम होने से स्थानीय जल स्रोत तो खतम ही हो गये हैं। यह समूचा क्षेत्र नहरी पानी के भरोसे ही है। आये दिन इस परियोजना की पाइप लाइन टूटने एवं लीकेज होने के कारण पीने का पानी नहीं मिलने से चारों ओर पानी की त्राहि-त्राहि मची है।

सिवाना में 700 दिनों से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। बालोतरा में भी लोग हड़ताल पर आतुर हैं। सर्दी के दिनों में यह हाल है तो गर्मियों में क्या

(श्री मदन प्रजापत)

होगा? सरकार परियोजना के तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारियों के पद भरे, बालोतरा में 15 दिनों के स्टाक हेतु रिजर्वायर का निर्माण करे, इस हेतु खेड में जमीन उपलब्ध है। पचपदरा को सीधा जोड़े, परियोजना के 4 बी एवं 4 सी चरण में पूरा बजट देकर कार्य को गति प्रदान करे एवं बालोतरा शहर सहित मुगडा-उमरलाई, वरिया, टापरा-जागसा, बिठूजा-कनाना एवं आसोतरा-किटनोद के अंतिम छोर तक मीठा पानी पहुंचाने का इंतजाम करे। समय रहते पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जायेगी। समस्या के समाधान हेतु सरकार विभागीय अधिकारियों को पाबन्द करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल जी।

डूंगरगढ़ में बिजली की कटौती की समाप्ति तथा पाले से खराब फसलों का मुआवजा

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, नियम 295 के तहत बोलने का मौका दिया। पिछले 15 दिनों से लगातार कृषि की बिजली में कटौती की जा रही है और साथ ही पिछले कुछ दिनों से भयंकर शीतलहर और बर्फबारी से किसानों की फसल तबाह हो गयी है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि किसानों के फसल खराबे का तुरंत आकलन करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। घरेलू एवं कृषि में विद्युत कटौती को तुरंत बंद किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुरेश मोदी।

सीकर में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का कार्य

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा सीकर जिले में पेयजल की समस्या को देखते हुए पिछले बजट में 8 हजार करोड़ रुपये की कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना मंजूर की थी जिसका अभी कोई काम धरातल पर नहीं आया है। अभी डी.पी.आर. भी स्वीकृत नहीं हुई है। जनता की इतनी गम्भीर समस्या पर इतनी धीमी गति से काम चल रहा है कि जानकर ऐसा लगता है कि अधिकारी बिलकुल समस्या के समाधान हेतु गम्भीर नहीं है।

इस सदन में कई बार मांग करने पर योजना स्वीकृत हुई एवं हम लोग बेसब्री से योजना का पानी आने का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना की स्वीकृति के बाद जल जीवन मिशन में भेजे जा रहे प्रस्ताव यह कहकर

(श्री सुरेश मोदी)

अस्वीकृत किए जा रहे हैं कि यहां पर कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का पानी आयेगा। क्या यह सदन जनता के हित के आवश्यक कार्यों को समयबद्ध सीमा में पूरा करने हेतु कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता? पहले यह स्वीकृति 2014-15 के द्वितीय फेज में आ चुकी थी जिसकी लागत अब दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। पिछले बजट में भी इसके लिए 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई थी। मेरा सदन के मार्फत निवेदन है कि सरकार सीकर जिले की इस महती परियोजना पर तेजी से कार्रवाई करे।

श्री सभापति: श्री प्रताप लाल जी।

बडगांव पंचायत समिति (गोगुन्दा) में सड़क निर्माण से प्रभावित परिवारों को मुआवजा

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बडगांव, पंचायत समिति बडगांव में नगर विकास प्रन्यास द्वारा 60 फीट सड़क निर्माण प्रस्तावित है। प्रस्तावित निर्माण में जो आवासीय मकान तथा दुकानें प्रभावित हो रही हैं, उनसे लगभग 125 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। जो परिवार इस सड़क निर्माण से प्रभावित हो रहे हैं, उन परिवारों से वैध दस्तावेज लेकर वार्ता करें। जो वर्तमान में मुआवजा राशि दी जा रही है वह लगभग 900 रु. स्क्वायर फीट के अनुसार मुआवजा राशि दी जा रही है जबकि बाजार रेट लगभग 3 से 4 हजार रु. स्क्वायर फीट है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि आराजी नं. 564 से 568 व 549 जो बडगांव क्षेत्र में हैं, उन स्थानों के लिए नगर विकास प्रन्यास द्वारा 3 हजार रु. से अधिक स्क्वायर फीट निर्धारित की गई है जबकि परिवारों को 900 रु. ही क्यों दिए जा रहे हैं? अत: विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकरण की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

अलवर शहर में सीवरेज निकास की समुचित व्यवस्था

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में जल-मल के निकास के निराकरण के संबंध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

(श्री संजय शर्मा)

सभापति महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में अनेक वार्डों में जल-मल निकास की कोई व्यवस्था नहीं होने से आम जनता को नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी या तो खाली पड़े प्लाटों में भरा रहता है या फिर सड़कों पर ही छोड़ दिया जाता है। इस समस्या के समाधान हेतु माननीय मंत्री महोदय को अलवर आगमन के दौरान भी अवगत कराया था, लेकिन आज तक उक्त संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर की मुगस्का, जनता कालोनी, टाइगर कालोनी, एन ई बी के पीछे एवं 200 फीट रोड के बीच का क्षेत्र (श्रीराम नगर, नेहरू नगर, विजय नगर, विमला कालोनी, जवाहर नगर, ओमकार कालोनी आदि) तिजारा फाटक का उत्तरी क्षेत्र (शिव कालोनी, गणपति विहार, यादव नगर, विश्वकर्मा कालोनी, आनन्द विहार, जसवन्त नगर, राठ नगर, भगवानपुरा), मनुमार्ग हा. बोर्ड का कुछ भाग, चौर डूंगरी, पुराना भूरासिद्ध क्षेत्र में सीवरेज लाइन नहीं है। पानी के निकास की कोई प्रबंध व व्यवस्था नहीं है जिसके चलते उक्त क्षेत्रों में सदैव सड़कों पर पानी का भराव रहता है इसलिए इन कालोनियों में जल्दी से जल्दी सीवरेज की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

अतः राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर शीघ्र से शीघ्र अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में सीवरेज लाइन डलने से शेष रहे क्षेत्रों में भी सीवरेज लाइने डलवाने की व्यवस्था करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश जी हुड़ला।

सैनी समाज की आरक्षण की मांग की पूर्ति एवं युवाओं पर दर्ज मुक़दमों की वापसी

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत प्रदेश में सैनी समाज की आरक्षण से संबंधित 11 सूत्री मांगों को मंजूर करने तथा सैनी समाज के युवाओं पर दर्ज मुक़दमों को वापस लेने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा साहेब डाक्टर भीमराव अम्बडेकर द्वारा बनाये गये भारत के संविधान के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकार

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

के समक्ष अपनी मांग रखने का तथा आंदोलन करने का अधिकार है। संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार के तहत प्रदेश के समस्त सैनी समाज के लोगों ने जयपुर में समाज की 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के समक्ष शांतिपूर्वक अपनी मांग रखने का प्रयास किया था। उस आंदोलन के दौरान सैकड़ों सैनी समाज के युवाओं पर मुकदमा दर्ज किया गया था और सरकार द्वारा उन मुक़दमों को वापस लेने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक सैनी समाज के युवाओं पर दर्ज उक्त मुक़दमों को वापस नहीं लिया गया है।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर मेरा निवेदन है कि सैनी समाज की 11 सूत्री (आरक्षण संबंधी) मांगों को जल्दी से जल्दी मंजूर करते हुए सैनी समाज के युवाओं पर दर्ज मुक़दमों को शीघ्रातिशीघ्र वापस लिया जाए। जय हिन्द। जय सर्व समाज।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर उत्तर की कोटड़ा आवासीय योजना एवं हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य में कतिपय आबंटित भूखण्डों की निरस्ती

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि ए.डी.ए. द्वारा अजमेर उत्तर विधान सभा क्षेत्र स्थित कोटड़ा आवासीय योजना एवं हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य में फेसिलिटी सेन्टर कम रूबाथ, गेस्ट हाउस आफ तेलंगाना स्टेट एवं अल्पसंख्यक छात्रावास हेतु भूखण्ड आबंटित किया गया है। चूंकि यह क्षेत्र पूर्णतः आवासीय कालोनी है जिसमें छात्रावास एव गेस्ट हाउस खोलने, दूसरे राज्य के लोगों के आने-जाने, निवास करने और उनकी धार्मिक गतिविधियों के कारण कालोनीवासियों को न केवल अनेक समस्याओं का सामने करना पड़ेगा बल्कि उनके शांतिमय जीवन में भी खलल पैदा होगा। निकट ही प्राचीन चामुण्डा माता मन्दिर, राजा भर्तृहरी की गुफा, लक्ष्मी पोल, देवनारायण मन्दिर सहित अनेक हिन्दू धर्म के धार्मिक स्थल होने कारण इन धार्मिक स्थलों की पवित्रता भी क्षीण होने की संभावना है।

इस संबंध में प्रशासन ने स्थानीय लोगों को अंधेरे में रखने का काम किया है। प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रवासियों को प्लाटों के आबंटन करने के दौरान इस क्षेत्र में किसी प्रकार की मजहबी गतिविधि एवं उनके गेस्ट हाउस एवं

(श्री वासुदेव देवनानी)

अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण की जानकारी नहीं दी गई। गुस्साये कालोनीवासियों द्वारा जिला कलेक्टर एवं ए.डी.ए. कमिश्नर से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया तब उन छात्रावास को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का आश्वासन भी दिया। प्रशासन द्वारा छात्रावास के लिए इसी स्थान पर भूमि आवंटन करना निश्चित ही न्यायसंगत नहीं है जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। उक्त छात्रावास हेतु भूमि आबंटन एवं निर्माण की स्वीकृति तुरंत निरस्त करने और इसके डिमांड के पारित प्रस्ताव को तत्काल वापस लिए जाने की आवश्यकता है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार "अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर स्थित कोटड़ा आवासीय योजना एवं हरिभाऊ उपाध्याय नगर मुख्य में फेसिलिटी सेन्टर कम रूबाथ, गेस्ट हाउस आफ तेलंगाना स्टेट एवं अल्पसंख्यक छात्रावास हेतु आबंटित भूखण्ड को निरस्त करने" की दिशा में संबंधित विभाग को पाबंद करते हुए संबंधित आवश्यक कार्रवाई कराकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करावे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हाकम अली खां। श्रीमती सूर्यकान्ता जी व्यास (अनुपस्थित)। श्री हाकम अली खां।

फतेहपुर में शीतलहर से हुए नुकसान का फसल बीमा कम्पनियों द्वारा भुगतान

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर (सीकर) व आस-पास के क्षेत्रों में सर्दी के मौसम में कई बार तापमान जीरो डिग्री से नीचे माइनस में चला जाता है। खराबे की जानकारी के लिये जिला कलेक्टर, सीकर ने गिरदावरी के आदेश दिये हैं, परन्तु गिरदावरी में खराबा आने के बाद भी किसानों को बीमा कम्पनियां क्लेम नहीं देगी क्योंकि फ़सलों की बीमा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर भिन्न-भिन्न ब्लाक के लिये भिन्न-भिन्न फ़सलों एवं क़िस्मों को नोटिफाई कर दिया जाता है। बीमा कम्पनियां उस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में पैदावार होने वाली फसल का चुनाव कर, किसान को फसल बीमा कर देती हैं, चाहे किसान ने अपने खेत में अन्य फसल ही क्यों न बोयी हो।

(श्री हाकम अली खां)

माननीय महोदय, कई बार किसान द्वारा अपने खेत में सरसो की फसल बोयी जाती है परन्तु बैंक व बीमा कम्पनी द्वारा किसान को बताए बिना अथवा सरकार के नोटिफिकेशन का हवाला देकर उसके खेत के लिये गेहूं की फसल बीमा कर दी जाती है। ऐसे में यदि उस किसान के खेत में सरसो की फसल खराब हो जाती है तो बीमा कम्पनी आसानी से क्लेम आवेदन को अस्वीकार कर देती है तथा किसान व सरकार द्वारा भरी गई बीमा प्रीमियम राशि डकार जाती है।

अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नियम बनाकर फसल बीमा के संबंध में बीमित होने वाली एवं बोयी जाने वाली फसल का चुनाव करने का अधिकार किसान साथियों को दिया जाए ताकि किसानों को उचित लाभ/राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

रामगंज मण्डी की अनुसूचित जाति की छात्रा से बलात्कार एवं पुलिस द्वारा बलात्कारियों को संरक्षण

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि रामगंजमण्डी स्कूल की एस सी छात्रा के साथ 06 दिनों तक लगभग आधा दर्जन से ज्यादा तथाकथित शान्तिदूतों ने सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने 14 सितम्बर, 2022 को रामगंज मण्डी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद 18.09.2022 तक कोई कार्रवाई नहीं की। अकस्मात छात्रा के परिजनों के पास जांच अधिकारी रौनक अली का 18.09.2022 रात्रि को फोन आया कि तुम उद्योग नगर थाना आ जाओ। परिवारजन वहां गये तो थाने में कुछ कमरों की लाइट बन्द थी। उस अंधेरे कमरे में उनको ले जाया गया जहां पीड़िता लहूलुहान हालत में पड़ी थी। ऐसी हालत में भी परिवारजनों को उससे नहीं मिलने दिया बल्कि दूर से ही देखने को कहा और ऐसी हालत में ट्रेन में बैठाकर ए.एस.आई. रौनक अली रामगंज मण्डी ले गये, जहां पर छात्रा को डराया धमकाया और उसके कहे अनुसार अदालत में बयान देने को कहा। डर के मारे जैसा रौनक अली ने कहा था वैसे ही बयान दिये परन्तु परिवारजनों के शिकायत करने पर अदालत ने पुनः बयान करवाने की अनुमति दी तो छात्रा ने पूरी बात सही-सही बता दी, जिसमें बलात्कारियों के द्वारा बलात्कार करना, स्वयं रौनक अली के द्वारा छेड़खानी करने की बात भी सामने आई।

(श्री मदन दिलावर)

(समय: 12.37 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

परन्तु अभी तक भी बलात्कारी व बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले तथा छेड़खानी व अश्लील हरकतें करने वाले ए.एस.आई. रौनक अली भी स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं क्योंकि इनको सत्ता का संरक्षण है। अतः अविलम्ब सम्बन्धित को गिरफ्तार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, अधिसूचनाएं। श्री रामलाल जाट।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

राजस्व विभाग

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्न 05 अधिसूचनाएं सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: प.6 (14) राज-4/81 पार्ट/159 दिनांक 28.09.2022, जिसके द्वारा राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड में सदस्यों का मनोनयन किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या: प. 9 (27) राज-6/2015/175 दिनांक 31.10.2022, जिसके द्वारा कतिपय ज़िलों की तहसील/उपखण्ड क्षेत्र हेतु गठित भू-आबंटन सलाहकार समिति में सदस्यों का मनोनयन किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या: प.4 (4) राज-6/2021/186 दिनांक 18.11.2022, जिसके द्वारा राजस्थान राजस्व (भू-अभिलेख, भू-प्रबन्ध और उपनिवेशन) अधीनस्थ सेवा नियम, 2019 में संशोधन किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या: प. 9(27) राज-6/2015/189 दिनांक 02.12.2022, जिसके द्वारा कतिपय ज़िलों की तहसील/उपखण्ड क्षेत्र हेतु गठित भू-आबंटन सलाहकार समिति में सदस्यों का मनोनयन किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या: प.6 (14) राज-4/81 पार्ट/208 दिनांक 28.12.2022, जिसके द्वारा श्री होशियार सिंह, सेवानिवृत्त आर.ए.एस. को सचिव, राजस्थान भूदान बोर्ड के पद पर मनोनीत किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज़ पर रखती हूं:-

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 52वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2020-21)

1. राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 52वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2020-21; एवं

राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

2. राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20.

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली।

आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम-32 के अन्तर्गत आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन की मेज़ पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शान्तीकुमार धारीवाल, आप दुबारा इसको प्रस्तुत करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

श्री अध्यक्ष: कम्पनी अधिनियम, पूरा पढ़ें आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पूरा पढ़ूं?

राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2022-23; एवं

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी आथोरिटी, जयपुर) (वर्ष 2020-21)

2. रियल एस्टेट एक्ट 2016 की धारा-77(4) के अन्तर्गत राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी आथोरिटी, जयपुर के 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविंद राम।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर सिंह भाटी।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): (श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री) ऊर्जा के स्थान पर) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग) (वर्ष 2021-22)

1. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104(4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन; एवं

(डा. सुभाष गर्ग)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22.

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इतनी बार कहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जो आपने कहा, इस सदन के बीच में मैंने चीफ सैक्रेटरी को बुलाया है और इस बारे में अब एक निर्णय करेंगे। कटारिया साहब, आपका कथन बिलकुल सही है। इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने एक मीटिंग बुलायी है और इसमें समुचित कार्रवाई करेंगे।

अनुरोध एवं मांग

मंत्रीगण की सदन में उपस्थिति के पश्चात् भी अन्य मंत्रीगण द्वारा सदन पटल पर दस्तावेजात रखा जाना उपयुक्त नहीं

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मतलब, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब मंत्री सवेरे यहां सदन में उपस्थित होते हैं तो उनकी रिपोर्ट रखने के लिए भी दूसरों को कहा जाये तो यह व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर वे सदन के प्रति इतनी जिम्मेदारी भी नहीं निभा सकते हैं कि उनका इसके बाद स्वयं को रखना है, वे यहां से चले जायें और दूसरे को पकड़ा जाये, यह परिस्थिति अच्छी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय पार्लियामेंट्री मिनिस्टर साहब, आप इस आब्जर्वेशन का ध्यान रखें। श्री सुखराम विश्नोई।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ऐसा कभी-कभी इसलिए हो जाता है कि साहब, कोई घटना ऐसी हो जाये कि जिसमें उस मंत्री को कहीं पर जाना हो तब ही ऐसा होता है बाकी अदरवाइज तो 99 परसेंट तो करीब-करीब वे ही मंत्री रखते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2017-18)

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-27(5) के अन्तर्गत राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती जाहिदा खान।

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर के वार्षिक लेखे मय आडिट रिपोर्ट (वर्ष 2021-22)

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन के नियम-46 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर के वार्षिक लेखे मय आडिट रिपोर्ट वर्ष 2021-22 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी तीन बजे स्टेटमेंट देंगे। अतिवृष्टि के सम्बन्ध में तीन बजे स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट जो है वे तीन बजे देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। वैसे मैंने आपसे व्यक्तिगत भी कहा है कि चर्चा के लिए आज और कल दो ही दिन मिलेंगे और सब माननीय सदस्य बोलना भी चाहते हैं तो मैं यह सोचता हूं कि थोड़ा-सा इसको आठ बजे तक तो कम से कम सत्र चलायें जिसके कारण से कुछ लोगों को ज्यादा बोलने का मौका

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मिल जाये। समय भी हमने इतना कर्टेल किया है कि दस मिनट से भी सात मिनट पर ले आये तो मैं यह सोचता हूं कि सात मिनट में कोई भी अपनी बात को रख नहीं पायेगा। आप कोशिश करिये और थोड़ा इसको बढ़ाइये।

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि जो समय आपकी पार्टी ने दिया है उस पार्टी के समय में वे अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करें जिससे ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को हम बोलने का मौका दे सकें अन्यथा अनप्लेजेंट ड्यूटी हमें करनी पड़ेगी। देखिये, फिर से दुबारा निवेदन है कि जितना समय दिया है, उसी समय में अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करें। श्री जगदीश चन्द्र।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार पिछले चार साल से राज्य की जनता की सेवा कर रही है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस सरकार के दो साल कोरोना महामारी में चले गये हों और दो साल सरकार को काम करने का समय मिला। कोरोना महामारी के दौरान दो-दो लॉकडाउन हुए और सरकार की आर्थिक हालत भी आपके सामने थी, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का जो बेहतरीन प्रबंधन था, उस प्रबंधन की निश्चित तौर पर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क इस बात की सराहना कर रहा है कि किस तरीके से कोरोना महामारी को कंट्रोल किया। किस तरीके से जन घोषणा-पत्र में जो हमने बात कही उस बात को कामयाब होने में हम लोगों ने कोशिश की, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोरोना महामारी का समय था तो मार्च के महीने में जो सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन होता है, उसमें भारी गिरावट आयी थी, लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब थी। सरकार की तनख्वाह देने के लिए भी स्थिति खराब थी। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद इस बात के लिए देना चाह रहा हूं कि जब 2018 में सरकार मिली थी तो सरकार की आर्थिक स्थिति क्या थी, सारा

(श्री जगदीश चन्द्र)

राजस्थान इस बात को जानता है। 20 हजार करोड़ रुपये तो एक मात्र बिजली बोर्ड का घाटा था और बाकी संस्थाओं की तो मैं चर्चा भी नहीं करूंगा लेकिन राजस्थान राज्य को विकसित बनाने के लिए हमने जनता के साथ में एक संकल्प किया था, वादा किया था और जनता ने उसी विश्वास के आधार पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनायी थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी पर विश्वास किया, हम लोगों पर विश्वास करके पांच साल का सेवा करने का जो मौका जनता ने हमको दिया है, निश्चित तौर पर मैं राजस्थान की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहला प्रदेश है जो मॉडल प्रदेश के रूप में विकसित हिन्दुस्तान के अन्दर हुआ है। राजस्थान में वर्ष 2021-22 में 11.04 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल करके हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डबल डिजिट जी.डी.पी. ग्रोथ रेट के साथ देश में सैकण्ड स्थान हासिल करना सरकार के लिए कुशल वित्तीय प्रबंधन एवं राजस्थान के समग्र तथा समावेशी विकास को दर्शाता है।

'सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म' की भावना को हर वर्ग तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का सफल प्रयास किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले चार वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि एवं कृषक कल्याण, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, युवा कल्याण, बुनियादी विकास, ऊर्जा एवं उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर देश में मिसाल कायम की है।

मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर चर्चा करूं तो यह पहली बार राजस्थान हिन्दुस्तान में ही नहीं, दुनिया में एक मात्र प्रदेश है जहां पर स्वास्थ्य की ऐसी योजनाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी हैं। दस लाख रुपये तक के फ्री इलाज की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कोई भी मरीज अगर प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो जेब में कम से कम पांच रुपये तो चैक करवाने के लिए होने चाहिए थे उसके पास में, लेकिन राजस्थान में एक जन भावना के हिसाब से 2020 में मुख्य मंत्रीजी ने जो निरोगी राजस्थान का एक संकल्प लिया था उसको आगे बढ़ाते हुए मुख्य मंत्रीजी ने जो चिरंजीवी बीमा योजना लागू की है यह निश्चित रूप से राजस्थान में एक क्रांतिकारी कदम स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाया गया है, जिसकी पूरे देश के लोग तारीफ कर रहे हैं।

(श्री जगदीश चन्द्र)

पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने इस योजना को जो पिछली सरकार के दौरान, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, दस हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी, हमने इसको बढ़ाकर बीस हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। 1750 अस्पताल इसमें पंजीकृत किये गये हैं। 88 परसेंट लोग अब तक अपना स्वास्थ्य बीमा करवा चुके हैं। यह आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर का 44 परसेंट है जबकि हमारा 88 परसेंट है और करीब-करीब 31 लाख 58 हजार लोगों का उपचार किया गया है और लगभग 3 हजार 625 करोड़ रुपये अब तक इस पर हमने खर्च कर दिये हैं।

(समय: 12.49 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की दवा योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 2022 तक करीब 949 करोड़ रुपये व्यय कर 7 करोड़ 50 लाख मरीजों को हमने यह लाभ दिया है। यह एक ऐसी योजना है जिसकी समय के हिसाब से आवश्यकता थी। जब इस देश के अन्दर कोरोना महामारी का समय था तो लोग जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे, कोई सुनने वाला, कोई बात करने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन मुख्य मंत्रीजी की संवेदनशीलता और सरकार का बेहतरीन कोरोना महामारी का प्रबंधन जहां सरकार का, हमारे हास्पिटल्स का जो ढांचा था, उसको ठीक करने का प्रयास किया गया। कई डाक्टर्स की भर्तियां हमने कीं, नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की गयी, हास्पिटल्स में आक्सीजन प्लांट हमने लगाये ताकि लोगों को एक सुरक्षा प्रदान की जा सके और मुख्य मंत्रीजी का जो फैसला था कि 24 घंटे में से 16-16, 17-17 घंटे काम करके इस बीमारी को कंट्रोल करने का, राज्य की जनता के सहयोग के साथ हमने प्रयास किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि पिछला बजट जब आया था तब हमने सरकार के माध्यम से यह बात कही थी कि हम 60 लाख पानी के कनेक्शन देंगे और राजस्थान की सरकार उसमें कामयाब हुई है।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 39 हजार 521 गांवों में 10 हजार 655 सिंगल एवं मल्टी विलेज योजनाओं तथा 133 वृहद् परियोजनाओं सहित 69 हजार 940 करोड़ रुपये की 10 हजार 788 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। अब तक 31 लाख 26 हजार से अधिक परिवारों को 'हर घर जल

(श्री जगदीश चन्द्र)

कनेक्शन' के माध्यम से पेयजल पहुंचाया गया है। सरकार का कमिटमेंट है कि 60 लाख कनेक्शन हम इस साल लोगों को देंगे जिसमें सरकार आगे बढ़ रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान के भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारे राजस्थान के 80 परसेंट आबादी खेती पर आधारित है। पहली बार राजस्थान की सरकार ने खेती के लिए सिंचाई की परियोजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण काम किये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2022-23 में विभिन्न सिंचाई योजनाओं पर दिसम्बर, 2022 तक करीब 01 हजार 429 करोड़ रुपये हमने खर्च किये थे। 710 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता हमने सृजित की थी।

पारदर्शी जल प्रबन्धन के उद्देश्य से बांधों और नहरों के लिए एक स्काडा योजना सरकार चालू करने जा रही है जिससे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन पारदर्शी और ठीक तरीके से हो सके। इसमें नर्मदा नहर, गंगनहर, भाखड़ा नहर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पार्वती, जिला धौलपुर की नहर व अन्य नहरों का कार्य प्रगति पर है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरहिंद फीडर के माध्यम से गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में पानी आता है, वह फीडर लम्बे समय से जर्जर हो चुका है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों की संवेदनशीलता और सिंचाई की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए एक किसान मुख्य मंत्री होने के नाते पहली दफा वर्ष 2018 में 03 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। कोरोना बीमारी फैलने के बावजूद भी पिछली बार 425 करोड़ रुपया अलग से दिया ताकि पैसा कम नहीं पड़ जाए और सरहिंद फीडर का काम पूरा हो जाए। जिस दिन सरहिंद फीडर का काम पूरा हो जाएगा, उस दिन मैं मानता हूं कि भाखड़ा का हमारा अन्तरराज्यीय बंटवारे के हिसाब से जो शेयर बनता है, हमें पूरा पानी मिलेगा।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि पहली दफा फिरोजपुर फीडर नहर के लिए 450 करोड़ की डी.पी.आर. बनी है। इसमें आधा पैसा हमारा है और आधा पैसा पंजाब सरकार का है। मुख्य मंत्रीजी ने 200 करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया। डी.पी.आर. बन गई है। जिस दिन काम स्टार्ट हो गया और जिस दिन यह काम पूरा होगा तो

(श्री जगदीश चन्द्र)

2700 क्यूसेक्स की गंग कैनाल की जो हमारी नहर है, उससे किसानों को पूरा पानी मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि लम्बे समय से यानी 70 साल से भाखड़ा नहर के खाले पेंडिंग पड़े हुए थे। पिछली सरकार ने तो खाले बनाये ही नहीं थे। हमारी सरकार ने भाखड़ा के लिए 200 करोड़ के बजट की जो घोषणा की थी, वह जमीन पर आ चुकी है, जिससे खाले बनने प्रारम्भ हो गये हैं। मुख्य मंत्रीजी ने सिंचाई के लिए जो बेहतरीन प्रबन्ध किया है उसका कोई जबाव नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे 13 जिले पीने के पानी के लिए तथा दो लाख हैक्टेयर की सिंचाई की जमीन जिससे सिंचाई होगी, वह योजना पेंडिंग है। केन्द्र सरकार को हमने बार-बार निवेदन किया, लेकिन भारत सरकार से इस बात का हमेशा गोलमोल जबाव आया। इस पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का कमिटमेंट है कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के मामले में सीमित संसाधनों के बावजूद भी इस पर काम करेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि कल-परसों आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। हमारे जन घोषणा पत्र में यह बात थी कि 50-50 हजार रुपये का कर्जा को-आपरेटिव बैंक का, भूमि विकास बैंक का, हम माफ करेंगे। हमने माफ किया। 22 लाख किसानों के 14 हजार करोड़ रुपये हमने माफ किये हैं। माननीय सदस्य यह भी कह रहे थे कि ठाकरी के किसान ने रायसिंहनगर में कर्जे की वजह से आत्महत्या की। मैं माननीय सदस्य कहना चाह रहा हूं, आप यह भी बोलते कि किसानों का 140 दिन तक आन्दोलन चला जिसमें 700 किसानों की कुर्बानी हुई है तीन खेती-बाड़ी के कानून को लेकर। अगर उसकी भी चर्चा करते तो निश्चित तौर पर हम समझते कि ये लोग किसानों के प्रति गम्भीर हैं। इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। हमारी कांग्रेस की सरकार ने पहली बार कृषि का अलग से बजट पेश किया। हमने अलग से बजट का प्रावधान किया ताकि सारे किसान साथी देख सकें कि किस मद पर कितना-कितना पैसा हमने खर्च किया। यह सरकार की मंशा थी। सरकार का किसान के साथ कमिटमेंट था। हमने यह करने का प्रयास किया। एम.एस.पी. के हिसाब से हमने फसल की खरीद भी की है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से पूछना

(श्री जगदीश चन्द्र)

चाह रहा हूं कि इस देश के 242 किसान संगठन हैं, भारत सरकार बताये कि एम.एस.पी. पर किसान संगठनों से क्या समझौता हुआ जो कि आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि वह बताये कि जब आन्दोलन खतम हुआ था तब किस शर्त के आधार पर समझौता हुआ था। एम.एस.पी. का इश्यू आज तक भारत सरकार के लेवल पर पेंडिंग पड़ा हुआ है और 700 किसानों की जो कुर्बानी हुई है, उसका भी अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है। उनके परिवारों को किस प्रकार से कम्पन्सेट किया जायेगा, इस बात की भी चर्चा नहीं की गई। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस पर भी केन्द्र सरकार गौर करे।

सभापति महोदय, मैं राशन की भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार राशन व्यवस्था को बन्द करना चाह रही थी, पी.डी.एस. सिस्टम को लेकिन पांच राज्यों के चुनाव थे। भारत सरकार बन्द नहीं कर पायी। भारत सरकार को इस बात का डर था कि एक रुपये किलो के हिसाब से पी.डी.एस. का सिस्टम जो हमने शुरू कर रखा है, अगर उसको गलती से बन्द कर दिया तो देश का वातावरण खराब हो सकता है। सरकार के लिए उल्टा पड़ सकता है। सरकार डरी हुई थी लेकिन दो साल से भारत सरकार का पोर्टल बन्द था। हमारी सरकार ने उस पोर्टल को चालू किया। उसके माध्यम से बी पी एल और स्टेट बी.पी.एल. तथा दूसरी योजनाओं में अब तक 386 करोड़ रुपये की राशि हमारी सरकार द्वारा खर्च की गई है। तीन लाख परिवारों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि राशन की जो व्यवस्था है उसको केन्द्र सरकार अल्टीमेटली बन्द करेगी। अभी केन्द्र सरकार का जो बजट आ रहा है, उसमें देखना, या तो उसका पैसा कम कर दिया जायेगा या कोई दूसरा रास्ता निकालकर इसको बन्द करने की साजिश भारत सरकार की तरफ से की जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं ट्रांसपोर्ट विभाग की बात करना चाहता हूं। वर्ष 2018 में जिस हालत में हमें यह विभाग दिया गया था, उस समय उसकी क्या स्थिति थी? पूरे विभाग को बेचने की तैयारी कर ली थी। राजस्थान की सरकार द्वारा उसको तन्दुरुस्त करने की कोशिश की गई है।

हमारे जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, सरकार ने उनका ध्यान रखते हुए पहली बार 80 लाख 59 हजार परीक्षार्थियों को नि:शुल्क यात्रा

(श्री जगदीश चन्द्र)

सुविधा का लाभ दिया है ताकि बच्चे परीक्षा दे सकें। गरीब बच्चा जो सरकारी नौकरी में आना चाह रहा है, उसका बन्दोबस्त हमने किया है।

सभापति महोदय, अगर मैं खेलों की बात करूं तो राजस्थान सरकार ने खेलों में एक अहम रोल अदा किया है। पहली बार खेल को प्रायोरिटी के आधार पर हमने दो परसेंट आउट आफ टर्न जाकर खिलाड़ियों का नौकरी के लिए कोटा निश्चित किया है। मेजर ध्यानचन्दजी के नाम पर हमने गांव और देहात के अन्दर स्टेडियम अनाउंस किये कि स्टेडियम बनें और खेल का वातावरण बने। 30 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण ओलम्पिक के माध्यम से हमारे बच्चों का हुआ है। शहरों में भी ओलम्पिक की तैयारी हो रही है। आउट और टर्न जाकर नौकरी का प्रावधान किया है। खेलों का वातावरण बन रहा है और हमारे जो बड़े-बड़े शहर हैं जैसे जोधपुर है, वहां आई पी एल क्रिकेट प्रतियोगिता हेतु स्टेडियम की तैयारी की जा रही है। दूसरी जगह भी तैयारियां की जा रही हैं। खेलों का वातावरण बनाने के लिए हरियाणा और पंजाब की तरह से खिलाड़ियों को इनाम देने की जो योजना है, उसकी राशि को भी हमने बढ़ाया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि कानून-व्यवस्था की बात बी.जे.पी. के लोग बार-बार करते हैं। कहते हैं कि राजस्थान के अन्दर कानून-व्यवस्था खराब है, कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, आये दिन धरने प्रदर्शन होते हैं। मैं कानून-व्यवस्था की बात करूं तो हमेशा 156(3) में कोर्ट के माध्यम से एफ.आई.आर. दर्ज की जा सकती थी। हमने कानून बनाया और व्यक्ति जो एफ.आई.आर. दर्ज करवाना चाह रहा है उसका कम्पल्सरी एफ.आई.आर. के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया। अब एफ.आई.आर. ज्यादा दर्ज हुई हैं और इनको लगता है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि एफ.आई.आर. को डाउनलोड की व्यवस्था हम लोग बैठा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति एस.एम.एस. के माध्यम से अपनी एफ.आई.आर. को डाउनलोड कर सकता है और उसको पता लग सकता है कि मेरी भी एफ.आई.आर. दर्ज हुई है या नहीं हुई है। यह व्यवस्था हमने की है। थानों में हमने सी सी टी वी कैमरे भी लगाये हैं, स्वागत कक्ष भी बनाये गये हैं और

(श्री जगदीश चन्द्र)

खासकर के हमारी महिलाओं के लिए अलग से एडिशनल एस.पी. लेवल का एक अधिकारी हमने नियुक्त किया है। 'क्राइम अगेंस्ट वुमेन' सेल का गठन किया गया है। अगर किसी महिला के साथ क्राइम होता है तो इस सेल में जाकर उसका ट्रायल हो सकता है, एफ आई आर दर्ज हो सकती है और अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पहले 129 दिन का टाइम था, अब हमने उसको घटाकर 72 दिन कर दिया है ताकि लोगों को यह पारदर्शी और साफ सुथरा लगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। समाप्त करें।

(समय: 13.00 बजे)

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): अभी तो शुरू ही हुआ है माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पहली बार सरकार ने जिला लेवल पर साइबर क्राइम के थाने खोलकर साइबर अपराध को कंट्रोल करने की व्यवस्था की है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पहला राज्य है भारत का, जहां आप ऑनलाइन जेल की कार्रवाई देख सकते हो। हमने जेल को भी ऑनलाइन किया है। यह भी अपने आपमें बहुत बड़ी बात है।

माननीय सभापति महोदय, बार-बार रीट के बारे में आन्दोलन किया जा रहा है कि रीट की परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक हो रहे हैं। कम से कम हमने परीक्षा कराने की कोशिश तो की।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): 2013 से 2018 का समय भी तो आप याद करो, जब कोर्ट की तरफ से सरकार की कितनी नौकरियों पर स्टे हुआ था, कितनी नौकरियां लगी थीं? कम से कम हमने हिम्मत तो की, हमने एग्जाम तो कराया और जो लोग पेपर लीक में शामिल थे, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। हमारे बोर्ड के अध्यक्ष को हमने सस्पैण्ड किया, उसको जेल भेजा गया, लेकिन जिस तरह से आज प्रदेश में वातावरण इनके द्वारा खराब किया जा रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। बार-बार सी.बी.आई. इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, कोई दूसरी इंक्वायरी की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। प्लीज, सहयोग करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): यह तो मुख्य मंत्रीजी की संवेदनशीलता है कि हर मुद्दे पर विचार करते हैं। (व्यवधान) धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, महामहिम के अभिभाषण के पैरा 7 और 13 में अपनी सरकार को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही सुशासन वाली सरकार बताया और कृषि और कृषक कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली सरकार बताया। जिस सरकार की शुरुआत ही वादाखिलाफी के साथ हुई है, किसानों के साथ वादाखिलाफी की कि हम सत्ता में आते ही आपके 10 दिन में ऋण माफ कर देंगे और आज चार साल पूरे हो गये इस सरकार के, प्रदेश के लाखों काश्तकार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है जाते-जाते कहीं इनको सद्‌बुद्धि आ जाये और जो वादा किया है उसको निभा दें।

माननीय सभापति महोदय, किसान के हित में अगर किसी ने काम किया है तो वह देश का यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी है, जिसने एक नहीं, कई योजनाएं लागू करके किसान के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का भरसक प्रयास किया है। किसान सम्मान निधि, जितने भी किसान हैं, साल का छह हजार रुपया उनके खाते में स्वत: ही चला जाएगा। माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने अब तक 2 लाख करोड़ रुपया किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर कर दिया। इससे बड़ा कोई भी किसान का हितैषी हो नहीं सकता। अगर प्राकृतिक आपदा से किसान की फसल नष्ट हो जाये तो उसके लिये भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की और परिणाम क्या निकला कि अब तक 01 लाख 28 हजार करोड़ रुपये का क्लेम जो प्रभावित किसान हैं न, उनको मिला है। हमारे प्रदेश के किसानों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 20 हजार करोड़ का क्लेम मिला है। यानी कुल क्लेम के 17 प्रतिशत से भी ज्यादा राजस्थान के किसानों को यह राशि मिली है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए किसान के कल्याण की बात आप मत करो, आपके मुंह से यह शोभा नहीं देता।

माननीय सभापति महोदय, आपकी हालत क्या है? अभी भी आपका 2020-21 का 246.83 करोड़ का जो प्रीमियम है फसल बीमा का, वह आपको देना बाकी है। 2021-22 और 2022-23 के प्रीमियम का कोई अता-पता ही नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, किसान को उसकी उपज की अच्छी कीमत मिल जाये, तो उसके लिये भी MSP की गारंटी दी कि जो लागत आती है,

(श्री ज्ञानचंद पारख)

उसका डेढ़ गुना किसानों को मिलेगा। सारे राज्य किसानों की फसल की खरीद कर रहे हैं, पर राजस्थान सरकार किसान की अनदेखी कर रही है। हरियाणा में, यू.पी. में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में वहां की सरकार 2,100 रुपये में बाजरा खरीद रही है और यहां भारत सरकार के बार-बार पत्र लिखने के बाद भी आपने किसानों की फसल की पूरी कीमत मिल जाये, उसकी अनदेखी की और यहां किसान को मजबूरी में 1,100 रुपये में अपना बाजरा बेचना पड़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, किसान को उसके हक का यूरिया मिल जाये, ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो, तो उसकी व्यवस्था भी भारत सरकार ने अपने स्तर पर नीम कोटेड यूरिया के रूप में की।

माननीय सभापति महोदय, हालत क्या है? अभी जो फसल का समय था, कैसी हालत हुई DAP की, कहां कमी आ गयी? भारत सरकार को आपने डिमांड भी लेट भेजी 8 लाख टन की और उसके बदले में भारत सरकार ने आपको 12 लाख टन DAP दिया, पर आप समय पर जहां-जहां आपके केन्द्र थे न, जहां से किसानों को खाद लेना था, आप समय पर वहां खाद नहीं पहुंचा पाये। किसानों को यूरिया कम, DAP कम और डण्डे ज्यादा पड़े। वहां पर हंगामा हुआ और कई किसानों को तो मजबूरी में ब्लैक में भी यह खाद लेनी पड़ी। कोई गुजरात से लाया, कोई हरियाणा से लाया और कुछ ने तो यहां से ब्लैक में लिया। आप किसानों के प्रति इतने गैर-जिम्मेदार हो।

माननीय सभापति महोदय, बात करते हैं कि किसान के कल्याण की सरकार है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री तो कितनी दूर की सोचते हैं कि जो मिट्टी है, उसका उपजाऊपन भी किसान की फसल को, उसकी पैदावार को बढ़ा सकता है। यह देश का पहला प्रधान मंत्री है, जिसने मृदा योजना के माध्यम से मिट्टी का परीक्षण करवाकर उसका उपजाऊपन कैसे बढ़ जाये, उस दिशा में भी काम किया, ताकि किसान की पैदावार बढ़ सके।

माननीय सभापति महोदय, किसानों की अनदेखी के जो नमूने हैं न, मात्र कृषि विभाग नहीं, इनका सहकारिता विभाग देखो। जो ऋणी किसान हैं, उनको दो योजनाओं के तहत बीमा की सुरक्षा दिया जाना होता है। सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जो ऋणी किसान है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसने लोन ले रखा है, तो उसका सारा का सारा लोन माफ होने का प्रावधान इस योजना में है। 2019-20 में आपने बीमा कम्पनी से MOU नहीं किया,

(श्री ज्ञानचंद पारख)

जिसकी जानकारी मैं सदन में लाया था। मंत्री महोदय ने गलती मानी और यहां आश्वासन भी दिया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। न तो कार्रवाई हुई और इस अवधि के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हो गयी, जो क्लेम के हकदार थे, बीमा के हकदार थे, उनको सरकार ने किसी प्रकार की कोई राशि नहीं दी। दूसरी योजना है सहकार दुर्घटना बीमा योजना। इसमें यदि किसी काश्तकार की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपये का क्लेम उसको बीमा कम्पनी देती है। 2019-20 में आपने बीमा कम्पनी से MOU नहीं किया, जबकि ऋण लेते हुए सारे किसानों की उनकी बीमा की प्रीमियम की राशि की बाकायदा कटौती की थी, उसकी राशि कटने के बाद भी उसको लाभ नहीं दिया जाना, इससे बड़ी कोई घटना किसानों के विरुद्ध में किसी सरकार की हो नहीं सकती।

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार बात करती है कि हम किसान के हितैषी हैं, मेरे ही क्षेत्र में JPMIC, जो पाली, जोधपुर सीमा पर है, किसानों की भूमि उद्योगों को देने के लिये अधिगृहीत कर ली। माननीय सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री ने स्पष्ट प्रावधान किया कि यदि किसी इंडस्ट्री के लिये जमीन लेंगे तो किसान को उस भूमि की कीमत का चार गुना पैसा सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में दिया जायेगा पर यहां की सरकार का आप काम करने का नमूना देखो, जमीन आपने ले ली, 2013 में ही वहां पर जो 9 गांव हैं, उनके भू-परिवर्तन पर, भू-रूपांतरण पर आपने रोक लगा दी। उसके कारण वहां की DLC सही निर्धारित नहीं हो सकी। वहां के किसानों ने बार-बार कहा कि आप हमारी DLC को दुरुस्त करवा दो, क्योंकि हमारे यहां पर रूपान्तरण पर रोक लगी हुई है। माननीय सभापति महोदय, इसमें प्रावधान भी है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि आज की बाजार दर से, न कि DLC से। बाजार दर का मतलब उन 9 गांवों के जो क्षेत्र हैं, वहां यदि किसी खेत की जमीन की रजिस्ट्री हुई, पंजीयन हुआ है तो वह बाजार दर मानी जाती है, न कि आपकी DLC और माननीय सभापति महोदय, वहां पर जो DLC है और वहां जो बाजार कीमत है, उसमें चार गुने का अन्तर है और वहां पर किसानों को जो पैसा मिलेगा, आज का जो बाजार मूल्य है, उसकी तुलना में आधा पैसा भी उनको नहीं मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, यह जो अधिगृहीत भूमि है, इसमें वह भूमि भी आपने अधिगृहीत कर दी जो कि गांव की आबादी से चिपकती भूमि है। गांव की आबादी से चिपकती भूमि में आपका नियम भी है कि पंचायत मुख्यालय पर

(श्री ज्ञानचंद पारख)

आबादी के 500 मीटर तक यदि कोई मकान बन गया, कोई रहवास कर रहा है तो उस भूमि को कभी डिस्टर्ब नहीं किया जायेगा लेकिन आपने गूगल से नक्शा लिया, जो आबादी भूमि थी, उसके अलावा जितनी भी भूमि थी, न आपने मौका-मुआयना कराया, चाहे वहां पक्के मकान बने हुए हैं, इन 9 गांवों में 500 से भी ज्यादा पक्के मकान इस आबादी भूमि से चिपकती भूमि पर बने हुए हैं। आपने वह सारी की सारी भूमि जेपी.एम.आई.सी. के खाते में दर्ज कर ली। वहां के जो किसान हैं उनकी खेती की भी जमीन गयी और जहां रहवास कर रहा है, वह जमीन भी आपने उनके खाते में दर्ज करवा दी। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि यह आपका अंतिम वर्ष है, अभी भी आप नहीं सुधरे तो यह किसान आपकी अंतिम क्रिया कराने में ज्यादा देर नहीं करेंगे। मेहरबानी करके इनकी सुध लो। जो मकान बने हुए हैं वह बच जायें, उनको आप कम से कम उससे बाहर कर दो। उसके दायरे से बाहर कर दो।

माननीय सभापति महोदय, नियम क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी जमीन हम इंडस्ट्री के लिये लेंगे तो बाजार दर का 4 गुना उसको मुआवजा देंगे। अब आपको मुआवजा पूरा देना नहीं है। यहां भी आपकी नीयत ठीक नहीं है। आपने क्या किया? पूरा का पूरा ग्रामीण बैल्ट है। इसको आपने जोधपुर की जे.डी.ए. के समीप मानते हुए, यह जोधपुर से जिला ही अलग है, यह पाली जिला अलग है, उसको आपने विशेष विनिवेश रीजन घोषित कर दिया। वहां नियम क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में तो है 4 गुना और इसमें आपका नियम है बाजार दर का ढाई गुना, मतलब कि दोहरी मार है उसके ऊपर। कोई उसका दम निकालना हो, वैसा काम आपने अधिगृहीत भूमि में किया है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि जिस किसान कल्याण के लिए आप दंभ भरते हो, मेहरबानी करके आप थोड़ी किसानों की सुध ले लो, वरना जो किसान की आज हालत है, देखा होगा आपने, यह 2 दिन में जो ओलावृष्टि हुई है, जो अतिवृष्टि हुई है, जो बरसात आयी है, जो शीतलहर आई है, वह पहले से ही मरा हुआ है। अभी तो आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र की भी अरंडी की, चने की जो अन्य फसलें हैं, वह पूरी की पूरी नष्ट हो गयीं। आप अपने जिले के जो अधिकारी हैं, उनको थोड़ा स्पष्ट आदेश दो, साफ मन से आदेश दो कि वह सही गिरदावरी कर दे, वरना लीपापोती वह कर देते हैं। खराबा पूरा होता है, उसको दिखाते नहीं हैं और उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है, इसलिए मेहरबानी करके किसान के प्रति नरम रुख अपनाते हुए, उनको बर्बाद फसलों का सही मुआवजा मिल जाये। सही

(श्री ज्ञानचंद पारख)

फसलों का मुआवजा वह आपसे नहीं मांगता, लेकिन जो वास्तव में बीमारी हुई है, उस फसल के लिये तो मुआवजा लेने का उसका हक बनता है।

आपने जो सम्पत्तियों के पंजीयन शुल्क पर 10 परसेंट सरचार्ज आपदा राहत के नाम से लगाया है। यह जो आपका सरचार्ज का पैसा है, वह करोड़ों रुपया आपके खाते में पड़ा है। यह जनता ने आपको ऐसे कामों के लिये ही दिया है। मेहरबानी करके यह जो आपदा राहत का पैसा है, बाकी कम पड़े तो आपकी सरकार के खाते में से लेकर, वाकई में जो किसान प्रभावित हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई हो जाये, उतनी मदद आप करवा दो।

माननीय सभापति महोदय, यह जो महामहिम राज्यपाल का प्रतिवेदन है, ऐसा लगता है कि कोई बेबस और मजबूर सरकार का प्रतिवेदन है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का पहला और दूसरा काल भी देखा है। कैसे मजबूत मुख्य मंत्री थे वह, लेकिन इस बार, मजबूत की जगह मजबूर मुख्य मंत्री बन गये। हमारे यहां कहते भी हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, पर हमारे प्रदेश में क्या हो गया? मजबूरी का नाम राजस्थान का गांधी। यह राजस्थान का गांधी इतना मजबूर हो गया। कहता है कि हमने दो कोविड झेले। एक तो चाइना वाला कोविड, वह तो देश के प्रधान मंत्री ने देश से भगा दिया और एक आपके अपनी पार्टी के कोरोना का है यह वायरस, यह शायद आपकी सरकार की मजबूरी बन गया है। इससे आप संभल नहीं पा रहे हो। वह आपकी सांसें निकाल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे में प्रदेश को संभालना थोड़ा मुश्किल काम हो गया। हमने कांग्रेस देखी है। देश की मजबूत कांग्रेस भी देखी है। प्रदेश की मजबूत कांग्रेस भी हमने देखी है। कैसी कांग्रेस थी, कभी दुश्मन देश के दो टुकड़े करने का दंभ भरने वाली कांग्रेस, दंभ भरते हैं न कि हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े करवा दिये, आज वही कांग्रेस टुकड़े-टुकड़े करने वाली गैंग के चंगुल में लगातार फंसती जा रही है। यह जो राहुल गांधी जी की यात्रा है, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो देश के टुकड़े-टुकड़े करने के मंसूबे पाल रहे हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके बारे में इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी जी देश में शांति, अमन का पैगाम दे रहे हैं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैं तो कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूं। मैं तो कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूं कि कैसी कांग्रेस थी आपकी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): दुनिया में प्यार का संदेश, शांति का संदेश देने आ रहे हैं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैंने तो कांग्रेस की तारीफ की है कि कितनी मजबूत कांग्रेस थी। अब भी आप संभल जाओ। मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूं कि थोड़ा उनको दूर रखो, वरना जनता आपको लगातार कुर्सी से दूर रखेगी। अभी भी आपने सबक नहीं लिया। लोक सभा में आपकी कैसी हालत है? पूरे देश में 3 राज्यों में आप सिमट गये हो। ऐसे लोगों के बूते आपकी सत्ता आने वाली नहीं है। कम से कम देश हित के विरुद्ध काम करने वाले व्यक्तियों को अपने से दूर रखो। हम तो चाहते हैं कि ताकतवर कांग्रेस हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इंटरवीन नहीं करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैंने ताकतवर कांग्रेस की बात की।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इनवाइट नहीं करें। इधर आसन की तरफ देखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, इसको एक्सपंज किया जाये, नहीं तो हम भी बोलेंगे। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, सहयोग करिये। विराजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): रसोई गैस हजार रुपये के पार गयी। डालर सस्ता नहीं हुआ।

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये, माननीय सदस्य। वक्ता जिसको मैंने इजाजत दी है, उसके अलावा आप किसी का अंकित नहीं करेंगे।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): भ्रष्टाचारियों के सामने भी यह सरकार कितनी बेबस, कितनी मजबूर हो गयी, नजारा देखा आपने? एक बार शिक्षक सम्मेलन में माननीय मुख्य मंत्री जी, सद्भावनावश कह रहा हूं मैं, शिक्षकों से पूछ बैठते हैं कि आपको ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिये पैसा तो नहीं देना पड़ता? क्या जवाब मिला था, याद है न आपको? सारे शिक्षकों ने चिल्लाकर कहा, देना पड़ता है, देना पड़ता है, देना पड़ता है। मुख्य मंत्री जी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

को विश्वास नहीं हुआ। कहीं लोगों ने गलत नहीं सुन लिया हो, इसलिए दुबारा पूछा।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): दुबारा पूछा, तो कुर्सी पर खड़े होकर कहा, देना पड़ता है। कहां मजबूरी है मुख्य मंत्री जी की? पैसा देना पड़ता है, सब कह रहे हैं तो जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, पैसा लेने वाले हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते?

हमने 1985 में उस कांग्रेस को भी देखा है कि जहां जो दागी आपके नेता थे, चाहे कितने भी दागी दिग्गज नेता हो, भ्रष्टाचारी था, बेईमान था, आपने उसको टिकट से भी वंचित कर दिया था। आज आप उनके चंगुल में लगातार फंसते जा रहे हो। मेहरबानी करो और यह भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने का प्रयास करो।

जहां भी जाओ, ट्रांसफर का पैसा, पोस्टिंग का पैसा, काहे काहे का पैसा?

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, होता क्या है कि जब कोई भी अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, बयान क्या देता है कि हमको ऊपर पैसे देने पड़ते हैं। यह ऊपर वाला कौन है? थोड़ा बता दो आप, जिसको वह पैसे पहुंचाता है, आपके लिये वह भ्रष्टाचार करता है, आपके लिये वह रिश्वत लेता है। ऊपर वाले जिस दिन इस सिस्टम को बंद कर देंगे तो नीचे वाला भ्रष्टाचार स्वत: ही समाप्त हो जायेगा। भ्रष्टाचारियों को कितना संरक्षण है।

मेरी अपनी नगर परिषद् में एक ठेकेदार ने भ्रष्टाचार के चलते अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। उसने सुसाइड कर लिया। हमारी पार्टी का था, हमारी पार्टी ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुसाइड नोट की फोरेंसिक जांच भी हो गयी। उसकी राइटिंग मानी गयी। अब तक न तो सरकार ने कार्रवाई की और न पुलिस ने कार्रवाई की। उसके परिवार वालों ने चार-चार बार मुख्य मंत्री जी के सामने फरियाद कर दी कि हमको न्याय दिलाओ, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करो, पर मात्र आश्वासन मिला। कैसे मुख्य मंत्री से? जो कभी मजबूत और भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुख्य मंत्री माने जाते थे। चार बार ज्ञापन देने के बाद भी, चार बार फरियाद करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, कहते हैं कि हम संवेदनशील सरकार हैं, काहे की संवेदनशीलता आपकी? पाली में अभी सीवरेज और पाइप लाइन के लीकेज की वजह से सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए। पांच-सात मकान तो ऐसे हैं जिनको गिराने की नौबत आ गई।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): बाकी मकानों में दरारें आ गई हैं। जनता ने कई बार प्रशासन से गुहार कर ली, जिला कलेक्टर महोदय ने वहां से रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को भी भिजवा दी कि वाकई में इतने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। विराजें आप।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): उसके बावजूद भी अब तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। वो कहां निवास करेंगे?

श्री सभापति: विराजिये आप। सहयोग करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, एक बात और है। कांग्रेस के हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं, अच्छे मंत्री हैं, वो लगातार जिले का दौरा करते हैं। वो वहां पर करते क्या हैं? टूटी-फूटी कांग्रेस की....

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री रामनारायण मीना।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: कृपया सहयोग करें। विराजिये आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज। अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: माननीय नेता, प्रतिपक्ष। माननीय नेता, प्रतिपक्ष।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आगे के वक्ता का समय काट लूंगा। (व्यवधान)

मैं सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करूंगा कि जो समय आपका निर्धारित किया गया है, इधर से 7 मिनट और उधर से 10 मिनट, इधर वक्ता ज्यादा और उधर वक्ता कम। समय का ध्यान रखेंगे। जब आसन आपको निर्देश दे कि आप विराजिये तो आप विराजिये, अन्यथा आगे वाले

(श्री सभापति)

वक्ता बोल नहीं पाएंगे और मैं निश्चित समय पर आपको बैठाने के लिए पाबंद करूंगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी कृपया सहयोग करेंगे। श्री रामनारायण मीना।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में अपनी कुछ बात अर्ज करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य करप्शन के बारे में कह रहे थे। यह परिपाटी कब चालू हुई? माननीय कटारिया साहब को भी पता है कि ए.सी.बी. के केस में इजाजत देने की मुनादी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। यह पहला केस, पहला उदाहरण, आप इसके रिकार्ड को उठाकर देख लें। यह सही है कि यदि हम संवेदनशील हैं, शुचिता पारदर्शिता की बात करते हैं तो हमको इस परिपाटी को तोड़ना चाहिए। हर केस में यदि वह मेड-आउट है तो हमें कर्मचारियों को बचाने की परिपाटी छोड़नी चाहिए। यदि हम कर्मचारी को बचाने की परिपाटी चालू रखेंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, यह सही है कि पिछले चार साल में प्रदेश ने काफी प्रगति की है, अच्छी योजनाएं लागू हुई हैं। मेरे क्षेत्र में नवनेरा डैम का निर्माण हो रहा है। यह वही नवनेरा डैम है जिसके बारे में हमारे प्रधान मंत्रीजी सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। यह सही है कि राजस्थान में पेयजल की काफी कमी है, विशेषकर पूर्वी राजस्थान में, पहले पश्चिमी राजस्थान में थी लेकिन जो नवनेरा डैम की योजनाएं बनाई जा रही हैं, हम पिछले दिनों हवाई सर्वे में माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ गए थे। नवनेरा डैम में, माननीय कटारिया साहब उसको क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, मैं अर्ज नहीं करना चाहता, लेकिन इस डैम में कितने मीटर पानी ऊपर था? यह योजना जिसने भी बनाई, माननीय वसुन्धराजी ने बनाई या किसी और ने, लेकिन योजना डिफेक्टिव है और इस योजना का पुनरीक्षण होना चाहिए, विचार होना चाहिए। जितनी लिफ्ट योजनाएं इसके आधार पर हैं, वो सही नहीं हैं। आप देख लीजिएगा क्योंकि इस योजना का क्यों भार पड़ा, आज कानून और व्यवस्था की दृष्टि से यदि बात करें, पांचना बांध का पानी सबसे पहले किसने रोका? आज वह न पेयजल के काम आ रहा है और न सिंचाई के काम आ रहा है।

(श्री रामनारायण मीना)

माननीय सभापति महोदय, जहां फ्लो से पानी दिया जाता रहा है, यह दुर्भाग्य है कि वहां पर लिफ्ट योजनाएं बनाई जा रही हैं। मैं बी.जे.पी. पर जात-पात का तो आरोप नहीं लगाता, लेकिन पिछले दिनों जब प्रधान मंत्रीजी राजस्थान में आए तो एक वाकया हुआ। कांग्रेस के किसी सदस्य को, समाज वाले को नहीं बुलाया गया। इन्होंने पहले कश्मीरी पंडितों की बात करके जात-पात को जिस तरह से बढ़ावा दिया, वही स्थितियां राजस्थान में अब हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान देश को हो रहा है। जो 188 सम्पत्तियां आदरणीय पंडित जवाहर लाल नेहरू और इंदिराजी ने तैयार की थीं, उनमें से कई सम्पत्तियों को बेचा जा चुका है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जयपुर के एयरपोर्ट तक को बेचा जा चुका है।

माननीय सभापति महोदय, अभी किसानों की एम.एस.पी. की बात हो रही थी। 1964 में स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारतीय खाद्य निगम की स्थापना इसलिए की थी कि किसान को उसकी उपज का सही भाव मिले और भारत सरकार अपने किसानों की उपज को खरीदकर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से डिपोजिट करे और सही भाव आने के बाद में जनता के हित के मामले में उसको निकाल ले लेकिन आज की सरकार उस भारतीय खाद्य निगम को भी बेचने की साजिश रच रही है और यही कारण है कि भारतीय खाद्य निगम एक तरह से अस्तित्व में न रहे, इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, हम अपनी-अपनी पार्टी की बात करते हैं विधान सभा में, सदन के बाहर भी, लेकिन देश को कमजोर करने का काम किसने किया? देश को कमजोर करने का काम जिस प्रकार से हो रहा है, आज हम एक जाति विशेष को, धर्म विशेष को टारगेट बनाकर, जिस प्रकार से देश का माहौल खराब कर रहे हैं उसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। डाक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी का जो माननीय प्रधान मंत्रीजी के बहुत नजदीकी मित्र हैं और राज्य सभा सदस्य रहे हैं। उन्होंने प्रधान मंत्रीजी से एक ही प्रश्न किया, माननीय प्रधान मंत्रीजी, हम पाकिस्तान को खतम करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ऊंचाई पर हमारी कितनी सामरिक टेकरियों पर हमसे कब्जा छीनकर चीन काबिज हो चुका है। उसका आज दिन तक, करीब एक वर्ष होने को आया, आज दिन तक उसका कोई जवाब नहीं मिला।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना

(श्री रामनारायण मीना)

चाहता हूं कि यह प्रदेश और देश का शामलाती सवाल है, इसके बारे में हमें मंथन करना चाहिए और मंथन करके हमें इसके ऊपर जिस प्रकार भी सम्भव हो सके, विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं स्वीकृत की हैं, अनगिनत घोषणाएं की हैं। यह पहली मर्तबा है कि राजस्थान में चार साल में इतने काम कभी मंजूर नहीं हुए थे, लेकिन मैं यहां पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर विराजमान कल्ला साहब से निवेदन करूंगा कि वैसे आपकी कृपा रही है कि आपने बहुत से काम मंजूर किए हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में काफी योजनाओं पर काम चालू नहीं हो सका है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि सुल्तानपुर बाईपास की घोषणा हुए दो वर्ष हो चुके हैं लेकिन फील्ड में आज भी काम नहीं है। धीवरी चम्बल नदी पर काम चालू नहीं हुआ है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो सम्भवत: वैसे तो लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा। ये ही हालात रहे तो, ...(व्यवधान) वहम ही नहीं है। आप डायरी में लिख लीजिए।

श्री सभापति: आप अपनी बात चालू रखें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, ये बीच में बोल रहे हैं, इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा। आपके माध्यम से दे देता हूं।

श्री सभापति: आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): ये डायरी में लिख लें, जिस प्रकार से आपकी लाइन चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 2023 में शासन में नहीं आ रही है। मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं, आप किसी कीमत पर नहीं आ सकते। हमारे यहां तो यह व्यक्ति लड़ रहा है, वह व्यक्ति लड़ रहा है, उसका निपटारा जनता कर रही है। (व्यवधान) मैं वसुन्धरा जी की बड़ाई नहीं कर सकता। आदरणीय कटारिया साहब को जिस तरह से आपने डॉक में डाल रखा है यहां विधान सभा में जवाब देने के लिए, मैं इनके बारे में नहीं कहना चाहता। इस आदमी को आप बनाना नहीं चाहते, नाम नहीं ले रहा, मैं ओम बिरला साहब या ओम माथुर की बात नहीं करता, मैं सतीश पूनियां जी की बात नहीं करता। (व्यवधान) किसकी बात करते हैं आप? ओम बिरला मुझसे

(श्री रामनारायण मीना)

जीतकर गये हैं, इसीलिए आप ऐसा मत करें कि वे मुख्य मंत्री बनने जा रहे हैं। आप थोड़ा शान्त होकर सुन लीजिए। प्रदेश नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जिसने किसानों के हितों के खिलाफ काम किया है, वह शासन में आये। आज भी जिस प्रकार की भारत सरकार की पालिसीज हैं, हम स्टेट को दोष देते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): रोजगार खतम हो चुका है। रेल की पटरियां बेची जा रही हैं। माननीय सभापति महोदय, जो स्थितियां देश की बन रही हैं, वही ये प्रदेश की बनाना चाहते हैं। मैं आपसे साफ अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान बहुत ही उन्नतिशील प्रदेश बनने जा रहा है और वह केवल और केवल कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगा। सभापति महोदय, मेरा आपसे एक ही अर्ज करना है कि हमारे प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल किसान की एम.एस.पी. के ऊपर बनता है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर वह खरीद करे।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, लहसुन की खरीद के लिए इन्होंने मात्र 3,000 रुपये की एम.एस.पी. की घोषणा की। एक भी पोथी, एक भी कली नहीं खरीदी गयी। केवल वॉट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर श्रेय लेने के लिए आपने बहुत कुछ किया है। अभी पिछली कांग्रेस सरकार के टाइम पर...

श्री सभापति: समाप्त करें। कन्क्लूड करें जल्दी। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): अभी से?

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मैं सुन नहीं पा रहा हूं आजकल। मशीन लगानी पड़ेगी।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग कीजिए। विराजिए। श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, डिप्टी स्पीकर रहे हैं, सीनियर मेम्बर हैं...

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मेरी आपसे कोई तकरार नहीं है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, समय निर्धारित किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा। माननीय सदस्य, प्लीज, विराजिए आप। सहयोग करें। श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, पृष्ठ संख्या 3, पैरा संख्या 13 पर राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से सरकार ने कहलवाया है कि पिछले चार वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं कृषक कल्याण, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा एवं उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर देश में मिसाल कायम की है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कृषकों के बारे में बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कही गयी हैं। कृषकों को आये दिन मार पड़ती है। किसानों को समय पर बीमा नहीं मिलने का कारण सरकार की उदासीनता है। मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूंगा। सिंगरासर पटवार मण्डल में एक पटवारी है। क्रॉप कटिंग के समय कृषि पर्यवेक्षक और कम्पनी के बन्दे वहां गये और क्रॉप कटिंग करके नाप-तौल कर लिया। बाद में उस पटवारी ने अपने पैन से आगे तो '1' लिख दिया और एक जगह '6' लिख दिया। यह बात पूर्णत: सत्य साबित हो गयी। जिला कलेक्टर के पास गांव के लोग जब शिकायत करने गये तो कलेक्टर महोदय ने यह बात स्वीकार कर ली कि बिलकुल, इसने क्रॉप कटिंग के बाद में अपने हाथ से एक जगह '6' लिखा है और एक जगह '1' लिखा है। उस पटवारी को 17 सी.सी.ए. का नोटिस दे दिया, परन्तु किसान बर्बाद हो गया। कलेक्टर महोदय ने रेवेन्यू बोर्ड को लिखा है, "वाकई में इस पटवारी ने गलती की है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इस तरह के पटवारी को तुरन्त सस्पैंड किया जाए।"

इतना ही नहीं, 2022 में सावन की फसल में ग्वार के मामले में भी उसी पटवारी ने उसी हलके में अपने हाथ से आगे अक्षर बढ़ाकर लिख दिये और पैदावार ज्यादा दिखा दी और ग्वार के बीमे से वे काश्तकार वंचित रह गये। मैं आपके समक्ष प्रमाण भी रख सकता हूं, जिसमें हाथ से अक्षरों की कटिंग की हुई है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि जब भी पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक और बीमा कम्पनी का व्यक्ति गांव में क्रॉप कटिंग के लिए जाता है तो गांव में सूचना दी जाए, पूरा ढिंढोरा पीटा जाए ताकि कृषक सचेत होकर अपनी क्रॉप कटिंग के समय उपस्थित रहे। उन्हें उस क्रॉप कटिंग की नकल हाथ की हाथ मिलनी चाहिए।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सभापति महोदय, इसी तरह से छोटी-छोटी बातों को लेकर कहीं गांव का नाम गलत लिख देते हैं, कहीं बीमा करने वाले गलत लिख देते हैं, कहीं बैंक वाले गलत लिख देते हैं। मेरे क्षेत्र में 2019 से लेकर 2022 तक का हजारों किसानों का मुआवजा बीमा कम्पनी ने नहीं दिया। किसानों ने बीमा प्रीमियम जमा करवा दिया। उनकी कोई गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ यह है कि वे जो मेरी उम्र के लोग हैं, वे अनपढ़ हैं और नौजवानों पर भरोसा नहीं करते। यह एक बीमारी और है सबसे बड़ी। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जब क्रॉप कटिंग के लिए कर्मचारी/ अधिकारी जाएं, उस समय पूरे गांव में सूचना देकर क्रॉप कटिंग की जाए ताकि काश्तकार आये दिन यह पीड़ा नहीं भुगते और बीमे की राशि से वंचित न रहें। यह काम करने के लायक है। इसमें सरकार का कोई ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला। सभापति महोदय, इस पटवारी के बारे में तो आप जरूर इतना ध्यान करियेगा।

एक, माननीय कल्ला साहब आप समझते हैं, पटवार हलका। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे क्षेत्र में ठेठार गांव का हलका है, जिसमें ठेठार पूरा नहरों और ट्यूबवैल्स से सिंचित है। उसके साथ एक गांव है एटा, जो पूर्णत: बारानी है। जब ठेठार का क्रॉप कटिंग का नम्बर आता है, तब एटा बीमा से वंचित रह जाता है, क्योंकि वह जो क्रॉप कटिंग हुई है, वह सिंचित क्षेत्र में हुई है, वहां अकाल होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

इसी तरह से दूसरा हलका सोमनसर पटवार मण्डल है। उसमें कालूसर गांव है, जो पूर्णत: बारानी है, कोई सिंचाई सुविधा नहीं है। सोमनसर में जब क्रॉप कटिंग होती है, भयंकर अकाल होता है, पर कालूसर बीमा से वंचित रह जाता है। इन छोटी-छोटी कमियों के बारे में सरकार को अवगत करवा दिया। जिला कलेक्टर को लिखित में अवगत करवा दिया, और हम क्या कर सकते हैं? विधान सभा में यह बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर सरकार चाहे तो एक मिनट का काम है।

सभापति महोदय, सरकार कहती है कि उसने पशुपालन में आमूलचूल परिवर्तन किया है चार वर्षों में। आमूलचूल परिवर्तन तो कहीं दिखाई नहीं दिया, परन्तु मुझे राजस्थान में लाखों की संख्या में दुधारू गायें मरते हुए दिखाई दीं। लम्पी बीमारी से पशुधन बर्बाद हो गया। किसानों के पास इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह तो भला हो उन लोगों का जो दानवीर हैं।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से दवा के लिए पैसा दिया। रही-सही कमी इस विधान सभा के सदस्यों ने अपने कोटे से दवाई हेतु राशि देकर पूरी की, पर दवाई देने वाला गांवों में कोई नहीं था। बहुत बड़ी विडम्बना है कि सरकार ने राज्यपाल महोदय के मुख से चार साल में आमूलचूल परिवर्तन का कहलवाया है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अब तो सरकार का ही परिवर्तन होगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): यह तो पक्का है, कोई शर्त लगाओ न। सरकार ने विकास के मामले में अपनी पीठ थपथपाई है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले चार वर्ष के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र में विकास के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं लगी। अब जो कार्य शुरू हुआ है वह या तो पंचायतों में पुराना पैसा पड़ा हुआ था या प्रधान मंत्री जी सीधा जो पंचायतों के खाते में विकास के लिए पैसा भेजते हैं, उन पैसों से निर्माण कार्य अब आनन-फानन में शुरू किया है, यह है आपकी उपलब्धि।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, पृष्ठ संख्या 11 पैरा संख्या 45 में कहा गया है कि बिजली के मामले में राजस्थान आत्मनिर्भर हो गया और 23 हजार 489 मेगावाट बिजली पैदा होना बताया है, बिजली में उपलब्धि हासिल की। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले चार वर्ष के अन्दर लाइट के मामले में पूरे राजस्थान का कृषक त्राहि-त्राहि कर रहा है, बहुत बुरी हालत है। आपने कहा कि एक पैसा नहीं बढ़ाएंगे, पर दुनिया भर का पैसा बढ़ा दिया और 6 घंटे भी पूरी लाइट मिलती नहीं है। बार-बार बिजली कटौती होती है। इतना ही नहीं, पावर कम होने से, वोल्टेज कम होने से आये दिन किसानों की मोटरें जलती हैं। लाख-लाख रुपये मोटरों के लगते हैं और एक बार मोटर जल गयी तो किसान तो पूरा बर्बाद हो गया तथा अगर साल में दो बार जल गयी तो उसकी कमाई बट्टे खाते गयी। स्टार्टर जल जाते हैं। यह व्यवस्था क्यों हो रही है, क्योंकि आप वाहवाही लूटने के लिए लाखों की संख्या में कनेक्शन करते जाते हो, पर स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं करते, जी.एस.एस. वगैरह का निर्माण नहीं करते, नई लाइन नहीं खींचते जिसके कारण से वोल्टेज डाउन रहते हैं जिससे काश्तकारों का आये दिन नुकसान हो रहा है। हजारों की संख्या में जी.एस.एस. बनाने की बात राज्यपाल के अभिभाषण में कही गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 7-8 वर्ष से 132 के.वी.जी.एस.एस. थर्मल प्लांट के अन्दर प्रभात नगर में मंजूर है पर उसका कार्य बड़ी धीमी गति से

(श्री रामप्रताप कासनियां)

चल रहा है। मुझे कहते हुए शर्म आती है, इस हाउस के अन्दर पिछले चार साल से मैं चिल्ला-चिल्लाकर थक गया, बहुत चिल्लाया हूं पर यहां बोलना मेरे समझ से परे है। एक समय होता था जब विधान सभा के अन्दर कोई सदस्य, पक्ष-विपक्ष बोलता था तो उस पर सुनवाई होती थी, पर आज तो बोलना महज बोलने के लिए दिखावा ही रह गया है। मैं फिर सरकार से कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर बिजली की कोई समस्या है तो उस जगह का नाम सूरतगढ़ तहसील है। सरकार समय रहते चेते, नहीं तो मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस सरकार को यह बिजली और पानी ही निगलेगा। यह आप याद रखना, अच्छी तरह से नोट कर लो, लिख लो। आपसे किसान बिलकुल ही खुश नहीं है। गांव के अन्दर घरेलू बिजली ही नहीं मिलती है। खाना खाने के टाइम में बिजली कटती है और सभापति महोदय, ताज्जुब करोगे कि शहर के अन्दर 6-6, 8-8 घंटे बिजली कटती है। यह सरकार कहती है कि राजस्थान के अन्दर राजस्थान सरकार ने बिजली के मामले में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वाह रे सरकार, मुझे तरस आता है आपके कथन पर कि आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो, परन्तु कुछ सोच-समझकर भाषण करना चाहिए।

सभापति महोदय, सरकार ने पेज नम्बर 11 के पैरा संख्या 46 पर 534 फीडरों का निर्माण करने की बात कही है। फिर मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि छोटे 33 वाले फीडर मेरे क्षेत्र में भी 8 वर्ष पहले मंजूर हुए थे, पर आज भी उनका कार्य तक शुरू नहीं हुआ है। यह हकीकत है।

सभापति महोदय, सरकार आमूलचूल परिवर्तन करने की बात कह रही है और पेज संख्या 5 के पैरा संख्या 19 में कहा है कि मुख्य मंत्री......

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): साहब, मैं तो कभी-कभी ही बोलता हूं, थोड़ा मेरे ऊपर रहम करो। पेज संख्या 5, पैरा संख्या 19 में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना का कहा गया है। खूब वाहवाही लूट रहे हो और दुनियाभर के अरबों रुपये के तो आपने गहलोत साहब के चित्र लगा रखे हैं। इतना पैसा आप दवाई पर और जांच के उपकरणों में खर्च करते। मैं यह बात दावे के साथ कहता हूं कि न तो गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में दवाई मिलती है और न शहरी क्षेत्र में मिलती है, जांच भी नहीं होती। सूरतगढ़ जाएं तो कह देते हैं कि हमारे यहां मशीन ठीक नहीं है, आप गंगानगर जाओ और गंगानगर

(श्री रामप्रताप कासनियां)

वाले कह देते हैं कि बीकानेर जाओ, यह हकीकत है। विधायक हैं और हमारे पास पास बने हुए हैं, सब कुछ हैं पर प्राइवेट वाले इलाज नहीं करते, वे आनाकानी करके टरका देते हैं। अभी की बात है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं खुद गया हूं। मैं कोई शिकायत वाली बात नहीं कर रहा हूं योजना बहुत अच्छी है पर धरातल पर लागू नहीं हुई है। आज भी डाक्टर दवा लिखते हैं, वे एक तो यह कहते हैं कि सरकारी दवा के ऊपर से लोगों का भरोसा खतम हो गया, बिलकुल ही उठ गया। डाक्टर बोलता है कि यह सरकारी दवा ले लो, काम तो करेगी नहीं। उससे मरीज घबरा जाता है और वह मजबूरी में पैसा खर्च करके दवा खरीदता है। यह उनकी मजबूरी है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): पेयजल के बारे में सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है। जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य हो रहा है, घर-घर जल और नल में सरकार ध्यान दे।

श्री सभापति: समाप्त करें। प्लीज, सहयोग करें, विराजें। श्री गणेश घोघरा। अंकित नहीं होगा। श्री गणेश घोघरा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये-विराजिये। प्लीज, विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: मैं आपके आगे वाला जो वक्ता है उसका समय काट लूंगा। प्लीज, सहयोग करें। विराजें आप। प्लीज, सहयोग करें, विराजिये। श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

हमारे विपक्ष के सदस्यों ने सरकार की कई कमियां निकालीं और कई प्रकार की बातें भी कीं। मैं कहना चाहूंगा कि ये बता रहे हैं कि इन्होंने चार साल में कुछ काम नहीं किया तो मैं चार साल तो नहीं मानता क्योंकि दो साल तो कोरोना में निकल गये, लेकिन दो साल में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने इतना काम किया है कि पूरे हिन्दुस्तान में ऐसा काम इतिहास में कभी नहीं हुआ और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता

(श्री गणेश घोघरा)

हूं। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी को लोग, जनता जादूगर के नाम से जानती है, अशोक महान के नाम से जानती है, राजस्थान का गांधी के नाम से जानती है और गरीबों का मसीहा के नाम से अशोक गहलोत को जानती है। भले आप कितना भी उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर लें, लेकिन जनता के दिलों में अशोक गहलोतजी बैठे हुए हैं। यहां आने वाले समय में वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप भले ही कितना ही उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर लें। लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने दो साल तक कोरोना होते हुए भी काम किया है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ ही, मुख्य मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यह ऐसी योजना है जो गरीब के लिए संजीवनी जड़ी-बूटी बनकर काम कर रही है। पैसे वाले तो अमेरिका में इलाज करा लेंगे, गुजरात में इलाज करा लेंगे, बाहर विदेशों में इलाज करा लेंगे, लेकिन एक गरीब जो मजदूरी करता है, जो दिहाड़ी करता है, उसको इस योजना का कितना फायदा मिल रहा है, वह आप उस गरीब से जाकर पूछो, उस गरीब जनता से जाकर पूछो। वह बताएगी कि वास्तव में सरकार ने ऐसी योजना लागू की है, जिससे हमको काफी फायदा मिला है। हमारे वहां गुजरात पास पड़ता है। पहले लोग इलाज के लिए गुजरात जाते थे। अब हमारे सामान्य चिकित्सालय में नि:शुल्क जांच, 10 लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज हो रहा है। लोग काफी खुश हैं कि हमारा 10 लाख तक का नि:शुल्क इलाज हो रहा है।

उसके साथ ही साथ 5 लाख का दुर्घटना बीमा योजना। किसी का एक बेटा है, मां-बाप ही रहे हैं, उनके बच्चे की मृत्यु हो गई है। उनकी देखरेख के लिए बुढ़ापे का सहारा कौन बने तो 5 लाख रुपये उस परिवार को मिलेंगे। यह है, मुख्य मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्य मंत्री दुर्घटना बीमा योजना। जनता को इसका काफी लाभ मिल रहा है।

पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी ने और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश की नेता सोनिया गांधीजी ने नरेगा चालू की। उस नरेगा से कोरोना में सबको रोजगार मिला, उनके घर चले। कोरोना में उस समय ऐसी आफत आ गई थी, तब मोदीजी ढोल बजवा रहे थे, तालियां पिटवा रहे थे, मोमबत्ती लगा रहे थे, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी रात-दिन चिन्तित थे। उन्होंने किसी को भूखा सोने नहीं दिया। भीलवाड़ा मॉडल बनाया और घर-घर किट पहुंचाई। यह काम कोई कर सकता है तो अशोक गहलोतजी और

(श्री गणेश घोघरा)

कांग्रेस सरकार कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खाली बातें करती है, धरातल पर कुछ भी काम नहीं कर सकती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): देश में महंगाई की, गैस के सिलेण्डर पर, डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ाना।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): उसके बाद नरेगा में 25 दिन बढ़ाये। वह हमारे लिए काफी लाभदायक है।

श्री सभापति: कृपया शान्ति रखें। आपस में वार्तालाप नहीं करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): हमारे लोगों को कभी पलायन नहीं करना पड़ेगा। 25 दिन हमें एक्स्ट्रा मिले, उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उसके साथ-साथ शहरों में भी इन्दिरा गांधी शहरी गारंटी योजना लागू की। उससे जो दलित वर्ग के लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको घरों पर कोई काम पर लगाता नहीं था, उनको घरों पर काम पर कोई लगा नहीं सकता था, ऐसे में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चालू करके, उनको रोजगार देने का काम किया। आज उनको वहां पर काफी रोजगार मिल रहा है, खुश भी हैं।

उसके बाद इन्दिरा रसोई योजना चालू की। आज 8 रुपये में भरपेट पौष्टिक भोजन मिल रहा है, वह भी बिठाकर। ऐसा काम कोई कर सकता है तो अशोक गहलोतजी कर सकते हैं। अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री ही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है।

किसान मित्र योजना, 50 यूनिट बिजली फ्री। हमारे गांव में गरीब को मजदूरी करके 200 रुपये भरने पड़ते हैं, उनका बिल फ्री हो रहा है। सरकार किसानों का 1,000 रुपये जमा कर रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? केन्द्र कोयला ही नहीं दे रहा है, मोदीजी खाली बातें कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि हमारी यह स्थिति हो गई, वह स्थिति हो गई। अभी तो हमारे नि:शुल्क, जीरो बिल आ रहे हैं। आपके टाइम में, पूर्ववर्ती सरकार में घरों में लाइट नहीं आती थी, बिलों में करंट आता था। आपकी सरकार थी तब बिलों में करंट आता था। आपके समय लाइट बिलकुल नहीं आती थी, बिलों में झटका लगता था, बिल पकड़ते ही झटका लगता था। हमारे यहां बिलकुल जीरो बिल आ रहा है। लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री गणेश घोघरा)

शिक्षा के क्षेत्र में, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलीं ताकि एक गरीब का बच्चा इंग्लिश पढ़ सके, आगे बढ़ सके, लेकिन विपक्ष के हमारे जो सदस्य हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ना नहीं चाहिए, अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, वह आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है लेकिन, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने हर ब्लाक पर अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलकर हमारे वहां जो गरीब लोग थे, वे अब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और उनको काफी फायदा मिल रहा है। लोग भी काफी तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा काम कोई कर सकता है तो अशोक गहलोत कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है।

कई स्कूलें एक से आठ तक क्रमोन्नत भी कीं। स्कूल यूनिफार्म फ्री दी, सिलाई के दो सौ रुपये बच्चों के खाते में जमा कराये। आप तो 50 रुपये भी नहीं दे सकते हो, दो सौ रुपये की बात कर रहे हो। (व्यवधान) सर, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप एक मिनट विराजिए। माननीय सदस्य, कोई सदस्य अपनी बात कहना चाह रहा है और आप इतना इंटरवीन कर रहे हो। आप लोगों में इतनी भी शालीनता नहीं है। आप संसदीय परम्पराएं सीख लेंगे तो घट नहीं जाएंगे? एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, यह बीमारी है। आप विराजिए, विराजिए। यह बीमारी है, अपने आपको सुधार लीजिए। यह सदन जिसमें आने के लिए आपने एड़ी-चोटी का जोर लगाया, यदि आप सदन को गम्भीरता से नहीं लेंगे तो आने वाला वक्त भी आपको गम्भीरता से नहीं लेगा। आप पुराने माननीय सदस्य हैं, आसन आपको माननीय सदस्य कहकर सम्बोधित कर रहा है, आसन आपसे अपेक्षा करता है कि निर्देशों का पालन करें, शालीनता बरतें और संसदीय परम्पराओं का निर्वहन करें। एक माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाह रहे हैं और आप बीच में उनको बोलने नहीं देंगे। आपकी फ्री डिबेट करा दूं, आप भी जितना मर्जी हो-हल्ला मचायें। प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): हमारी सरकार ने 'प्रशासन शहरों के संग', 'प्रशासन गांवों के संग', जो अलाटमेंट कैम्प लगाये और लाखों लोगों को, जो वंचित थे, गरीब थे, उनको पट्टे दिये। लोगों में खुशी की लहर भी है कि ऐसा पहली बार हुआ है। शहरों में भी जो वर्षों से मकान बनाकर रह रहे थे, गांवों में मकान बनाकर रह रहे थे, जो सौ-डेढ़ सौ सालों से पैनल्टियां भर रहे थे, उनके

(श्री गणेश घोघरा)

कभी खाते नहीं हुए। पटवारी के रोज चक्कर मारते थे। उनका अलाटमेंट कैम्प लगा, लोगों को खातेदारी हक मिला तो इस कैम्प से आम जनता में खुशी और लोगों को काफी फायदा भी हुआ है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरकार ने, अशोक गहलोत साहब ने जो मांगा वह दिया। भले कृषि महाविद्यालय हो, विधि कालेज हो, आर्चरी एकेडमी हो, रामसागड़ा कालेज हो, पालदेवल कालेज हो, गामड़ी तहसील हो, पालदेवल तहसील हो और विपक्ष के साथी कहते हैं कि हमारा कोई काम नहीं हुआ। कई काम ऐसे हैं जिसका मैंने शिलान्यास भी कर दिया और उद्घाटन भी कर दिया। यह पहली बार इस सरकार में हुआ है, लेकिन असत्य बोलना इनका काम है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी से मांग करना चाहूंगा कि हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र में, पूरे उदयपुर सम्भाग में, हमारे युवाओं की यही मांग है जो मैं पहले भी विधान सभा में बोलता आया हूं कि जनसंख्या के आधार पर सरकारी नौकरियों में हमें आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद राजस्थान में 12 प्रतिशत एस.टी. को आरक्षण मिलता है। उसमें से हमको पृथक से टी.एस.पी. की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और हमारी सामाजिक स्थिति को देखते हुए 6 प्रतिशत आरक्षण प्रशासनिक एवं राज्य सेवा में अलग से मिलना चाहिए। हमारे युवाओं की यह लम्बे समय से मांग है। मैं सी.एम. साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अबकी बार हमारी मांग पूरी की जाए तो हमारे पूरे सम्भाग में खुशी की लहर होगी, क्योंकि हमारे यहां आर्थिक पिछड़ापन है। वहां आदिवासी भील समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। यहां की हम बराबरी नहीं कर सकते हैं। हमारे वहां कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, हमारे बच्चों के पास बाहर एजुकेशन के लिए चंदा नहीं है, फीस नहीं भर सकते हैं तो हमें हमारा आधा हक दिया जाए। इसमें किसी को तकलीफ नहीं है। मैं सरकार से पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी ये दो विशेष मांगें हैं, इनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

उसके बाद पैरीफेरी के नाम से मालपुर, भाटपुर, बिलड़ी, गोकुलपुरा, ददोड़िया, सूरपुर में विशेष भूमि अलाटमेंट कैम्प लगाया जाए। क्योंकि यहां वर्षों से बैठे हुए हैं, लेकिन नगर परिषद् पेरीफेरी के नाम से उनको अलाटमेंट कैम्प लगाने नहीं दे रही है। उनके पास खाली एक-दो बीघा जमीन है, इसके अलावा उनके रोजगार का कोई साधन नहीं है। वो खाली मजदूरी करने जाते हैं, तो उनके लिए अलाटमेंट कैम्प लगाकर एक-एक, दो-दो बीघा जमीन

(श्री गणेश घोघरा)

आबंटित कर उनको राहत दी जाये जिससे उनको फायदा हो जायेगा और वह रोजगार भी कर सकते हैं, उनको भविष्य में कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

(समय: 14.00 बजे)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नरेगा एक वरदान साबित हुई है हमारे लिये, लेकिन आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, हमारे वहां पर कई पंचायतों में मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है तो वहां फिंगर कैसे, थम्ब कैसे होगा? मेटों की हाजिरी नहीं हुई और मेटों को पेमेन्ट नहीं मिला है, कारीगरों का पेमेन्ट नहीं मिला है, मैटेरियल का पेमेन्ट नहीं मिला है। सरपंच भी परेशान हैं और मजदूर काफी परेशान हैं कि वहां ऑनलाइन हाजिरी नहीं हो रही है। हमारे गहलोत साहब ने तो पच्चीस दिन बढ़ा दिये लेकिन सौ दिन क्या, किसी के पचास दिन भी नहीं हो पा रहे हैं और मोदी जी की तो यही सोच है कि नरेगा बन्द कर दो। लोगों को रोजगार नहीं देना, यही इनकी सोच है।

मैं कहना चाहूंगा कि हमारे वहां नरेगा में दो सौ दिन किये जाएं। वहां पर कोई उद्योग-धन्धे नहीं हैं, कोई रोजगार का अन्य साधन नहीं है नरेगा के अलावा। या तो उनको सूरत जाना पड़ता है या गुजरात जाना पड़ता है। नरेगा के अलावा कोई वहां पर ऐसा रोजगार का साधन नहीं है इसलिये टी.एस.पी. क्षेत्र में उदयपुर सम्भाग में नरेगा के दो सौ दिन किये जाएं और जो ऑनलाइन हाजिरी हो रही है और इनका भुगतान समय पर नहीं हो रहा है उसको जल्दी कराया जाये। ऑनलाइन जहां नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है उसका कोई सिस्टम करें कि ऑफलाइन भी इनकी हाजिरी ली जाये, जिससे समय पर इनको पूरे दिन मिल पायें।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): वनाधिकार के काफी पट्टे हमारी सरकार ने दिये लेकिन कुछ लोग काफी वर्षों से बसे हुए हैं, उनकी अभी तक फाइलें जमा हैं, लेकिन उनको वनाधिकार के पट्टे भी नहीं दिये गये हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में एप्लाई किया है, लेकिन अभी तक नाम जुड़े नहीं हैं। जो ए.पी.एल. पास बना हुआ है, खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ने से उसको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और कोई भी जो सरकार की योजना है वह नहीं मिल पा रही है, उनको गेहूं भी नहीं मिल पा रहा है तो खाद्य सुरक्षा में जिसने एप्लाई किया है उसका नाम जोड़ा जाये और उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाये। यह मैं सरकार से मांग करूंगा।

(श्री गणेश घोघरा)

हमारे बच्चे कालेज में पढ़ने गुजरात बोर्डर से डूंगरपुर आते हैं। बीच में एक बार आटो भी पलट गया था। बच्चों का एक्सीडेंट भी हुआ। कई बार मैंने मंत्री जी को भी निवेदन किया था कि डूंगरपुर से गामड़ी, रामसागड़ी वाया होता हुआ गुजरात सीमा वीरपुरसरम तक सरकारी बस चालू की जाये, डूंगरपुर से पालीछोड़ा तक सरकारी बस चालू की जाये और डूंगरपुर से रतनपुर तक यह तीन बस बहुत ही अनिवार्य हैं हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र में, जनजाति बहुल क्षेत्र में, वहां पर जल्दी से जल्दी बस चालू की जाये तो वहां आम लोगों की जो समस्या है उनकी समस्या का निराकरण हो सके और बच्चे जो कालेज स्कूल पढ़ने जाते हैं वह भी समय पर जायें। जो प्राइवेट टैक्सी वाले होते हैं उनसे मोटी रकम वसूल करते हैं और समय पर पहुंच नहीं पाते हैं। कभी अन्धेरा पड़ जाता है, जंगल का एरिया है, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये बसें हमारे जल्दी से जल्दी चालू की जाएं।

हमारे क्षेत्र की मांग है कि जो डूंगरपुर के संस्थापक, जिन्होंने डूंगरपुर बसाया था डूंगर बरंडा की मूर्ति नया बस स्टैण्ड पर लगायी जानी चाहिये। यह हमारे क्षेत्र की पूरी जनता की मांग है। दूध डेयरी के पास आई.टी.आई. रोड पर माला कटारा की मूर्ति लगाने की मांग है और शहीद कालिया मनात जो भारत-पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए थे, तो उनकी भी देवल खास में मूर्ति लगनी चाहिये।

कल गुजरात में जो पेपर लीक हुए और जहां-जहां बीजेपी की सरकार थी जहां पेपर लीक हुए, वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने वापस पेपर भी कराये और जिन्होंने ऐसा काम किया उनको जेल में भी डाला और जो उनकी बिल्डिंग्स थीं उनको भी ध्वस्त किया। यह काम संवेदनशील अशोक गहलोत जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की जिस भी राज्य में सरकार है वहां पेपर लीक हुए, वहां उन्होंने वापस एग्जाम भी नहीं कराये, उस पर कार्रवाई नहीं की। ये खुद मिले हुए हैं, ये क्या कार्रवाई करेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से और जो सदस्य विपक्ष में बैठे हुए हैं उनसे कि मोदी जी ने घरेलू गैस के तो 1,100 रुपये प्रति सिलेण्डर कर दिये, तो नरेगा में मजदूरों के भी हजार रुपये करने चाहिये। मैं यह मांग करता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, खाली एक और कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: हां, बतायें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): कृषि महाविद्यालय की हमारे यहां तीन-तीन जमीनें अलाट हो चुकी हैं। प्रशासन ने जमीन अलाट करके भी दे दी, लेकिन कई अधिकारी, कई कर्मचारी ऐसे बैठे हुए हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं। तीन-तीन जगह जमीन बता दी फिर भी वो काम चालू नहीं करना चाहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, सी.एम. साहब से निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी यह कृषि महाविद्यालय वहां पर चालू कराया जाये। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, सरकार ने माननीय राज्यपाल से अपनी सरकार की उपलब्धियों के गुणगान कहलवाये, जो सत्य से परे हैं। कहा गया कि हमने नये-नये प्रत्येक क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किये। सत्ता पक्ष के लोग उनके गुणगान गा रहे हैं, विपक्ष के लोग उनकी कमियों को बता रहे हैं लेकिन वास्तविकता जो धरातल पर है, मैं केवल कुछ वाक्यों में आपके सामने रखना चाहूंगा।

6 जनवरी, 2023 को जोधपुर में मीडिया के सामने बोलते हुए मुख्य मंत्री जी ने कहा, मन करता है माफिया के बाल काट कर परेड करायें पर आगे डैश-डैश। मुख्य मंत्री किसके आगे मजबूर हैं, जो वो एस.एम.एस. में भर्ती होते हैं तो वहां की सारी व्यवस्थाओं को देखकर कहते हैं कि मुझे शर्म आती है। जब जोधपुर में सड़कों को देखते हैं तो कहते हैं कि ठेकेदारों, इंजीनियरों की मिलीभगत है। आप मुख्य मंत्री हो, आपको कार्रवाई करने से रोका किसने है? मुझे लगता है कि इस राज्य को बरबाद कर रहे हैं और कांग्रेस के अन्दर जो सत्ता संघर्ष है, जिसमें मुख्य मंत्री और पूर्व उप मुख्य मंत्री के बीच जो सियासी लड़ाई चल रही है उसमें जनता पिस रही है। मुख्य मंत्री केवल कुर्सी से चिपके रहने के कारण पूरी लाचारी की मुद्रा में हैं और इसका खामियाजा प्रदेश और प्रदेश की जनता भुगत रही है। और तो और, अधिकारी मंत्री की नहीं मानते, मंत्री मुख्य मंत्री की नहीं मानते। इस तरह की जो स्तरहीन बयानबाजी हो रही है उससे राजस्थान की पूरी छवि बिगड़ रही है।

पैरा 147 में सुदृढ़ कानून-व्यवस्था की बात कही गयी है। कल ही

(श्री वासुदेव देवनानी)

रात को, आज अखबारों में पढ़ा होगा, किस तरह से जी क्लब के परिसर में खुले आम गोलीबारी हुई सोलह गोलियां चली। 8 जनवरी को चेतावनी दी गई, लेकिन आज तो लगता है कि राजस्थान के अन्दर आम जन के अन्दर भय है और अपराधियों में विश्वास है। इस प्रकार की आज गैंगस्टर की लड़ाई किस तरह से हो रही है, राजस्थान के अन्दर 500 गैंगस्टर सक्रिय हैं। और तो और आस-पास के राज्यों के वहां के मुख्य मंत्रियों ने, यू.पी. के मुख्य मंत्री ने वहां पर जो उनको टाइट किया, उनको कसा तो पड़ोसी राज्यों के अपराधियों को भी राजस्थान सुरक्षित लगने लगा है। इसके कारण से राजस्थान आ रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को तो शायद पाक से भी फंडिंग हो गई हो।

डकैती, हत्या, लूट, अपहरण, दुष्कर्म में राजस्थान नम्बर 1 पर है और यहां पर न पुजारी, न मन्दिर, न मन्दिर की बाकी जमीन सुरक्षित है। पूरी तरह राजस्थान आज अपराधियों से घिर गया है। रिकार्ड 8 लाख 41 हजार से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दौसा में आदिवासी महिला का अपहरण कर गैंगरेप कर जला कर कुए में फेंक दिया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, पता नहीं कब गैंगवार हो जाये इससे जनता अपने आपको काफी असुरक्षित महसूस करने लगी है। यहां तक कि सीकर में राजू ठेहट की खुले आम हत्या, नागौर में अदालत परिसर के बाहर दिनदहाड़े गोलीबारी, अजमेर, जोधपुर, किशनगढ़ सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर फायरिंग, यह सारी की सारी घटनाएं कह रही हैं कि आज राजस्थान में जंगलराज है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इस बारे में मैं प्रत्यक्ष आपसे निवेदन करना चाहूं कि यह स्थिति इसलिए बनी कि मुख्य मंत्री जी लाचार और मजबूर हैं। राजस्थान को एक मजबूत मुख्य मंत्री चाहिये। यह घोषणा तो कर रहे हैं कि हम 156 आयेंगे लेकिन इतिहास कह रहा है कि जब-जब अशोक गहलोत के मुख्य मंत्री रहते हुए यहां पर चुनाव हुए हैं उस समय कांग्रेस की दुर्गति हुई है। अब यह तो कांग्रेस को तय करना है कि किसके मुख्य मंत्री काल में वो चुनाव करायें। दुर्गति करवानी हो तो ये जानें और इनको अच्छा आना है तो ये तय करें। यह हमारा विषय नहीं है, लेकिन कम से कम जो राजस्थान इस समय अपराधियों का है, इस दाग को तो मेहरबानी करके साफ कीजिये। इसके बिना आज हम सब लोग बड़े परेशान हैं। भ्रष्टाचार की बात करूं तो आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 2018 में 372 घटनाएं हुईं, 2020 में बढ़कर 445 हुईं, 2022 में

(श्री वासुदेव देवनानी)

511 हुईं। यहां तक कि ए.सी.बी. पकड़ती है पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलती। अब तो हद हो गई जिस एस.ओ.जी. की बार बार इस सदन में चर्चा होती है, उस एस.ओ.जी. की एडिशनल एस पी दिव्या मित्तल 2 करोड़ की रिश्वत मांगते हुए पकड़ी जाती है। इससे ज्यादा क्या दुर्गति हो सकती है? दो वर्ष में 46 आई.ए.एस., आर.ए.एस. सस्पेंड होते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की सरकार में इनके अफसरों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं?

पेपर लीक की चर्चा चली, इस पेपर लीक में आज 6 दिन से किरोड़ी लाल जी मीणा युवकों के साथ धरने पर बैठे हैं और इस कांग्रेस के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। पेपर लीक के बारे में जो राजस्थान पत्रिका ने सर्वे करवाया उसमें 87 परसेंट युवकों ने राज्य सरकार की कार्रवाई को केवल दिखावा बताया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जारोली को बर्खास्त किया गया, उस जारोली से आज तक पूछताछ क्यों नहीं हुई, इसका मुख्य मंत्री जी जवाब दे देंगे तो सामने आ जायेगा। जब हमारे सांसद किरोड़ी जी ने तीन मंत्रियों और छह एम.एल.ए. की लिप्तता का संदेह व्यक्त किया तो उन मंत्रियों और एम.एल.ए. से पूछताछ क्यों नहीं हो रही? पूछताछ तो करो, दोषी होंगे तो दोषी ध्यान में आयेगा, लेकिन पूछताछ नहीं करेंगे। एंटी चीटिंग बिल जरूर बना लेकिन आज तक एक को भी सज़ा नहीं हुई। एस ओ जी जिनको फरार कहती है, वह खुलेआम कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। इस प्रकार की पेपर लीक की घटना एक नहीं 16 हुईं। कहने को कहेंगे कि आज गुजरात में हुआ। आप राजस्थान की बात करो, गुजरात में विपक्ष में कांग्रेस वहां भी है, वह वहीं बात कर लेंगे लेकिन राजस्थान में तो स्पष्ट कहो कि 16 पेपर क्यों लीक हुए? दोषी कौन है, कौन पकड़ा गया? मैं तो इस बारे में आपसे स्पष्ट बात करना चाहूंगा कि इन सारी बातों पर आज अगर हम विचार करेंगे तो राजस्थान की जनता अपने आपको बिलकुल बेसहारा पा रही है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बातें आईं, आज वहां 10 वर्षों की आडिट बाकी है जबकि आडिट हर वर्ष होनी चाहिये। उसके एक पूर्व वित्तीय सलाहकार ने बोर्ड की राशि निजी काम में व्यय कर ली, उसका पता नहीं। करोड़ों रुपये के घोटाले उसमें सामने आते हैं।

मैं युवकों की बात करता हूं तो आज देश में बेरोजगारी केवल 8.3 प्रतिशत है जबकि राजस्थान में 28.5 परसेंट है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): देश में हम दूसरे नंबर पर हैं और आज 27 लाख बेरोजगार राजस्थान में हैं, केवल 50 हजार को ही आप दे रहे हैं। कोई जवाबदेही नहीं है? इसी विधान सभा में 35 हजार प्रश्न लगाये गये, आज भी 30 परसेंट प्रश्नों के उत्तर तक नहीं दिये गये। आम आदमी पर जिस प्रकार से कर्ज बढ़ रहा है, आप वाहवाही तो खूब लूट रहे हैं लेकिन 2018 तक राजस्थान पर कुल 3.41 हजार करोड़ का कर्ज था और मार्च, 2022 में बढ़कर वह 4.74 हजार करोड़ हो गया है, अर्थात्, प्रत्येक परिवार पर आज 3.37 लाख रुपये का कर्ज है।

भर्तियों की बात मैंने एक प्रश्न के माध्यम से पूछी। आज यदि तेलंगाना, उत्तराखंड की सरकारें स्थानीय रहवासियों को नौकरियों में शत-प्रतिशत दे सकती है तो राजस्थान क्यों नहीं? आप कहते हो कि उसका कोई प्रावधान नहीं है, तो बाकी प्रांतों में कैसे प्रावधान है? एम.पी., पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ इसी राह पर चल पड़े हैं। यह सारी सरकार की नाकामी को साबित करता है और सरकार केवल वोट बैंक के आधार पर इन सारी बातों को जनता की राहत को न देखते हुए किस तरह से तुष्टिकरण करके अपना काम चला रही है। कल ही अजमेर की दरगाह में देशद्रोह के नारे लगे। आपस में दो खेमे झगड़ पड़े। यानी तुष्टिकरण की नीति जिसने उदयपुर में कन्हैया की घटना करवाई, करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर में करवाई। कम से कम यह तुष्टिकरण न करके कानून की व्यवस्था तो करो। खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है, उसको कौन रोकेगा? मुख्य मंत्री जी, आप भी लाचारी अनुभव करोगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? यह कोई बता दे तो शायद जनता को कुछ राहत मिलेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपने मुझे जितना टाइम दिया उसी में मैं एक मिनट लूंगा, इससे अधिक मैं आपका एक मिनट भी नहीं लूंगा। (व्यवधान) जिसने भी करवाई, उसको पकड़ो। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए। प्लीज सहयोग कीजिए। अंकित नहीं होगा किसी का।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हमारी बात यह है कि उसको पकड़ो। गृह मंत्री का दायित्व बनता है कि वह उसको पकड़े और जनता के सामने सच लाये।

श्री सभापति: श्री सुरेश मोदी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इस तरह से आज राजस्थान बरबाद हो रहा है। राजस्थान की स्थिति बहुत ही भयंकर खराब है।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिए, विराजिए।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): माननीय सभापति महोदय, 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और उसके बाद उसने कई कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश की जनता के हक में शुरू कीं। इनमें सबसे प्रमुख है चिरंजीवी योजना। यह योजना बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, 88 प्रतिशत जनता को इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। इसके क्रियान्वयन में कई प्राइवेट अस्पताल आनाकानी करते हैं, इलाज करने से मना करते हैं, कोई न कोई बहानेबाजी करते हैं। एक बात और देखने में आई है कि अगर आप चिरंजीवी योजना के तहत इलाज कराओगे तो जूनियर डाक्टर इलाज करेंगे और अगर पैसे देकर इलाज कराओगे तो सीनियर डाक्टर इलाज करेंगे। मेरा सुझाव है कि आपने एक टोल फ्री नंबर दे रखा है, लेकिन वह टोल फ्री नंबर कई बार जवाब नहीं देता, कई बार मिलता नहीं है और मिलता है तो वह संतोषजनक कार्रवाई नहीं कर पाता, आप इतना बड़ा खर्चा इस योजना पर कर रहे हैं और आपकी मंशा भी यह है कि इसका लाभ आम जनता तक पहुंचे, तो इसके लिये कोई एक सीनियर अधिकारी इस तरह का नियुक्त किया जाये जो जनता को सुलभ अवेलेबल हो और वह इसकी शिकायतें सुने और उनका निराकरण करे।

आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है, कर्मचारियों ने इसको बहुत सराहा है। इसी तरह से आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ राजस्थान की जनता को मिल रहा है।

बिजली की अभी बहुत समस्या चल रही है। किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल पा रही है और इससे बड़ी परेशानी हो रही है। सरकार दावा कर रही है कि हम बिजली में सरप्लस हैं। सरप्लस हैं तो या तो कहीं न कहीं हमारे सप्लाई तंत्र में कोई गड़बड़ी है। मेरे यहां दो 33 के.वी. सब-स्टेशन के लिये मैं चार साल से लगातार प्रयास कर रहा हूं। नीचे से रिकमंड होकर भी

(श्री सुरेश मोदी)

आ गये हैं लेकिन किसी स्तर पर वह दबे पड़े हैं। कई जगह बहुत सारे 33 के.वी. के, 132 के सब-स्टेशन लग रहे हैं, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कोला की नांगल में और एक मंडोली में बहुत लंबे समय से मांग चलती आ रही है। एक जगह तो लगभग 48 किलोमीटर लंबा फीडर है जबकि नियमों के हिसाब से 9 किलोमीटर से लंबा फीडर नहीं होना चाहिये। उस 48 किलोमीटर के फीडर पर भी 33 के वी का सब-स्टेशन सरकार की ओर से मंजूर नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है कि उसे शीघ्र स्वीकृत कराया जाये और बिजली की सप्लाई की व्यवस्था को कम से कम जब तक फसल का काम रहता है तब तक तो बहुत अच्छी की जाये। 6 घंटे तो कम से कम उनको बिजली दी जाये। अभी तक हमारे पूरे प्रदेश में 22 घंटे टू-फेज की बिजली मिलती थी, लेकिन इन दिनों टू-फेज की बिजली शाम को 6 बजे काट दी जाती है। ये वे पीक ऑवर्स हैं, जिस समय हर व्यक्ति को बिजली की आवश्यकता होती है। ऐसे समय पर बिजली काट देना परेशानी का कारण बनता है। 6 बजे से शाम को 10 बजे तक कम से कम टू-फेज की बिजली की कटौती न की जाये, यह मेरा सरकार से आग्रह है।

फसल खराबे की बात माननीय सदस्यों ने पहले भी कर दी है। मैं भी यहां पर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरसों की फसल में बहुत बड़ी खराबी हुई है। पाला पड़ा है बर्फ पड़ी है और इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे किसान भाइयों को जल्दी से जल्दी उस खराबे का आकलन करके उसका मुआवजा शीघ्र दिया जाये। Delayed justice is not justice. उस फार्मूले पर कार्य करते हुए हमको तुरन्त उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। किसानों की लागत लग चुकी है। किसान बड़ी मुश्किल से अपनी फसल बोता है और उसको तैयार करता है। उसका बहुत सारा खर्चा लगता है। आजकल हमारे सारे इनपुट्स.. चाहे विपक्षी सदस्य कितनी भी बात कर लें कि हमने इतना डी.ए.पी. दे दिया, इतना यूरिया दे दिया, लेकिन वस्तुस्थिति इसके बिलकुल विपरीत है। किसानों को केन्द्र सरकार की नाकामियों की वजह से समय पर खाद नहीं मिला पा रहा है, तो ऐसे हालात में किसानों को शीघ्र से शीघ्र मुआवजा दिया जाना बहुत आवश्यक है।

सिलिकोसिस के बारे में सरकार की बहुत अच्छी योजना चल रही है लेकिन जैसी अच्छी योजना है और जैसी सरकार की मंशा है, उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। जो कैम्प लगाये जाते हैं, जो बीमार मरीज अधिकारियों

(श्री सुरेश मोदी)

और डाक्टरों के पास जाते हैं तो बजाय सिलिकोसिस के उनको किसी और कारण से बीमार होना बता देते हैं, सांस की बीमारी है, चेस्ट में और कोई खराबी है। वे लोग इस बात से कतराते हैं कि उसको सिलिकोसिस का बीमार बताया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारी ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं, मैंने कई बार निवेदन किया कि इनका पॉल्यूशन डिपार्टमेंट सही ढंग से मुआयना करे और उनको नियमों की पालना करवाये। डस्ट कम से कम उड़े, वे पानी का छिड़काव करें। वे अपने वर्कर्स को मास्क वगैरह का यूज करवायें। इन नियमों की अगर कड़ी पालना करवायी जायेगी तो इस बीमारी की रोकथाम में मदद मिलेगी। इसकी जांच के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए, जिससे कि हम इस बीमारी के नुकसान को कम कर सकें।

जल-जीवन-मिशन की कई सदस्यों ने बात की। मैं भी इस विषय में मेरे कुछ विचार रखना चाहता हूं। जल जीवन मिशन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो ड्राई पाइंट्स हैं, जो कि सूखे निकल जाते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। उनको दुबारा लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी गांव में योजना स्वीकृत है और आपने वहां पर दो बोरिंग लगा दिये और अगर दोनों बोरिंग सूखे निकल गये तो आपकी सारी योजना धरी की धरी रह गयी। आपकी जो सोच है कि हम हर घर तक पानी पहुंचायेंगे, आपकी वह सोच वहीं की वहीं धरी रह जायेगी। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो बोरिंग सूखे निकल जायें, उनकी एवज में और नये बोरिंग लगवाने का प्रावधान इस योजना में किया जाये। इसके अन्दर देरी बहुत हो रही है, काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। ठेकेदार लोग बहुत सारे जिलों का काम ले लेते हैं, पूरे जिले का काम ले लेते हैं। उसकी जितना काम करने की कैपेसिटी नहीं है, उससे ज्यादा वह काम ले लेता है और उसका नतीजा यह निकलता है कि काम की गति धीरे रहती है। हमारे यहां पर कई पंचायतें ऐसी हैं, जहां पर काम शुरू ही नहीं हो पाया है। पूरे जिले का एक ही ठेकेदार है, उसके पास सीमित साधन हैं। उसके पास जितने साधन हैं, उनको कभी इधर लगा देता है, कभी दबाव लगता है तो दूसरी तरफ भेज देता है, तो पहले वाला बन्द हो जाता है। इस तरह से या तो आप ठेका देते समय यह देखें कि इस व्यक्ति की इतनी कैपेसिटी है, इसको इससे ज्यादा ठेका नहीं दिया जाये या उसके खिलाफ आप इस तरह के कोई नियम बनायें, जिससे कि वे समय पर उस काम को पूरा कर सकें। बिजली के कनेक्शन भी कई जगह पर...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): सरकार ने सैकण्डरी स्कूल्स को सीनियर सैकण्डरी में कन्वर्ट करके एक बहुत अच्छा कदम उठाया था। शिक्षा मंत्री जी विराजे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों को इसी तरह से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाये। हालांकि, यह सम्भव नहीं है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार ज्यादा मात्रा में उनको क्रमोन्नत करे। इस तरह का इस बजट में मैं प्रावधान करने का निवेदन करता हूं।

जनता क्लिनिक की घोषणा हुई थी। कई सारी बजट घोषणाएं ऐसी हैं जिन पर अभी धीमी गति से काम चल रहा है। मेरे यहां भी जनता क्लिनिक की घोषणा हुई थी। मैंने जमीन भी विभाग के नाम करवा दी, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है।

बसों की कई माननीय सदस्यों ने बात की। एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी बस का चलना बहुत जरूरी है। सरकार इस बजट में रोडवेज को कैसे भी ज्यादा प्रावधान करके दे, लेकिन सरकारी बसें हर विधान सभा क्षेत्र में ज्यादा चले, इसकी व्यवस्था करे।

कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का काम तेजी से चालू करवाया जाये। नगरपालिका का जो पैरिफेरी एरिया है, उस एरिया को शामिल करते हुए, वे सब लोग पैसा तो नगरपालिका की दर से दे रहे हैं, लेकिन उनको वे सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। मेरा निवेदन है कि नीम का थाना नगरपालिका का क्षेत्र बढ़ाकर पैरिफेरी क्षेत्र को उसमें शामिल किया जाये। हमारे यहां पर जो मास्टर प्लान है, उसके रिविजन के लिए हमने बहुत समय से प्रयास कर रखा है, निवेदन भी किया है, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की गयी है। उसको जल्दी से जल्दी कराया जाये।

महंगाई और बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहां कृषि का कार्य बन्द हो गया, उसकी वजह पानी की कमी है। यमुना का पानी सिंचाई के लिए जिन जिलों में आ सकता है, उन जिलों में यमुना का पानी तेजी से लाया जाये। हम पाकिस्तान का कई तरह से नुकसान करने की सोचते हैं, लेकिन हमारा कितना ही पानी हमारे काम में नहीं लेने की वजह से पाकिस्तान में चला जाता है तो दोतरफा काम होगा, हमारे यहां उन्नति होगी, विकास होगा, कृषि को बढ़ावा मिलेगा और पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है, उस पानी को रोका जा सकेगा।

(श्री सुरेश मोदी)

सभापति महोदय, मेरे यहां एक बड़ी मांग है, जो कि जिला बनाने की मांग है। सभापति महोदय, मैं पुन: सदन के माध्यम से निवेदन करता हूं कि नीम का थाना को जिला बनाया जाये। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख से जो अभिभाषण पढ़ाया गया है और उसमें सरकार के बारे में कहा गया है कि इन्होंने चहुंमुखी विकास किया है उसकी एक बानगी आपको बताना चाहता हूं। हम यदि बात करें कि किसान के हित में कितना काम किया है, तो किसान को एक तरह से बर्बाद करके सरकार ने छोड़ दिया है। बिजली विभाग के बिजली का डिमांड नोट जमा कराने के लिए किसानों ने अपने जेवर गिरवी रखे, सामान गिरवी रखा, यह सोचकर कि हमको दो-तीन महीनों में बिजली का कनेक्शन मिल जायेगा, लेकिन मिला नहीं। डिमांड नोट जमा कराये हुए साल भर हो गया। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो कि कनेक्शन के लिए इधर-उधर घूम रहे हैं, लेकिन उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। जो फसलें उन्होंने इसलिए बो दी थीं कि इनको मैं पानी दे पाऊंगा, उनकी वे फसलें नहीं हो पायी हैं और किसान बर्बाद हो गया है। जिन किसान के खेतों में फसल लहलहा रही है और उनको बिजली की आवश्यकता है, उनको बिजली नहीं दी जा रही है, जबकि घोषणा की गयी थी कि बिजली हम दिन में देंगे, ताकि किसान को इस ठिठुरती सर्दी में रात में खेत में न जाना पड़े। यदि वह खेत में नहीं जायेगा तो बीमार नहीं होगा और मौत का ग्रास नहीं बनेगा, लेकिन हुआ इसके विपरीत है। रात में ही बिजली मिल रही है, दिन में बिजली नहीं मिल रही है। दिन में बिजली नहीं मिलने के कारण से रात भर किसान खेत में खड़ा रहता है। टकटकी लगाकर खड़ा रहता है, वह देखता रहता है कि कब बिजली आये, कब गयी, कब आयेगी। 10 मिनट के लिए आती है, फिर 5 मिनट के लिए चली जाती है, इसलिए किसान की फसलें इससे काफी खराब हो गयी हैं।

किसान को यह भी कहा गया था कि हम आपको बिजली के बिल में एक हजार रुपये महीने की छूट देंगे। 10 हजार रुपये साल की छूट की माननीय वसुन्धरा राजे जी मुख्य मंत्री जी थीं, उन्होंने भी घोषणा की थी और लगातार दे रही थीं, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद ढाई साल तक उसको बन्द रखा और ढाई साल तक बन्द रखने के कारण से हर किसान की

(श्री मदन दिलावर)

इस सरकार ने 25 हजार रुपये की जेब काटी। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में किसी सरकार ने प्रदेश के सारे किसानों की जेब काटी होगी, मैंने किसी सरकार को नहीं देखा है। यानी ये सरकार 25-25 हजार रुपये साल की भी किसान की जेब काट सकती है, यह मैंने पहली बार देखा है।

सभापति महोदय, इसमें सरकार ने यह भी कहलवाया है कि शिक्षा में अंग्रेजी के विद्यालय खोलकर गरीबों को अंग्रेजी पढ़ाने का यत्न किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि विद्यालय क्रमोन्नत कर दिये गये हैं, शिक्षक नहीं लगाये हैं। शिक्षक कुछ लगाए तो हिन्दी माध्यम के वहां लगा दिये हैं। इससे हिन्दी माध्यम के स्कूल खाली हो गये हैं। हिन्दी माध्यम के शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इस कारण से अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र भी बरबाद हुए और हिन्दी पढ़ने वाले छात्र भी बर्बाद हुए यानी राजस्थान भर के सभी छात्रों का भविष्य अंधकारमय इस सरकार ने कर दिया है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी ज्यादती विद्यार्थियों के साथ कभी-भी किसी भी सरकार ने नहीं की होगी।

यह सरकार कह रही है कि हम विद्यार्थियों को ड्रेस दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेता इस बात को कह रहे थे कि दो-दो ड्रेस दे रहे हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि 60 प्रतिशत पैसा भारत सरकार का है। माननीय मोदी जी राजस्थान सरकार को ड्रेस का 60 प्रतिशत पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन उस पूरे पैसे को भी लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही है और उसी पैसे में काम चलाकर ये कह रहे हैं कि हम ड्रेस दे रहे हैं। उस 60 परसेंट पैसे को ही विद्यार्थियों को बांट रहे हैं और राजस्थान सरकार का उसमें एक भी पैसा नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, सभी छात्रों को ड्रेस दी जा रही हो, मैं समझता हूं यह कहना बेमानी होगा। 30 प्रतिशत से ज्यादा छात्रों को ड्रेस नहीं मिल रही है। आज वह ड्रेस के कारण से इधर-उधर घूम रहे हैं। इस ठिठुरती सर्दी में गरीब मां-बाप के बच्चे ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं लेकिन सरकार को चिंता नहीं है। ये वह सरकार है जो बच्चों के मुंह से दूध छीन सकती है। दुधमुंहा बच्चों के मुंह से दूध छीन सकती है। जिन बच्चों को सप्ताह में 6 दिन तक दूध मिलता था, उनको 2 दिन कर दिया, 1 दिन कर दिया और एक-डेढ़ साल तक तो दूध को बिलकुल बंद ही रखा। मैं समझता हूं कि बच्चों का दूध भी ये सरकार पी जाएगी, बच्चों की ड्रेस भी ये सरकार खा जाएगी। मैंने कभी यह नहीं सोचा था, लेकिन इस सरकार ने यह कर दिखाया है। यानी बच्चों की दुश्मन भी ये सरकार बनी है।

(श्री मदन दिलावर)

इन्होंने ये भी कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये हम विश्वविद्यालय खोलेंगे। कहां है विश्वविद्यालय दिव्यांगों का? कहां, कौन-से विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं? इस प्रकार की थोथी घोषणा करने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इस अभिभाषण में ये कहलवाया गया कि हमने ये सब कुछ करने का यत्न किया है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, ये भी इन्होंने घोषणा की थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के लिए हम 100 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रहे हैं, यानी कि उसको बढ़ा रहे हैं। 400 करोड़ रुपये बढ़ा रहे हैं। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस सरकार ने 100 करोड़ से 500 करोड़ रुपये किये? उसकी गाइडलाइंस बना दी? उसके आदेश जारी कर दिये? क्या अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यानी अनुसूचित जाति व जनजाति के हिस्से का 500 करोड़ रुपया भी यह सरकार डकार गयी है। अनुसूचित जाति के बच्चों का भी, अनुसूचित जाति के लोगों का भी पैसा सरकार डकार सकती है तो फिर क्या कर रही होगी?

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने कहा कि हम सबके स्वास्थ्य की चिन्ता कर रहे हैं, सब का नि:शुल्क इलाज कर रहे हैं। कागजों में तो नि:शुल्क इलाज हो रहा है, योजना भी है इनकी, लेकिन क्या अस्पतालों में डाक्टर्स हैं? क्या पैरामेडिकल स्टाफ है? क्या इनकी जांच की मशीने हैं? क्या इनकी एम्बुलेंस हैं? जहां एम्बुलेंस हैं वहां ड्राइवर्स हैं? नहीं हैं। गांव के गांव खाली पड़े हैं। मैं मेरे रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो ट्रोमा हास्पिटल घोषित है और 75 बेडेड हास्पिटल घोषित है, लेकिन 6 डाक्टर रहते हैं। जहां 36 डाक्टर होने चाहिए थे, वहां 6 डाक्टर हैं। वह क्या करेंगे? वहां एम्बुलेंस है लेकिन ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर कभी डेली वेज पर ले आते हैं तो डीजल नहीं है। माननीय विधायक कोष से दी हुई एम्बुलेंस भी खटारा होकर पड़ी है क्योंकि ड्राइवर नहीं होने के कारण से उसको चला नहीं पाये।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मेरी बात कड़वी जरूर है, लेकिन गरीबों के हित में जो इन्होंने कहा था, वह किया नहीं है।

श्री सभापति: आप समाप्त कीजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार का अभिभाषण इन्होंने कहलवाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है।

श्री सभापति: प्लीज, आप विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इन्होंने ये भी कहा था कि गोशालाएं खोलेंगे, नन्दी शालाएं खोलेंगे।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग कीजिए। आप विराजिए। श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कहां हैं गोशालाएं?

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: प्लीज, माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं पुन: आपसे आग्रह कर रहा हूं, विराजिए। आपके आने वाले वक्ता के समय में कर्टेल कर दूंगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज विराजिए। आसन आपसे अपेक्षा करता है, आप विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: जो भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, उनका समय काट रहा हूं मैं। माननीय सदस्य, आप इतने वरिष्ठ हैं, आसन के निर्देश आप नहीं मानेंगे? श्री मीना जी।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं हमारी कल्याणकारी सरकार की कुछ नीतियों के बारे में, जिनका राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया था, उनके समर्थन में बोलना चाहता हूं।

सबसे बड़ी योजना जिसका व्यापक रूप से हमारी जनता को फायदा हुआ है, वह है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। मैं यह मानता हूं कि ऐसी योजना हमने सुनी नहीं थी, न इसकी कल्पना की थी। जो यह योजना है, इसका हर

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

क्षेत्र में स्वागत किया जा रहा है और कई प्रदेश भी इसको लागू करने की सोच रहे हैं। मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने गरीब से गरीब परिवार को भी 10 लाख रुपये की लाभकारी योजना इलाज के लिए उपलब्ध कराई है। इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है।

महोदय, इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली गयी हैं, मैं मानता हूं शिक्षा के रास्ते से जो गुणवत्ता प्रदान की गयी है, उससे हमारे ग्रामीण, गरीब क्षेत्रों में लाभ मिलेगा और हमारे गरीब व ग्रामीण क्षेत्रों के जो नौजवान हैं, बच्चियां हैं, उनके भविष्य को संवारने के लिये यह बहुत अच्छा कदम उठाया गया है।

एक अन्य योजना जिसका बहुत ज्यादा स्वागत किया गया है, जिसकी मांग बहुत बढ़ रही है वह है 'इंदिरा रसोई योजना'। महोदय, यह बहुत ही अच्छी योजना है। 8 रुपये में पौष्टिक भोजन मिलता है। इसकी एक कमी ये है कि ये सिर्फ नगरपालिका क्षेत्रों में है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कम से कम तहसील मुख्यालयों पर भी इसका विस्तार किया जाए। जहां तहसील है, नगरपालिका नहीं है, मैं सरकार से आग्रह करूंगा क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा मांग बढ़ रही है, हमारे बहुत बड़े-बड़े कस्बे हैं, उनमें भी इसको लागू किया जाए।

महोदय, इसी तरह जनता क्लिनिक, सरकार ने जो जनता क्लिनिक योजना दी है, मैंने स्वयं ने कुछ दिन पहले हमारे उनियारा शहर में इसका शुभारम्भ करवाया था। इतना अच्छा रेस्पोंस मिला है और इसकी भी मांग है, चूंकि ये भी सिर्फ नगरपालिका क्षेत्रों के लिए है, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो बड़े-बड़े कस्बे हैं, जहां दस हजार से ऊपर की आबादी है, उनमें भी इसकी इजाजत दी जावे ताकि हमारी जनता को सस्ता व सुलभ इलाज मिल सके।

मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा जो सरकार ने कोरोना के दौरान व्यवस्था की थी। राजस्थान का उदाहरण ऐसा था जिसमें किसी भी गरीब को या किसी भी रोगी को बिना इलाज के या बिना भोजन के नहीं जाना पड़ा। इसकी सर्वत्र तारीफ हो रही है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा।

महोदय, इसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र के संबंध में मेरे कुछ सुझाव भी हैं। जैसे बजट 2022-23 में मेरे विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की घोषणा की गयी थी। आज तक न तो उसके लिये भूमि आबंटित हुई है और न ही किसी प्रकार की प्रशासनिक या वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, कृपया इस बजट घोषणा को लागू करवाने का प्रयास करें।

इसी तरह प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन कर उनके गोदाम निर्माण एवं सहकारी समितियों को गौण मंडी का दर्जा देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारम्भ किये जाने की घोषणा थी, यह अभी तक लागू नहीं हुई है। इस बजट घोषणा को भी कृपया लागू करवाई जाए।

इसी तरह विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के ग्राम पंचायत मुख्यालय बिलासपुर, गावड़ी, रूपपुरा, रूपवास, बौसरिया, रिजोदा, गोठला में पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा यहां अतिशीघ्र पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोलने की व्यवस्था करवाए। विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के ग्राम पंचायत मुख्यालय ओखलाना, रिजोदा, श्योराजपुरा, मंडावरा, देवली, आमली, खेलनिया, बौसरिया, बीलोता, देवीखेड़ा, संथली, सीतापुरा, टोडा का गोठड़ा, रतनपुरा, बीसलपुर, ख्वासपुरा, डाबरकलां पर अभी तक ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन नहीं किया गया है, इनका अविलम्ब गठन किया जावे।

सर, ऊर्जा के क्षेत्र में गत बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र के शावता ग्राम में 33 के.वी.जी.एस.एस. खोलने की घोषणा की गई थी, परन्तु आज तक उक्त जी एस एस का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि बजट घोषणा को लागू करवाया जाए।

इसी प्रकार देवली-उनियारा विधान सभा के पायगा, कोटड़ी, कोटडी मोड एवं पालड़ी गांव में 33 के.वी.जी.एस.एस. स्वीकृत किये गये हैं, परन्तु उनका कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। इस बजट घोषणा को लागू किया जाए, अन्यथा जनता में इसका गलत संदेश जाता है।

बिजली विभाग के सहायक अभियन्ता, उनियारा के अधीन लगभग 40 हजार बिजली कनेक्शन हैं, अत: अलीगढ़ में नवीन सहायक अभियन्ता कार्यालय खोला जाना अति आवश्यक है क्योंकि अन्य विधान सभा क्षेत्रों में 15-15, 16-16, 17-17 हजार कनेक्शनों पर 2-2 कार्यालय हैं, मेरे 40 हजार कनेक्शन पर एक ही है, तो इसमें दूसरा खोला जाना आवश्यक है।

सर, बिजली के ही क्षेत्र में नगर फोर्ट कस्बा एवं आस-पास में कई ग्राम

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

पंचायतों को वर्तमान में विद्युत विभाग के दूनी 220 के.वी.जी.एस.एस. से बिजली सप्लाई दी जाती है, जो कि लगभग 40 किलोमीटर दूर है, जिससे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति निरन्तर बाधित होती रहती है, अत: 132 के.वी.जी.एस.एस. खोला जाना अति आवश्यक है और इसके प्रस्ताव राज्य सरकार व बिजली विभाग के पास विचाराधीन है।

सर, शिक्षा के क्षेत्र में गत बजट में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की घोषणा के बावजूद देवली-उनियारा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय रिजोदा पर विद्यालय नहीं खोला गया है। नीतिगत फैसला है, वहां पंचायत मुख्यालय है तो वहां खोला जाना चाहिए। मैं सरकार से आशा करता हूं कि अपने जवाब में इसकी घोषणा करेंगे।

सर, इसी प्रकार 5 हजार से ज्यादा आबादी वाले ग्रामों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। इसके बावजूद भी मेरे विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के कस्बा घाड, राजमहल, सोप, फुलेता, थांवला, नगर फोर्ट, आवां, ककोर, पचाला, चोरू, धुआ कलां में अब तक महात्मा गांधी मॉडर्न स्कूल नहीं खोले गए हैं, जिनकी आबादी 5 हजार से कहीं ज्यादा है। यह नीतिगत फैसला है, तो नीतिगत फ़ैसले को नीतिगत तरीके से लागू किया जाए, इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। देवली-उनियारा विधान सभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालय नगर फोर्ट एवं उप तहसील मुख्यालय बनेठा व नासिरदा में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता है।

महोदय, आजकल गरीब क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है। किसान हो, मजदूर हो, वह चाहता है कि उसके बच्चे-बच्ची पढ़ें। जब स्कूल और कालेज ही नहीं हैं, तो पढ़ेंगे कहां? उनके पास इतनी क्षमता नहीं है, इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वह यहां से 50 किलोमीटर दूर भेज सकें। इसलिये मेरे तीनों शहरों में, जो तहसील मुख्यालय हैं, नगर फोर्ट, बनेठा व नासिरदा में, मैं सरकार से मांग करता हूं कि अतिशीघ्र राजकीय महाविद्यालय खोलने की कृपा करें।

गत सत्र में विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के विभिन्न विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, परन्तु, शिक्षा मंत्री महोदय, आपने क्रमोन्नत तो कर दीं, स्कूल 8वीं से 12वीं तक कर दीं,

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

घोषणा कर दी, 8वीं से 12वीं जब होती है तो चार क्लास बढ़ती है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, सर 4-4 कमरें तो दे दीजिए। उन्हीं 8 कमरों में, 8वीं वाली स्कूल में 12वीं वाली चल रही है। अतिरिक्त 4 अध्यापक तो दे दीजिए, ताकि यह सार्थक हो जाए और जनता को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। मैं आग्रह कर रहा हूं कि जो-जो आपने क्रमोन्नत की हैं, उनमें उसी अनुपात में सुविधाएं बढ़ाई जाएं।

सर, मैं चार साल से आग्रह कर रहा हूं, पर सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी अनुसूचित जाति छात्रावास नहीं खोला, एक भी अनुसूचित जनजाति छात्रावास नहीं खोला और एक भी अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं खोला है, जबकि मेरे क्षेत्र में तीनों वर्गों की 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी हैं। क्या कारण है, क्या पक्षपात है, यह मैं नहीं कहता। मैं यह मांग करता हूं मेरे यहां एक अनुसूचित जाति छात्रावास, अनुसूचित जनजाति छात्रावास और अल्पसंख्यक छात्रावास खोला जाए, ताकि वहां के गरीब लोगों को शिक्षा का लाभ मिले।

एक घोर अन्याय हुआ है। मैं 2018 से एम.एल.ए. बना हूं तब से मांग करता रहा हूं, सरकार आश्वासन भी देती है लेकिन वह लागू नहीं हुई। सर, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में, 2012 में मेरे विधान सभा क्षेत्र उनियारा के गांव श्रीपुरा में 18 करोड़, 95 लाख की लागत से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इस विद्यालय की कक्षा 6 से 12वीं तक जनजाति वर्ग के बालक-बालिकाओं को पढ़ने तथा रहने की सुविधा दी जानी थी, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल स्वीकृति भी निकल गई, इसका शिलान्यास भी हो गया, पर पता नहीं क्या हुआ उसके बाद, वह स्कूल वहां नहीं बनी, उसको उदयपुर डिवीजन ले गए। मैं किसी डिवीजन के खिलाफ नहीं, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं, परन्तु जो चीज जहां के लिए स्वीकृत है, जहां बजट आ गया, जहां शिलान्यास हो गया, उसको वहां नहीं खोलना एक हल्की सोच का प्रतीक है। हमारे क्षेत्र की जनता के साथ न्याय किया जाए। इसका बजट भी जारी हो गया, टेण्डर भी जारी हो गया, शिलान्यास भी हो गया, काम चालू हो गया, उसके बाद जिसने भी किया, मैं उसको सज्जन आदमी नहीं कहूंगा। यह गलत कार्य है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, बिलकुल दो मिनट में ही कर दूंगा। हमारी सरकार की एक पालिसी है, राज्यपाल महोदय ने अपने

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

भाषण में जिक्र किया था, जीरो टालरेंस फोर करप्शन, भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं, मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु एक उदाहरण मेरे सामने आया है (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शान्त रहें। शान्त रहें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): एक उदाहरण मेरे सामने आया है। मेरे पास एक आदेश है, अगर आप कहें तो मैं इसको टेबल कर दूं। यह आदेश 19 अक्टूबर, 2022 का है। पी.डब्ल्यू.डी. के चीफ इंजीनियर द्वारा दस्तखतशुदा है। उसने एक अधिकारी का कार्य सड़क निर्माण में घटिया स्तर का पाया और उसको उन्होने ए.पी.ओ. कर दिया और जांच शुरू कर दी। अब दो महीने बाद, पता नहीं क्या हृदय परिवर्तन होता है मंत्री महोदय का, किसका, उसको मेरी विधान सभा से हटाया और उसको फिर दो महीने बाद वहीं लगा दिया। अब कैसे जांच होगी? मैंने अधिकारी, चीफ इंजीनियर से बात करी। महोदय, यह क्या कर रहे हो? कि, साहब, मेरा काम था वह मैंने कर दिया, अब मंत्री महोदय की मंत्री महोदय जानें तो यह चीज जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति के खिलाफ है। जब तक वह जांच पूरी नहीं हो, उस अधिकारी को वहां लगाना न्यायोचित नहीं है।

महोदय, इसी तरह गवर्नर महोदय ने कहा था कि हमारी सरकार अत्याचार रोकने के लिए, मुक़दमों के फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए, एक नई नीति लायी है कि कोई भी मुकदमा, कही भी दर्ज करवा सकता है। यह नीति शुरू से ही थी, जब से आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी. लागू हुई है, इस देश में थी, कोई मुकदमा कहीं भी दर्ज करवा सकता है। मैं खुद की बताता हूं, मुझे एक मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दस दिन तक आंदोलन करना पड़ा। अगर एम.एल.ए. को यह करना पड़ा (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): तो आम आदमी की पीड़ा समझ सकता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शान्त रहें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जिस अधिकारी ने मुकदमा दर्ज नहीं किया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे दस दिन के आंदोलन के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया, उस मुक़दमे में एफ.आर. दे दी गई।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): न तो आपने उसके साथ कोई न्याय किया, न ही जो दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): मैं मानता हूं कि अफसरशाही जो हावी हो रही है, अफ़सरों के कारण हमारी कल्याणकारी सरकार बदनाम हो रही है। इस अफसरशाही को हमें काबू में रखना चाहिए।

मैं पुन: सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं लाई है, जो गवर्नर साहब ने कहा है उसका स्वागत करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, जो सरकार के विजन का एक आईना होता है, इस पर हमें बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा 281 बिन्दुओं के माध्यम से सरकार के कार्यकलापों को सदन में रखा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पक्ष-विपक्ष ने अपना धर्म निभाते हुए इस अभिभाषण का विश्लेषण अपने-अपने तरीके से किया। बाकी इसका सारा विश्लेषण देवली-उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरीके से किया, मुझे ऐसा लग रहा है माननीय विधायक महोदय, कहीं न कहीं पूरा देश चाइना से आए हुए कोरोना की चपेट में था। आप जरूर, हो सकता है जिस कोरोना वेरिएंट का मुख्य मंत्री जी ने शोध किया, उस कोरोना से चार साल से पीड़ित रहे हों, तभी आपके अधिकतर काम नहीं हुए। मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता।

मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से सरकार से यही निवेदन करुंगा कि चूंकि चुनावी साल है और प्रदेश के आमजन की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ गई है। प्रदेश का किसान पिछले चार साल से उम्मीद लिए बैठा है कि उसका ऋण माफ होगा। जब माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर दें, तब एक से दस की गिनती करके, समस्त किसानों का, समस्त ऋण माफ करने का आप जरूर तोहफा दें क्योंकि इस बार अखबारों में यह बार-बार आ रहा है कि यह जो बजट है यह किसानों और जवानों को समर्पित होगा, तो मैं ऐसी आशा रखता हूं।

(श्री नारायण बेनीवाल)

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण की शुरुआत में महाराणा प्रताप से लेकर दुर्गादास, मीरा, पन्नाधाय, नानी बाई, अमृता देवी आदि का जिक्र तो कर दिया, लेकिन इनको सरकार कभी तो स्कूलों के कोर्स में शामिल करती है तो कभी हटा देती है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि इन लोगों के जहां पर स्थल हैं वहां पर पैनोरमाओं का निर्माण किया जाये और पहले से जो पैनोरमा निर्माण किये हुए हैं उनकी सास्-सम्भाल भी सरकार करे क्योंकि खरनाल के अन्दर जो तेजाजी का पैनोरमा है, वह खुलने से पहले ही जर्जर हो गया और एक भी व्यक्ति को उनके इतिहास से रूबरू होने का मौका नहीं मिला, तो मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा।

बिंदु संख्या-3 और 4, जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय ने मारवाड़ी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थानियों व राजस्थान दिवस का गुणगान तो कर दिया, लेकिन इन मारवाड़ियों की अपनी जुबान, राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की कोई बात नहीं की है। इस बार 30 मार्च को राज्य के निर्माण की हीरक जयंती वर्ष के मौके पर राजस्थानी भाषा को मान्यता प्रदान करायें तो राजस्थानियों के लिए यह एक गर्व भरा पल होगा।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश को मॉडल स्टेट बनाने व प्रदेश के विकास की बात की है तो मैं यह बता दूं कि नागौर जिला मुख्यालय पर दो आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य चल रहा है जो दिनांक 14.12.2018 को पूर्ण होना था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसा मॉडल स्टेट होता है क्या कि कोई काम तय समय सीमा से चार साल बाद में भी पूरा नहीं हो?

माननीय सभापति महोदय, संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन की बात कही गयी है लेकिन सरकार के मंत्री ही अपराध के आरोपों के लपेटे में हैं। जिस प्रदेश में कोर्ट के सामने एस.पी. और कलेक्टर के आवास से महज 100 मीटर दूर दिनदहाड़े हत्या कर दी जाती है और बदमाश भाग जाते हैं तो फिर कौनसे सुशासन की बात की गयी है, यह समझ से परे हैं।

कोविड महामारी के दौरान भी विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध बताया है, लेकिन कई विभागों ने कोरोना महामारी की आड़ में बजट तक भी जारी नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, 'सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म' है। जन सेवा को समर्पित ये चार साल बताये हैं लेकिन किस प्रकार हर विभाग में भ्रष्टाचार

(श्री नारायण बेनीवाल)

व्याप्त है, बिना पैसे लिये शायद ही कहीं पर सेवा होती होगी। मैं इतना धन्यवाद मुख्य मंत्रीजी को इस बात का दूंगा कि इस बार इन्होंने ट्रांसफर्स पर बैन ही नहीं लगाया, तो सबसे बड़ा जो उद्योग है और जिसके अन्दर भ्रष्टाचार पनपा, उसके लिए मैं जरूर धन्यवाद मुख्य मंत्रीजी को दूंगा। कई मंत्रियों ने, मैं यहां सदन के अन्दर नाम नहीं लेना चाहता, उन मंत्रियों ने सात पीढ़ी का इंतजाम ट्रांसफर और पोस्टिंग के माध्यम से कर दिया, तो किस जवाबदेही और सुशासन की हम बात करते हैं?

माननीय सभापति महोदय, आज हर कार्य के लिए जब ऑनलाइन आवेदन का सिस्टम आ गया तो यह हार्ड-कापी जमा करवाने का सिस्टम कब तक चलेगा? आमजन से अधिकारी तो दूर, वहां का बाबू भी सीधे मुंह बात नहीं करता है। सरकारी कार्यालयों में दफ्तर-दफ्तर घुमाने की परम्परा आज भी कायम है। प्रदेश में प्रतिशत सिस्टम चल रहा है, कोई पांच परसेंट, कोई दस परसेंट।

ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र की बात, हमारे सांगानेर से आने वाले माननीय विधायक ने बहुत ही अच्छी बात की थी कि ओ.बी.सी. के सर्टिफिकेट का हर साल, हर दो साल के अन्दर जो रिन्युअल है, उसके अन्दर बहुत पैसा ओ.बी.सी. का खर्च होता है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि इस पर भी कोई अच्छी कार्ययोजना बने। उसकी कोई जाति तो बदलती नहीं है, तो ओ.बी.सी. का सर्टिफिकेट यदि एक बार जारी हो जाता है तो सालों साल तक वही चलता रहे।

माननीय सभापति महोदय, बिंदु संख्या 15 से 22 चिकित्सा से सम्बन्धित है। आज चूंकि चिकित्सा मंत्री यहां पर मौजूद नहीं हैं, मैं जब पिछली बार उनका भाषण सुन रहा था तो 'निश्चित' शब्द उनके मुंह से निकला। मैं बैठे-बैठे यह नोट कर रहा था तो 'निश्चित' शब्द उनके मुंह से 72 बार निकला, 72 बार 'निश्चित' शब्द उन्होंने कहा था कि 'निश्चित' रूप से ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति सुधरेगी। मैं यह कह सकता हूं कि राइट टू हैल्थ बिल लाने की हमने तैयारी कर दी तो निश्चित रूप से इस प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्थाओं का बेड़ा-गर्क भी होगा, यह भी निश्चित रूप से आप कहीं नोट कर लें इस चीज को, क्योंकि आज हालत ही यह है।

2013 के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोतजी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के पांचला सिद्धा के अन्दर सी.एच.सी. की घोषणा की, लेकिन

(श्री नारायण बेनीवाल)

आज तक वहां पर न तो भवन बना है और एक डाक्टर के अलावा न ही वहां पर नियुक्ति हुई है। पिछली साल जो सी.एच.सी. और पी.एच.सी. की घोषणा हुई तो न उनके भवन बने और न वहां पर स्टाफ लगाया। जो सब-सेंटर्स की बातें थीं जिलों के अन्दर, अभी जिलों के आंकड़े आप कहेंगे तो मैं अलग से टेबल कर दूंगा, पर स्थिति यह है कि कई जो ग्राम पंचायत के मुख्यालय हैं वहां पर भी सब-सेंटर्स की स्थितियां नहीं हैं। डाक्टर्स राइट-टू-हैल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं। हम यह कहते हैं कि यह कर देंगे, अपील में आप जा नहीं सकते। क्या ऐसी कोई कमेटी बनाकर इस मामले को यदि हम एक रोल-मॉडल के रूप में देश को देना चाहते हैं राइट-टू-हैल्थ बिल को, तो इसके अन्दर पूरा विश्लेषण करके हम इसको आगे बढ़ायें।

शिक्षा मंत्रीजी भी यहां पर विराजमान हैं। शिक्षा मंत्रीजी, इस प्रदेश के अन्दर जिस तरह राइट-टू-एजुकेशन का जो हश्र हुआ, यह कोई हमसे छिपा हुआ नहीं है। कहीं पर ऐसा नहीं हो कि इस देश के अन्दर हम मॉडल तो अच्छा बनना चाहें और हम खलनायक के रूप में इस देश में राजस्थान की विधान सभा को याद करें, ऐसा भी कोई कारनामा हम न कर दें।

मुझे याद है कि अभी दो दिन पहले जब इस अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी तब गांधीजी के कथन को आपने बिलकुल कहा था कि सच बोलना चाहिए, सच के सिवाय यहां कुछ नहीं बोलना चाहिए और हमारे डूंगरगढ़ से जो माननीय विधायक आये हैं, उन्होंने यह कहा था कि मेरे इलाके के अन्दर सारे के सारे शिक्षकों के पद भरे हुए हैं। मैं यह रिकार्ड लेकर आया हूं कि मंत्रीजी के गृह जिले बीकानेर के डूंगरगढ़ ब्लाक में प्रधानाचार्य के 30 पद, व्याख्याता के 57 पद, वरिष्ठ अध्यापकों के 207 पद, अध्यापक लेवल-2 के 152 पद, अध्यापक लेवल-1 के 195 पदों सहित कुल 641 पद डूंगरगढ़ के अन्दर रिक्त हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं तो हमारे डूंगरगढ़ से जो माननीय विधायक आये हैं, इनको यही निवेदन करूंगा कि आपने सरकार बचाने के अन्दर बहुत अच्छा सहयोग कर दिया, कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन कम से कम आप इस पवित्र सदन के अन्दर ऐसा असत्य तो नहीं बोलें क्योंकि आपकी एक-एक चीज जो है, आप मेरी बात को पहले सुनें, माननीय विधायक महोदय, यहां पर जो बात होती है, वह बात नोट होती है। (व्यवधान) इसलिए ऐसा कोई काम आप नहीं करें कि हम यहां पर असत्य सूचना देकर प्रदेश के अन्दर एक नयी नीति बनायें, ऐसा भी नहीं हो।

(श्री नारायण बेनीवाल)

जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात आयी थी, जो कि अखबारों के अन्दर बहुत बड़ा छपा था कि पिछले दिनों शिक्षा निदेशक, बीकानेर ने कुचामन ब्लाक में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के निरीक्षण के दौरान दो कार्मिकों को अपने मूल पद पर इसलिए भेज दिया क्योंकि उन्हें बिलकुल अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी। इंटरव्यू लेने वाली कमेटी ने उनसे अंग्रेजी में संवाद किया या हिन्दी में? तो आप कोई न कोई ऐसी नीति बनाओ कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाना चाहते हो, इसके अन्दर प्राइवेट स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा पैदा करके हम अच्छी फ्लूएंसी उनमें पैदा करना चाहते हैं तो कम से कम इंटरव्यू के अन्दर भी एक पूरी अच्छी कार्ययोजना बनायें।

आज तृतीय श्रेणी अध्यापकों की ट्रांसफर की बात माननीय सभी विधायक करते हैं। आज जॉब का सैटिस्फैक्शन उन बच्चों में नहीं है। एक तरफ तो हम यह कह रहे हैं कि हर व्यक्ति में सामाजिकता आनी चाहिए, परिवार का वह ख्याल रखें। अब आजकल तो सिंगल फैमिली होती है, नागौर का वह व्यक्ति बाड़मेर के अन्दर पांच सौ किलोमीटर दूर बैठा है तो कैसे उसमें सामाजिकता रहेगी? कैसे वह अपने परिवार का ध्यान रखेगा तो जब आपने लाखों तबादले शिक्षा विभाग में कर दिये और मैं मेरे इलाके की यह सूचना लेकर आया हूं। मेरे पूरे ब्लाक नागौर जिले के अन्दर, नागौर के सारे माननीय विधायक भी यहां पर बैठे हैं, 22,791 पदों में से 5,200 पद हमारे नागौर जिले के अन्दर खाली हैं। जब आपने इतने बड़े तबादले कर दिये तो दस-बीस हजार तबादला तृतीय श्रेणी अध्यापकों के भी कर देते, उसके लिए कोई ठोस नीति ही बना लेते। जिनकी कोई ज्यादा मजबूरी है, उन लोगों के करते, मैं इतना ही निवेदन आपसे करूंगा।

उच्च शिक्षा मंत्रीजी आज यहां पर विराजे हुए नहीं हैं। उच्च शिक्षा मंत्रीजी को मैं जरूर धन्यवाद दूंगा कि पिछली बार मेरे इलाके के अन्दर दो बालिका महाविद्यालय और एक महाविद्यालय उन्होंने खोलने की घोषणा की। उन्होंने भवन के लिए पैसा भी जारी कर दिया, भवन भी बन रहे हैं लेकिन आज स्थिति यह है कि उन महाविद्यालयों को चलाने के लिए सिर्फ एक-एक व्याख्याता ही है, तो उनके पद भी भरे जायें, तब हमारी जो योजना है वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं आगे बढ़ेगी।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, आपने 15 मिनट तो हमारी

(श्री नारायण बेनीवाल)

पार्टी को टाइम दिया है। 15 मिनट में हम कम से कम अपनी पूरी बात तो कहें, हम नये विधायक चुनकर आये हैं, हम तो कोई एलिगेशन भी किसी पर नहीं लगायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सी.एच.ए. को जिस प्रकार से एक ही झटके में घर बैठा दिया, बेरोजगार सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर हैं। आज यदि हम राइट-टू-हैल्थ की बात करते हैं तो आधुनिक मशीनों के होते हुए भी आज अस्पतालों में जांच सिर्फ नाम की ही निःशुल्क है। आज की हुई जांच की रिपोर्ट अगले दिन मिलती है। अब मेरा खींवसर विधान सभा क्षेत्र 200 किलोमीटर लम्बा है, इसमें जब कोई व्यक्ति जीवन और मौत के बीच में जूझ रहा है तो उसके लिए अगले दिन आयी जांच का मतलब क्या है? इसलिए मेरी यह मांग है कि ऐसी मशीनें भी वहां पर लगायें कि एक-दो घंटे के अन्दर जो छोटी-मोटी जांच हो, उसका निराकरण उसमें हो। सोनोग्राफी जांच के नाम पर तो आज यह हालात हैं जिला मुख्यालय पर कि उसको दस और पन्द्रह दिन का समय दिया जाता है, तो दस और पन्द्रह दिन बाद यदि सोनोग्राफी की रिपोर्ट आयेगी तब तक तो वह मरीज इतना गम्भीर हो जायेगा कि फिर उसको बचाना हमारे बस की भी बात नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण का बिंदु संख्या-37 जो है, आज भी सभी किसानों को ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया जा रहा है। सभी पात्र किसानों को अल्पकालीन ऋण देने की विशेष व्यवस्था की जाये। सहकारिता मंत्रीजी यहां पर विराजमान नहीं हैं, सहकारिता आंदोलन से यदि हम किसान का भला करना चाहते हैं तो सहकारिता आंदोलन को हमें और मजबूत बनाना पड़ेगा। सहकारिता के अन्दर इस बार हमने देखा कि एम.एस.पी. की खरीद ढंग से नहीं हो पायी। किसानों को यूरिया और डी.ए.पी. नहीं मिल पाया, तो इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। इफको और आई.पी.एल. जैसी कम्पनियों ने सहकारी सिस्टम को बिलकुल धता बताते हुए निजी दुकानदारों को जरूर आई.पी.एल. ने यूरिया और डी.ए.पी. उपलब्ध करवाया लेकिन सहकारी संस्थाएं जो हैं, वे दिन पर दिन घाटे में जा रही हैं।

हम यदि आर.जी.एच.एस. की बात करें तो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जो दवाइयां बिक रही हैं, उन सहकारी संस्थाओं को समय पर पैसा नहीं मिल रहा है।

(श्री नारायण बेनीवाल)

(समय: 14.59 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

प्राइवेट व्यक्ति, जो दुकानदार आर.जी.एच.एस. का काम कर रहा है उसको तुरंत पैसा मिल जाता है, तो इतना बड़ा जो भार है वह सहकारी संस्थाएं भी नहीं झेल पाएंगी तो मेरा यह निवेदन रहेगा कि सहकारी तंत्र को भी मजबूत करें।

इस बार सहकारी तंत्र में आपने चुनाव की शुरुआत कर दी। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं कि सहकारी तंत्र को मजबूत करने के लिए आपने बीड़ा उठाया है।

(समय: 15.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज हो गया।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ी-सी मेरी मांगें रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य। प्लीज, आपका टाइम हो गया है। It is more than sufficient.

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, 15 मिनट तो आपने दिये ही हैं।

श्री अध्यक्ष: No. Who said it? किसने कहा 15 मिनट? आपकी पार्टी से और कोई नहीं बोलेगा?

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): नहीं।

श्री अध्यक्ष: पुखराजजी, आपकी पार्टी से और कोई नहीं बोलेगा?

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): नहीं, एक ही बोलेगा।

श्री अध्यक्ष: पार्टी से कोई नहीं बोलेगा फिर एक भी दिन? तीन दिन हैं अभी। Please understand it. The time is allotted to your party; not for an individual. एक दिन में 15 मिनट नहीं हैं।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, सिर्फ 2 मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज। Please, wind-up.

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): 2 मिनट सर। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायती राज के सारे सरपंच संघ आमरण अनशन पर बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि वहां किसी अधिकारी को भेजें। उनके साथ बैठकर उनकी मांगों का विश्लेषण करके उनका आमरण अनशन तुड़वाया जाए और पंचायती राज शोध संस्थान की घोषणा पिछली बार मंत्रीजी ने कर दी थी, लेकिन उसके लिए बजट जारी नहीं किया था, उसकी भी मैं मांग करता हूं।

(श्री नारायण बेनीवाल)

खींवसर में ट्रोमा सेन्टर, शंखवास में सी.एच.सी., करनाड, पीपलिया, भोमासर, ग्वालू में पी.एच.सी., एक 32 के.वी. शंखवास के अन्दर और खजवाना में महाविद्यालय, पांचोली व शंखवास में उप तहसील की मेरी मांग है।

अध्यक्ष महोदय, तीन वर्ष से कम उम्र के बछड़ों के परिवहन पर रोक के सम्बन्ध में आपने जो कमेटी बनायी है, माननीय कृषि मंत्रीजी विराजमान हैं, इसका पूरा विश्लेषण करके छूट दें, ताकि मेलों की रौनक वापस आये और किसानों को लाभ मिले।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्य, अब नहीं।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): इसके अलावा खींवसर के अन्दर सिविल न्यायालय और मॉडल स्कूल तथा कृषि मण्डी हेतु बजट दिया जाए। चावण्डिया-हिसावा-पांचला-सिद्धा से लेकर नारवा-कांटिया-खींवसर-माधानियों की ढाणी तक 60 किलोमीटर लम्बी सड़क।

श्री अध्यक्ष: और कोई बाकी बचा है क्या?

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): खींवसर महाविद्यालय का नाम तेजाजी के नाम पर नामकरण करने का श्रम करावें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: टाइम को 'adhere' नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है। माननीय पुखराजजी, the allotted time is for party, not for individuals. आपका डिबेट में टाइम है 15 मिनट। एक दिन का 15 मिनट नहीं है।

माननीय मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

प्रदेश में ओलावृष्टि एवं शीतलहर से फसलों का नुकसान

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हाल ही में प्रदेश के कतिपय इलाकों में ओलावृष्टि एवं शीतलहर से फसलों को हुए नुकसान के बारे में सरकार की ओर से अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

महोदय, राज्य में रबी मौसम में औसतन 103 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में विभिन्न फसलों की बुआई होती है, जिनमें मुख्यतः गेहूं, जौ, चना, सरसों

(श्री लालचन्द कटारिया)

व तारामीरा सम्मिलित हैं। रबी 2022-23 फसल मौसम में 109 लाख 55 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई है। हाल ही में दिनांक 6 एवं 7 जनवरी को तथा दिनांक 14 से 19 जनवरी तक पाले एवं शीतलहर से फसलों में क्षति हुई है। प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार गेहूं की फसल का 29 लाख 65 हजार हैक्टेयर बोये गये क्षेत्रफल में से लगभग 42 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में खराबा हुआ है। जौ फसल का 4 लाख 8 हजार हैक्टेयर बोये गये क्षेत्रफल में से 19 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में खराबा हुआ है। चना फसल में 20 लाख 57 हजार हैक्टेयर बोये गये क्षेत्रफल में से 2 लाख 25 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में 2 से 40 प्रतिशत तक खराबा हुआ है। सरसों व तारामीरा का कुल बोया गया क्षेत्रफल 39 लाख 36 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में से 9 लाख 83 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में 2 से 65 प्रतिशत तक का खराबा हुआ है। इसी तरह सब्जियां एवं उद्यानिकी फसलों का कुल बोया गया 15 लाख 89 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में से 2 लाख 22 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में 2 से 60 प्रतिशत तक खराबा हुआ है।

इस प्रकार माह जनवरी, 2023 में पाले एवं शीतलहर से कुल बोये गये 109 लाख 55 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में से लगभग 14 लाख 92 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में 2 से 65 प्रतिशत तक फसल खराबा होने की सूचनाएं हैं।

यह खराबा मुख्यतः श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, चूरू, झुन्झुनूं, जयपुर, जालौर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, सीकर, भरतपुर, पाली, अजमेर, जोधपुर और प्रतापगढ़ में हुआ है। श्रीगंगानगर की सादुलशहर तहसील, झुन्झुनूं की मलसीसर, सूरजगढ़ व बुहाना सहित प्रदेश की अन्य तहसीलों में खराबे की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

पाला एवं शीतलहर से रबी 2022-23 अन्तर्गत फसलों में हुए नुकसान के दृष्टिगत राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के पत्र दिनांक 17.01.2023 के द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को रबी 2022-23 में बोयी गई फसलों में पाला एवं शीतलहर से नुकसान का तत्काल सर्वे करवाकर प्रभावित ग्रामों में आवश्यकतानुसार निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत विशेष गिरदावरी शीघ्रताशीघ्र करवाकर रिपोर्ट आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

राज्य में दिनांक 29.01.2023 को औसत 2.6 मिलीमीटर वर्षा व दिनांक 30.01.2023 को औसत 93 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई है। दो दिवस में प्रमुख रूप से राजसमन्द में 54.7 मिलीमीटर अजमेर में 41.7

(श्री लालचन्द कटारिया)

मिलीमीटर, सवाई माधोपुर में 30.7 मिलीमीटर, भीलवाड़ा में 29.2 मिलीमीटर, सिरोही में 27.8 मिलीमीटर, पाली में 27.6 मिलीमीटर, उदयपुर में 27.1 मिलीमीटर, बून्दी में 26.3 मिलीमीटर, टोंक में 25.5 मिलीमीटर, दौसा में 24.6 मिलीमीटर, जयपुर में 22.8 मिलीमीटर, अलवर में 20.2 मिलीमीटर, नागौर में 19.8 मिलीमीटर, प्रतापगढ़ में 18.9 मिलीमीटर, सीकर में 18.7 मिलीमीटर और चित्तौडगढ़ में 18.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। राज्य में वर्तमान में वर्षा का दौर जारी है। जहां इस वर्षा से रबी फसलों की उपज में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर जिला चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमन्द, कोटा व बूंदी में वर्षा, तेज हवाओं व ओलावृष्टि से गेहूं, जौ, चना, सरसों एवं सब्जियों की फसलों में प्रभावित क्षेत्र में नुकसान होने का प्रारम्भिक अनुमान है।

आरम्भिक अनुमान के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिले में कुल बुआई क्षेत्रफल 3 लाख 19 हजार हैक्टेयर में से चित्तौड़गढ़ एवं बेगूं विधान सभा क्षेत्र में 2 लाख 94 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में ओलावृष्टि से खराबा हुआ है। पाली जिले में कुल बुआई क्षेत्रफल 3 लाख 18 हजार हैक्टेयर में से पाली, सुमेरपुर, बाली, मारवाड़ जक्शन, सोजत व जैतारण विधान सभा क्षेत्र में 39 हजार 5 सौ हैक्टेयर क्षेत्रफल में खराबा हुआ है। उदयपुर जिले में कुल बोये गये क्षेत्रफल 1 लाख 33 हजार हैक्टेयर में से मावली, वल्लभनगर व उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में 11 हजार 2 सौ 25 हैक्टेयर में खराबा हुआ है। सिरोही जिले में कुल बोये गये क्षेत्रफल 77 हजार 8 सौ हैक्टेयर में से रेवदर, आबू, पिण्डवाड़ा व सिरोही विधान सभा क्षेत्र में 14 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में खराबा हुआ है। इसके अतिरिक्त कोटा जिले के सांगोद व इटावा ब्लाक व बूंदी जिले के हिण्डौली ब्लाक तथा राज्य के अन्य जिलों में भी ओलावृष्टि व तेज हवा से फसल खराबे की सूचना प्राप्त हुई है।

उपरोक्त फसल खराबे की विस्तृत रिपोर्ट हेतु विशेष गिरदावरी के आदेश पूर्व में ही जारी किये जा चुके हैं। विशेष गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आपदा राहत कोष से सहायता प्रदान की जायेगी। साथ ही ओलावृष्टि तथा जल भराव के कारण खड़ी फसल में तथा असामयिक वर्षा व ओलावृष्टि के कारण खेत में काटकर सुखाने के लिए रखी गई फसल को हानि होने पर स्थानिक आपदा के तहत फसल बीमा का लाभ देय है। इसके लिये जिन काश्तकारों ने फसल बीमा करा रखा है, उन्हें अपने फसल खराबे की

(श्री लालचन्द कटारिया)

सूचना 72 घण्टे के भीतर बीमा कम्पनी अथवा कृषि विभाग के कार्यालय में देना आवश्यक है। विभाग द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों को फसल खराबे की सूचना के लिये पाबन्द किया गया है तथा प्राप्त सूचना का दो सप्ताह के भीतर इनका सर्वे करवाकर फसल बीमा क्लेम से लाभान्वित की कार्रवाई की जायेगी।

राज्य सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई करने एवं उनके हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जायेंगे। कृषि विभाग, आपदा राहत विभाग एवं राजस्व विभाग मिलकर संयुक्त रूप से फसलों को हुई क्षति को लेकर गम्भीरता से कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान के अन्दर...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह डिबेट जनरल डिस्कशन नहीं है। टू-द-पाइंट ब्रीफ में बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा डिस्कशन हो पायेगा।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने इस चर्चा में भाग लेने और बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद। विशेषकर मेरे क्षेत्र के अन्दर शीतलहर के कारण फसलें ज्यादातर खराब हुई हैं जिसमें सरसों ईसबगोल, कणक, चना सर्दी की वजह से पूरे बीकानेर जिले में किसानों का भयंकर रूप से खराबा हुआ है। मैं सरकार से यही मांग करना चाहूंगा कि उसका जल्दी से जल्दी आकलन और गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिलवाने का कष्ट करें। यही मेरा सरकार से निवेदन है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल (अनुपस्थित)। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। मंत्रीजी, आपने जो अभी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की है, आपकी रिपोर्ट यह कहती है कि इस बार कुल मिलाकर 14 लाख 92 हजार हैक्टेयर में से 102 लाख हैक्टेयर में बुआई हुई थी, उसमें 65 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। प्रारम्भिक नुकसान जिन जिलों में हुआ है, वह सारी रिपोर्ट आपके पास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, SDRF बना हुआ है। केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर 50

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रतिशत राज्य सरकार की और 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार की होगी। इसके पीछे मकसद एक ही था, इसके टर्म और रेफरेंस को अगर आप पढ़ोगे तो जब कभी भी किसान पर ऐसी आपदा आये और उस आपदा के लिये तत्काल उनको राहत देने के लिये SDRF नोर्म्स से आपको किसान को तत्काल सहायता देनी चाहिये। अब आप स्पेशल गिरदावरी करवा रहे हैं। आपने जिस तरह आदेश दिये, ऑनलाइन गिरदावरी हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं मंत्री महोदय को कि इस ऑनलाइन गिरदावरी के अंदर न तो जन-प्रतिनिधियों को पता, क्योंकि मेरे खुद के इलाके में नुकसान हुआ है, न वहां की ग्राम पंचायत को पता और ऑनलाइन गिरदावरी वहां बैठे-बैठे की जा रही है। जब आपका खुद का प्रथम आकलन यह कह रहा है, कितना नुकसान हुआ है, तो SDRF में 19 हजार करोड़ रुपये आपके पास पड़े हैं, इससे आप तत्काल उनको सहायता दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ आपको याद होगा इसी सदन के अंदर, इसी मौके पर सदन स्थगित होकर दो दिन तक सर्वे के लिये जन-प्रतिनिधियों को भेजा था और उस समय जो फसल खेत के अंदर बरबाद हो गयी, उस फसल को अब किसान को उठाकर निकालकर ले जाने के लिये उस वक्त नरेगा और दूसरी चीजों के साथ कोलोबरेशन करके एक पैकेज बनाया गया था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उस पुराने पैकेज का अध्ययन कर लें और उसमें तत्काल किसानों को राहत प्रदान करें, क्योंकि इसमें जितनी बरबादी हुई है, वह आपके सामने है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 200 ग्राम तक के ओले पड़े हैं। इस दो दिन की बरसात ने किसान की कमर और तोड़ दी। कई जिलों के अंदर खड़ी हुई फसल बरबाद हो गयी। आप जिस बरसात की बात कर रहे हैं, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बरसात तेज हवा के साथ आयी, इससे खड़ी फसल गिर गयी, इसलिए भगवान के लिये SDRF में आपके पास पैसा पड़ा है। आपके इन पैसों के अनुसार आप किसानों को तत्काल मुआवजा दिलायें।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण बेनीवाल (अनुपस्थित)। श्री हमीर सिंह भायल। (व्यवधान) हाथ खड़े करने से नहीं, जिन्होंने स्थगन पर लिखकर दिया है, वे ही बोलेंगे।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पिछले

(श्री हमीर सिंह भायल)

दो दिनों में बिना मौसम जो बारिश हुई है, बारिश होने से कई जिलों में ओले भी गिरे हैं। तेज हवा चली है और बारिश हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर और जालौर जिले में अरण्डी की फसल होती है, अरण्डी में ओले न भी गिरें, वहां बारिश कम हुई है, पर ठण्डी हवा चली है। दूसरा, जीरा एक नाजुक फसल है। जीरा ठण्डी हवा के सामने जाता है, वहां पर इतना नुकसान हुआ है, इसकी अगर सही समय पर गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत नहीं दी गयी, किसान तो इस बार यूं भी बरबाद हो चुका है, क्योंकि किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलने की वजह से फसल चौपट हो गयी है। आज की तारीख में वहां पर इतना खराबा हो गया है। बारिश से बोयी हुई अरण्डी, आंकड़ा, बबूल ठण्डी हवा के सामने जाकर जल जाती है तो ऐसी स्थिति हो गयी। इसका सही समय पर सर्वे करवाकर किसानों को राहत दें और किसानों के जो चार माह के बिजली के बिल हैं, इनको माफ करें। किसान बरबाद हो गये हैं। अगर इनके बिजली के बिलों को माफ नहीं करेंगे तो किसान की हालत खराब हो जायेगी। न तो उनको समय पर बिजली मिली और इस ओलावृष्टि से किसान पैरों पर खड़े नहीं रह पायेंगे। यही मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से बारिश हुई है, बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, पूरे मेवाड़ में ओलावृष्टि हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी मेवाड़ से पधारते हैं और प्रतिपक्ष के नेता भी वहां से आते हैं। वहां पर आधा-आधा किलो के, ढाई सौ ग्राम की ओलावृष्टि हुई है। सड़कों की यह स्थिति हुई है कि सड़कों से ओलों को JCB से हटाया गया। मैं आपको बताऊं, यह न्यूज़पेपर में भी है कि वहां पर यह कंडीशन है। हमारे वहां पर अफीम की फसल पैदा होती है और पूरे जिले में अफीम की फसल तहस-नहस हो गयी है और अफीम के डोडे फूटने के बाद दूध एक बार बाहर निकलने के बाद किसी भी कंडीशन में उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। हमारे वहां जौ है, गेहूं है, सरसों है, वह पूरी फसल तहस-नहस हो गयी है। कल हमारे सभी जन-प्रतिनिधियों ने जाकर फील्ड में भी देखा है। वहां पर किसानों की हालत बहुत नाजुक है। पहले भी शीतलहर की वजह से फसलें नष्ट हो चुकी हैं और बची हुई फसल इस ओलावृष्टि से नष्ट हो चुकी है। हमारे वहां पर काफी धरने-प्रदर्शन भी हो रहे हैं, वहां पर ज्ञापन भी दिये

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय हम भी एम.एल.ए. थे, हम लोगों को फील्ड में भेजा था कि आप दो दिन इसका सर्वे करवा लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप सभी एम.एल.एज. को भी भेजें। वहां पर एक टीम बनाकर भेजें। इस नुकसान की वजह से जिस प्रकार से किसान की कमर टूट गई है, इसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं। SDRF के थ्रू 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है, 50 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। मंत्री महोदय भी किसान परिवार से आते हैं और वे भी देखते हैं कि किसान परिवार की क्या हालत होती है, क्योंकि किसानों की पिछले चार सालों में आपने कैसी हालत कर दी, वह आप लोगों के सामने है। ऊपर से अगर भगवान भी नाराज हो जाये और सरकार भी नाराज हो जाये तो उस किसान का क्या होगा? सरकार तो पहले से ही किसानों से नाराज है और भगवान भी नाराज हो गया तो एक बार आप सरकार को कहकर सर्वे करवा दें, क्योंकि वह जी नहीं पायेंगे, किसान रह नहीं पायेंगे। पटवारी से गिरदावरी करवा दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत दयालु हैं अगर आप एक बार टीम बनाकर भेजेंगे तो 100 प्रतिशत हमारे वहां के किसानों को फायदा हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया और किसानों की बात रखने का मौका भी दिया और ओलावृष्टि के लिये मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि एक बार इसकी गिरवादरी करवाकर सर्वे करवा लें और कलेक्टर साहब को आप आज ही आदेश फरमावें कि किसानों के प्रति वे सहानुभूति रखें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से, माननीय कृषि मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि शीतलहर से रबी फसलों में 65 फीसदी तक नुकसान हुआ, यह नागौर कलेक्टर ने आदेश दिये हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन गिरदावरी की बात कही जा रही है। इसमें न तो जन-प्रतिनिधियों को इसके बारे में सूचना है, न ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी सूचना है। क्रोप कटिंग के अलावा, कई जगह विशेष नुकसान हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा की भी हम बात करें तो फसल बीमा के भी कई प्रकरण आपके यहां पेंडिंग हैं और इन सारे मामलों में, मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि सबसे ज्यादा नुकसान कुचामन के अंदर दिखाया गया है, जबकि

(श्री नारायण बेनीवाल)

इसके अलावा डीडवाना, लाडनूं, परबतसर में भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अनुमानित नुकसान सरसों के अंदर सबसे ज्यादा दिखाया, जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय, जीरा और ईसबगोल की खेती हमारे इलाके में बहुत बड़ी तादाद में होती है। जीरा और ईसबगोल तो बड़ी नाजुक खेती है। इसके अंदर तो बारिश के थोड़े से छींटे भी पड़ जाएं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है क्योंकि इसका प्रीमियम भी बड़ा होता है और इसका यदि मुआवजा देना पड़े तो वह भी बड़ा होता है, इसलिए बीमा कम्पनियां इससे कहीं न कहीं कतराती है कि मुआवजा नहीं मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसकी विशेष गिरदावरी में जन-प्रतिनिधियों को भी शामिल करके कहीं न कहीं ठोस कार्ययोजना बनायें कि किसान, जो कि वास्तव में दु:खी है, उसको मुआवजा मिले और बिजली के जो बिल हैं इस बार के, उनको भी माफ करने की सरकार यहां घोषणा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट पढ़ा है, मैं कहता हूं आपको, इसकी और सही जांच करायें। कारण क्या है कि केवल और केवल आपकी मशीनरी भेज दें, उस पर डिपेंड नहीं रहकर एक बार पुन: सर्वे करवायें। कारण यह है कि दो चीजों को अलग करने का प्रयास करो। आपदा राहत का अलग पैसा है और फसल बीमा अलग है। कई बार हम इन दोनों को जोड़ देते हैं इससे किसान को बहुत नुकसान हो जाता है। मैं सोचता हूं कि आपदा राहत में हमारे पास पर्याप्त शक्तियां हैं कि हम जब चाहें, जिस समय चाहें, किसान को तुरंत मदद पहुंचाने का अधिकार हमको आपदा राहत में है। फसल बीमा में नहीं है। फसल बीमा में तो जब तक बीमा कम्पनी तय नहीं करेगी, तब तक अपन नहीं कर पायेंगे। मैं स्वयं तो उदयपुर नहीं था, पर मेरे संभाग में पहली बार इतनी भारी ओलावृष्टि लोगों ने अपने समय में नहीं देखी। एक-एक फीट तक ओलों की परत सड़कों के ऊपर जम गयी और उनको हटाने के लिये JCB लगाकर सड़कों को खाली करना पड़ा। खेतों में भी इसी प्रकार इतनी ज्यादा ओलावृष्टि हुई है कि सारी की सारी फसल खराब हो गयी और जमीन ठोस हो गयी और पानी भरने के कारण से सारी फसल उसमें डूब गयी। अभी जो प्रारम्भिक रिपोर्ट आपने दी है, केवल इसी पर आप डिपेंड मत करना। कारण क्या है कि उदयपुर जिले का मावली और वल्लभनगर तो नंबर वन पर खराबे में रहा ही है, लेकिन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोई भी एरिया नहीं बचा है। कोटड़ा नहीं बचा, गोगुन्दा नहीं बचा, झाड़ौल नहीं बचा। केवल थोड़ा सा एरिया, कम अगर प्रभावित हुआ तो खेरवाड़ा और ऋषभदेव का एरिया, थोड़ा सलूम्बर का एरिया कम प्रभावित हुआ। बाकी सारा एरिया उससे प्रभावित है।

मैं आपसे निवेदन यह कर रहा हूं कि हमने पिछली बार भी कहा कि खराबा हुआ, लेकिन समय पर पैसा नहीं मिला। आप एक तो कृपा करके दोनों को मत जोड़ो। आपदा राहत का पैसा आपकी स्वतंत्र सोच के आधार पर है। आप उसमें से कुछ पैसा तो तुरंत, जैसे जानवर मर गया, आप दो मिनट में उसको रिलीज कर सकते हो। अगर वहां उसकी खेती को किसी और प्रकार का नुकसान है, बिजली गिर गयी, उसको तुरन्त राहत पहुंचा सकते हो। आपदा राहत का मतलब ही यही है। अगर उसको समय पर हम नहीं दे पाये तो वह आपदा राहत नहीं रहा। मैं सोचता हूं कि इन दोनों को अलग करें।

आपदा राहत में भगवान की कृपा से जैसा हमारे पास केन्द्र से और आपका, दोनों का जो आया हुआ है वह आज की तारीख में बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास सुरक्षित है। हमने पिछले सालों में आपदा राहत के अंतर्गत पैसे का पेमेंट नहीं किया। मैं चूंकि आपदा राहत मंत्री रहा, इसके कारण से मुझे लगता है कि हमने तुरंत निर्णय किया। 17 हजार पर-हैक्टेयर के हिसाब से तुरंत रिलीज करके हजारों करोड़ रुपया दिया। पूरे एरिया में दिया। कोई विधान सभा ऐसी नहीं रही, कहीं 20 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ हमने दिया।

मैं सोचता हूं कि हम इस सदन के माध्यम से आज इस चर्चा को यहीं वाइंड अप नहीं करें। अभी हमारे पास एक्चुअल फिगर्स जो आने चाहिए, वे सारे के सारे नहीं आये हैं। उन फिगर्स को आप तुरंत मंगाने का प्रयास करें। एक बार सदन समाप्त होने के पहले आप अपने सारे फिगर्स को उठाकर, आपदा राहत के तहत आप क्या-क्या घोषणा कहां-कहां करने वाले हो, वह अगर सदन में करेंगे तो राजस्थान की जनता को यह लगेगा कि हमारे जन-प्रतिनिधि ने जो पैरवी की है उसके कारण से हमको यह राहत तुरंत मिल गयी।

अब आपके यहां समस्या क्या आ रही है कि जहां आपका फसल बीमा कर रखा है, आपने जिसको केवल फसल बीमा का पेमेंट कर दिया, उसको आपदा राहत में नहीं जोड़ना चाहते। जिसको आपदा राहत में कर दिया, उसे फसल बीमा में नहीं जोड़ना चाहते। इन दोनों को भी स्पष्ट करिये। इसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कारण से राजस्थान के किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं सोचता हूं कि दोनों अपने आप में अलग हैं। इनको ध्यान में रखते हुए तुरंत इस गिरदावरी को मंगायें। जैसे आपने स्वयं ने माना और वास्तव में अब की बार जिस प्रकार से फसल का नुकसान हुआ है, सरसों तो हमारे एरिया में कटकर के इकट्ठी हो गयी, वह सारी की सारी नष्ट हो गयी। अब यह हो सकता है कि वह 100 किसानों की हुई या 500 को हुई। यह मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन जिस एरिया में भी यह जो ओलावृष्टि हुई है, वहां बिलकुल 100 परसेंट नुकसान हो गया है। वहां कोई पर्सेन्टेज दिखाने की जरूरत नहीं है।

आपका डिपार्टमेंट जो कई बार फिगर्स भेजता है कि यहां फसल का 60 परसेंट नुकसान हुआ, यहां 12 परसेंट हुआ। कुछ थोड़ी-बहुत सहानुभूति रखो। यहां 7 परसेंट, 13 परसेंट के आधार पर अगर उस किसान को आपदा में अगर 33 परसेंट से नीचे आ गया तो नुकसान होने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिलेगा। मैं सोचता हूं कि थोड़ा-बहुत मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए डिपार्टमेंट को कहिये कि अगर करीब भी आता है तो उसको उस सीमा में लायें ताकि उसको तुरंत राहत मिले। मैं सोचता हूं कि इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है।

स्पीकर साहब, मैं आपसे इतनी जरूर प्रार्थना करता हूं कि एक बार इनके सारे फिगर्स आ जाने के बाद दुबारा इस पर अपना स्टेटमेंट दें कि वास्तव में राजस्थान में किस एरिया में पाले से नुकसान हुआ। कई बार तो यह जो आपके इंश्योरेंस वाले हैं, वह कहते हैं कि पाला हमारे में कवर ही नहीं होता है। अब उसके कारण से वह उसमें से निकल जाते हैं। वह अगर पाले से कवर नहीं होता तो कम से कम आपदा में कवर करके तो उनको राहत देने का प्रयास करो, तब तो उसके सही रूप से बैठेगा। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में तुरंत करें।

पशुओं का नुकसान हुआ उसको भी आपको देखना है। लोगों के एक तरह से मकान ढहे हैं। उनके केलु फूटने के कारण, गिरने के कारण सारा का सारा चौपट हो गया। उन सबको भी तुरंत आकर के आपदा राहत के तहत जितनी सहायता आप दे सकते हो, उतनी खुले मन से सहायता दें, ताकि हम किसान की मदद कर सकें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर।

श्री अध्यक्ष: No please. Not allowed. I say, not allowed. बैठ जायें प्लीज। नो, नो, रिकार्ड नहीं होगा। गलत परम्परा डालना चाहते हैं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिस प्रकार की ओलावृष्टि हुई है, माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष और माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने और माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की, उसमें मैं स्वयं भी यह कह सकता हूं कि उदयपुर के कई वीडियोज किसानों ने डाले। ये मेरे व्हाट्सएप पर आये हैं। वे वाकई इतने भयानक हैं कि कई-कई खेतों में तो 2-2 फीट की चादर चढ़ी हुई है।

कुछ लोगों का यह कहना है कि कई वर्षों के बाद में, दशकों के बाद में इतनी ओलावृष्टि उदयपुर संभाग में हुई है। जैसे भायल साहब कह रहे थे कि अलग-अलग जगह अलग-अलग तरह का वातावरण बना है। कहीं हवाएं इतनी तेज चली हैं कि सरसों की फसल, गेहूं की फसल, जौ की फसल और कपास तथा अन्य जो दूसरी फसलें हैं चित्तौड़ साइड में, वह गिरकर के खराब हो गयीं। कहीं ओलावृष्टि हुई, कहीं बरसात ज्यादा हो गयी। जैसे भायल साहब ने कहा कि आपके अरंडी का मामला है, यह अरंडी ज्यादातर गुजरात में बोयी जाती है। कुछ सालों से राजस्थान के जो निकटवर्ती जिले हैं उनमें भी बोयी जाती है। अरंडी में तो हल्का सा पाला भी पड़ गया तो वह पेड़ खतम हो जाता है। यह बात भी पहले हमारे पास आ चुकी थी।

मैं तो सदन को यह विश्वास दिला सकता हूं कि यह सारा प्रकरण सरकार गंभीरता से देख रही है, विभाग भी देख रहा है, राजस्व विभाग भी देख रहा है, आपदा प्रबंधन भी देख रहा है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो बात कही है कि तुरंत राहत कैसे पहुंचायी जाये। यह बात भी सही है कि जो स्थिति बनी है, उसमें कहीं पशुओं की डैथ भी हुई है। सूचनाएं अभी निकलकर आयेंगी। कहीं पर मकानों में भी नुकसान हुआ है। कहीं टीनशेड थे, उनमें भी नुकसान हुआ है। ये सारी बातें 2-3 दिन में क्लियर होंगी।

मैं सदन को और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि दलगत राजनीति तो अलग है, लेकिन यह बात सही है कि पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है। मैं 3-4 दिन पहले हनुमानगढ़ गया था तब चूरू होकर के निकला था। वहां कई खेतों में मैंने देखा कि पाले की वजह से सरसों में भारी नुकसान है। हनुमानगढ़ तक मैं जाकर के आया था। कई जगह मुझे किसान भी मिले। उन्होंने मुझे ले जाकर के सरसों के खेत भी दिखाये। नुकसान सभी जगह है।

(श्री लालचन्द कटारिया)

आपदा प्रबंधन में और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हमने दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। सख्त दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं कि मौके पर खेतों में जाकर हमारे जो कृषि पर्यवेक्षक हैं, पटवारी हैं, गिरदावर हैं, वे अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को दें।

मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा, शायद सदन दो दिन और चलेगा, उसके बाद में बजट की छुट्टियां हैं, अपन सभी जन प्रतिनिधि हैं, किसान का मामला है, आपको भी जो सूचनाएं कहीं से मिलें तो निश्चित रूप से जब आप पधारें तो वे सूचनाएं हमें उपलब्ध करा दें ताकि कहीं कोई कमी-बेशी रहे या कहीं कोई कमी दिखे, किसी प्रकार की लापरवाही अधिकारी लेवल पर हो तो उसको हम दूर कर सकें। किसान का मामला है, किसान बड़ी उम्मीद से था।

कई जिले ऐसे भी हैं जहां लाभ भी हुआ है। बिजली की बचत हुई है। हमारे पास बिजली कम थी, पानी कम था, कई समस्याएं हो रही थीं। कुछ जिलों में तो किसान खुश भी हैं लेकिन जहां नुकसान हुआ है वहां भारी नुकसान हुआ है। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि यह जो विशेष गिरदावरी है, इसमें हम पूरा ध्यान रखेंगे। जो नुकसान किसान का हुआ है, उसका पूरा मुआवजा दिलाने की भरसक कोशिश की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जो सदन की भावना है, जब स्पेशल गिरदावरी करा रहे हैं तो गिरदावरी करने वालों को कहें कि जन प्रतिनिधियों को भी उनके साथ इन्वाल्व करें, जिससे गिरदावरी प्रभावशाली ढंग से लागू हो सके।

सदन अभी लम्बा चलेगा। आपने स्पेशल गिरदावरी के लिये दो सप्ताह में कहा है। सदन के इस दो सप्ताह के बाद जो-जो भी मेजर्स लेने हैं कि बीमा में कितना होगा, अकाल में कितना देंगे, कितना इंडिविजुअल जिस आदमी को नुकसान हो गया, मकान का हो गया, जानवर का हो गया, उस तरह की व्यवस्था और उसकी विस्तृत जानकारी लेकर दुबारा सदन के अंदर यह चर्चा करें। मैं समझता हूं कि इससे जो किसान की मंशा है, उसमें उसकी तकलीफ के साथ हम भागीदार बन सकेंगे। चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामलाल मीणा।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्य मंत्री जी अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान नये आयाम स्थापित कर रहा है। मुझे गर्व है कि राजस्थान ने वर्ष 2021-22 में 11.04 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं डबल डिजिट जी.डी.पी. ग्रोथ रेट के साथ राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर आया है। यह सूबे के मुख्य मंत्री की जादूगरी है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन 4 सालों में जो योजनाएं लांच की हैं, उन योजनाओं का प्रदेश भर में, पूरे विश्व में बखान हो रहा है। चाहे मुख्य मंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना हो, जब हम सब यहां आये थे, उस समय हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था, कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि और कभी अनावृष्टि से फसलें नष्ट हो जाती हैं और किसान बिजली के बिल समय पर नहीं भर पाते थे। अभी हमारे माननीय सदस्य, गणेश घोघराजी बोल रहे थे कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, करंट बिजली के तारों में नहीं आकर बिजली के बिलों में आता था। यह बात सही है कि अगर दो बार बिजली के बिल नहीं भर पाते थे तो बिजली विभाग के अधिकारी आकर उसका ट्रांसफार्मर उतारकर ले जाते थे, तार उतार देते थे। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने किसान मित्र योजना लागू करके पूरे राजस्थान के किसानों का भला किया है। हर बिल के अंदर 1,000 रुपया प्रति माह आप जमा करा रहे हैं जिससे किसानों को बिजली भी मिल रही है और उसका बिल भी 'जीरो' हो रहा है। मई, 2021 से दिसम्बर, 2022 तक 12 लाख 88 हजार किसानों को करीब 1 हजार 727 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। इससे लगभग 8 लाख 93 हजार किसानों का बिजली का बिल 'शून्य' हो गया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो यह काम किया है वह किसान के लिए वरदान साबित हुआ है।

(श्री रामलाल मीणा)

मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान योजना में 50 यूनिट तक घरेलू कनेक्शन में बिजली फ्री कर दी, उसके बाद सब्सिडी दे दी, जिसमें अब तक 3 हजार 972 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है। लगभग 39 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 'शून्य' आया है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आज आपने 5 जिलों में दिन में लाइट देने का काम किया है, उसमें प्रतापगढ़ सबसे पहला जिला था जिसके अंदर किसानों को दिन में लाइट मिल रही है। एक समय था, कड़ाके की ठंड में किसानों को पाणत करनी पड़ती थी और इस दौरान कई हादसे हो जाते थे। जहरीले जानवर काट खाते थे, जिससे किसानों की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आज दिन में ही लाइट किसानों को मिल रही है। दिन में ही मिल रही है, दिन के साथ-साथ किसानों को फ्री में लाइट मिल रही है। मैं बता रहा हूं कि चार साल के कार्यकाल में एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसने बिजली का बिल जमा नहीं कराया हो और उसका ट्रांसफार्मर बिजली विभाग के अधिकारी लेकर चले गए हों। पहले आए दिन ये घटनाएं होती रहती थीं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय को कि आपने किसानों के लिए बिजली व्यवस्था के लिए इतना सब किया। इतने नये जी.एस.एस. खुले, मेरे सिर्फ प्रतापगढ़ में 16 जी.एस.एस. पहले थे, 16 जी.एस.एस. ही आपने चार साल के कार्यकाल में नये खोले। अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय से एक और निवेदन है कि 132 के.वी. बारावरदा में भी आपने खोला, प्रतापगढ़ के पानमोड़ी और अरनोद में भी 132 के.वी.जी.एस.एस. खोलने की मैं मांग करता हूं। उसके बाद में नए जी.एस.एस. आपने खोले हैं, 33 के वी के 586 जी.एस.एस. आपने खोले हैं। गंदेर, गादोला, विरावली, बजरंगगढ़, पंडावा, बोरीएल, झोलर, गयासपुर, हाट सालमगढ़ में 33 के.वी.जी.एस.एस. की मांग करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पेयजल की बात हो, राजस्थान में तो आपने किया ही है, मेरे अकेले विधान सभा क्षेत्र में 1,620 करोड़ रुपये की घोषणा बजट सत्र के अंदर करके जाखम का पानी पूरे विधान सभा क्षेत्र सहित धमोतर पंचायत समिति के गांवों के अंदर एक-एक घर पर नल का कनेक्शन करने का आपने काम किया है।

(समय: 15.33 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

(श्री रामलाल मीणा)

माननीय सभापति महोदय, आप सड़क के मामले में देख लो, प्रतापगढ़ को टूटी-फूटी सड़कों के नाम से जाना जाता था। पूरे राजस्थान में सड़कें गड्ढों में तब्दील थीं, लेकिन हजारों किलोमीटर सड़कें आपने डबल पट्टी की की हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई सड़कें आज डबल पट्टी की हो गईं और सभी जगह गांवों में एक-एक, दो-दो सड़कें निकल रही हैं। इसके लिए मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में भले कोरोना जैसी महामारी हो, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने तत्परता से काम करते हुए कोरोना महामारी के अंदर भले वी.सी. के माध्यम से हो, हम सबने, मैंने खुद कोरोना महामारी के अंदर कम से कम 10 से 15 बार पी.पी.ई. किट पहन कर हास्पिटल में जाकर एक-एक मरीज की सेवा की है। सारे डाक्टर बराबर तरीके से लगे रहे। पूरे देश में राजस्थान मॉडल था। प्रधान मंत्रीजी ने खुद ने, माननीय मुख्य मंत्री महोदय का जो कोरोना काल का प्रबंधन था, उसकी प्रशंसा की है।

माननीय सभापति महोदय, आज पूरे राजस्थान के हर जिले में मेडिकल कालेज स्थापित हो रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ मेडिकल कालेज से वंचित है, इस बार के बजट में हमारे प्रतापगढ़ को भी मेडिकल कालेज दिया जाए। दल और सुहागपुरा चूकना को सी.एच.सी., खेरोड़, पान मोड़ी, बड़ी सांकली, घोटारसी, लोहारिया, बोरीएक में पी.एच.सी. की जाए।

माननीय सभापति महोदय, आपने देखा होगा, मैं भाषण में भी कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक समय था, पूर्ववर्ती सरकार के अंदर लोग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते थे और अपना जीवन खतम कर देते थे, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 10 लाख रुपये तक के इलाज की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लांच की, इससे हर व्यक्ति को इलाज मिल रहा है। इस पालिसी के अंतर्गत 750 अस्पताल पंजीकृत किये गये हैं, राज्य के करीब 88 प्रतिशत लोग स्वास्थ्य बीमा धारक हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका आंकड़ा 41 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अब तक 31 लाख 58 हजार लोगों का इलाज किया जा चुका है तथा कैशलेस उपचार पर लगभग 3 हजार 625 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। पूर्ववर्ती सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मद के लिए होने वाला खर्च केवल

(श्री रामलाल मीणा)

10 हजार करोड रुपये ही था, जिसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपये किया है।

आज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर व्यक्ति को यह चिंता नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा इलाज कैसे होगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो योजना लागू की है, मैंने कई बार भाषणों में भी कहा है कि भगवान की तस्वीर के साथ-साथ एक तस्वीर अशोकजी गहलोत साहब की भी रखी जानी चाहिए ताकि जो 10 लाख रुपये के इलाज की सुविधा दे रहे हैं, उससे गरीब लोगों को कहीं कोई तकलीफ नहीं आ रही है। यहां तक कि पहले किसी की मृत्यु हो जाती थी एक्सीडेंट के अंदर तो मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के लोग और उसके बच्चे अनाथ हो जाते थे, लेकिन अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कह दिया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, उसके अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपये तक का इलाज, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की कापी अगर ई-मित्र पर जमा कराई जाती है तो 15 से 20 दिन के अंदर उसके खाते में 5 लाख रुपये जमा हो जाते हैं। यह बहुत बड़ा काम है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह सब काम किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2022-23 में कुल 240 नवीन महाविद्यालय खोले गए। प्रतापगढ़ के अंदर पहले एक ही कालेज हुआ करता था, 5 नए कालेज वहां खोले हैं, उनमें कन्या महाविद्यालय, पीपलखूंट महाविद्यालय, दलोत महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय हैं। 5 महाविद्यालय प्रतापगढ़ जैसे छोटे-से जिले के अंदर भी खोले हैं। इस हेतु मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आज रोजगार के मामले में विभिन्न विभागों में बंपर भर्तियां निकल रही हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं को मौका मिल रहा है। रोजगार गारंटी योजना, यू.पी.ए. की सरकार में मनमोहन सिंह जी जब प्रधान मंत्री थे तो देखा कि आदिवासी क्षेत्र के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनको रोजगार नहीं मिलता है, उनका जीवन यापन सही तरीके से नहीं हो सकता है, इसलिए रोजगार गारंटी योजना को लागू किया। आपने देखा होगा कि कोरोना के अंदर यदि रोजगार गारंटी योजना नहीं होती तो विकट परिस्थिति हो सकती थी, लेकिन माननीय पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी

(श्री रामलाल मीणा)

और कांग्रेस सरकार को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने दूरगामी परिणाम को देखते हुए रोजगार गारंटी योजना को लागू किया। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 40 रुपये रोजगार गारंटी योजना में मिलते थे जो आज 120 से 150 रुपये इस योजना में मिल रहे हैं। आज रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शहरी क्षेत्र के अंदर भी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना को लागू किया और इसके अंदर ऐसे लोग हैं जो शहर के अंदर जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं थे, यह योजना आज उनके लिए एक वरदान साबित हो रही है। इसमें उनको 100 दिवस का रोजगार मिल रहा है। इसके अंदर 10 हजार 505 कार्यों हेतु लगभग 573 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी हो चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था कि मेरे कार्यकाल के अंदर कोई भूखा नहीं सोये, उसके लिए शहरों में इंदिरा रसोई योजना को लागू किया। हर जगह 8 रुपये के अंदर हर गरीब को स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार मिल रहा है। निश्चित रूप से यह योजना भी बहुत बढ़िया साबित हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, प्रशासन शहरों के संग शिविर के अंदर 6 लाख पट्टे जारी किये गये। 18 लाख 66 हजार पुराने प्रकरण, जो काफी लम्बे समय से चल रहे थे, उनको इन शिविरों के माध्यम से निस्तारित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा योजना में 3 लाख नये परिवारों को और जोड़ा गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट घोषणा में नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने की घोषणा की थी, उसी की तर्ज पर सभी जगह उचित मूल्य की दुकानें खुल रही हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से राज्य के अन्य स्थानों पर 4 हजार की आबादी पर पंचायतें बनीं लेकिन टी.एस.पी. क्षेत्र के अंदर 1 हजार 500 तक की आबादी पर पंचायतें बनी हैं इसी प्रकार से टी.एस.पी. क्षेत्र में भी उचित मूल्य की दुकानें, जहां पर 2 हजार यूनिट की बात है वहां 250 राशन कार्ड पर नई राशन की दुकान खोली जाए।

माननीय सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि ओल्ड पेंशन के लिए पूरे देश के कार्मिक आंदोलन कर रहे थे, किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की,

(श्री रामलाल मीणा)

लेकिन आपने एक ही झटके के अंदर 01 जनवरी, 2004 के पश्चात् नियुक्त राजस्थान के सारे कर्मचारियों के लिए ओ.पी.एस. लागू की, इसलिए मैं राजस्थान के कर्मचारियों की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री, अशोक जी गहलोत साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

आज प्रतापगढ़ में पांच बांध स्वीकृत हुए। चुनार डैम देवद कराड़िया बांध, मोटाधामनिया एनीकट, पाटावाला खोरा, चोरायता एनीकट, बिलेसरी, बागलिया, मोबाखेड़ी, दालाकोंड, जाम्बूखेड़ा, नरवाली, इन सभी जगह एनीकट की मैं मांग करता हूं। आज इस चार साल के कार्यकाल में प्रतापगढ़ में 3 पंचायत समितियों, 70 पंचायतों, 2 तहसीलों और 80 पटवार मण्डलों का गठन हुआ।

आज 4 आवासीय विद्यालयों का काम प्रतापगढ़ में चल रहा है। गोतमेश्वर को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। पूरे उदयपुर सम्भाग के आस-पास के लोग वहां आकर अस्थियों का विसर्जन करते हैं। वहां 70 सालों में कभी किसी ने कोई काम नहीं कराया, लेकिन इस बार वहां 2 करोड़ रुपये की लव-कुश वाटिका का निर्माण चल रहा है। गोतमेश्वर के दोनों तरफ सीढ़ियां बना दी गयी हैं। एक तरफ सी.सी. रोड का काम चल रहा है। बुजुर्ग लोगों को नीचे उतरने में परेशानी होती है। इसके लिए लिफ्ट का निर्माण भी बहुत जल्दी करवाया जाएगा। उसकी भी स्वीकृति हो गयी है।

आज दिवाक माता जैसा स्थान, जो एक बड़े मगरे के ऊपर है, कम से कम 10 से 15 हजार लोग वहां हमेशा आते हैं। वहां भी 1.40 करोड़ रुपये की पर्यटन विभाग ने घोषणा की है। दोनों तरफ सड़कों, गार्डन की पूरे तरीके से व्यवस्था वहां हो रही है। मैं मांग करता हूं, सीता माता, जहां 4-5 राज्यों के लोग मेले में आते हैं, बहुत ही दर्शनीय स्थल है। दीपेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव, नीलकण्ठ महादेव, कमलेश्वर महादेव, रिछड़ी महादेव, जानागढ़, इनके विकास की भी मांग करता हूं।

आज कई वर्षों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग छात्रावास की मांग कर रहे थे पर किसी ने सुना नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने गत बजट में अनुसूचित जाति का छात्रावास खोल दिया।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): उसे खोलने के बाद में आज वहां उसका टेंडर भी हो गया और छात्रावास का काम भी चालू हो गया, इसलिए

(श्री रामलाल मीणा)

माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। 17 जिलों में नयी नन्दीशालाएं स्वीकृत कर 45 लाख रुपये की राशि आबंटित कर 7 करोड़ 45 लाख रुपये प्रत्येक पंचायत समिति के स्तर पर भी 1 करोड़ 57 लाख रुपये की लागत से नन्दीशालाओं का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और 40 संस्थाओं के साथ अनुबन्ध भी हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 01 करोड़ की लागत से गौ आश्रय बनाये जा रहे हैं। प्रथम चरण में 1,500 ग्राम पंचायतों में आश्रय स्थल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 1,377 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में जनजाति विकास की राशि 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये की गयी थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और जनजाति मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा।

आज प्रतापगढ़ सहित सभी टी.एस.पी. जिलों में एवं उदयपुर, कोटा, जयपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु बहुमंजिला कोचिंग सेंटर स्थापित हो चुके हैं। बहुत जल्दी उन लड़कों का वहां एडमिशन भी हो गया है।

पेंशन बढ़ा दी गयी। पालनहार योजना में भी 0 से 6 वर्ष वालों के लिए 500 से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिये। 6 से 18 वर्ष वालों के लिए 01 हजार रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिये। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए भी पहले 3 रुपये की सब्सिडी बढ़ायी थी। उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा।

आज ओलावृष्टि से फसलें नष्ट हो गयीं। पूरे उदयपुर सम्भाग में किसान निराश हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपदा का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिसमें किसानों को 10 से 15 हजार रुपये मासिक मिलें, क्योंकि अन्नदाता की फसलें कभी ओलावृष्टि, कभी अनावृष्टि और कभी अतिवृष्टि से नष्ट हो जाती हैं और वह निराश होकर घर बैठ जाता है। उसके परिवार के पालन-पोषण की भी व्यवस्था नहीं रहती है। अत: मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि किसानों को 10 से 15 हजार रुपये मासिक दिये जाएं ताकि उनके परिवारों का भरण-पोषण हो सके।

माननीय सभापति महोदय, टी.एस.पी. क्षेत्र में दो से ढाई हजार

(श्री रामलाल मीणा)

कार्मिक ऐसे हैं, तत्कालीन शिक्षा मंत्री और हमारे प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा जी ने घोषणा की थी कि नॉन-टी एस पी के जो कार्मिक टी एस पी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें टी एस पी से नॉन-टी एस पी क्षेत्र में करके वहां के स्थानीय लोगों की नौकरी लगायी जाएगी। सभी पार्टियों के लोग चाहते हैं कि वहां टी एस पी के लोग नॉन-टी एस पी के क्षेत्र में चले जाएं। फाइल प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी इस पर मुहर लगा दी जाए।

आर ए एस और आर जे एस में हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहां शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर है। 12 परसेंट का जो आरक्षण मिल रहा है, उसमें जितनी हमारी जनसंख्या है, हमें एम बी बी एस में अलग से दे दिया, इंजीनियरिंग में अलग से दे दिया, इसी प्रकार आर ए एस और आर जे एस में हमें अलग से मिल जाए, ताकि हमारे बच्चों का आर ए एस, आर जे एस बनने का सपना साकार हो सके। जनसंख्या के अनुपात में हमें आरक्षण मिल जाए। ओ बी सी वर्ग को टी एस पी क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिल रहा है, जिससे ओ बी सी वर्ग नाराज है, इसलिए ओ बी सी वर्ग के लोगों को भी वहां आरक्षण दिया जाए।

कोविड सहायक को पुन: बहाल करने की मांग करता हूं। नर्सिंग भर्ती, 2013 को भी पूरी करने की मांग करता हूं। प्रतापगढ़ में कई सारी मांगें मैंने कर रखी हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी से पूरी आशा है कि इस बजट में प्रतापगढ़ क्षेत्र का सम्पूर्ण तरीके से विकास होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। यह राज्यपाल का अभिभाषण इस सरकार का लास्ट अभिभाषण है। सरकार ने काफी घोषणाएं, काफी चर्चाएं, काफी बातें इन चार सालों में कीं।

कोरोना भी आया। दो साल तक यह सरकार कोरोना में रही। एक और कोई 'कोरोना' सरकार में आ गया। क्या पता कौन-सा कोरोना था, इस सरकार को बिलकुल आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, सब मंत्रियों को हिलाकर रख दिया। अभी राठौड़ साहब भी उस सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, महेश जी भाई साहब भी चर्चा कर रहे हैं, रघु शर्मा जी भी काफी चिन्तित हैं इस सरकार के प्रति कि यह नया कोरोना कौन-सा आया। ये भी गुजरात जाकर कोरोना लेकर आये। क्या पता किस प्रकार का कोरोना आया है।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

माननीय सभापति महोदय, मैं तो पेपर लीक के बारे में बात करना चाहता हूं, अगर सरकार ही पूरी लीक हो जाए तो पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से...

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): वह पेपर लीक तो गुजरात में हुआ। ठीक कह रहे हैं आप।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): साहब, आप भी गये, गहलोत साहब भी गये। गुजरात में आपकी क्या हालत हुई, देखें तो सही। आप प्रभारी थे। आपके ऊपर प्रभारी गहलोत साहब थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य...

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): साहब, इनका जवाब नहीं दूं? (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका समय निर्धारित है। इन्वाइट मत करें उन्हें। अपने समय में अपनी बात रखें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सर, गुजरात की बातें कर रहे हैं, गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, मोदी जी की बात कर रहे हैं। साहब, मोदी जी की तुलना में इन्हें सात जन्म लगेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें आप। इस वार्तालाप में आपकी कहने वाली बात रह जाएगी। अपने क्षेत्र की बात कर लीजिए तो आपका कुछ कंटेंट आ जाएगा। अपनी बात कहिये आप। इन्वाइट मत करें उन्हें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, इस पेपर लीक के बारे में बात करना चाहता हूं। हमने विधान सभा में इस मैटर को काफी उठाया और आज हमारे किरोड़ी लाल जी भी इस बात को उठाकर धरने पर बैठे हैं। पूरे राजस्थान के युवा काफी दु:खी हैं, सरकार भी अपने आप में दु:खी है, इनके एम एल ए भी दु:खी हैं, मंत्री भी दु:खी हैं, पर सी एम इनकी सुनने वाले नहीं हैं, इसलिए दु:ख कहें तो कहें किसे। इस प्रकार ये भी जान रहे हैं, पर आने वाला युवा जिस प्रकार दु:खी है, माननीय सभापति महोदय, आपके मन में भी कितना दु:ख होगा, आप सीकर से विराजते हैं, शिक्षा का हब है सीकर। जिस प्रकार का नुकसान युवाओं को हुआ है। युवा यह देख रहे हैं, अभी सरकार सुने तो ठीक, नहीं तो यह दिसम्बर जो आ रहा है, 1 दिसम्बर से 7 दिसम्बर के बीच में युवा इन्हें अच्छी तरह देख

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

लेंगे। सी बी आई को इसकी जांच दें जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो। कौन अधिकारी सम्मिलित है, कौन मंत्री सम्मिलित है, कौन विधायक सम्मिलित है, उसका पूरा मामला आ जाए, उसके बारे में सरकार बात करे, चर्चा करे। सभापति जी इतने सीनियर हैं, इस बात को जरूर रखेंगे, इस बात को जरूर करवाएंगे।

राजस्थान की कानून-व्यवस्था जिस प्रकार बिगड़ी है, इतनी चोरियां, इतनी डकैतियां, इतने एनकाउंटर, कोई दो दिन के लिए, दो घण्टे के लिए या दो मिनट के लिए भी घर छोड़ दे, चिकित्सा मंत्री जी, आप सुन रहे हैं न, आपके वहां दौसा में भी आपने देखा होगा, किस प्रकार की कानून-व्यवस्था पूरे प्रदेश में तहस-नहस हुई है। थानों में चोरियां, डिप्टी आफिस में चोरियां, एस पी आफिस में चोरियां। हमारे साथी एम एल ए साहब की गाड़ी भी चोरी हो गयी। उन्हें धमकी भी देकर गये। इस प्रकार की कानून-व्यवस्था इस प्रदेश में बिगड़ी है, इसे भी आप दिखवाएं।

भ्रष्टाचार की तो सभी हदें पार हो गयी हैं। गहलोत साहब ने कोई अच्छा काम किया या नहीं किया, पर सी एम साहब को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जिस प्रकार से राजस्थान में ट्रांसफर पर रोक नहीं लगायी, यह बहुत अच्छा हुआ। बहुत से मंत्रियों के काम अच्छे हो गये। बहुत से अधिकारियों के काम इतने अच्छे हुए, जिसकी कोई हद नहीं। इसे रेगुलर रखना चाहिए दिसम्बर तक। मैं मेरे वहां की बात करता हूं। मेरे वहां यू आई टी है। यू आई टी में वहां इतना भ्रष्टाचार है कि जितने भी रिटायर्ड अधिकारी हैं, 8-8, 10-10 साल के रिटायर्ड अधिकारी वहां बैठे हुए हैं। यू डी एच मंत्री जी बैठे हैं, रिटायर्ड अधिकारी लगे हुए हैं और पूरी यू आई टी में कमिश्नर के अलावा सभी अधिकारी रिटायर्ड लगे हुए हैं। वे रिटायर्ड अधिकारी इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि आप देखो, मेरे किले तक के पट्टे काट दिये हैं। अगर वहां विपक्ष जिन्दा नहीं हो तो किला भी बिक जाए, इस प्रकार की पोजिशन वहां है। वहां पर हमारी धार्मिक जमीनें चाहे लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर की हों या दूसरी जमीनें हों, वे सारी जमीनें आज की तारीख में बिक चुकी हैं। वहां के जन-प्रतिनिधियों ने, वहां के पूर्व एम एल ए ने इस प्रकार की जमीनें वहां बेची हैं इसलिए यू डी एच मंत्री जी, आप उसकी भी जांच करवाएं। वहां रिटायर्ड अधिकारी, कर्मचारी लगेगा तो उसको करना क्या है भले ही वह घर पर चला जाए, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर हो रखी है तो उस बारे में आप सोचें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

बिजली के बारे में मैं आपसे चर्चा करूं तो पहले वसुन्धरा जी की सरकार में हम सब एम एल ए थे, गुलाब जी भाईसाहब मंत्री थे तब उन्होंने बिल माफ किये, पर बिल आपने वापस चालू कर दिये। फिर चुनावी कंडीशन देखकर बिल वापस माफ कर दिये तो कौनसा आपने नया काम कर दिया? आपने कहा कि 8 घंटे बिजली देंगे, पर 8 घंटे बिजली कहां आ रही है? दो-दो, तीन-तीन घंटे बिजली आ रही है। आदमी भोजन करे, उस समय बिजली जा रही है। आज बिजली की व्यवस्था इतनी खराब है कि 15-15, 20-20 दिन, एक-एक महीने तक वहां से ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं। 2013-14 की जो फाइलें जमा हैं, उनके बिजली कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। आपने कहा कि हम इतने बिजली कनेक्शन दे देंगे पर एक भी बिजली कनेक्शन नहीं हो पाया। जिस प्रकार की वी सी आर भरी जा रही हैं, जिस प्रकार की फर्जी वी सी आर भरी जा रही हैं, जिस प्रकार कांग्रेस-बी जे पी कहकर वी सी आर भरी जा रही हैं उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। हम लोगों की भी सरकार थी, सरकारें होती हैं पर इस प्रकार कांग्रेस-बी जे पी सोचकर वी सी आर नहीं भरी जाती हैं। अभी जो वी सी आर भरी जा रही हैं वे वी सी आर एक-एक, दो-दो, तीन-तीन लाख रुपयों की भरी जा रही हैं। किसान वर्ग अपनी जमीन बेचकर, अपनी जायदाद बेचकर, अपनी रकम बेचकर इस प्रकार की वी सी आर भर रहे हैं। मंत्री महोदय, इसको आप देखो। अब कौन मुखिया है, कौन क्या है पर आने वाले दिनों में इसकी सज़ा आप सब लोगों को भुगतनी पड़ेगी और पहले तो आप 20 आये, पर अब मुझे नहीं लगता कि 20 भी आयेंगे और टेम्पो जैसी स्थिति आपकी होगी इसलिए इस बिजली की व्यवस्था अभी भी सुधार दो तो अच्छा होगा।

संविदाकर्मियों की आप लोगों ने भर्ती की कि हम संविदाकर्मी ले रहे हैं, संविदाकर्मियों को रेगुलर कर रहे हैं पर आज संविदाकर्मी रोड पर हैं, वे धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए उनकी व्यवस्था भी आप देख लें और उनको भी आप रेगुलराइज करें, उनके बारे में सोचें। एक कल्ला जी की कमेटी बनाई, पर उस कमेटी का न अता है, न पता है कि उसने क्या किया, इसके बारे में गुलाब जी भाई साहब बात करेंगे।

शिक्षा विभाग में आपने स्कूलें तो खोल दी हैं पर न कमरे हैं, न टीचर हैं, कोई चीज नहीं है। इंग्लिश स्कूल खोल दिये, पर वे पहले वाले बच्चे कहां जाएंगे? आपने गर्ल्स स्कूल में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दिये, जिससे वे

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

गर्ल्स स्कूल बन्द हो गए। मेरे वहां बस्सी और सावा दो स्कूलें हैं जहां आज की तारीख में वहां की बच्चियां वापस बाय्ज स्कूल में भर्ती हो गईं। बस्सी और सावा मेरे बड़े कस्बे हैं जहां कम से कम 700-800-1000 बच्चे हैं। गर्ल्स स्कूल में मां-बाप सोचते हैं कि मेरी बच्ची सुरक्षित स्कूल में है, पर आज वह सुरक्षित नहीं है इसलिए इस शिक्षा विभाग के बारे में सोचें, टीचर्स के बारे में सोचें, उच्च शिक्षा के बारे में सोचें, क्योंकि पूरा शिक्षा विभाग तहस-नहस हो गया। जो ट्रांसफर किये हैं वे इस प्रकार के ट्रांसफर आपने कर दिये कि कौन कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, एक-एक आदमी के दो-दो ट्रांसफर हो गये। इस बारे में आप सोचें। मंत्री महोदय यहां विराज रहे हैं, शिक्षा विभाग के बारे में वे सोचेंगे। आप ब्राहमण हैं, उच्च कुल के हैं और इस बारे में निष्पक्ष रूप से सोचेंगे कि पूरे 200 विधायक मेरे हैं और मैं ऐसे नहीं सोचूं कि यह इसका है, वह उसका है। इस प्रकार से नहीं सोचें क्योंकि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की लम्बे टाइम 25-30 साल तक रहेगी तब आप भी कभी फोन करेंगे तो कहेंगे कि चन्द्रभान जी मेरा काम करवा देना; गुलाब जी भाई साहब, मेरा काम करवा देना; राठौड़ साहब, मेरा काम करवा देना, पर हम कहेंगे कि कल्ला जी, उस दिन हमारी एक नहीं सुनी तो अब 5-6 महीने में आपकी क्या सुनें। इसलिए आप ऐसे मत सोचो और थोड़ा निष्पक्ष रूप से काम करो।

इसके अलावा जो नया कोरोना आया है इससे भी पूरा राजस्थान तहस-नहस हुआ है, पूरा खराबा हुआ है। हकीकत में यह कोरोना का नया वायरस तो इतना खराब आया कि आप सोच भी नहीं सकते हो, सभापति महोदय। अन्दर ही अन्दर कोरोना इतना नुकसान करेगा कि आपकी सारी जड़ें अन्दर से साफ हो गईं। जो नया वाला 'निकम्मा' कोरोना आया, राठौड़ साहब, आप सोच नहीं सकते कि वह इतना खराब आया, यह मैं आपको हकीकत कह रहा हूं और बहुत बुरा कोरोना है जिसके बारे में आप सोच लें।

आपने बेरोजगारी भत्ते के बारे में बात की कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। उस समय चुनाव थे तो आप लोगों ने कहा कि आओ, अच्छा हो रहा है और आपने फार्म भरवाये, सब कुछ किया कि 3,500-3,500 रुपये दे देंगे और वाहवाही लूट ली पर आज वह बेरोजगार रो रहा है। आज उसके मां-बाप रो रहे हैं कि उस बच्चे से उस समय इस प्रकार लुभावनी बातें कर लीं कि यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, 3,500 रुपये में हमारा कर्जा चुक जाएगा।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सर, मेरे दस मिनट नहीं हुए, एक बार आप मिनट चैक कर लें। मैं टाइम देख रहा हूं। सभापति महोदय, रामलाल जी के फूफाजी हैं तो मुझको कहीं न कहीं माफ जरूर करेंगे, एक बार वह देख लें।

किसानों की कर्जमाफी का मामला है पर कर्जमाफी हुई नहीं। कर्जमाफी में आपने कहा कि हम सम्पूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। आपने छोटा-मोटा सहकारी समितियों में कर दिया, हो सकता है आपने भूमि विकास बैंक में कर दिया होगा पर नाममात्र का किया। जो पहले वसुन्धरा जी की सरकार में हुआ था, ठीक है छोटा-मोटा पैसा आपको देना पड़ेगा पर एडजस्टमेंट में आप समझ गये, इसलिए ऐसा मत करो और उस कर्जे को भी माफ कर दो। अभी भी आपके पास समय है, हो सकता है 10 तारीख को बजट है। (व्यवधान) नहीं हो रहा है, आप मत करो, साहब।

धार्मिक जगहों को आप लोगों ने तहस-नहस कर दिया। मंत्री महोदय, सभापति महोदय, इन धार्मिक जगहों को बचा लो। ईश्वर है, भगवान है, उस भगवान की जगह को बचा लोगे तो कहीं न कहीं भगवान आपके साथ जरूर रहेगा। शकुन्तला जी मंत्री हैं, पर जब विपक्ष में बैठते थे, तब उस टाइम तो कहते थे कि मैं शेरनी हूं, वह हूं पर अब पता नहीं क्यों बिलकुल खतम हो गये हैं। उनको क्या पता था कि ऐसी सरकार में मैं आ जाऊंगी और मंत्री बन जाऊंगी। एक भी इनकी नहीं चल पाई और बहुत बुरी कंडीशन में हैं। +++

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): मेरी चल रही है इसलिए जलन हो रही है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: जो भी व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है उन्हें विलोपित कर दो। विराजिये, आप। जो भी व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई हैं उन्हें विलोपित कर दो।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत से विकास, डवलपमेंट के काम भी बाकी हैं, उनको कर दें। 5-7 महीने का समय है और भगवान ने आप लोगों को मौका दिया है इसलिए अगर आप कहीं विकास और डवलपमेंट कर लेंगे तो ईश्वर भी आप लोगों का साथ देगा। क्या पता यहां देगा या नहीं देगा, हो सकता है आपको नगरपालिका चेयरमैन बनने में साथ दे, नगरपालिका का सभापति बनने में साथ दे, जिला प्रमुख बनने में आपका साथ दे।

श्री सभापति: विराजिये। श्री सुरेश टाक। अंकित नहीं होगा। विराजिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है, विराजिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। बोलने का वक्त होता है तब तो बोलते नहीं।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

मैं अपनी बात राज्य के लोकप्रिय मुख्य मंत्री को अनन्त धन्यवाद के साथ शुरू करूंगा, जिनकी सोच में पूरा राजस्थान रचा-बसा है। एक बार फिर यह अभिभाषण सरकार की क्रियाशीलता एवं जन-जन के प्रति अपनी जवाबदेही को दर्शाता है। विगत चार वर्षों में राज्य में विकास के नित नये आयाम स्थापित हुए, कई नवाचार हुए, जिसमें अन्तिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति लाभान्वित हुआ। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बाद भी राजस्थान के विकास की रफ्तार कभी नहीं रुकी। यह राज्य के मुखिया का एक सफलतम कार्य है, जिसके प्रति मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि दो साल के उस कठिनतम काल के बाद भी जिसमें राज्य की रेवेन्यू कम हुई, राज्य में आय नहीं हुई और उसके बाद भी निरन्तर हर बजट एक ऐतिहासिक बजट बना और इस बार भी जैसे पूरा राजस्थान कह रहा है कि यह आखिरी बजट है और यह आखिरी बजट राजस्थान के लिए एक बेमिसाल बजट होगा। यहां की जनता को बहुत सारी नई-नई, बड़ी-बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। मैं भी उन भाग्यशाली लोगों में शामिल हूं जो पहली बार विधान सभा में चुनाव जीतकर आये और सरकार का हिस्सा बनकर अपने विधान सभा क्षेत्र के आमजन की उन अनछुई समस्याओं का निराकरण कर लोगों का दिल जीता। यह सब माननीय मुख्य मंत्री जी की असीम अनुकम्पा थी जिसकी वजह से हमारी हर मांग को, जो हमने जनता के हित की बतायी, उसका तुरन्त समाधान हुआ। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपके कुशल नेतृत्व व सबको साथ लेकर चलने की सोच से हमारा सम्मान हमारे विधान सभा क्षेत्र में बढ़ा और हमारा विश्वास भी लोगों के बीच में बढ़ा। निश्चित रूप

(श्री सुरेश टाक)

से मैं यह बात कह सकता हूं कि जन भावनाओं को अभिव्यक्ति देने वाला राजस्थान का यह उच्च सदन अपने गठन से लेकर अब तक राज्य के विकास के लिए अपना प्रभावी और गतिशील नेतृत्व देता आया है। आज राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की सोच हमारी सरकार ने जो संजोयी थी उसे साकार करते हुए देखना हम सबके लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।

विगत चार वर्षों में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किये हैं। एक मिसाल कायम की है और विकास का यह क्रम अभी भी निरन्तर जारी है। सभी वक्ताओं ने इस बात को बोला है और बोलना भी चाहिए।

(समय: 16.00 बजे)

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अपने आप में एक अनुकरणीय योजना है, एक अनूठी योजना है। कोरोना काल के बाद जो तकलीफें लोगों को आई थीं, पोस्ट कोविड के बाद जो बीमारियां आई थीं, उन बीमारियों से लोगों को जीवनदान मिला। कोरोना काल के बाद चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 5 लाख रुपये का नि:शुल्क इलाज था, अगर यह उपलब्ध नहीं होता तो शायद कोरोना काल में मौतें और बढ़ सकती थीं, परन्तु इस योजना की वजह से लोगों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिला। उसके बाद एक कदम और आगे बढ़ते हुए इसको 10 लाख रुपये किया और 10 लाख के बाद 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा इसमें जोड़ा गया, जो एक गरीब आदमी के जीवन को चलाने के लिए बहुत बड़ी राशि है। यह कहीं न कहीं उसके जीवन को, उसके बच्चों के जीवन को एक नया जीवनदान देने के लिए बहुत-बड़ा काम है। इसकी आमजन में बहुत-बहुत प्रशंसा है। यह योजना पूरे राजस्थान में मॉडल बनी है। इसकी वजह से कोरोना जैसी महामारी के बाद यह राजस्थान खड़ा हो गया। आज हमें इस बात की थोड़ी बहुत भी चिन्ता नहीं है कि अब आने वाले समय में अगर कोई घटना या कोई ऐसा काल आया तो उससे किस तरह निपटेंगे।

अभी जब कोरोना की तीसरी, चौथी लहर की बात चल रही थी, तब भी राजस्थान में ऐसा कोई भी केस नहीं आया जिसकी वजह से हमें वापस पीछे मुड़कर देखने की जरूरत पड़े क्योंकि हमने इतने संसाधन डवलप कर लिये थे, लोगों को इतना मजबूत बना लिया था कि शायद चौथी लहर में, पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में ऐसा कुछ नहीं हो पाया जिससे हमें सोचने की जरूरत पड़े।

(श्री सुरेश टाक)

इसी के साथ-साथ मुफ्त दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना, ये सभी ऐसे काम हैं, जिनसे आम गरीब आदमी स्वास्थ्य के प्रति चिन्ता छोड़ चुका है। यह निश्चित रूप से सरकार का एक बहुत-बड़ा पार्ट है जिसमें उसने उस गरीब और वंचित परिवार, जो अन्तिम छोर पर बैठा हुआ पीड़ित और शोषित आदमी है, जो अपनी रोजी-रोटी कमाने की चिन्ता करता है, अपने इलाज की व्यवस्था कहां से करेगा, उसके लिए सरकार खड़ी है। यह एक बहुत बड़ा काम है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

आज 88 प्रतिशत लोगों ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। 31 लाख 58 हजार लोगों का इस योजना में इलाज हुआ है। राज्य के किसी भी सम्बद्ध अस्पताल में दुर्घटना होने पर 72 घन्टे तक नि:शुल्क उपचार, यह एक बहुत बड़ा काम है। पहले लोग दुर्घटना होने पर अस्पताल नहीं ले जाते थे। अब अस्पताल ले जाने के लिए कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं है और अस्पताल ले जाने के बाद 72 घन्टे तक उसका नि:शुल्क उपचार होगा। यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी और बहुत बड़ी योजना है जिसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

प्रत्येक जिले में मेडिकल कालेज खोलना और वहां भवन निर्माण हो जाना, यह एक बेमिसाल काम है। यह केवल घोषणा ही नहीं रही है, करीब-करीब हर जिले में कालेज खुले भी हैं, कालेज बन भी गये हैं और कालेज चालू भी हो गये हैं।

पशु चिकित्सा के क्षेत्र में 275 नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोले गये हैं। करीब-करीब हर पंचायत में पशु चिकित्सा केन्द्र खुल गये हैं। जिससे किसानों को अपने पशुओं की बीमारी में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़े।

दिव्यांग छात्र-छात्राओं की स्कूटियों की संख्या 2 हजार से बढ़ाकर 5 हजार करना। ऐसे लोग जिन पर ईश्वर की कृपा कम रही, जो कहीं न कहीं अपने एक हाथ से, एक पैर से, एक आंख से, ऐसे में सरकार उनके साथ खड़ी हुई। स्कूटी देने से वे बच्चे और आगे बढ़ पायेंगे, अपना जीविकोपार्जन कर पायेंगे। सरकार ने यह सुविधा देकर उन सब दिव्यांगों को एक बहुत बड़ी ताकत दी है।

'प्रशासन गांवों के संग अभियान' 2021 में चलाया गया था। एक

(श्री सुरेश टाक)

बहुत बड़ा काम था, लेकिन मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगा कि इसकी एक बार पुन: समीक्षा की जानी चाहिए। केवल एक बार के अभियान से लोगों को उतना फायदा नहीं हुआ, जिस सोच के साथ सरकार ने इस अभियान को चालू किया था, शायद वह अभी अधूरा है क्योंकि इसके बाद जो फॉलो-अप कैम्प लगाये गये थे तब कोरोना आ गया था। फॉलो-अप केन्द्र में लोगों ने रुचि नहीं दिखाई और प्रशासनिक दृष्टि से भी ये कैम्प इतनी मजबूती से नहीं लग पाये। मैं यह चाहूंगा कि अभी 6-7 महीने का वक्त है, इस वक्त में एक बार फिर 'प्रशासन गांवों के संग अभियान' में कैम्प लगाने चाहिए। जितनी शिकायतें रजिस्टर्ड हुई हैं, कम से कम उन शिकायतों का तो निस्तारण हो जाए ताकि सरकार का मकसद पूरा हो। जिस उद्देश्य के साथ कैम्प लगाये गये थे कि आम जन-जीवन, जो गांवों में रहता है, जिनके बहुत सारे झगड़े हैं, चाहे बंटवारे का हो, चाहे आबादी क्षेत्र के विस्तार का हो, चाहे और कोई छोटे-मोटे काम हों, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अभी भी अधूरे पड़े हैं। उन कामों को पूरा करने के लिए मेरा एक सुझाव है कि इन कैम्पों को एक बार फिर लागू किया जाए। चाहे एक दिन की चौपाल लगाकर किया जाए, पर कमप्लीट बी एल ओ के साथ हर पंचायत में एक दिन का कैम्प लगाया जाए ताकि लोगों को वापस राहत मिल सके और सरकार का उद्देश्य पूरा हो सके।

इसी तरह 'प्रशासन शहरों के संग अभियान' में स्थितियां थोड़ी उलट हैं। पट्टे किस तरह मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक कॉकस-सा बना हुआ है। कहां-कहां क्या हो रहा है, एक गैंग बन गई है, पार्षद की, चेयरमैन की, कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से लोगों को बिना पैसे के पट्टा नहीं मिल रहा है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि सरकार ने बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत बड़ा काम किया था कि लोगों को पट्टे मिलें, घर-घर जाकर, वार्ड-वार्ड जाकर कैम्प लगें, पर उन कैम्पों में प्रभावी रूप से काम नहीं हो रहा है। उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। आप किसी भी तरह से जब तक कैम्पों में विधायकों को इन्वाल्व नहीं करेंगे, तब तक सरकार की सोच वहां तक नहीं पहुंच पायेगी। अधिकारी अपने तरीके से काम करता है, सभापति अपने तरीके से काम करता है, चेयरमैन अपने तरीके से काम करता है। फिर पार्षद और ये सब लोग मिलकर फाइलों को अपने घर ले जाते हैं, कई पटवारी अपने घर ले जाते हैं, कई ए टी पी अपने घर फाइलों को ले जा रहे हैं और ले जाने के बाद फाइल तभी घर से वापस मिलती है, जब तक उसका

(श्री सुरेश टाक)

कोई न कोई सेवा कार्य पूरा नहीं हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि इनकी मॉनिटरिंग की जाए और ऐसे लोगों को वहां से हटाया जाए जिनके बारे में हमने लिखकर भी दिया है।

शहरों में जो नरेगा योजना चलाई गई है, मैं उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। कोरोना काल के बाद रोजगार की दृष्टि से ऐसे लोग जो वंचित रह गये थे, जिनकी रोजी-रोटी पर सवाल खड़ा हो गया था, उनके लिए कहीं न कहीं 100 दिन का रोजगार जीवन देने का काम करेगा। अपने भविष्य के संकट दूर करने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। एक बड़ी सोच के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई है। यह शहरों में रोजगार का एक नया अवसर प्रदान कर रही है। लोग आगे बढ़कर इसमें अपनी रुचि ले रहे हैं और खूब लोगों को इसमें रोजगार भी मिला है। इसके माध्यम से दूसरे काम, जो नगर परिषद्, नगरपालिकाएं नहीं कर पा रही थीं, वे काम भी पूरे हो रहे हैं। इससे दोहरा काम हो रहा है। एक तो रोजगार मिल रहा है, दूसरा वे काम जो बहुत दिनों से पैंडिंग थे, उन कामों को भी पूरा किया जा रहा है।

ई आर सी पी एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह ईस्टर्न राजस्थान के लिए जीवनदायिनी है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाये, ताकि जो 13 जिले हैं, अजमेर भी उसमें शामिल है, इन 13 जिलों में पेयजल को लेकर किसी तरह की समस्या नहीं हो। बीसलपुर अकेले अजमेर के लिए बना था, लेकिन आज पता नहीं कितने जिलों में बीसलपुर का पानी चला गया है। हमारी जे जे एम योजना उसकी वजह से अधूरी पड़ी है। उसकी एफ.एस. जारी हो गई है, उसकी टी.एस. जारी हो गई है पर उनका अभी तक वर्क आर्डर नहीं दिया गया है। यह कहकर रोका जा रहा है कि पीने का पानी उपलब्ध नहीं है इसलिए अभी जे जे एम लागू नहीं होगी। इतनी बड़ी वृहद् योजना, जिसमें घर-घर पेयजल पहुंचाने का काम था, जिसके लिए काम पूरा भी कर लिया गया, टी.एस. हो गई, एफ.एस. हो गई थी, टेंडर हो गये थे, केवल वर्क आर्डर जारी करना था, लेकिन पानी की कमी बताते हुए इस काम को रोक दिया गया। मुझे नहीं लगता है कि यह काम ठीक है। लोगों को उम्मीद है, इन्तजार है 2024 तक पीने का पानी उपलब्ध हो, इस पर एक बार पुनर्विचार किया जाए। हम ई आर सी पी पर जितना जल्दी काम स्टार्ट कर सकें, ई आर सी पी का काम शुरू करते हुए नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा को लिंक करने का जो काम था, इस काम को भी सरकार जल्दी से

(श्री सुरेश टाक)

जल्दी कराये ताकि बीसलपुर में पीने के पानी की कमी नहीं रहे। फिर ये सारे जिले जयपुर, अजमेर, दौसा और भीलवाड़ा, ये सब इसमें जुड़ जायेंगे और पीने के पानी की एक बड़ी समस्या का समाधान शायद बीसलपुर बांध से हो जायेगा यदि इस लिंक का काम समयबद्ध तरीके से पूरा हो गया। वैसे सरकार ने इसके वर्क आर्डर भी जारी कर दिये हैं, इसकी डी पी आर के लिए भी आदेश कर दिये हैं, इसकी टीम भी बन गई है, इसके लिए कर्मचारी भी लगा दिये गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने ईआरसीपी पर और नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा के लिए अपना बड़ा योगदान देकर वहां पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी, शायद पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए काम बाकी है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसी कार्यकाल में जल्दी से जल्दी इस लिंक परियोजना का काम पूरा हो।

सड़क के मामले में चार वर्षों में बहुत बेमिसाल काम हुए हैं मैं इस बात का पूरी तरह से गवाह हूं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की जहां तक बात करूं तो इतनी बड़ी सौगातें मुझे मिली हैं, मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इतनी बड़ी सड़कें दी गई हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए। मुझे दो स्टेट हाई-वे मिले, जिसका 60 सालों से लोगों को इन्तजार था, वह इन्तजार खतम हुआ। मेरा एक 67 किलोमीटर का किशनगढ़ से मालपुरा तक का रोड है, जो करीब-करीब कम्प्लीट होने को तैयार है। अरांई से सरवाड़ मार्च में स्टार्ट हो जायेगा। वह 44 किलोमीटर का है, 450 करोड़ रुपये की यह योजना है और इस योजना से पूरा अजमेर जिला लाभान्वित होगा। कनेक्टिविटी बढ़ेगी और इससे लोगों को संसाधन, हमारे बच्चों की शिक्षा की कनेक्टिविटी, आने-जाने के माध्यम बढ़ेंगे और रोजगार बढ़ेगा, हमारे उद्योग-धन्धों को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा।

पूरे राजस्थान में सड़कों के बेमिसाल काम हुए हैं। पहली बार शहरी क्षेत्रों में शहर के लोगों को भी सुविधा मिली है सड़कों की, इसके लिए सरकार ने बजट में घोषणा की। नगर परिषद्, नगरपालिका और नगर निगम क्षेत्रों में अलग-अलग सड़कें देकर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। पहली बार चार करोड़, पांच करोड़, दस करोड़ उसके बाद सात करोड़, छः करोड़ और दस करोड़ अलग-अलग निगम, परिषद् आदि के हिसाब से दी गई, जिससे शहरी क्षेत्र में बहुत ही गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनी हैं।

(श्री सुरेश टाक)

पी डब्ल्यू डी का काम अपना अलग काम है। नगर परिषदें जो सड़कें बनाती हैं उसके बनिस्बत पी डब्ल्यू डी की सड़क ज्यादा गुणवत्तापूर्ण होती है और ज्यादा अच्छे तरीके से बनती है तो सरकार ने यह बहुत बड़ा काम करके शहरी लोगों को भी अपने साथ जोड़ा है और उनको खाली स्वायत्तशासी संस्थाओं के भरोसे नहीं छोड़कर अपना पार्ट समझा और अपना पार्ट समझते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने करोड़ों रुपयों की सड़कें शहरों में देकर एक बेमिसाल काम किया है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे किसी भी प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहें, इसके लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलकर एक नया नवाचार और एक ऐसा नवाचार जिससे स्कूलों में एक बाढ़ सी आ गई है। अब एडमिशन के लिए सिफारिशें आ रही हैं, लाइन लगी पड़ी है क्योंकि बहुत लिमिटेड एडमिशन हो रहे हैं और लिमिटेड एडमिशन होने की वजह से गरीब बच्चे जो अपने आपको इनफीरियर फील करते थे बात करते हुए, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो अंग्रेजी में बात करते थे, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समझ भी नहीं पाते थे। अब सरकार ने यह सुविधा की है तो कहीं न कहीं उन बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और वो भी इस प्रतिस्पर्धा के युग में अपने आपको अग्रिम पंक्ति में खड़े होने का प्रयास करेंगे। ये स्कूलें माइल स्टोन साबित होंगी। यह बहुत बड़ा काम है।

माननीय चन्द्रभान जी ने अभी यह बात बोली थी, मैं सहमत हूं उस बात से कि स्कूलें खुली हैं लेकिन स्कूलों के साथ संसाधन भी बढ़ें, टीचर्स भी बढ़ें और टीचर ऐसे लगें जो वास्तव में अंग्रेजी पढ़ा सकें। कम से कम इस पर फोकस करें ताकि यह जो सोच सरकार की है इस सोच को पंख लगे और इसके सकारात्मक परिणाम आयें। यह जरूरी भी है कि वहां के बच्चों को पढ़ाने के लिए उच्चतम स्तर के शिक्षक वहां लग जाएं और पर्याप्त टीचर लगें ताकि ये जितनी स्कूलें खोली हैं इनका रिजल्ट बहुत ही सकारात्मक आये।

जहां तक भवन की बात है, मैं भी आग्रह करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि स्कूलों में भवनों की बहुत कमी है और इस कमी को देखते हुए आप एक बृहद् योजना बनायें, उस योजना में चाहे समसा हो, चाहे डी एम एफ टी का पैसा लगे, चाहे कहीं का पैसा लगे पर सबसे पहली प्राथमिकता स्कूलों में कमरे बनें, ताकि हमारे बच्चे खुले में नहीं पढ़ें, धूप में नहीं पढ़ें, बरसात में नहीं पढ़ें और उनको एक अच्छा वातावरण मिले स्कूल में जाते ही।

(श्री सुरेश टाक)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक रिक्वैस्ट और करना चाहूंगा आपके माध्यम से।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): जी, मैं मेरी बात को जल्दी समाप्त कर रहा हूं। मर्ज हुए जो प्राथमिक विद्यालय हैं जो पूर्व में मर्ज हुए थे आबादी कम थी। नामांकन कम था, नामांकन कम होने की वजह से स्कूल जो प्राथमिक स्कूल थे वो डीमर्ज हो गए। अब उन डीमर्ज स्कूलों में वहां पर आबादी बढ़ गई। वहां पर इतनी मांग बड़ी है। कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो स्कूल तो अति आवश्यक है एक बजरंग कालोनी है शहरी क्षेत्र का और एक डोहरिया स्कूल है आकोड़िया पंचायत का। मैं उन दोनों स्कूलों को खोलने की मांग करूंगा। वहां पर लोग बहुत बड़ा स्कूल का भवन देने को तैयार हैं, सब कुछ देने को तैयार हैं। बच्चे बहुत दूर स्कूल जाते हैं, वहां से तीन-तीन चार-चार किलोमीटर स्कूल नहीं हैं इसलिये जरूरी है कि ये स्कूलें वापस खुल जायें जो पहले डीमर्ज होकर बंद हो गई थीं।

उच्च शिक्षा में आपने कन्या महाविद्यालय खोलकर बहुत बड़ा काम किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक कन्या महाविद्यालय खुला है जिसका भवन निर्माण चालू हो गया है। हमने कालेज चालू कर दिये हैं। हमारी बच्चियों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और इसका निश्चित रूप से हमारी बच्चियों की शिक्षा पर बहुत बड़ा असर जायेगा और वो उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसर होंगी। हमारे पेरेंट्स जो को-एड में नहीं पढ़ा पा रहे थे बच्चियों को, कन्या महाविद्यालय खुलने से बच्चियों को कालेज जाने के लिए उनका रास्ता आसान हो जायेगा जिससे वो अपनी उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ेंगी और अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए उनको बहुत बड़ा रास्ता मिलेगा।

सरकार ने पटवारियों की नियुक्ति भी की है लेकिन पटवारी वापस ट्रेनिंग में चले गये हैं, जल्दी से उनकी नियुक्ति करा दें क्योंकि लोगों को असुविधा हो रही है। आज जो तकलीफ हुई है कल जो ओलावृष्टि हुई है इसकी गिरदावरी करने के लिए भी स्टाफ पूरा नहीं है इसलिये जल्दी से जल्दी उन पटवारियों की नियुक्ति हो जाये ताकि इस ओलावृष्टि का जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान के लिए जल्दी से जल्दी गिरदावरी होकर उन किसानों की भरपाई हो सके।

(श्री सुरेश टाक)

मैं राशन की दुकानों के बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार ने अभी बहुत सारी दुकानें खोली हैं, घोषणा की है सरकार ने, पर अजमेर जिले में केवल दो ही जगह अभी दुकानें आबंटित हुई हैं। किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र भी एक है तो मेरा आग्रह है आपके माध्यम से सरकार से कि जल्दी से जल्दी किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की भी जो नयी आबंटित दुकानें हैं, उनको खोलने के लिए किया जाये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मैं अन्त में, एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं यह चाहूंगा कि आगामी बजट में किशनगढ़ में एम सी एच, मदर चाइल्ड हैल्थ केयर विंग खुल जाये जिससे किशनगढ़ जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, वहां पहले उप जिला अस्पताल था और माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से वह जिला अस्पताल हो गया। अब मैं यह चाहूंगा माननीय चिकित्सा मंत्री जी यहां विराज रहे हैं इस बजट में हम किशनगढ़ के लोगों को एम सी एच की विंग जिसकी मैं पिछले दो सालों से मांग कर रहा हूं, इस बार मेरी इस मांग पर गौर फरमायेंगे और किशनगढ़ को एम सी एच विंग मिलेगी जिससे हम चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत परफेक्ट होंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): दो मिनट में खतम कर रहा हूं। सन्त नागरीदास पैनोरमा में जाने के लिए एक पुलिया बहुत टूटी हुई है। चारपांच केजुअल्टी हो चुकी है लोग मर चुके हैं, वहां पर कनेक्टिविटी नहीं है। वह पुलिया क्षतिग्रस्त है, उस पुलिया की डी पी आर बनकर आ चुकी है। मैंने बजट में दे दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि इस बजट में सन्त नागरीदास पैनोरमा की पुलिया की घोषणा करें। शहरी क्षेत्र में एकमात्र सड़क है जिससे पूरा शहर गुजरता है। इतना ट्रैफिक है कि बार-बार जाम लगते हैं जिसके लिए एक बाईपास का मैंने दिया है तो मेरी उम्मीद है कि इस सड़क की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी अभी बजट में करेंगे।

बोराड़ा में महाविद्यालय की कमी है, बहुत दूर क्षेत्र है मेरा। साठ किलोमीटर मेरे विधान सभा क्षेत्र से दूर है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री सुमित गोदारा।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): एक मिनट में खतम कर रहा हूं, एक मिनट में बस। बोराड़ा में महाविद्यालय खोला जाये। अरांई में हमारी सी एच सी का भवन जर्जर हो गया है एक नये भवन की स्वीकृति करायें। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, आपने मुझे दो पी एच सी दी हैं अभी एक खंडाच और एक अरांई। खंडाच में आर के मार्बल का गांव है, अशोक पाटनी जी का गांव है और वो शुरू से इस बात की स्वीकृति दे चुके हैं सरकार को भी पत्र लिख दिया है, आपको भी पत्र लिख दिया है। मेरे माध्यम से भी मैंने आपको दे दिया है। वो पूरा भवन अपनी जमीन पर बनाकर देने को तैयार हैं। आप यह स्वीकृति जारी करें तो कम से कम वहां एक पी एच सी का भवन बन जाये। ऐसे भामाशाह कम होते हैं जो आगे होकर भवन बनाने के लिए अपनी स्वीकृति जारी कर रहे हैं अपनी जमीन भी दे रहे हैं और भवन के लिए पैसा भी दे रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। प्लीज सहयोग करें। विराजिये। श्री सुमित गोदारा।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): इसी तरह ढसूक में भी एक नयी पी एच सी की स्वीकृति जारी करायें।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभार। राज्यपाल का अभिभाषण जब मैं अपने बीकानेर के कार्यालय में लेकर बैठा था तो बहुत से किसान साथी आये और देखा, युवा किसान पढ़े-लिखे हैं। बड़ी रुचि होती है उन्हें भी पढ़ने की तो पढ़ कर उनमें से कइयों ने कहा कि इस विषय को जरूर रखना जो मैं आपके सामने रख रहा हूं।

माननीय सभापति जी, पृष्ठ संख्या 22 और पैरा संख्या 28 'राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। राजस्थान ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व आयाम स्थापित किये हैं।' अभूतपूर्व आयाम, अब अभूतपूर्व आयाम कैसे स्थापित किये हैं, बिजली में, जैसे किसान भाई को बिजली चाहिये होती है तो सब वक्ताओं ने यह कहा, वही बात पूरा राजस्थान कह रहा है कि राजस्थान के गांवों में लाइट नहीं है और

(श्री सुमित गोदारा)

जब शाम को परिवार के साथ थका-हारा किसान आता है और वह खाना खाने बैठते हैं तो लाइट उस समय अवश्य जाती है। फोन करते हैं कांग्रेस के नेताओं को कि यह क्या कर रहे हो तो वे कहते हैं कि जब आप भी खाना खा रहे हो तो लाइट भी खाना खाने जाती है। इस तरह का मजाक करके किसानों के साथ भद्दा मजाक यह कांग्रेस की सरकार यहां कर रही है, जिसमें तो विडम्बना यह है कि जिस जिले से मैं आता हूं वहां पिछले सवा चार साल में दोनों ऊर्जा मंत्री हमारे बीकानेर जिले के हैं और जी एस एस मेरे लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में एक भी नहीं बना है। किसानों को लाइट नहीं मिल रही है। रोज किसान लड़ते हैं, रोज हमें यह कहते हैं कि क्या करें, तो मैं कहता हूं कि सवा चार साल हो गये, आठ-दस महीने दोरे-सोरे निकालो। यह पांच साल की सरकार है, यह नारा ही देती है समृद्ध किसान, खुशहाल किसान। कहीं समृद्ध हुए, कहीं खुशहाल हुए? कहीं खुशहाल नहीं है। लाइट नहीं आती है। वह बी जे पी के टाइम को याद करते हैं, बी जे पी के टाइम में लाइट मिलती थी पूरे वोल्टेज के साथ और अब लाइट मिलती नहीं है बिलकुल ही क्योंकि इन्होंने जी एस एस तो बनाये नहीं पर एक काम जरूर किया है माननीय सभापति जी, फीडर जरूर निकाल रहे हैं नये-नये, क्योंकि फीडर में जो घोटाला होता है बड़ा-बड़ा, वह आप और हम किसान नहीं समझ पाते। यह अधिकारी और नेता मिलकर फीडर के नाम पर बड़ा-बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यह भी एक जांच का विषय होना चाहिये कि फीडर इतने निकाले पर नये जी एस एस आपने क्यों नहीं बनाये?

पण्डित दीनदयाल योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पिछले कार्यकाल में ढाणी-ढाणी में लाइट गयी थी। किसान याद करता है उस समय को। अब सवा चार साल में ढाणियां भी नयी बनी, परिवार भी अलग हुए, वो लाइट के लिए दर-दर ठोकर खा रहा है पर उसे लाइट कहीं नहीं मिल रही है। इस राज में खुशहाल किसान नहीं है। माननीय सभापति महोदय, खुशहाल वह व्यापारी है जो इन्वर्टर का व्यापार करता है। वह बार-बार अगरबत्ती करता है कांग्रेस सरकार आये, क्योंकि कांग्रेस सरकार में लाइट रहती नहीं है और उसके इन्वर्टर बिकते हैं। वह राज़ी है। बाकी आम किसान से लेकर हर व्यक्ति इस सरकार से पीड़ित है और इंतजार कर रहा है कि 8 महीने बाद जब प्रदेश में बी जे पी की सरकार आयेगी और जिस तरह प्रधान

(श्री सुमित गोदारा)

मंत्री मोदी जी ने प्रत्येक क्षेत्र में काम किया है, उसी तरह लाइट में जो आर डी एस स्कीम लेकर आ रहे हैं जिससे गांवों का फीडर अलग होगा, किसानों का फीडर अलग होगा, दिन में किसान को लाइट मिलेगी, वह बी जे पी की सरकार आयेगी और केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना लागू होगी, तब राजस्थान का किसान खुशहाल होगा।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दूसरा बिन्दु आपने लिखा पृष्ठ संख्या 13 पर वही 'समृद्ध किसान, खुशहाल किसान'। मैं अपने क्षेत्र लूणकरणसर में गया, हमारे यहां भी सरसों का रिकार्ड तोड़ उत्पादन हो रहा है। मेरे क्षेत्र का भी मूंगफली के क्षेत्र में भारत में नाम है। वहां पाले से सरसों का बहुत नुकसान हुआ है। हमारा क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र होने की वजह से बहुत ठंडा रहता है। वहां जब हम गये, जिस दिन मैं दौरे पर था, उस दिन तो पटवारी ने रिपोर्ट दी, बाकी सब पटवारियों का पीछे से फोन आता है कि ऊपर बात कर लो, ऊपर के अधिकारियों का निर्देश है 20 से 25 परसेंट खराबा दिखाना है, आप ज्यादा खराबा मत दिखा देना। मैंने कहा कि यह तो सरसों का सारा नुकसान हुआ है। कहते हैं कि हमें अधिकारियों से, सरकार से यही आदेश है कि हमें किसान को फायदा नहीं देना है, 20 से 25 परसेंट से ज्यादा खराबा मत दिखाना। यह खुशहाल किसान है। अधिकारियों को यह निर्देश है कि किसान परेशान होता रहे लेकिन अपने को किसान का कहीं भला नहीं करना है। बात समृद्ध किसान की करते हैं पर यूरिया डी ए पी के क्या हाल थे? मुझे याद है, मैं एक उप चुनाव में ड्यूटी में था तो हमारे क्षेत्र का सारा यूरिया डी ए पी वहां आ रहा था। राजस्थान में कोई बड़े नेता यात्रा निकाल रहे थे तो वहां पर यूरिया डी ए पी भेजा गया। केन्द्र सरकार से यूरिया डी ए पी की कहीं कमी नहीं थी, राजस्थान सरकार की पहली गलती तो यह रही कि इन्होंने यूरिया डी ए पी की मांग कम रखी जबकि केन्द्र सरकार ने दोनों में 15-20 परसेंट बढ़ोतरी करके घोषणा की थी। मैंने लाइट के बारे में बात की कि मोदी जी ही इस सब संकट के मोचक हैं, वही इलाज करते हैं। ऐसे ही राजस्थान के किसान, मेरे क्षेत्र के किसान गुणगान करते हैं कि आजादी के बाद पहली बार नरमा 9-10 हजार में बेचा। सरसों के भाव कभी साढ़े तीन-चार हजार रहते थे, 6-7 हजार में बेचा और मूंगफली इस बार रिकार्ड साढ़े सात हजार में बेची। उन्होंने कहा कि जिंदगी में किसान ने ऐसे अच्छे दिन नहीं देखे। मोदी जी के राज में किसानों को जो भाव मिल रहे हैं, उसके लिये

(श्री सुमित गोदारा)

खुशहाल किसान है। वह धन्यवाद देता है प्रधान मंत्री मोदी जी को, जिनके कारण यह भाव मिल रहे हैं।

पृष्ठ संख्या 33 पैरा नंबर 161 में लिखा, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के विषय पर तो जितना कहा जाये उतना ही कम है क्योंकि यह युवाओं के खिलाफ सरकार है। जब राजस्थान का मुखिया कहता है कि रगड़ाई जरूरी है तो लोगों को वह दिन याद आते हैं जब 1998-2003 में यही मुखिया राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, तब 1998-2003 में किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी गई थी। मुझे वह दिन याद है जब मैं घर में परिवार के भाइयों से बात करता था कि पढ़ क्यों नहीं रहे तो कहते थे कि अशोक गहलोत की सरकार है, नौकरियां तो निकलती नहीं तो पढ़कर क्या करेंगे। वही दिन वापस आ रहे हैं। अब नौकरी तो निकाल रहे हैं लेकिन पेपर लीक करके ऐसे ही कर रहे हैं जिससे युवा नौकरी नहीं लग जाये। उनका तो यही है कि नालायक, निकम्मा रहे और उसकी रगड़ाई होती रहे और हम अपना शासन करते रहें। हमारी सरकार से यह मांग है कि सी बी आई से जांच हो। सरकार क्यों सी बी आई से डरती है? जब छोटे-छोटे प्रसंगों में सरकार सी बी आई की जांच के लिये आगे रहती है तो इसमें सी बी आई की जांच से सरकार के मुख्य मंत्री और सरकार के मंत्री क्यों डर रहे हैं? पेपर चोरी की जांच होनी चाहिये।

शिक्षा मंत्री हमारे बीकानेर जिले के हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में पैरा संख्या 186 व 187 में विद्यालयों का क्रमोन्नयन, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, इस विषय को बड़ी गहनता से रखा है। माननीय सभापति जी, विद्यालयों का क्रमोन्नयन तो कर दिया लेकिन हालत यह है कि हमारे बीकानेर लूणकरणसर में सब जगह गांवों में 25 परसेंट भी मास्टर नहीं हैं, सारी स्कूलें खाली हैं और प्राइवेट स्कूलें भरपूर चल रही हैं। सब यही कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल वालों से सरकार की सांठ-गांठ थी, उनको चलाने के लिये इन्होंने क्रमोन्नयन की असत्य घोषणा कर दी। मास्टर है नहीं, कक्षा कक्ष है नहीं और अंग्रेजी विद्यालय एक खोलो, दो खोलो, हर जगह अंग्रेजी विद्यालय का कहां औचित्य है? साइंटिफिकली बात यह है कि बच्चा अपनी मदर टंग में जितना अच्छा कर सकता है उतना किसी दूसरी भाषा में नहीं कर सकता। जब देश के प्रधान मंत्री एम बी बी एस की पढ़ाई हिन्दी में करा रहे हैं तो हम क्यों अंग्रेजी की तरफ इतना जा रहे हैं? जब पूरे वर्ल्ड में देश अपनी भाषा की ओर जा रहे हैं तो हमें ऐसा क्या है? राजस्थान में किस नीति के तहत हर जगह अंग्रेजी के विद्यालय खोल रहे हैं?

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): साहब, अभी तो पांच मिनट ही बोला हूं, एक मिनट। माननीय सभापति जी, अभी किशनगढ़ से आने वाले विधायक कह रहे थे कि सड़कें अच्छी हैं। मुझे वह दिन याद आते हैं जब राजस्थान के मुख्य मंत्री अपने गृह जिले जोधपुर में 10 किलोमीटर का उद्घाटन करने के लिये हेलिकॉप्टर से जाते हैं तो पूरा राजस्थान शर्मसार हो जाता है कि राजस्थान के मुखिया के जिले में यह हाल है तो राजस्थान की सड़कों का क्या हाल होगा।

अफसरशाही की बात करें तो कांग्रेस सरकार के पूर्व उप मुख्य मंत्री ने राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी के हावी होने की बात कही। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट आपका संरक्षण चाहूंगा, संरक्षण इसलिए कि राजस्थान में भ्रष्टाचार में पकड़े गये टॉप पांच आई ए एस आफिसर की जो सूची आई है, यहां की चीफ सेक्रेटरी कहती हैं कि जीरो टोलरेंस रहे, उसमें भ्रष्टाचार में पकड़े गये टॉप पांच आई ए एस अफसरों में, हमारे यहां बीकानेर में एक साल से संभागीय आयुक्त भेजा हुआ है जो सबसे भ्रष्ट अधिकारी है और वहां आकर वही काम कर रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो हर जगह यह लिखते हैं, जो आर एस एल डी सी घूस कांड में पकड़े गये, उनके बारे में दो शब्द मैं जरूर कहूंगा कि कार्रवाई के तत्काल बाद ए सी बी ने संदेह के आधार पर कौशल विकास निगम के चेयरमैन आई ए एस नीरज के. पवन के दो आईफोन और जब्त कर लिये और उन्होंने चैट डिलीट कर दी। एसीबी ने सत्यापन के दौरान आरोपी मैनेजर से परिवादी को घूस के अलावा कहा कि साहब लोग रंगीन मिज़ाज के हैं, उनके लिये दिल्ली में अच्छे स्तर की अच्छी व्यवस्था कीजिए। शर्म आती है, इस तरह के अधिकारी हमारे यहां बैठे हैं और वह चला रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): जब पत्रिका में 25 जनवरी को यह आता है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ सुनिए, मंत्री जी, सुनिए। ऐसे भ्रष्टों की वजह से ही इंडिया में भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर वन है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। 25 जनवरी को पत्रिका में यह आता है कि ...

श्री सभापति: श्री पदमाराम। अंकित नहीं होगा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री पदमाराम। विराजिए। विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए। प्लीज सहयोग करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, विराजिए। माननीय नेता महोदय, विराजिए, विराजिए।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय उप नेता महोदय, प्लीज सहयोग करें। विराजिए। मैं आपके आगे के वक्ता का समय काट दूंगा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिए, मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा। माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, यह सदन नियम और परम्पराओं से चलता है। मेरे पास जो लिस्ट है उसमें 7 मिनट का टाइम दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने फिर कहा कि 7 से बढ़ाकर 10 मिनट कर दें। 10 मिनट के बजाय आप 12-12 मिनट बोलते हैं, उसके बाद भी आप आसन का निर्देश नहीं मानते। भविष्य में आप इस बात का ध्यान रखें। आसन इस तरह का आचरण बिलकुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छी बात नहीं है, कुछ सीखिए। सदन में आप अनुशासन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे चलेगा सदन? आसन का निर्देश नहीं मानेंगे? मुझे बाध्य होकर आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपका नाम लेना पड़ेगा। माननीय उप नेता महोदय, अपने माननीय सदस्यों को निर्देशित करें कि आसन के आदेशों की अवहेलना नहीं करें। माननीय पदमाराम जी। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए। अब किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के चार साल में राजस्थान के हर क्षेत्र में चहुंमुखी विकास हुआ है। उस विकास को अमलीजामा पहनाने के लिये माननीय राज्यपाल महोदय ने 23 तारीख को अभिभाषण दिया और उस अभिभाषण में चार साल में माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिये, राजस्थान का विकास करने के लिये

(श्री पदमाराम)

राजस्थान को हर क्षेत्र में चहुंमुखी विकास और प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए जो कार्य किया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। कोरोना के दो साल, भयानक बीमारी, जिसका नाम लेते ही आज राजस्थान के अलावा देश और विदेश में हर आदमी कांपने लग रहा है। ऐसी पहली बीमारी, आज से पहले मनुष्य, मनुष्य से नहीं डर रहा था। मां-बाप ने अपने बेटों को छोड़ दिया, बेटों ने अपने मां-बाप को छोड़ दिया। उन विषम परिस्थितियों में जब लॉकडाउन लग गया, फैक्ट्रियां बन्द हो गयीं, लोगों के रोजगार छिन गये, उन विषम परिस्थितियों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने आम आदमी की आवाज बनकर हर क्षेत्र में, चाहे जनता की जान बचाने की बात हो, लोगों को रोजगार देने की बात हो, असहाय लोगों को भोजन देने की बात हो, सभी स्थानों पर अच्छा काम किया। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, सामाजिक सुरक्षा और बाल विकास की बात हो, सड़कों की बात हो, हर क्षेत्र में राजस्थान ने जो अच्छा काम किया, उससे राजस्थान की आर्थिक विकास दर 11 से अधिक है और पूरे देश की जी डी पी के अन्दर राजस्थान का सैकण्ड नम्बर है।

हमारे विपक्ष के साथी बिलकुल सही कह रहे हैं। उनके दिल में दर्द है कि चार साल बीत गये, सरकार का विरोध क्यों नहीं हो रहा है तो हम किसी न किसी रूप में नया विवाद पैदा करके सरकार का विरोध करना चाहते हैं। जनता के अन्दर सरकार का विरोध नहीं है, जनता नाराज नहीं है। हर क्षेत्र के अन्दर सरकार की प्रशंसा हो रही है। उस प्रशंसा को दूर कैसे किया जाए, उसके अन्दर कुछ न कुछ विवाद कैसे हो, उसको मद्देनजर रखते हुए ये हमेशा नयी बात लेकर आते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यदि क्षेत्र के अन्दर विकास नहीं होता तो जी डी पी 11 परसेंट कैसे बढ़ी? रोजगार के साधन कैसे उत्पन्न हुए? प्रदेश की सड़कें मजबूत कैसे हुईं? चिकित्सा विभाग में हर पहलू में, दवाई नि:शुल्क, जांच नि:शुल्क। पूरे राज्य में हर हास्पिटल के अन्दर मरीज भारी तादाद में एकदम खुश हो रहे हैं। प्राइवेट हास्पिटलों के धन्धे बन्द हो गये हैं। मेडिकल बन्द हो गये हैं। इस कारण से इस चीज की चिन्ता है।

चिरंजीवी योजना, जो कि संजीवनी है, मनुष्य जीवन को बचाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने संजीवनी के रूप में, जीवनदायिनी के रूप में

(श्री पदमाराम)

चिरंजीवी योजना लागू की। पहले पांच लाख रुपये तक का इलाज फ्री था, अब दस लाख रुपये तक इलाज फ्री। आज किसी गरीब को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। किसी गरीब की जेब में पैसे नहीं है तो उसको टेंशन नहीं है कि मेरा बेटा बीमार हो जायेगा, मेरी मां बीमार हो जायेगी, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हो जायेगा, उसकी रक्षा करने के लिए राजस्थान सरकार तैयार है। राजस्थान सरकार के मुखिया ने आदेश दिया है कि यदि चिरंजीवी योजना के अन्दर उसका नाम नहीं है और गम्भीर बीमारी से ग्रस्त है तो कलेक्टर साहब के यहां से आदेश आयेगा, उसका नि:शुल्क इलाज किया जायेगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी की हर स्थान पर प्रशंसा हो रही है और उनको दुआ दे रहे हैं कि ऐसे मुख्य मंत्री जिन्होंने आम आदमी, गरीब आदमी और मजदूर की आवाज सुनकर चिरंजीवी योजना लागू की। 88 परसेंट लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। बाहर के लोग भी एस एम एस हास्पिटल में आकर इलाज करा रहे हैं। क्या यह कोई कम चीज है? अगर किसी के यहां दुर्घटना हो जाये तो दुर्घटना बीमा में पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। बहुत अच्छी योजना है। पूरे राजस्थान में, पूरे भारत के अन्दर ऐसी योजना कहीं पर लागू नहीं है। भारत के अन्दर प्रशंसा हो रही है। कोरोना टाइम के अन्दर भीलवाड़ा मॉडल की पूरे विश्व के अन्दर उसकी चर्चा हुई। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कभी किसी चीज की प्रशंसा नहीं की, परन्तु माननीय गहलोत साहब की प्रशंसा की कि भीलवाड़ा मॉडल के अन्दर, कोरोना काल में जो मैनेजमेंट किया है, उन विषम परिस्थितियों में जो आर्थिक मैनेजमेंट, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में घोषणा कर दी।

हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि कर्जा माफी नहीं हुई है। सम्पूर्ण कर्जा माफ की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की जनता ने 25 एमपी जिताकर सेन्टर में भेजे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी हर घोषणा की बात कर रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके अंडर में सेन्ट्रलाइज बैंक हैं, वे राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ करने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। दूसरों की बुराई करना आसान है, खुद की गिरेबां में झांके। सेन्टर में आपकी खुद की सरकार है। महंगाई की मार करके एक्साइज ड्यूटी हमेशा बढ़ा रहे हैं। आप लाखों, करोड़ों, अरबों रुपये कमा रहे हो, किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए ऐसी कौनसी योजना लागू की? देश को महंगाई की मार के अन्दर दिनों-दिन दबा रहे हो। किसान निधि योजना, छह हजार रुपये। आप हिसाब लगायें कि एक साल के छह हजार रुपये दे रहे हैं

(श्री पदमाराम)

और एक परिवार के हर आदमी से और हर बच्चे से हर साल के कितने रुपये वसूल कर रहे हैं, उसका भी हिसाब तो दो। एक गरीब जो बच्चा जन्म ले रहा है, उससे भी आप 24 हजार रुपये वसूल कर रहे हैं और 6 हजार रुपये दे रहे हो। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, पेंशन योजना के तहत कोई कंडीशन नहीं है, वे भी हर परिवार को दे रहे हैं। हर परिवार के 58 साल का पुरुष और 55 साल की स्त्री को हर महीने 1,500 रुपये दे रहे हैं। वह कोई बात नहीं, वह बात नहीं करनी। 75 साल से अधिक की उम्र वाले हर दम्पत्ति को हर साल 24 हजार रुपये दे रहे हैं, वह बात नहीं करनी। राजस्थान आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की मजबूती हो रही है। राजस्थान की सरकार का तंत्र मजबूत हुआ है, शिक्षा का तंत्र मजबूत हुआ है। राजस्थान ने उद्योग के अन्दर प्रगति की है, वह बात नहीं करनी। वह बात करने से राजस्थान का नुकसान हो जायेगा। वह बात करने से ये वापस राज में कैसे आयेंगे? हर आदमी बात कर रहा है। (व्यवधान) आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, जनता दिखायेगी। जनता आपको देख रही है। आपकी बातों को जनता सुन रही है। आप जो बात कर रहे हैं।

अभी आक्या साहब कह रहे थे कि कुछ नहीं किया, कुछ हुआ नहीं तो चार साल पहले आपकी सरकार थी, आपके समय में पूरा विकास हो रखा है, कोई चीज की कमी है ही नहीं, तो अभी किस चीज की मांग कर रहे हो? यदि आपके पांच साल में विकास ही विकास हुआ और राजस्थान ऊपर पहुंच गया था तो हमने चार साल तक राजस्थान को नीचे दबाने का कौनसा काम किया? बताओ तो सही। वह बात करेंगे तो हम आपकी बात सुनेंगे कि बिलकुल आप जनता के सच्चे जन सेवक हैं और जनता के हित में सच्ची बात करते हैं। यह बात आप नहीं करेंगे। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। आप धार्मिक स्थानों की बात कर रहे हैं। धार्मिक स्थानों के अन्दर अशोक गहलोत सरकार ने कौनसा नुकसान कर दिया? मेरे यहां डूंग, परमेश्वर जी का मठ है, वहां पर माननीय गहलोत साहब से छह करोड़ रुपये सैंक्शन हुए। इससे पहले महर्षि जगदीश पुरी जी चार बार वसुन्धरा जी को वहां ले गये। हमारे सभी जन प्रतिनिधि यहां पर आकर दस बार मिले, एक पैसा भी सैंक्शन नहीं किया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने किसानों को मजबूती देने के लिए हर सम्भव काम किया है। बिजली देने की बात हो, 3 लाख 80 हजार कनेक्शन दिये। आपने तो बिजली का एक कनेक्शन भी

(श्री पदमाराम)

नहीं दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर चार जी एस एस दिये, आपने कहा कि कुछ नहीं किया। किसानों को समय पर बिजली देने के लिए, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा है, हमारे ऊर्जा मंत्री जी की मंशा है कि किसानों को सही बिजली दें, दिन में बिजली दें, आप मेहरबानी करके कोयले की व्यवस्था तो करायें। कोयला तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है। वहां से कोयला क्यों रोक रहे हैं, किसी ने एक दिन भी बात की?

परसों माननीय प्रधान मंत्री जी यहां पर आये थे, आप सब वहां पर गये थे। माननीय प्रधान मंत्री जी यहां आये, बिलकुल अच्छी बात है। देवनारायण मन्दिर की बात की, बहुत अच्छी बात है। वहां ऐसी कौनसी घोषणा करके गये जिससे राजस्थान को मजबूती मिले? 13 जिलों के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी तो सब लोग पियेंगे, कांग्रेस के पियेंगे, बी जे पी के पियेगें, सपा-बसपा सब पियेंगे। उनके लिए तो घोषणा करें। भारतीय पेयजल मिशन के तहत पहले 90 परसेंट मिल रहा था, अब उसको जल जीवन मिशन के अन्दर 45 परसेंट राजस्थान को दे रहे हैं और 45 परसेंट दूसरे को दे रहे हैं। यह दोहरा मापदंड है। इससे ऊपर उठकर राजस्थान का विकास कैसे हो, राजस्थान को मजबूती कैसे मिले, राजस्थान के हर बच्चे को शिक्षा मिले, राजस्थान के हर किसान को उच्च क्वालिटी की बिजली मिले। किसानों की फसलें बर्बाद हो गयी हैं। शीतलहर के अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर अरंडी, ईसबगोल और जीरे की फसलें खराब हुई। हमने उसी दिन माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय और कृषि मंत्री जी के यहां फोन किया। घंटे भर के अंदर गिरदावरी का आदेश कर दिया। हमको विश्वास है राजस्थान के लोक कल्याणकारी मुख्य मंत्री, राजस्थान के जन नायक, आम आदमी की आवाज बनकर किसानों के हित के अंदर जल्दी फैसले लेंगे और किसानों की जो फसलें बर्बाद हो गयी हैं, उसके अंदर किसानों को कृषि आपदा के अंदर जरूर फायदा देंगे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू की है। बहुत अच्छी बात है। प्रधान मंत्री जी वहां पर डायरेक्शन जारी करते हैं, बीमा योजना, मैं उनसे, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, उसके अन्दर ये कंडीशन डाल दी है कि दो परसेंट टेम्प्रेचर नीचे आयेगा तब उनको बीमा मिलेगा। वह कब आयेगा? उसके बाद में किसानों के करोड़ों रुपये आपने बीमे के ले लिये तो किसानों के साथ कुठाराघात कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? उसके बारे में तो बात कीजिए। वह योजना आपने लागू की है, अच्छी बात है। उस योजना के अन्दर किसानों के हित में फैसला कैसे हो?

(श्री पदमाराम)

किसानों को ज्यादा से ज्यादा बैनेफिट कैसे मिले? किसान दिन को, रात को, सर्दी में, गर्मी में कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनकी जो उपज है उसका जो खर्चा आ रहा है, उसकी भी पैदावार पूरी नहीं मिलती है। एक आम आदमी का, पूरे भारत के महान उद्योगपतियों, महान पैसे वाले, महान नेताओं के पेट भरने का काम किसान करता है तो किसान के हित के अन्दर जो फैसले होते हैं, किसान को मजबूती कैसे मिले, किसान पैदावार करके अपने बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा कैसे दे, अच्छा मकान कैसे बनाए, अच्छे कपड़े कैसे पहने, उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसी नई योजना लागू करें, ऐसी एक नई सोच पैदा करें जो किसान की उपज से अधिक उसको मजदूरी मिले। हर स्कीम से किसानों को जोड़कर किसानों को मजबूती देने के लिए आप नई पहल करेंगे तो राजस्थान के किसानों ने पहले भी आशीर्वाद दिया, आने वाले समय में भी आशीर्वाद देंगे और वापस 2023 के अन्दर कांग्रेस की सरकार आयेगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, दुनिया जाग चुकी है, दुनिया देख चुकी है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, गोमाता के नाम पर बात करके अब दुनिया गुमराह होने वाली नहीं है। भाषण देने से किसी का पेट भरा नहीं जाता। भाषण बहुत दे सकते हैं। बड़े-बड़े भाषण दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए परंतु किया क्या, ये तो बताइए।

श्री सभापति: कृपया शांत रहिए। सहयोग कीजिए।

श्री पदमाराम (चौहटन): सेंटर में पिछले नौ साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आप बताइए, जवाब दीजिए जनता को आपने सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अन्दर कितनी नौकरियां दी हैं? ये जवाब दीजिए।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री पदमाराम (चौहटन): आपने किसानों के हित में ऐसी कौनसी योजना लागू की? वह जवाब दीजिए। आप किसानों को यह बताइए कि हमने आपके आशीर्वाद से राजस्थान के अन्दर 25 सांसद जिताकर भेजे हैं, राजस्थान के लिए ऐसी कौनसी नयी योजना लेकर आए, उसके बारे में चर्चा कीजिए।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो विकास किया, हम उसके गुणगान गाते हैं। हम ऐसे ही असत्य बातें नहीं कहने वाले हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिये मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कई करोड़ों रुपये का काम हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा

(श्री पदमाराम)

प्रधानमंत्री सड़क योजना, कितने साल से बंद है? आप बताइए आपके क्षेत्र में कितनी सड़कें आयीं? कौन मना करता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना कहां आयी और जो पुरानी प्रधानमंत्री सड़क योजना, आज के दस साल पहले जो सड़कें बनी थीं, उनकी क्या कंडीशन है? पिछले तीन साल से कोई पैसा नहीं आ रहा है, इसके बारे में बात कीजिए।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पदमाराम (चौहटन): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां का 220 का जी एस एस सैंक्शन हो रखा है, परंतु उसकी स्वीकृति नहीं हुई है। मेरा पूरा क्षेत्र डबल क्रोप है। किसानों को बिजली मिल रही है, परंतु उसकी पूरी क्वालिटी नहीं मिल रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी 220 का जी एस एस सैंक्शन है, उसकी स्वीकृति, टेंडर जल्दी जारी करें। किसानों के हित में अच्छा फैसला करें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अच्छा काम किया है। हर पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल पहले भी खुली थी और अभी-भी जो नयी पंचायतें बनीं, उनके अंदर सीनियर सैकण्डरी स्कूल हो गयी है। दसवीं थी, उसको भी बारहवीं कर दी। अभी जो भर्तियां हुई हैं, उसके अन्दर शिक्षा मंत्री जी, जहां बिलकुल स्टाफ नहीं है, वहां दूर-दराज क्षेत्र में पहले पद वहां खोले और वहां पर भरे जाएं तो किसान के, मजदूर के बेटे को शिक्षा मिलेगी।

श्री सभापति: विराजिए। श्री जोराराम कुमावत।

श्री पदमाराम (चौहटन): गरीब का बेटा, किसान का बेटा, सीमा क्षेत्र का बेटा आगे बढ़ेगा तो राजस्थान खुशहाल होगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: विराजिए। आप सब विराजिए। (व्यवधान) आप सब विराजिए। अंकित नहीं होगा। कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय पदमाराम जी के अलावा कुछ भी अंकित नहीं होगा। विराजिए। (व्यवधान) श्री जोराराम कुमावत। विराजिए।

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

प्लीज विराजिए। अपने लोगों से कहिए। ये क्या तरीका है? प्लीज, अपने-अपने आसन पर जाइए। अपने-अपने आसन पर जाइए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(श्री सभापति)

प्लीज-प्लीज, अपने-अपने आसन पर जाइए। (व्यवधान) आप लोगों को नहीं बोलना क्या? श्री जोराराम कुमावत। श्रीमती संतोष। श्री छगनसिंह राजपुरोहित। श्री धर्मेन्द्र मोची। श्री हमीर सिंह भायल। श्री गोविन्द सिंह। श्री फूल सिंह मीणा। श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय,...

श्री सभापति: आप अपनी बात कहिए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): साहब, बीच में बोल रहे हैं।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, सभापति महोदय। (व्यवधान) वे बोलना चाह रहे हैं।

श्री सभापति: मुझे ध्यान है। (व्यवधान) आप अपनी बात कहिए। जो कुछ भी कहना है, बोलिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के (व्यवधान) अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। चिरंजीवी की जो योजना सरकार लेकर आयी..

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव, जो भी बोलना है आप बोलिए अपनी बात। (व्यवधान) सब सुन रहे हैं। मुझे सुनने में आ रहा है, आप बोलिए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। जो दस लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त देने की बात है (व्यवधान) उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। इसके साथ ही, मुझे बोलने तो दीजिए।

श्री सभापति: आप तो अपनी बात बोलिए। आपको बोलना है?

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, जो पेपर लीक हुआ, वह वास्तव में दु:ख की बात है और मैं भी इसकी निन्दा करता हूं। (व्यवधान) मैं विपक्ष के साथियों से प्रार्थना करता हूं कि वे दूसरे साथियों को भी अपनी बात कहने दें। सभापति महोदय, देश को आजाद हुए 74 साल हो गए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(समय: 16.50 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

74 साल के अन्दर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय कटारिया जी, अपने को सदन चलाना है कि नहीं चलाना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): चलाना है।

श्री अध्यक्ष: तो माननीय सदस्य, पहले अपनी जगह पर बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सवाल सिर्फ इतना सा है, (व्यवधान) पांच दिन से राज्य सभा के सांसद धरने पर बैठे हैं। (व्यवधान) सरकार ध्यान नहीं दे रही। मंत्री बात कर ले।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय कटारिया जी। माननीय राठौड़ साहब। माननीय कटारिया जी, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, अपने को सदन चलाना है या नहीं चलाना है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): चलाना है।

श्री अध्यक्ष: तो सदन चलाने का यह तरीका नहीं है। (व्यवधान) सरकार वीक है कि मजबूर है, इसका फैसला 5 साल बाद होगा। अभी सदन चलाना है कि नहीं चलाना है? कोई तकलीफ नहीं। सदन चलाना है? (व्यवधान) ऐसे नहीं होता। मिस्टर, हो गया, यह कोई तरीका नहीं है। माननीय सदस्य, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य को सड़क पर आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, पर सदन चलाने की एक परम्परा है। सदन चलाने की परम्परा का आप निर्वहन करना चाहे तो सदन चलना है, अगर नहीं करना है तो सदन को एडजॉर्न करें। डिबेट का तो डिबेट का तरीका ही होगा। आपको गवर्नर स्पीच में अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। आपकी पार्टी के आदमी आंदोलन कर रहे हैं, उसके बारे में पूरा अधिकार है। जो इश्यु हैं, उनको डिस्कस करने का अधिकार है, यही तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ताकत है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारी गवर्नर की, जो हमारी डिबेट है, उस डिबेट को हम करें। जो भी माननीय सदस्य, अपनी पार्टी के जो भी बिन्दु बोलना चाहें, बोलें और डिबेट को सार्थक रूप में चर्चा करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो नियम हैं, उस हिसाब से चर्चा करें तो मैं समझता हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य बलजीत जी बोल लें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं उनको दुबारा बोलने का मौका देंगे, लेकिन सदन को हम गम्भीरतापूर्वक चलाएं, यह मेरी आप सबसे सानुरोध प्रार्थना है। माननीय बलजीत यादव।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, टाइम....

श्री अध्यक्ष: हां, टाइम बढ़ा दें। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्रवाई दो घंटे बढ़ाई जाए?

(स्वीकृत)

सदन की कार्रवाई दो घंटे बढ़ाई जाती है।

माननीय बलजीत यादव।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने काफी कुछ अच्छे कार्य किए। चिरंजीवी योजना, जिसमें गरीब को दस लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है, इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही, मैं एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूं कि चिरंजीवी योजना में गांव के बहुत सारे अनपढ़ लोग जुड़े हुए हैं। जब किसी को अटैक आ जाता है तो तुरन्त हास्पिटल ले जाते हैं, उसके पास आधार कार्ड की हार्ड कॉपी नहीं होती है, हास्पिटल जाने पर उससे आधार कार्ड मांगा जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अंगूठा लगाने से, उसके फिंगर प्रिंट से तमाम उसकी जानकारी आ जाती है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। उसके आधार कार्ड की भी, दूसरी चीज की भी जानकारी आ जाती है, तो उसके आधार पर ही उसको अलाउ किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि हार्ड कापी की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए।

(श्री बलजीत यादव)

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि देश को आजाद हुए 74 साल हो गए। 74 साल में लोक सभा में भी चर्चा होती है और विधान सभाओं में भी चर्चा होती रही है कि कैसे आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए। मेहनतकश आदमी, किसान-मजदूर आदमी, अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से, सरकार को टैक्स भी देता आ रहा है 74 साल से कि इससे डवलपमेंट के कार्य होंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि 74 साल के बाद आज भी गरीब आदमी सीवर का मिला पानी पीने को मजबूर है। आज भी देश का किसान अपने खेत में पानी के लिए तरस रहा है, बिजली के लिए तरस रहा है, खाद के लिए तरस रहा है। लोक सभा में हो तो वहां पर भारत माला बनाने जा रहे हैं, मेज़ें थपथपाई जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट में हो, ये सड़कें बना रहे हैं, वे सड़कें बना रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर देश को उन्नति के पथ पर ले जाना है तो सबसे पहले किसान के खेत तक पानी पहुंचा दो और किसान को बिजली दे दो, हिन्दुस्तान वैसे ही आबाद हो जाएगा, लेकिन पता नहीं, यह विचार क्यों नहीं आ रहा। मुम्बई तक हाईवे ले जा रहे हैं, यह गुजरात तक जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि सब कुछ छोड़कर, एक बार सब पर बजट रोक कर, एक बार नहर से, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा कि नदियों को जोड़ें। उन नदियों को जोड़कर, किसी भी तरह से राजस्थान के किसान के खेत तक सरकार पानी पहुंचाएं जिससे वह किसान आबाद हो। अध्यक्ष महोदय, किसान के खेत में पानी देना तो दूर की बात, पीने का पानी भी किसान गांव में खरीद कर पी रहा है। गांव के गांव वीरान हो गए।

मेरे गांव के अन्दर, सभी गांव के किसानों के बच्चे या तो फौज में भर्ती होते थे या पुलिस में भर्ती होते थे। अब फौज में जाओ तो उनको कह दिया कि सिर्फ चार साल के लिए ही जाना है। कोई तो मात्र ढाई साल नौकरी करेंगे, उसके बाद अपने घर चले जाओ। पुलिस में जाओ तो वहां एक्सरसाइज करके, बहादुर बच्चा जाता है तो वहां उसको आई ए एस के जैसा पेपर पकड़ा दिया जाता है कि इसको सॉल्व करो, वह कैसे सॉल्व करे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार पुलिस कान्स्टेबल भर्ती करना चाहती है या सरकार आई ए एस बनाना चाहती है? पुलिस कान्स्टेबल बहादुर होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए जो गुण्डों से लड़ सके, मवाली से लड़ सके, लेकिन सरकार कहती है कि हमें बलिष्ठ चाहिए ही नहीं, हमें तो बिलकुल चश्मा लगा हुआ, पढ़ने वाला

(श्री बलजीत यादव)

हो, जिसको कोई रे-कारा भी कह दे तो बाथरूम आ जाए, ऐसे को भर्ती कर लेंगे हम। सब की अलग-अलग अभिरुचि होती है, अलग-अलग क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता होती है, पर पता नहीं कौन पेपर बनाता है। फिर या तो भर्ती निकलती नहीं है और निकलती है तो उसका पेपर आउट हो जाता है। मैंने पहले भी सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक इस पेपर लीक के खिलाफ में दौड़ लगाई थी कि यह पेपर लीक रूकना चाहिए।

इसी सदन में चर्चा हुई थी। रामकृपाल मीणा जो प्राइवेट कालेज चलाता है, उसके कालेज में एग्जाम का सेंटर था, उस तिजोरी के पास उसकी कैसे ड्यूटी लगी, उसकी ड्यूटी किसने लगाई, तो इस सदन में बताया गया कि कलेक्टर ने ड्यूटी लगाई। तो वह कलेक्टर गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके खिलाफ होनी चाहिए थी। उस बड़ी मछली को किसने बचाया? यह छोटे-छोटे आदमी पकड़कर हम खानापूर्ति नहीं कर सकते। युवाओं का विश्वास हमारे ऊपर से उठता जा रहा है। हमसे पूछते हैं कि आपने विधायक बनकर हमारे लिए क्या किया? आपने कौनसा कानून बनवा दिया या कानून बना दिया? कानून बनाने से नहीं होगा, उसको इफेक्टिवली लागू करना होगा, ईमानदारी के साथ उस आदमी को पकड़ना पड़ेगा। हमारे गांव में कहावत है न, चोर नहीं चोर की मां को मारो, जो जनने से ही बन्द हो जाए। वहां पर वह काम करना पड़ेगा, तब जाकर विश्वास होगा। आज युवा भटकता फिर रहा है। चार-चार साल कोचिंग करता है, महंगी-महंगी कोचिंग में जाता है, स्कूल में भारी-भारी फीस देता है, प्राइवेट स्कूलों में जाता है, उसकी कमर टूटी पड़ी है। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार एक साथ कम से कम पांच लाख भर्ती निकाले, छह महीने में ज्वाइनिंग दे, दो महीने में एग्जाम करवाए, रिजल्ट निकालकर उनको ज्वाइनिंग दे, वरना तो केवल घोषणा हो जाती है। चुनाव के टाइम सिर्फ नौकरी मिलती है, चुनाव के बाद चार साल तक, चाहे कोई सरकार आए, चाहे इधर वालों की आए, चाहे इधर वालों की आए, कोई नौकरी नहीं निकलती है। किसान, मजदूर के बच्चे को नौकरी मिले। सी एच ए वाले भटक रहे हैं। न तो सरकार इनको यह कहती है कि नहीं लेंगे, न उनको नौकरी देती है। कभी कोई नेताजी लेकर जाता है, कभी किसी के पास जाते हैं, धक्के खाते फिर रहे हैं, इसलिए मेरी सरकार से विनती है। कोरोना के टाइम जान पर खेल कर उन्होंने जनता की जान बचाई है तो सहानुभूति रखते हुए सरकार को सी एच ए के लोगों को नौकरी देनी चाहिए, यह मेरी सरकार से गुजारिश है।

(श्री बलजीत यादव)

(समय: 17.00 बजे)

मैं सरकार को यह आगाह करना चाहता हूं कि सरकार युवाओं के गुस्से को अण्डर-एस्टिमेट कर रही है, किसान के गुस्से को अण्डर-एस्टिमेट कर रही है। सरकार को पता नहीं है कि किसान कितने गुस्से में है क्योंकि उनके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास पानी नहीं है तो वे एक तरह से ऐसे बारूद के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में इस बजट में व्यवस्था करे।

बाहर के दूसरे स्टेट के लोग यहां आकर नौकरी पा जाते हैं। राजस्थान के युवाओं का 22 स्टेट्स के अंदर सलेक्शन रेट जीरो है। एक भी राजस्थान के बेरोजगार को वहां नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने सरकार से पिछली बार भी यह मांग की थी और मुख्य मंत्रीजी ने यह वचन दिया था। राज्य सभा चुनाव के वक्त भी मैंने यह कहा था कि 90 से 100 परसेंट तक राजस्थान के युवाओं को आरक्षण मिले राजस्थान की सरकारी भर्तियों में और प्राइवेट में 75 परसेंट तक आरक्षण मिले क्योंकि राजस्थान का युवा कोई अनाथ नहीं है। दूसरे और स्टेट में जाएं तो वे यह कहते हैं कि बांग्ला-भाषा जानने वाला हो तब इसमें भर्ती लेंगे। कोंकणी भाषा जानने वाला हो तो आप एप्लाई कर सकते हो, गुजराती भाषा जानने वाला हो तो एप्लाई कर सकते हो। आप बिहार में जाओ तो कहते हैं कि हमारी बिहारी जानने वाला हो, हरियाणा में जाओ तो कहते हैं कि हमारा लोकल होना चाहिए तो राजस्थान का युवा कोई अनाथ नहीं है और हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है।

मैं तो चाहे चुनावी राजनीति से ही संन्यास लेकर उस राजस्थान के युवा, किसान के साथ में लड़ाई लड़ूंगा। आज ही यह घोषणा कर रहा हूं और 6 तारीख को सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक बहरोड़ का विधायक बलजीत यादव फिर दौड़ लगायेगा इन्हीं युवाओं की मांग के लिए, इन्हीं किसानों की मांग के लिए और सरकार ने यदि गम्भीरता से नहीं लिया तो मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, अकेला हूं, लेकिन याद रखे सरकार कि इसी फरवरी में ऐसा आंदोलन खड़ा करके बताऊंगा जो सरकार ने पूरे चार साल में नहीं देखा होगा। यह आज ही इसी सदन में बताना चाहता हूं और इसलिए मैं यह विश्वास रखता हूं कि इसी बजट के अंदर हमारी मांगों की पूर्ति होगी, राजस्थान के बेरोजगार को उसका हक मिलेगा, राजस्थान के किसान को उसका हक मिलेगा।

(श्री बलजीत यादव)

यह घोषणाएं हो जाती हैं कि साहब, पानी आ रहा है, चम्बल का आ रहा है। मेरे यहां पर होगी। लोगों ने हमारे को माला पहना दी कि ये चम्बल का पानी ले आये। अभी चम्बल का पानी तो क्या, वहां पर पीने के पानी का भी कोई अता-पता नहीं है, तो हर बार, पिछली सरकार में यह घोषणा हुई कि चम्बल का पानी आ रहा है तो पिछला एम.एल.ए. माला पहन गया, अबकी बार आयी तो लोगों ने हमें 18 जोड़ी मालाएं पहना दीं और वहां पर पानी-पानी कुछ नहीं है। अब चुनाव में जाएंगे तो वे कहेंगे कि कहां गया आपका वह चम्बल वाला पानी? मैं ज्यादा समझ नहीं सकता, मैं तो किसान का बेटा हूं, फौजी का बेटा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): चम्बल का पानी बह रहा था तो मेरा दिल रो रहा था। इतना बह रहा था कि साहब, यह भयंकर खतरे के निशान से बह रही है। पैसे नहीं लगते, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन सरकार तो कुश्ती लड़ने में लग रही है। कभी तो वह उससे लड़ रहा है, कभी वह उसके डुक मार रहा है, कभी वह उसके डुक मार रहा है और वे राज़ी हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): जे.सी.बी. से खोदकर एक नहर कच्ची ही ले आते तो पहुंच जाता बहरोड़ तक पानी वहां पर, उसमें कोई ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, लेकिन पता नहीं कि कभी ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक दिया, सेंटर वाले कहते हैं कि आप नहीं दे रहे हो, लेकिन किसान मर रहा है। इसलिए मेरी सरकार से यह गुजारिश है कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): हमारे को कमजोर नहीं समझें, हमारी सहनशक्ति जवाब देती जा रही है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रहा है जो हम किसी की परवाह करें। हमें कोई पोस्ट नहीं चाहिए होती है जो हम परवाह करें। हमें भेजा है जवान, मजदूर, किसान और 36 कौम के लोगों ने कि मेरे जैसे मामूली से आदमी को, बलजीत यादव जैसे आदमी को, दोनों पार्टियों को हरा कर विधान सभा में भेजा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): तो वह यह अपेक्षा रखती है और बलजीत यादव की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मैंने चुनाव के वक्त भी उनको यह वादा किया था कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, माननीय सदस्य, हो गया।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): ईमानदारी से आपकी बात को मैं सदन में रखूंगा और मैंने रखा है। मैं यह आशा रखता हूं कि यह सदन हमारी भावनाओं की कद्र करेगा और निश्चित रूप से इसके ऊपर निर्णय करेगा। मुख्य मंत्रीजी इस बजट में यह घोषणा करेंगे और मेरे बहरोड़, नीमराना जो आज वर्ल्ड मैप में आता है और जिले बनने के सारे मापदंड पूरे करता है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। प्लीज।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): उसको भी जिला बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

23 जनवरी, 2023 को माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने विधान सभा में 281 बिंदुओं वाला अभिभाषण पढ़ा। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण राज्य सरकार के कामकाज का आईना होता है। राज्यपाल महोदय ने भाषण के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां बताईं, लेकिन ये उपलब्धियां सिर्फ बजट घोषणा एवं कागजों में ही सिमटी हुई हैं धरातल पर जनता को इनका लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि आम-जन को मूलभूत सुविधाएं जैसे- बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क व सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था दे, लेकिन चार वर्षों से सरकार अपने घरेलू झगड़ों से ऊपर नहीं उठ पा रही है। नीचे बिना खेल सुविधा के आम लोगों को कबड्डी खिलवा रही है और ऊपर सरकार स्वयं कबड्डी खेल रही है।

सरकार को यह भी ध्यान नहीं है कि उन्होंने पिछले चार वर्षों में जो बजट घोषणाएं की हैं, वे धरातल पर नहीं उतरी हैं। सरकार ने सदन में भी कई घोषणाएं की थीं। विकास पथ बनाने की घोषणा की थी, मिनी विकास पथ बनाने की घोषणाएं की थीं। पंचायत समिति स्तर पर नंदी शालाएं बनाने की घोषणा की थी। प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने

(श्री जोराराम कुमावत)

की घोषणा की थी, जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की थी। किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा की थी। बेरोजगारों को भत्ता देने की घोषणा की थी पर गरीब परिवारों की ये घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई हैं। गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने हेतु, चार वर्ष से गरीब लोग दर-दर भटक रहे हैं, नाम जोड़ने की जगह उलटा कई जगह पर उनके नाम काट दिये हैं।

आज बजरी माफियाओं की बात करें तो 45 रुपये टन रायल्टी की जगह पर बिना रसीद के दो-दो हजार रुपये ट्रैक्टर वालों से वसूले जा रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है।

वर्ष 2019-20, 2020-21 में सवा दो लाख नौकरियां देने की सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन अभी तक बेरोजगार नौकरियों के इंतजार में खड़े हैं। यह सारी नौकरियां पेपर लीक की भेंट चढ़ गयी हैं। अभी जैसे विधान सभा के बाहर माननीय किरोड़ी लालजी के नेतृत्व में, वे पेपर लीक के दोषियों को सज़ा देने के मामले में धरना दे रहे हैं, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे सरकार को यह निर्देशित करें कि वह इस मामले में कार्रवाई करे और दोषियों को सज़ा दे और उनसे वार्ता करे।

सुमेरपुर क्षेत्र में जवाई बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा सरकार ने की थी, लेकिन तीन वर्षों में अभी तक स्वीकृति भी नहीं निकल पायी है। वसुन्धराजी की सरकार ने स्टेट हाईवे के टोल-टैक्स माफ किये थे, लेकिन आपने पुन: चालू करके जनता पर अतिरिक्त भार बढ़ाने का काम किया है।

33 के.वी. जी.एस.एस. की घोषणा की थी, वह भी धरातल पर नहीं उतर पायी है। 2021 तक किसानों को सभी कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी 2015 तक के कृषि कनेक्शन भी सरकार नहीं कर पा रही है। बिजली के मामले में देखें तो पिछले चार साल से अघोषित कटौती की जा रही है। कभी तो बिजली आती ही नहीं है, लोगों को यह मालूम ही नहीं पड़ता है कि कब बिजली आयेगी और कब बिजली जायेगी। किसानों के कनेक्शन करने के मामले में, ट्रांसफार्मर, पोल, तार, केबल और मीटर, ये जो आवश्यक चीजें होती हैं, इनका भी पर्याप्त मात्रा में सामान उपलब्ध नहीं होता है जिससे किसानों के कृषि कनेक्शन डेढ़ से दो-दो साल तक डिमांड भरने के बाद भी नहीं हो रहे हैं।

(श्री जोराराम कुमावत)

आज अगर पानी की बात करें तो पिछले साल अकाल था, लेकिन इस बार पर्याप्त बरसात हुई है। जवाई बांध में पर्याप्त मात्रा में पानी आया है पर क्षेत्र में दो दिन से लगाकर दस-दस दिन तक पानी नहीं आता है जबकि प्रतिदिन पानी देना चाहिए, लेकिन सरकार पर्याप्त पानी होते हुए भी अब पानी नहीं दे रही है।

(समय: 17.07 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

शिक्षा की बात करें तो राजस्थान की स्कूलों में 40 प्रतिशत अध्यापकों के पद रिक्त हैं और अध्ययन करने के लिए जो बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनको वहां अध्यापकों की कमी के कारण प्राइवेट स्कूलों में जाकर अध्ययन करना पड़ता है। आज यदि मैं मेरे सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो 137 विद्यालयों में लगभग 650 अध्यापकों के रिक्त पद हैं। तखतगढ़ में कन्या महाविद्यालय पिछले साल खोल दिया, लेकिन सभी के सभी पद रिक्त पड़े हैं और स्कूलों में वे कन्याएं जाकर आती हैं पर उनको पढ़ाई करवाने वाला कोई नहीं है।

राजकीय महाविद्यालय, सुमेरपुर में शैक्षणिक स्टाफ के आधे पद रिक्त हैं और गैर शैक्षणिक स्टाफ के सारे पद रिक्त पड़े हैं। पांच वर्ष पूर्व राजकीय महाविद्यालय के भवन हेतु फर्स्ट फेज की स्वीकृति हुई थी, लेकिन अभी तक राजकीय महाविद्यालय के भवन का काम पांच वर्ष बीत जाने के बाद में भी पूरा नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा कि वह जो भवन का काम चल रहा है उसे शीघ्र पूरा किया जाये और सैकण्ड फेज हेतु बजट आबंटित किया जाये जिससे महाविद्यालय का काम पूर्ण हो सके और महाविद्यालय को नयी बिल्डिंग में संचालन के लिए स्थापित किया जा सके।

आज यदि हम चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में मेरे सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में 8 सी.एच.सीज. में 40 डाक्टर्स के पद रिक्त हैं। 7 पी.एच.सीज. में 7 डाक्टर्स के पद रिक्त हैं और 206 नर्सिंग स्टाफ के पद रिक्त हैं। इतने सारे पद रिक्त होने से, वैसे मरीज हास्पिटल्स में जाता है लेकिन चैकिंग करने वाला कोई डाक्टर नहीं मिलता है तो वह वापस प्राइवेट हास्पिटल्स में जाकर महंगा इलाज करवाने के लिए मजबूर होता है। मैं आपके

(श्री जोराराम कुमावत)

माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा कि इन पदों को शीघ्र भरे जिससे लोगों को फायदा मिल सके।

सड़कों की बात करें तो पिछले पांच वर्ष में जितनी भी सड़कें स्वीकृत हुईं उनमें से 25 परसेंट सड़कें अभी तक पांच वर्ष में भी पूर्ण नहीं हो पायी हैं। वर्ष 2021-22 की जो मिसिंग लिंक की सड़कें स्वीकृत हुई थीं, दो साल बीत गये लेकिन वे सड़कें भी अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं। सरकार ने ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर से जोड़ने की सदन में घोषणा की थी, लेकिन आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में 23 गांव ऐसे हैं जो ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर से जुड़े हुए नहीं हैं। वे अभी तक नहीं जुड़े हैं। प्रमुख देवस्थानों को भी सरकार ने डामर की सड़क से जोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन उनकी भी स्वीकृति जारी नहीं हुई है। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में 50 से ज्यादा सड़कें ऐसी हैं जो पूर्ण क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन उन सड़कों के लिए अभी बजट आबंटित नहीं हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी बजट दे जिससे लोगों को सड़कों के मामले में राहत मिल सके।

अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो आज महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। एस.सी., एस.टी. पर भी अत्याचार बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान में चरम सीमा पर है। आज बजरी माफिया, शराब माफिया, सूद माफिया, भू-माफिया सरकार को चला रहे हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि कानून व्यवस्था को भी संभाले जिससे लोगों को राहत मिले।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा संख्या 16 में बताया गया है कि हमारी सरकार ने इस बार एक क्रांतिकारी पहल करते हुए 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' लागू की। इस योजना के माध्यम से राज्य के हर नागरिक को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया है।

सभापति महोदय, भाजपा सरकार की भामाशाह योजना में 03 लाख रुपये तक के इलाज का प्रावधान था और केन्द्र सरकार ने आयुष्मान योजना लागू की जिसमें पूरे भारत में अनुबंधित प्राइवेट हास्पिटल्स में 05 लाख रुपये तक का इलाज नि:शुल्क का प्रावधान है। आपने दोनों को मिलाकर नया नाम चिरंजीवी दे दिया। भामाशाह योजना में महिलाओं की सादा डिलीवरी, सिजेरियन

(श्री जोराराम कुमावत)

डिलीवरी और बच्चादानी का आपरेशन जो भामाशाह योजना में शामिल था, आपने चिरंजीवी योजना में शामिल नहीं किया जिससे आपने महिलाओं के साथ यह अत्याचार किया है। मैं सरकार और मंत्रीजी से मांग करूंगा कि वह इन बीमारियों को भी चिरंजीवी योजना में शामिल करावें।

सभापति महोदय, आयुष्मान योजना में पूरे भारत में अनुबंधित हास्पिटल्स में 05 लाख रुपये तक का इलाज नि:शुल्क था, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे चिरंजीवी योजना में शामिल कर राजस्थान तक सीमित कर दिया है। इससे राजस्थानियों को पूरे भारत में 05 लाख रुपये के इलाज से वंचित रखा गया है। मैं आपके मार्फत सरकार से मांग करूंगा कि उसको इस योजना में शामिल करे जिससे पूरे भारत में लोगों को 05 लाख रुपये का इलाज नि:शुल्क कराने में मदद मिल सके।

सभापति महोदय, सरकार ने रबी के सीजन में 2022 में समर्थन मूल्य पर चना खरीद किया। मैं आपके मार्फत सरकार को आगाह करना चाहूंगा कि राजस्थान में चना से ज्यादा बाजरा, रायड़ा, गेहूं का उत्पादन होता है। सरकार ने यह जिंस क्यों नहीं खरीदे? चना भी अंतिम समय में खरीद किया जब सभी किसानों ने अपने जिंस बाजार में बेचकर इतिश्री कर दी थी। किसानों को बाजरा 2,350 की जगह 1,500 से 1,600 रुपये में बाजार में बेचना पड़ा। अन्य फसलें सरकार की उदासीनता के कारण किसानों को बाजार में कम कीमत पर बेचनी पड़ी।

किसानों को बिना ब्याज मिलने वाले अल्पकालीन ऋण में भी भारी कटौती की गई। चार वर्ष पूर्व प्रत्येक किसान को को-आपरेटिव सोसायटी के माध्यम से डेढ़ लाख रुपये का ऋण बिना ब्याज के दिया जाता था। पिछले चार वर्षों से फसली ऋण बिलकुल बन्द कर दिया। दो साल से 25 से 40 हजार तक ही फसली ऋण दिया जाता है। यह किसानों के साथ अन्याय करने का काम इस सरकार ने किया है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से मांग करूंगा कि डेढ़ लाख के फसली ऋण को वापस किसानों को दिया जाए जिससे किसानों को राहत मिले।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर सहित पूरे पाली जिले में पिछले दिनों भारी शीतलहर और बरसात का प्रकोप हुआ है। भयंकर पाला पड़ा है जिससे किसानों की जीरा, तारामीरा, रायड़ा, चना, अरण्डा सहित अन्य फसलों का भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने गिरदावरी की घोषणा तो कर दी।

(श्री जोराराम कुमावत)

मेरा सरकार से आग्रह है कि पटवारियों को पाबन्द करे कि वे खेत में जाकर गिरदावरी करें। अधिकारियों को बीमा कम्पनियों के साथ बिठा कर क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट समय पर करावें जिससे किसानों को बीमा क्लेम मिल सके। सरकार से आग्रह है कि पिछले चार वर्ष से किसान परेशान हैं, कभी अतिवृष्टि, कभी अकाल से नष्ट हुए किसानों को फसल खराबे का अनुदान देने की घोषणा करावें। खरीफ की फसल 2022-23 के फसल खराबे का मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला है। खरीफ की फसलों के मुआवजे की भी घोषणा करावें।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में जवाई बांध व हेमावास बांध की नहरें कई जगह से क्षतिग्रस्त हैं जिससे बार-बार पानी का रिसाव होता है और रिसाव होने से भारी मात्रा में पानी व्यर्थ जाता है। समय पर नहरों की मरम्मत नहीं हुई तो ज्यादा टूटेंगी। आपसे विशेष रूप से निवेदन है कि जवाई बाँध व हेमावास बांधों की नहरों की मरम्मत हेतु बजट आबंटित करावें जिससे शीघ्र मरम्मत कार्य करवाया जा सके।

श्री सभापति: बिराजिए। अंकित नहीं होगा। श्रीमती संतोष।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): 000

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार का आईना होता है। अभिभाषण के द्वारा प्रदेश की जनता के सामने राज्य की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। इस अभिभाषण में प्रदेश की समस्याओं और चुनौतियों के बारे में पूरी तरह से मौन साधा गया है। अभिभाषण में केवल आंकड़े हैं तथा गांव, गरीब और किसान के जीवन में परिवर्तन लाने, समृद्ध बनाने, सुखी बनाने की कोई दृष्टि इसमें नहीं है।

सभापति महोदय, आज राजस्थान सरकार कई लोक-लुभावने वायदे करके पीछे हट चुकी है। अगर सबसे मुख्य बात हम करें तो आज राजस्थान में हमारे सामने एक बड़ा विषय यह है कि जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, उनके साथ धोखा किया गया है। उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। रीट पेपर सहित सारे पेपर लीक हुए हैं। स्थिति हमारे सामने स्पष्ट है कि किस प्रकार से एक गरीब बच्चा तैयारी करके नौकरी के लिए प्रयास करता है और जब पेपर आउट हो जाता है तो उस बच्चे को कितनी निराशा होती है।

(श्रीमती संतोष)

राजस्थान की सरकार द्वारा पेपर आउट कराने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो कैसे राजस्थान खुशहाल और समृद्ध बनेगा? हमारा बेरोजगार युवा पीड़ित है।

सभापति महोदय, अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो बहुत लोक-लुभावने नारे इस सरकार के द्वारा बजट के अन्दर किये गये। हमारे स्कूल्स भी क्रमोन्नत किये गये, लेकिन स्थिति हमारे सामने स्पष्ट है कि खाली स्कूल क्रमोन्नत करने से क्या होगा? मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जो एक ही अध्यापक के भरोसे चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्कूलों को क्रमोन्नत करने से कोई फायदा नहीं है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल सरकार के द्वारा बनाये गये हैं लेकिन हम सबको पता है कि उनमें एक भी अंग्रेजी माध्यम का शिक्षक नहीं लगाया गया है। अगर अलग से भवन बनाकर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल्स की ये घोषणा करते और शिक्षकों की व्यवस्था करते तब मानते कि राजस्थान में नया काम इनके द्वारा किया गया है। स्थिति ऐसी है कि हिन्दी मीडियम में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वे भी दुविधा में हैं क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन हो जाने के बाद उन बच्चों के साथ एक तरीके से धोखा ही किया गया है।

चिकित्सा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इस राजस्थान के अन्दर ऐसे अस्पताल कई हैं जिनमें डाक्टर्स नहीं हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की तो स्थिति के लिए मैंने बार-बार अवगत करवाया कि हमारे हास्पिटल में 14 पद सृजित हैं, लेकिन मात्र चार डाक्टर्स वहां कार्यरत हैं। महिला सर्जन तो वहां है ही नहीं। मंत्रीजी ने इसके लिए आश्वस्त भी किया था, लेकिन आज तक वहां पर एक भी डाक्टर नहीं लगाया गया तो निरोगी राजस्थान की बात जो सरकार कर रही है, नि:शुल्क दवा की बात कर रही है, वह कैसे सम्भव है? जो दवा है, वह भी प्रोपर रूप से नहीं दी जा रही है। डाक्टर जहां है, वहां मशीन नहीं है और जहां मशीन है, वहां डाक्टर और टेक्निशियन नहीं है। राजस्थान और मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अन्दर चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है।

सरकार ने एम्बुलेंस की बात कही थी। विधायक कोटे से अनुशंसा करने के बाद भी जहां जरूरत है, वहां एम्बुलेंस नहीं दी गई। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर रामसिंहपुर, 365 हैड, नारावाली ऐसे क्षेत्र हैं जहां की एम्बुलेंस की स्थिति बिलकुल जर्जर है और बहुत ज्यादा आवश्यकता भी है, लेकिन सरकार के द्वारा इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

(श्रीमती संतोष)

हमारे कोविड सहायकों को हमने कोरोना काल में देखा कि किस प्रकार से योद्धा बनकर उन्होंने सेवा की। उन कोविड सहायकों के साथ राजस्थान सरकार ने क्या हालात किये हैं कि आज वे आन्दोलनरत हैं। बिना कारण बताये ही उनको हटा दिया गया है। ऐसी सरकार जो चिकित्सा व्यवस्था की बात करती है, जो समृद्ध राजस्थान होगा, वह कैसे हो जायेगा?

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ शुद्ध पेयजल की हम बात करते हैं। आज राजस्थान के अंदर पेयजल एक महत्वपूर्ण विषय है। पेयजल को लेकर स्थिति ऐसी है कि पीने के लिये पानी नहीं है। आज इस सर्दी के मौसम में भी टैंकरों से पानी गिरवाना पड़ रहा है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो जो जल जीवन मिशन योजना के द्वारा भारत सरकार ने, जो इतनी महत्वपूर्ण योजना थी, इतना बजट दिया, उसको भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया हुआ है। कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है जहां सही तरीके से काम हो रहे हों। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग सभी पंचायतों में बिलकुल ही घटिया निर्माण हो रहा है। जो इतनी महत्वपूर्ण योजना है, उसको भी इन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था यह कहां से करेंगे? जल जीवन मिशन योजना के द्वारा अगर काम सही तरीके से हो जाये तो आने वाले समय में राजस्थान में जो पेयजल की समस्या है उसका भी समाधान हो सकता है, लेकिन ठेका पद्धति अपनाकर ये उस पूरी योजना को बुरी तरह से फेल यहां राजस्थान में कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ जो कानून-व्यवस्था है, उसका तो कहना ही क्या है। आज जो अपराधी हैं, वे सरेआम खुले घूम रहे हैं और जिस बोर्डर एरिये से मैं आती हूं, वहां पर नशे का कारोबार इस कदर बढ़ा हुआ है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, वह नशे के गर्त में डूबी जा रही है। कहने में यह कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी शह पर ही यह नशे का कारोबार चल रहा है। आये दिन कहीं-न-कहीं गोलीकाण्ड हो जाता है। आज हमारी बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कानून-व्यवस्था की जो धज्जियां आज राजस्थान में उड़ायी गयी हैं, वह हम सबके सामने है। आज अपराधी खुले घूम रहे हैं और आम जनता में भय है।

माननीय सभापति महोदय, नशे की मैं बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर घड़साना के अंदर नशे को रोकने के लिये हमारे भाई विजय जी एक मुहिम चला रहे थे, जो एक अधिवक्ता भी थे, उनको इतना प्रताड़ित इस

(श्रीमती संतोष)

प्रशासन के द्वारा किया गया कि वे अंत में अपने जीवन से जंग हार गये। ऐसी स्थिति आज हमारे राजस्थान के अंदर हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, कृषि और किसान की बात राजस्थान सरकार कर रही है और कृषि पर आधारित बजट भी यह लेकर आये थे, लेकिन जो वादे सरकार ने किये थे, वे धरातल पर कहीं भी उतरकर हमारे सामने नहीं आये हैं। सिंचाई में पानी समय पर नहीं दिया जा रहा है। अभी छह दिन लेट हमारे यहां पानी छोड़ा गया।

जो हमारे यहां मुख्य समस्या रहती है और पाले व कोहरे के कारण जो हमारी फसलें नष्ट हुई हैं, पूरी तरह से सरसों की फसल मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़, घड़साना, रामसिंहपुर, नानावाली में नष्ट हो चुकी है। किसान के सामने पूरी फसल तैयार करके जो दाना लास्ट में पड़ गया था, वह दाना पकाव पर था, उस समय स्थिति ऐसी हुई है, इसलिए तुरंत आपदा में लेकर किसान को राहत देनी चाहिये थी। किसान को मुआवजा देना चाहिये था, उस पर अब तक यह सरकार मौन है। जो खुशहाल और समृद्ध किसान की बात यह सरकार कर रही है, वह किस आधार पर कर रही है, यह समझ से बाहर है।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ सड़कों की स्थिति का तो कहना ही क्या है। रावला से रोजड़ी रोड के लिये हमारे यहां 6 महीने से धरना लगा हुआ है, लेकिन बार-बार अवगत कराने के बाद भी अभी तक सरकार के संज्ञान में वह विषय नहीं आया है। एक नानावाली रोड जो बनी थी, उसका सैकण्ड चरण भी इन्होंने रोक लिया है। विधायकों के कहने पर जिन सड़कों की अनुशंसा की हुई थी, उनके भी टेण्डर नहीं हो रहे हैं। कुल मिलाकर सड़कों की ऐसी स्थिति है कि देखकर लगता है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। स्थिति बहुत ज्यादा विकट है और राजस्थान सरकार आज जो विकास की बातें कर रही है, वह मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है।

श्री सभापति: दो मिनट में बात समाप्त करें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, अभी पूर्व वक्ता ने ग्रामीण ओलम्पिक और खेलों की बात कही है, लेकिन हमारे सामने स्थिति यह आयी है कि बच्चों के खेलने के लिये कोई सामान नहीं है, खेल का कोई मैदान नहीं है। ये खेल कहां करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, स्थिति समझ में नहीं आ रही है।

माननीय सभापति महोदय, बिजली की तो हम बात ही क्या करें।

(श्रीमती संतोष)

आज इतनी पावर कट हो रही है कि किसान चारों तरफ से मारा जाता है। उनकी मोटरें जल जाती हैं। डिमांड राशि भरवाने के बावजूद भी आज किसान को वह सामान भी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, तो ऐसी सरकार के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि आज राजस्थान की सरकार संवेदनशील, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना की कसौटी पर पूरी तरह से विफल हो चुकी है। विकास की बात सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन वह विकास राजस्थान के अंदर धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। वास्तविकता यही है, चाहे आप लोग वाहवाही कितनी भी कर लो, लेकिन धरातल पर कोई भी काम आज नहीं हुआ है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। आज मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान में भय, भूख और भ्रष्टाचार का शासन है। भय देखिये, आज के दैनिक भास्कर में खबर है कि राजधानी जयपुर में पांच करोड़ रंगदारी वसूलने के लिये बदमाशों ने फायरिंग की। यह पुलिस को खुलेआम चुनौती है। आपके मंत्रियों को भी अपराधियों से धमकी मिलने की खबर है। साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक साइबर थानों की स्थापना का कोई ठिकाना नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल हत्याकाण्ड में अगर सही समय पर उसकी पीड़ा सुन ली होती तो आज यह इतना बड़ा अपराध नहीं होता और वह कन्हैयालाल हमारे बीच में होता। पुलिस की लापरवाही की वजह से उस कन्हैयालाल की निर्मम हत्या करना पुलिस की कमजोरी है। अशोकजी गहलोत साहब, आप गृह मंत्री हैं और आपसे यह गृह मंत्री पद अगर नहीं संभलता है तो किसी काबिल विधायक को जिम्मेदारी दें। सारे के सारे आप लेकर बैठे हैं। जयपुर के अंदर अपराध हो रहे हैं, सरेआम गोलियां चल रही हैं, इसके ऊपर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की लापरवाही से गरीबों का गेहूं केन्द्र सरकार दे रही है, उसको भी हम उठा नहीं पाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है?

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री विद्या संबल योजना में प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। आज तक इस योजना का क्रियान्वयन नहीं

(श्री फूल सिंह मीणा)

हुआ। करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो रहा है। भ्रष्टाचार अलग देखिये, आपकी सरकार के उप मुख्य मंत्री रहे विधायक जी भी कहते हैं कि उच्चस्तरीय मिलीभगत और भ्रष्टाचार के बिना पेपर लीक नहीं हो सकता। राजस्व विभाग में एक ही अधिकारी द्वारा 80 लाख रुपये, पुलिस विभाग में 2 करोड़ रुपये मांगने के अपराध में पकड़ में आये।

'प्रशासन गांवों के संग, शहरों के संग' पट्टे देने की योजना थी। वह थोथी घोषणा बनकर रह गयी और जो भी पट्टे दिये, वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। माननीय सभापति महोदय, जो गरीब आदमी है, वह पट्टे के लिये तरस रहा है और जो पैसे वाले हैं, वे पैसे देकर पट्टे ले रहे हैं। वह गरीब आदमी आज भी पट्टे के लिये तरस रहा है। यह सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिये सरक-सरककर चल रही है। एक-दूसरे के ऊपर यह इलजाम लगा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, दुर्भाग्य है कि हमारे अशोक जी चांदना साहब नौकरशाही के बेलगाम होने का सार्वजनिक रूप से रोना रो रहे हैं और यह सरकार उनके ही मंत्रियों और विधायकों की नहीं सुन रही है। इतनी बार पेपर लीक हो चुके हैं कि RPSC परीक्षा सहित राज्य की सभी भर्ती एजेंसियों की विश्वसनीयता खतम हो चुकी है। युवाओं का सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। ये कुंठित और हताश होकर कोई नकारात्मक कदम न उठा लें, बेरोजगारी इतनी है कि बेरोजगार आत्महत्या पर उतारू न हो जाएं, इससे पहले मुख्य मंत्रीजी और सरकार चेत जाये।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी चिंरजीवी योजना की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं चिंरजीवी योजना के अंदर किसी का आपरेशन होता है और जयपुर से जब तक उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आपरेशन हो जाता है, ठीक हो जाता है, पांच-पांच दिन तक जयपुर का इंतजार करता है कि यहां से हमें अप्रूवल मिलेगी तब छुट्टी देंगे। कितने मरीजों को तो मैंने बिना छुट्टी दिये ही भेज दिया। जब आपकी अप्रूवल हो जाये तो वापस उनको बुलाकर के छुट्टी दे देना। यहां पर उनका इलाज हो गया। 5-5 आदमी उनकी सेवा के लिये रहते हैं। उनका खर्चा कहां से लायें? इस चिरंजीवी योजना के बारे में आपकी ही सरकार की विधायक दिव्या मदेरणा जी ने शिकायत की थी कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। जिसको चिरंजीवी योजना का लाभ मिलना चाहिए, उसको मना कर देते हैं कि इसमें यह नहीं आ रहा है। जब उसके डाक्यूमेंट्स निकलवाते हैं तो लगता है कि उसको वास्तव में लाभ मिलना चाहिए। ऐसा भ्रष्टाचार इस चिरंजीवी योजना के अंदर हो रहा है।

(श्री फूल सिंह मीणा)

सभापति महोदय, यह सरकार कहां जाकर रुकेगी? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना हमारी अन्नपूर्णा दूध योजना का दूसरा रूप है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में अभ्यर्थियों को भत्ता देने में बहुत सारे अड़ंगे लगा दिये हैं। यह बेरोजगारों के साथ में घटिया मजाक है। नि:शुल्क यूनिफार्म वितरण करने में 2 ड्रेसेज दे दी। एक बनियान सिलने का 200 रुपया ले लेते हैं। वह मजदूर 200 रुपये में कैसे यूनिफार्म सिलायेगा? मेरे पास एक मजदूर काम करता था। वह कह रहा था कि सरकार ने 2 ड्रेस दे दी। सिलाई के 01 हजार रुपये मांग रहे हैं, मैं कहां से दूं? तब पता लगा कि वास्तव में 200 रुपये में 2 ड्रेस कैसे सिलाई जा सकती हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल तो आपने खोल दिये, मगर वहां पर अंग्रेजी के अध्यापक नहीं हैं। हिन्दी माध्यम स्कूल के विद्यार्थियों के लिये कुछ भी नहीं सोचा। मेरे हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थी 10-15 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिये मजबूर हो गये। बच्चियों ने पढ़ाई छोड़ दी। सभापति महोदय, ट्राइबल एरिया में कोई साधन नहीं हैं। वे बच्चियां 12-15 किलोमीटर कैसे जायेंगी? उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। कहते हैं कि महिलाओं को बढ़ावा देंगे। यह सरकार द्वारा आधी-अधूरी असत्य घोषणाएं की जा रही हैं।

शहरी ओलंपिक खेल की घोषणा की। उसको वापस लेना पड़ा। बिना सोचे-समझे असत्य योजनाओं की घोषणा कर-करके वाहवाही तो उन्होंने ले ली, मगर उसको क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री सम्पर्क पोर्टल मात्र एक खानापूर्ति रह गया है। शिकायत करते हैं तो उसके अंदर कहते हैं कि काम हो गया, लेकिन काम नहीं होता है। वापस उनको कहते हैं, दुबारा वह लिखते हैं, फिर भी काम नहीं होता है। यह केवल थोथी घोषणाएं हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान की बैंच उदयपुर में खुलनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि हमारे उदयपुर के ट्राइबल केस जोधपुर जाकर के लड़ने पड़ते हैं। गरीब जेल में सड़ता रहता है। उस ट्राइबल बैल्ट के व्यक्ति से कोई छोटा-मोटा अपराध हो गया, उसको अगर जोधपुर भेज दिया तो जे.सी. के अलावा बचाने वाला कोई नहीं है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय की बैच उदयपुर में खोलने की मांग करता हूं।

(श्री फूल सिंह मीणा)

माननीय सभापति महोदय, मंत्री कलेक्टर को बिना कारण बताये बाहर निकाल देते हैं। अधिकारियों के साथ में बुरा सलूक अच्छा नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें अपनी बात।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, कलेक्टर को बाहर निकाल दें इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है?

सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये किसानों की बात कर रहे हैं, आज ओलावृष्टि हो गयी है, ऐसे ही अतिवृष्टि हुई थी पर उसका आज तक सर्वे नहीं हुआ। पूर्व में हुई अतिवृष्टि का भी पैसा नहीं मिला। मेरी उदयपुर ग्रामीण की गिर्वा पंचायत समिति में इतने ओले गिरे जिससे सारी फसल, सब्जी नष्ट हो गयी। किसान रो रहे हैं, वे त्राहि-त्राहि कर रहे हैं।

सभापति महोदय, खाद, बीज की जो बात कर रहे हैं। पेज नंबर 9 के पैरा 39 में है कि वर्ष 2022-23 में दिसम्बर माह तक राजफैड द्वारा करीब 37 हजार मीट्रिक टन डी.ए.पी., 49 हजार मीट्रिक टन यूरिया, 14 हजार मीट्रिक टन एस.एस.पी. खाद एवं 110 मीट्रिक टन बीज का वितरण किया गया। सभापति महोदय, यह कहां गया? हमारे किसान रो रहे थे कि खाद नहीं है, बीज नहीं हैं। इनके नेता दिल्ली से आये, उनकी जो यात्रा निकल रही थी वहां पर हजारों टन भेज रहे थे कि कहीं इस यात्रा में हमारा विरोध नहीं हो जाये। किसानों के साथ ऐसा अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गिरदावरी करवाकर तुरंत प्रभाव से इन किसानों का मुआवजा दिलाये।

सभापति महोदय, अन्नपूर्णा योजना को वास्तव में आपने इंदिरा रसोई योजना बना दी, मगर वहां आज भी बहुत सारी योजनाएं बंद पड़ी हैं। पूर्व सरकार ने 5 रुपये में नाश्ता देने का जो चालू रखा था, उसको बंद कर दिया। मजदूर जल्दी में होता है, सुबह नाश्ता करके मजदूरी के लिये जाता है, उसको भी आपने बंद करवा दिया।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का नाम बदल दिया। मगर मेरी विधान सभा क्षेत्र के अंदर एक रुपये का काम नहीं हुआ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): डी.एम.एफ.टी. फंड का 4 साल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पैसा खर्च नहीं हुआ। प्रशासन गांवों के संग में जो भ्रष्टाचार हुआ वह आपके सामने है। पैरीफेरी एरिया के अंदर जो हमारे

(श्री फूल सिंह मीणा)

गरीब किसान हैं, चाहे वे किसी भी समाज के हों, पट्टे के लिये तरस रहे हैं। आज दिन तक उनको पट्टा नहीं दिया गया है। कभी कहते हैं कि पंचायत के खाते में कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि यू.आई.टी. करेगी।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। समाप्त करें। सहयोग करें। विराजिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 2013 के बाद में जो भी रहवास कर रहा है, उसकी घोषणा है कि हम सबको पट्टा देंगे।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मगर एक को पट्टा नहीं दिया।

श्री सभापति: विराजिये। अब आप विराजिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): हमारे ट्राइबल के अंदर प्राधिकरण को ला रहे हैं।

श्री सभापति: श्री हाकम अली।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, एक मिनट। 40 किलोमीटर की पंचायतें हैं, ट्राइबल एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहां पर विकास नहीं हो सकता। हमारे किसानों ने खेती करने के लिये बंजर जमीन को उपजाऊ किया। उनको आज दिन तक अलाटमेंट नहीं हुआ। वन विभाग भी पट्टा नहीं दे रहा, सरकार भी अलाटमेंट नहीं कर रही है। किसान कहां जायेगा?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे ट्राइबल एरिया के सभी किसानों को अलाटमेंट करवाकर उनको हक दें ताकि वह अपनी रोजी-रोटी कमा सकें। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री हाकम अली।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, सामने 10 जने ही बैठे हैं।

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सामने 10 जने बैठे हैं।

श्री सभापति: हाउस एडजोर्न कर दूं? आपके वक्ता बोलने से रह जायेंगे। अपने स्थान पर जाइये। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, अपने

(श्री सभापति)

स्थान पर जाइये। बेवजह ही उत्तेजना पैदा करते हो। 2-4 लोग बोल लेंगे। एक मिनट लगेगा, हाउस एडजोर्न करता हूं। विराजिये, विराजिये। जब बोलने का वक्त आता है तब तो बोलते नहीं। बोले और निकल गये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने इस बार एक क्रांतिकारी कदम की पहल करते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की। इस योजना के माध्यम से राज्य के हर नागरिक को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया गया है।

सभापति महोदय, इस बीमा पालिसी के तहत करीब 1,750 अस्पताल पंजीकृत हैं। यह हमारे लिये एक खुशी की बात है कि राज्य के लगभग 88 प्रतिशत लोग अब स्वास्थ्य बीमाधारक हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा महज 41 प्रतिशत ही है। चिरंजीवी योजना से अब तक राज्य के 31 लाख 58 हजार लोगों का उपचार किया जा चुका है। कैशलेस उपचार पर लगभग 3,625 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

लम्बे समय से चिकित्सा एवं शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने की मांग होती रही है, लेकिन सत्यता यह है कि वह बढ़ नहीं सका। पूर्ववर्ती सरकार में इस मद पर होने वाला खर्च 10 हजार करोड़ रुपये का था, जिसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने लगभग 20 हजार करोड़ रुपये कर दिया है।

इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के तहत नवम्बर, 2022 तक करीब 949 करोड़ रुपये व्यय कर 7 करोड़ 50 लाख मरीजों को लाभांवित किया गया है। इस प्रकार हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय के प्रयासों से सम्पूर्ण प्रदेशवासियों को बेहतरीन चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल पाया है। इसके अलावा राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जहां पर प्रत्येक जिले में मेडिकल एवं नर्सिंग कालेज चरणबद्ध तरीके से खोले जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 19 मेडिकल कालेज विभिन्न जिलों में संचालित हैं तथा 12 जिलों में मेडिकल कालेज की स्थापना प्रक्रियाधीन है। सभी जिलों में नर्सिंग कालेज खोलने के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 7 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय प्रारम्भ किये जा चुके हैं। शेष जिलों में नवीन नर्सिंग महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 से प्रवेश कार्य

(श्री हाकम अली खां)

प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार हमारी सरकार ने प्रदेश में नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य का ध्यान रखने का कार्य किया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार किसानों के हित में भी पीछे नहीं रही। प्रदेश के किसानों की सहायता हेतु हमारी सरकार एवं हमारे यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री महोदय के प्रयासों द्वारा ऋण वितरण की प्रक्रिया को अति सुगम बनाया गया है। वर्ष 2022-23 में किसानों को दिसम्बर माह तक 16 हजार 402 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराया गया है। साथ ही लगभग 213 करोड़ रुपये का मध्यकालीन ऋण एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से लगभग 108 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण वितरित किया गया है। वर्ष 2022-23 में दिसम्बर माह तक राजफैड द्वारा करीब 37 हजार मीट्रिक टन डी.ए.पी., 39 हजार मीट्रिक टन यूरिया, 14 हजार मीट्रिक टन.एस.एस.पी. खाद एवं 110 मीट्रिक टन बीज का वितरण किसानों को किया गया है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए रबी सीजन 2022 में समर्थन मूल्य पर 1 लाख 30 हजार से अधिक किसानों से चना खरीदकर 1 हजार 564 करोड़ रुपये एवं 44 हजार 404 किसानों से मूंग खरीदकर करीब 415 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 11 वर्ष के अंतराल के बाद चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ कर दिसम्बर 2022 तक 6 हजार 389 समितियों के चुनाव करवाए जाकर समितियों के गठन का कार्य हमारी सरकार ने किया। माननीय सभापति महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 3 लाख 27 हजार से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन एवं 2 लाख 13 से अधिक बी पी एल श्रेणी के विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं। कृषि कनेक्शनों के लिए अलग से फीडर स्थापित किये जा रहे हैं, जिसके तहत प्रथम चरण में 1 हजार 534 फीडर का कार्य पूर्ण हो चुका है। हमारी सरकार द्वारा दिसम्बर, 2018 से नवम्बर, 2022 तक किसानों को बिजली बिलों में 60 हजार 755 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत मई, 2021 से दिसम्बर, 2022 तक लगभग 12 लाख 88 हजार किसानों को करीब 1 हजार 727 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान देकर लगभग 8 लाख 93 हजार किसानों का बिजली का बिल शून्य करने का काम हमारी सरकार ने किया है।

(श्री हाकम अली खां)

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने पशुपालकों की तरफ भी ध्यान रखा है। वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना शुरू की गई थी, परंतु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उसको बंद कर दिया गया था। हमारी सरकार ने पुन: आने के बाद वर्ष 2019 में इस योजना को शुरू कर दुग्ध उत्पादक पर 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान देना शुरू किया जिसे बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इस प्रकार करीब 4 लाख 63 हजार दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को प्रत्यक्ष रूप से लाभांवित करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, गोवंश के मामले में हमारी सरकार पीछे नहीं है। हमारे मुख्य मंत्रीजी की सोच गोमाता के लिए बहुत ही आगे है। हमारे सामने बैठे हुए प्रतिपक्ष के मेरे साथी गोमाता के नाम पर खूब हो-हल्ला करते हैं, चुनावों में वोट लेते हैं और गोभक्त बनने का पूरा नाटक करते हैं, परंतु धरातल पर गायों के लिए कुछ नहीं करते। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा प्रदेश में गोवंश के संरक्षण की दिशा में गत चार साल में विशेष ध्यान रखा गया, जिसमें हमारी सरकार ने गोशालाओं को भरण पोषण के लिए सहायता राशि 6 माह से बढ़ाकर 9 माह की। इस पेटे दी जाने वाली राशि में जो उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई, अब यह राशि बड़े पशु के लिए 40 रुपये एवं छोटे पशु के लिए 20 रुपये प्रति दिन प्रति पशु कर दी गई है। निराश्रित गोवंश को आश्रय प्रदान करने के लिए 17 जिलों में नंदी शाला स्वीकृत की गई है जिसके लिए 45 लाख रुपये प्रत्येक के लिए सहायता राशि आबंटित की गई है जिस पर अब तक 7 करोड़ 65 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने अल्पसंख्यकों के प्रति भी विशेष ध्यान दिया है और अल्पसंख्यकों के कल्याण की दिशा में कार्य करते हुए अल्पसंख्यक समुदायों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 16 राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय बालक-बालिका विद्यालयों को संचालित करने के साथ ही 47 अल्पसंख्यक बालक-बालिका छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना में 126 मदरसों में आधारभूत संरचना विकास हेतु 21 करोड़ 33 लाख रुपये तथा 500 स्मार्ट क्लास रूम स्थापित करने के लिए करीब 13 करोड़ 10 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु कार्य किया जा रहा है।

(श्री हाकम अली खां)

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय की सोच थी कि पहले भिखारी की तरह आदमी प्लेट हाथ में लेकर खाना खाता था, लेकिन प्रदेश का कोई भी निवासी भूखा न सोए, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में जरूरतमंद लोगों को मात्र 8 रुपये में सम्मानपूर्वक बिठाकर भरपेट, शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 980 रसोइयों के माध्यम से 9 करोड़ 45 लाख भोजन थाली वितरित की जा चुकी हैं। राज्य सरकार प्रति थाली 17 रुपये का अनुदान देकर जरूरतमंद लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवा रही है।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने और हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किये हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा गुणवत्ता सुधार की दिशा में अहम फैसले लिए गए जिसमें सत्र 2022-23 में 1 हजार 54 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में और 3 हजार 834 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। इसी प्रकार 548 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। 143 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। इस प्रकार स्कूलों की शिक्षा के आधार पर राजस्थान प्रदेश सम्पूर्ण देश में चौथे स्थान पर है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए भी हमारी सरकार ने एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बहुत सारे कार्य किये हैं। उच्च शिक्षा की पहुंच सुगम बनाने के लिए हमारी सरकार ने वर्ष 2022-23 में कुल 117 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले हैं, जिनमें बालिकाओं की शिक्षा को महत्व देते हुए 61 कन्या महाविद्यालय खोले गए हैं एवं 29 कृषि महाविद्यालय खोले गए हैं। हमारी सरकार द्वारा गत 4 वर्षों में 240 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें 94 कन्या महाविद्यालय हैं। वर्तमान में 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से 200 राजकीय महाविद्यालयों के नवीन भवनों का लोकार्पण एवं उन भवनों का निर्माण प्रगति पर है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा

(श्री हाकम अली खां)

क्षेत्र की कुछ मांगें और रखना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि नगरपालिका फतेहपुर, जिसमें 55 वार्ड हैं, जिसकी आबादी लगभग डेढ़ लाख है, उसको नगरपालिका, से नगर परिषद् में क्रमोन्नत किया जाए। रामगढ़ शेखावाटी जो एक उप खण्ड मुख्यालय है एवं तहसील कार्यालय है और नगर की आबादी करीब 70 हजार है। लगभग 50 गांवों के लोग यहां पर शहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज के लिए आते हैं, इसकी ओ.पी.डी. लगभग 600-700 है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए रामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 बैड से क्रमोन्नत कर 50 बैड का किया जाए ताकि वहां की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में फतेहपुर शहर एवं ग्रामीण, रामगढ़ शेखावाटी शहर और ग्रामीण और रोलसाहबसर में कुल 4 विद्युत सहायक अभियंता कार्यालय हैं। इन चारों कार्यालयों के अधीन लगभग 80 हजार विद्युत उपभोक्ता हैं। इन सब उपभोक्ताओं को अपने कार्य के लिए अधिशाषी अभियंता कार्यालय जाने के लिए करीब 35 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। अत: इस बात को देखते हुए, विद्युत उपभोक्ताओं के लोड को देखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में एक अधिशाषी अभियंता कार्यालय खोला जाए।

माननीय सभापति महोदय, फतेहपुर क्षेत्र में पशुपालकों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनको देखते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि यहां पर एक पशुधन सहायक केन्द्र खोला जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण जब मैंने पढ़ा तो शुरुआत में राजस्थान का शौर्य, वीरता, त्याग, तपस्या, बलिदान का बखान है, लेकिन पिछले चार वर्षों से हम देख रहे हैं कि जिस शौर्य, तपस्या और बलिदान के लिए राजस्थान जाना जाता था, आज वह महिला अत्याचार, बलात्कार, चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार के मामलों में अव्वल रूप से जाना जाता है।

(श्री छगनसिंह)

मैं अगर शिक्षा से शुरुआत करूं तो सभी माननीय सदस्यों की चिन्ता रहती है कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हो, आगे बढ़े। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 60 ग्राम पंचायतें हैं। नगरपालिका नहीं है। करीब 80 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। अभी वहां वार्षिकोत्सव थे। मुझे तीन-चार जगहों पर बुलाया था। वहां उन्होंने ज्ञापन दिये कि अध्यापकों के पद रिक्त, व्याख्याताओं के पद रिक्त, प्रिंसिपल के पद रिक्त, वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त। मुझे बड़ा दु:ख हुआ। वार्षिकोत्सव में जब अध्यापक मुझसे कह रहे थे कि आपको आना है तो मैंने मना कर दिया कि मैं किसी कार्यवश या विधान सभा सत्र के कारण नहीं आऊंगा, आप कार्यक्रम करें। ऐसा इसलिए, क्योंकि जब हम वहां जाते हैं तो अध्यापकों की कमी देखकर बड़ी पीड़ा होती है कि कहीं न कहीं हम अपने क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय नहीं करवा पा रहे। मेरा आपसे निवेदन है कि हरियाली, नौरवा, सुगालिया, मूलेवा, जोड़ा, ऊण, कवला, वलदरा, हरजी, संवड़ा, आदि ऐसे कई विद्यालय हैं, जहां पर पद रिक्त हैं। उनके बारे में सोचा जाए और छात्रों को पढ़ने में जो बाधा आ रही है, वह न आये।

सभी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की चर्चा कर रहे थे। हम भी चाहते हैं, हमारे गांवों के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त करें। अंग्रेजी माध्यम आज की आवश्यकता भी है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना, आपने देखा होगा, स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल, वहां की अगर आप अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई देखें, यदि उसे देखकर अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले जाते तो छात्रों का कहीं न कहीं भला होता, लेकिन अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की भी पोल माननीय सदस्यों ने खोली। जिन अध्यापकों को अंग्रेजी नहीं आती, उन्हें अंग्रेजी के अध्यापकों के रूप में नियुक्त कर दिया है। हम चाहेंगे, जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खुले हैं, उनकी पूरी मॉनिटरिंग की जाए और वहां अंग्रेजी बोलने और पढ़ाने वाले ही शिक्षक लगाये जाएं।

उच्च शिक्षा की बात करें तो मेरे चार लाख की आबादी वाले विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक राजकीय महाविद्यालय है। वह भी स्नातक स्तर का है। वहां भी सिर्फ कला संकाय है। मात्र 180 छात्रों का कालेज है। उसमें भी रोजाना छात्र अनशन, हड़ताल पर बैठते हैं, क्योंकि वहां प्रोफेसर होते ही नहीं हैं। इस प्रकार की शिक्षा की दुर्दशा हुई है। मात्र एक राजकीय महाविद्यालय में, जो कि सिर्फ स्नातक स्तर का है, वहां भी पूरे अध्यापक नहीं हैं।

(श्री छगनसिंह)

राज्यपाल महोदय से जिस प्रकार से अभिभाषण करवाया गया है, मुझे कहीं न कहीं शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बू आ रही है। मैं पिछले चार वर्षों से देख रहा हूं, राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण मैंने पढ़ा है, लगभग वही की वही बातें रिपीट होती हैं। बजट घोषणा में भी लगभग आधी वही की वही घोषणाएं होती हैं, लेकिन क्रियान्विति नहीं होतीं। चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें। हम आई.पी.डी., ओ.पी.डी. की चर्चा करते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र दो सी.एच.सी. हैं। मात्र दो सी.एच.सी. में भी पूरे के पूरे डाक्टरों के पद रिक्त हैं। मुख्यालय पर मात्र दो डाक्टर्स हैं। सिहाणा में भी यही हाल है। चाहे गाइनोकॉलोजिस्ट हो या अन्य कोई भी डाक्टर, पूरे के पूरे पद रिक्त हैं। जब पेशेंट आई.पी.डी., ओ.पी.डी. के लिए परिजनों के साथ आता है, उसे बाहर से ही जब पर्ची लिखवाने के लिए पूछते हैं कि आप किसलिए आये तो वे अपनी बीमारी बताते हैं। इस पर वे कहते हैं कि यहां क्यों आये हैं, यहां पर तो डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है। तुरन्त उन्हें प्राइवेट हास्पिटल में जाना पड़ता है। चिरंजीवी योजना को हर हास्पिटल से नहीं जोड़ सकते, इसलिए उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। चिकित्सा मंत्री जी यहां विराजे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे यहां मात्र दो सी.एच.सी. हैं। चार लाख की आबादी है। डाक्टरों के पद पूरे के पूरे रिक्त हैं। उन रिक्त पदों पर सोचा जाए और वास्तव में आप जनता की भलाई चाहते हैं तो वहां उन रिक्त पदों की पूर्ति करा दें।

चिरंजीवी योजना का जिस प्रकार से ढोल पीटा जा रहा है, सभी ने देखा होगा। कहा जा रहा है और अच्छी बात भी है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को क्रियान्वित करने के लिए आयुष्मान भारत कार्ड भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन चिरंजीवी योजना में मुख्य रूप से जो काम आने वाली सुविधा है, एक तो महिलाओं की डिलीवरी और आंखों का आपरेशन उस चिरंजीवी योजना में कवर्ड नहीं है। भामाशाह योजना में इन दोनों केसेज का मुफ्त में इलाज होता था। माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि चिरंजीवी योजना का सिर्फ ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा। ऐसे केसेज, जिनकी प्रत्येक घर में आवश्यकता रहती है, जैसे डिलीवरी केसेज हों, बुजुर्गों की आंखों के आपरेशंस हों, उन्हें इसमें जोड़ा जाए, जिससे आने वाले समय में आम जनता को बैनिफिट हो।

सड़कों की बात हो रही है। कई लोगों ने सड़कों के बारे में चर्चा की। सड़क की व्यवस्था जब देखते हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सौ किलोमीटर

(श्री छगनसिंह)

की बी.ओ.टी. रोड है, जो भाद्राजून होते हुए जिला मुख्यालय जालौर तक पहुंचती है। आज उसकी दुर्दशा देखिए, टोल रोड की ऐसी स्थिति है, आपके मंत्री जी भी वहां पहुंचे थे, उन्होंने भी उलाहना दिया कि इस प्रकार की रोड कैसे है।

जब हम 22 दिनों तक वहां पर बैठकर रात-दिन सोये, उसके बाद अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि सौ दिन के अन्दर यह रोड बना दी जाएगी, लेकिन उसके एक वर्ष बीत जाने के बाद भी वह रोड आज तक नहीं बनी। हमारे कुछ लोगों ने मिलकर हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने वहां से टोल हटाया और निर्देश दिया कि जब तक रोड नहीं बनेगी, तब तक टोल की वसूली नहीं होगी। यहां के अधिकारी और मंत्री ने अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। यह बड़ी विडम्बना की बात है कि सरकार एक बी ओ टी रोड का भी ठीक से रख-रखाव नहीं कर सकती और वह भी एक ऐसी सड़क, जिसका टोल आम जनता दे रही है। कल भी इस टूटे हुए रोड की वजह से छात्रसंघ अध्यक्ष सहित तीन युवाओं की दुर्घटना से मौत हो गयी। सैकड़ों हत्याएं उस रोड पर हुई हैं। मैं इन्हें हत्याएं ही कहूंगा। सरकार पर यह मेरा सीधासीधा आरोप है कि ये हत्याएं हैं, क्योंकि सरकार ने यह रोड ठीक से नहीं बनायी। हमेशा गड्ढों के कारण साइड से जाने की वजह से व्हीकल्स आपस में टकरा जाते हैं और इससे कई मौतें हुई हैं। आप रिकार्ड चैक कर लीजिएगा। इस सौ किलोमीटर की बी.ओ.टी. रोड पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि उसमें सरकार के मंत्री भी मिले हुए हैं। सरकार के मंत्री का कहीं न कहीं उसमें हस्तक्षेप है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं।

बजट में 22 किलोमीटर की रोड की घोषणा हुई थी। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उस रोड का काम शुरू हो गया है। जो पुरानी रोड बनी हुई थी, उसके ऊपर सीधा डामरीकरण कर दिया गया। जिन मापदण्डों के अनुसार बनानी थी, उस अनुसार नहीं बनायी। बजट घोषणा में चौड़ाईकरण की रोड थी 7 मीटर की। उसमें जहां पटरियां बनानी थीं, वे कुछ बनायी नहीं। जहां आगे बन रहा था, पीछे टूट रहा था, आज की स्थिति में वह रोड पूरी की पूरी बिखरी हुई है। मैंने दो बार लैटर्स लिखे, लेकिन मात्र उस अधिकारी को ए.पी.ओ. कर दिया। उसके बाद वापस उसे क्वालिटी जांच के लिए लगा दिया उसी जगह पर। मुझे शर्म आती है और दुःख भी होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब उस अधिकारी को ए.पी.ओ. कर दिया,

(श्री छगनसिंह)

उसके बाद भी उस रोड की अगर आप हालत देखें तो पूरी टूटी हुई है। उसके बाद जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि यह ऐसे ही बनेगी। उनकी तो मंत्रियों से सैटिंग है। अब मंत्रियों से कैसी सैटिंग है, यह तो आप जानें, सरकार जाने।

पेयजल की यदि मैं चर्चा करूं, मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र में नर्मदा के दो प्रोजेक्ट्स हैं- एफ.आर. प्रोजेक्ट और ई.आर. प्रोजेक्ट। एफ.आर. का पूरा काम नर्मदा के पहले फेज में हुआ था। अभी काम तो पूरा हो गया है, लेकिन पानी की सप्लाई महीने में पांच दिन आती है। हम पूछते हैं कि पानी क्यों नहीं आ रहा है तो कभी वे मेंटेनेंस के नाम से बन्द करवा देते हैं, कभी पाइप लीकेज हो गया, उसके नाम से करवा देते हैं, कभी लाइट नहीं होने का कारण देते हैं, कभी कहते हैं पी.एच.ई.डी. का काम है, कभी कहते हैं कि नर्मदा का कार्य है। इस प्रकार से एफ.आर. में पूरी जनता त्रस्त है। फिर ई आर क्लस्टर की जो स्वीकृति हुई है बजट घोषणा में, उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। वहां सतही जल नहीं है। पीने के पानी के लिए हमेशा इधर से उधर भटकना पड़ता है और कई बीमारियों से ग्रसित हैं।

(समय: 18.00 बजे)

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री छगनसिंह (आहोर): सरकार इस विधान सभा से सिर्फ वाहवाही लूटने का प्रयास करती है। मैं पक्ष में बैठे हुए विधायकों से निवेदन करूंगा कि जो भी कमियां हैं वे हमें यहां पर बोलनी चाहिए। अगर कमियां नहीं बोलेंगे, हम अगर अपनी जनता की भलाई नहीं करेंगे तो हमारा यहां आने से क्या फायदा होगा? हमें पक्ष और विपक्ष की बात जनता के बीच में जाकर करनी है वह अलग विषय है, लेकिन पीड़ा होती है। मैं मेरे क्षेत्र के हर विषय को लेकर बात करूं तो पेयजल जो मुख्य समस्या है उस समस्या को देखें तो आप सभी को पता चलेगा कि वास्तव में कितनी बड़ी समस्या है।

ऊर्जा की बात करें, विद्युत सप्लाई की बात करें तो राज्यपाल जी के अभिभाषण में सरप्लस की चर्चा हुई और मुख्य मंत्री जी की बजट घोषणा में भी सरप्लस विद्युत की बात हुई। मेरे गांव में जब भी मेरी माता, कोई बहनें खाना बनाने बैठती हैं, पूरे दिन मजदूरी कर घर पर आती हैं और खाना बनाने का समय होता है तो लाइट गुल हो जाती है। मैं सर्दियों के समय की बात कर रहा हूं। परीक्षा का समय है, पढ़ने के लिए शाम को जब बच्चे किताब खोलकर

(श्री छगनसिंह)

बैठते हैं तो लाइट गुल हो जाती है। वे बच्चे समझते हैं कि चलो रात को तो सो जाते हैं, सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करेंगे और जब सुबह 5 बजे उठते हैं तो लाइट नहीं होती है। जब एक्स.ईएन., एस.ई., एम.डी. से बात करते हैं तो वे एल टी मैसेज है जयपुर से, जोधपुर से और लाइट की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सभापति महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि राजस्थान में यह कैसी सरप्लस विद्युत है, इसकी मुझे जानकारी जरूर दें, यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

किसानों की अगर चर्चा करें तो अलग से किसानों के लिए बजट लाये हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय, अभी तो शुरू किया है, दो मिनट हुए हैं। जिन किसानों के लिए अलग से बजट लाया गया है उनके लिए विद्युत की बात की गई है और दिन में बिजली देने की बात हो रही थी। माननीय सभापति महोदय, आपको बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि पहले पूर्ववर्ती सरकार में जिन्हें दिन में लाइट मिलती थी उनको भी रात में मिल रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दस मिनट के स्थान पर आपको बारह मिनट बुला चुका, फिर भी आप कह रहे हैं कि अभी तो बोलना शुरू किया है।

श्री छगनसिंह (आहोर): मैं दो मिनट में पूरा कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई आवश्यकताएं हैं जिनको कहकर मैं पूरा कर देता हूं।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें अब आप।

श्री छगनसिंह (आहोर): बिलकुल एक मिनट में। मेरे वहां आलावा 'सी' अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्राथमिक विद्यालय है, वहां छात्र संख्या भी पूरी है और एक देवगढ़ छापरिया है। इन दोनों को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया जाए, यह मैं सरकार से मांग करता हूं। इसके अलावा देलदरी, सेलड़ी, मिठड़ी, सुमेरगढ़खेड़ा, बिजली, बेदाना कलां को भी उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जाए। बागरा, सियाणा, चांदराई को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया जाए और ऊण, शंखवाली, उम्मेदपुर में पी .एच.सी. खोली जाए। ऊण, शंखवाली की महती आवश्यकता है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि ऊण और शंखवाली में पी.एच.सी. की अगर घोषणा करेंगे तो वास्तव में जनता पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा।

(श्री छगनसिंह)

मेरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था की यदि चर्चा करें तो वह बहुत बिगड़ी हुई है इसलिए सी.ओ. आफिस की सख्त आवश्यकता है, वहां पर डिप्टी कार्यालय खोला जाए। उम्मेदपुर में पुलिस थाना और हरजी, पावटा, कंवला में यदि पुलिस चौकी खोली जाए तो बढ़िया होगा।

मेरा आहोर ग्राम पंचायत मुख्यालय 30 हजार आबादी का क्षेत्र है, वहां पर इस बार अगर नगरपालिका बनाने की घोषणा हो जाए तो अच्छा होगा। वास्तव में पूरे मापदण्ड तैयार हैं, लेकिन पूरे विधान सभा क्षेत्र में अभी एक भी नगरपालिका नहीं है जबकि वहां पर 20 हजार तो वोटर हैं और 30 हजार की आबादी रिकार्डेड है इसलिए उसको नगरपालिका बनाने की घोषणा की जाए जिससे वहां की सुरक्षा व्यवस्था सुहढ़ हो। जैसे फायर ब्रिगेड पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी नहीं है और नगरपालिका होगी तो वहां फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन है कि आहोर नगरपालिका की घोषणा की जाए।

बिजली विभाग की चर्चा करें तो 33 के वी का एक जी.एस.एस. भूती, कंवला या ऊण में खोला जाए। इसके अलावा चवरछा ररजी से सिरोही सीमा, भोरड़ा-बाला-भवरानी-ओडवाड़ा-नरसाना, बावड़ी आइपुरा बावड़ी, आहोर से सनवाड़ा, कुआरड़ा से धुम्बड़ा, एन एच 325 से बेदाना खुर्द और मिठड़ी से देचू की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और इनका अगर निर्माण करें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। भूती-रोड़ला जो पुल है, जिसकी पिछले चार वर्षों से मैं मांग करता आ रहा हूं, वह मात्र ढाई करोड़ का है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह 8 से 9 गांवों की मुख्य मांग है और भूती-रोड़ला पुल की अगर घोषणा हो जाए तो मैं आपका एहसान मानूंगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र मोची।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। राज्य सरकार ने असत्य का सहारा लेकर जिस प्रकार से महामहिम महोदय के मुख से जो असत्य बात कहलावायी है उसकी निन्दा भी करता हूं और उसके विरोध में मैं मेरी बात कहता हूं।

इस अभिभाषण में सरकार ने गरीबों की मुफ्त जांच व इलाज की बात कही है, परन्तु सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति इलाज कराने जाता है उसकी

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

कुछ चिकित्सकों द्वारा बाहर की दवाई व जांच लिखी जाती है पर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जांच के पैसे इतने होते हैं कि बाहर ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। मुख्य मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत अभी ऐसी बहुत सी आम व छोटी बीमारियां हैं जिनका इलाज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के तहत नहीं होता और यदि कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त होता है तो दूसरे शहर में इलाज के लिए जाता है, जिससे बीमा की राशि के अलावा उसे लाखों रुपये अन्य चीजों पर खर्च करने पड़ते हैं, जांच में खर्च करने पड़ते हैं जिसका उसे कोई क्लेम नहीं मिलता, प्रावधान नहीं है। उस मरीज को मुख्य मंत्री सहायता से कोई राहत नहीं दी जाती जिससे उस पर कर्ज हो जाता है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में सी एच ए एक पोस्ट इन्होंने सृजित की थी, जिस पर काफी बेरोजगारों को लगाया था। कोरोना काल में तो उन्होंने काम किया, परन्तु अब वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसलिए उनको परमानेंट करने का प्रावधान करें।

आप आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं जबकि रावतसर में आयुर्वेद औषधालय लम्बे समय से बन्द पड़ा है। एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर है और वहां एक चिकित्सक है फिर भी उसको डेपुटेशन पर अन्य जगह लगा दिया है जिससे रावतसर का आयुर्वेद औषधालय बन्द पड़ा है। मेरी सरकार से मांग है कि सी.एच.सी. में गर्भवती महिलाएं जाती हैं, उनकी हर महीने-दो महीने-तीन महीने में जांच होती है, परन्तु उस गर्भवती बहन के लिए अल्ट्रासाउंड की सी एच सी में कोई व्यवस्था नहीं है। पीलीबंगा, रावतसर, गोलूवाला व डबली में कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण से हनुमानगढ़ जाना पड़ता है, जिसके कारण से अतिरिक्त आर्थिक भार भी पड़ता है और उस बहन के तकलीफ भी होती है। आपने जो हमारे साथ भेदभाव किया, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे चार सी.एच.सी. पीलीबंगा, रावतसर, गोलूवाला और डबली में हैं, जिनके लिए मैंने बार-बार बैड बढ़ाने की मांग की है पर आपने अभी तक वहां बैड नहीं बढ़ाये हैं और न ही वहां पर रिक्त पड़े चिकित्सकों की भर्ती की है।

पैरा संख्या 41 में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आपने बात की है, परन्तु आज ग्राम सेवा सहकारी समितियों के भवन का निर्माण नहीं हो रहा है, उनमें चारदीवारी का निर्माण नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से हनुमानगढ़ जिले का मैंने पहले भी बताया था और आज फिर निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

इन सहकारी समितियों की जांच करायी जाए क्योंकि इनमें काश्तकारों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, उनका धन हड़पा जा रहा है और गबन हो रहे हैं, जैसे हरदासवाली में हुआ, जैसे रतनपुरा संगरिया में हुआ। हरदासवाली की जांच की तो कलेक्टर साहब और एस.डी.एम. साहब के सामने बात रख दी है पर फिर भी सही ढंग से उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ऐसे गबनों से इन संस्थाओं को बचाया जाए ताकि संस्था सुरक्षित रहे।

सभापति महोदय, कृषि कनेक्शनों की बात की जाए तो अभी भी लम्बित आवेदनों की संख्या सैकड़ों से ऊपर है, जिस पर विभाग का जवाब रहता है कि हो रहा है, अभी डिमांड निकल रहा है पर 2013 से लम्बित पड़े हैं। सरकार द्वारा कृषि कनेक्शन हेतु कनेक्शन की स्कीम चालू की उसमें किसानों की डिमांड राशि तो भरवा ली है, परन्तु कृषि कनेक्शन अभी तक नहीं हुए हैं। आप द्वारा ढाणियों में विद्युत कनेक्शन की योजना सुचारु नहीं है। सिंगल ढाणियों में कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। जो आपने नई योजना 'पहले आओ पहले पाओ' चालू की थी उसकी सारी राशि जमा करा दी है फिर भी उनके कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विद्युत व्यवस्था सुधार हेतु खेदासरी भैरूसरी, बड़ोपल तथा नूरपुरा में 33 के वी जी.एस.एस. स्वीकृत हुए थे तथा केंचिया पीलीबंगा में 400 के वी ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत हुआ था परन्तु आज तक उसका कार्य शुरू नहीं हुआ है। बेमौसमी घरेलू लाइट का एलडी कट लगाया जाता है जिसके कारण से पढ़ने वाले बच्चों को, माताओं-बहनों को शाम को खाना बनाने में परेशानी होती है, इसलिए उस एलडी कट को रोका जाए।

सभापति महोदय, लम्पी जैसी गम्भीर बीमारी से गोमाता पर प्रकोप आया, इनके इलाज के लिए पंचायत हैडक्वार्टर पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हर ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए। सभापति महोदय, गोवंश की नस्ल सुधार हेतु मेरे निर्वाचन क्षेत्र के रावतसर में एच जी एम बछड़ा पालन केन्द्र 2018 में स्वीकृत हुआ था और बनकर तैयार हो गया है, परन्तु अभी तक उसको सुचारु रूप से चालू नहीं किया जा रहा है। निराश्रित गोवंश को आश्रय देने के लिए आपने प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने की घोषणा की है, परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी नंदीशाला नहीं खुली है।

सभापति महोदय, पैरा संख्या 147 में सरकार ने यह दावा किया है

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

कि हमने चार साल में कानून व्यवस्था सुदृढ की है, परन्तु धरातल की बात यह है कि आम आदमी अभी भी थाने में जाने से डरता है और यदि थाने में जाता है तो इतना व्यापक भ्रष्टाचार है, उसको अपनी जेब भारी करके जाना पड़ता है। लूट, चोरियों की अभी तक बरामदगी नहीं हुई है।

सभापति महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर में बढ़ते हुए मेडिकल नशे को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेडिकल नशे में वृद्धि का मुख्य कारण पुलिस की विफलता है। हमारे क्षेत्र में हालत यह है कि हर कोने में पुलिस की नाक के नीचे चिट्टा, हेरोइन, स्मैक व नशीली गोलियां बिक रही हैं। हाल ही में पीलीबंगा में नशेड़ियों द्वारा जो स्मैक का धन्धा करते थे, उन्होंने पेट्रोल डालकर एक छोटा-सा मासूम बच्चा था और उसकी मां को जला दिया। उनकी मृत्यु हो गई पर पुलिस ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही स्मैक का धन्धा करने वालों को पकड़ रही है। सभापति महोदय, आप एक दिन इस बढ़ते नशे की रोकथाम के लिए सदन में चर्चा करायें, ताकि युवा पीढी को इस चुंगल से बचाया जाए।

सभापति महोदय, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी नई पुलिस चौकी स्थापित नहीं की है और न ही चौकी को थाने में क्रमोन्नत किया है। आपसे निवेदन है कि डबली चौकी को थाना बनाया जाए व गंधेली में नई चौकी स्थापित की जाए।

पैरा संख्या 162 व 163 में ढाणियों व बस्तियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे द्वारा सदन में हर बार सरकार का ध्यान दिलाया गया है। पेयजल योजना के तहत आपणी योजना, जो सबसे बड़ी योजना मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, परन्तु आपणी योजना का आज तक कोई विस्तार नहीं किया गया है, न ही जल जीवन मिशन से उसे जोड़ा गया है। जिन कृषि भूमि का 90 ए और बी के तहत भू-रूपान्तरण कर दिया गया है, उन कालोनियों में स्वच्छ पानी दिया जाए, ताकि वहां के लोग फ्लोराइड का पानी नहीं पीयें।

आपने पैरा संख्या 163 में जल जीवन मिशन के तहत कार्य की बात की है, परन्तु प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक अपने हिस्से की राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई। जल जीवन मिशन के तहत बहुत-सी ऐसी परियोजनाएं हैं, वहां सम्पूर्ण गांव की रसीद काट दी गई है, परन्तु आज तक वहां न तो पाइप डाली गई और न ही उनको किसी प्रकार का कनेक्शन दिया गया है।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ोपल डेर, जो बहुत बड़ा बारानी क्षेत्र है और 500 के लगभग ढाणियां हैं, स्कीम तो उनके नाम से बना दी गई हैं, परन्तु अधिकारियों द्वारा 500 ढाणियां को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। वे लोग फ्लोराइड का पानी पी रहे हैं।

सरकार ने अन्य क्षेत्रों को सिंचित करने की बात की थी। एटा सिंगरासर माइनर की मांग लम्बे समय से कर रहे थे, पहले सरकार ने डी पी आर बनाई, सारी बात की, परन्तु एटा सिंगरासर माइनर की आज तक कोई बात नहीं की है।

भाखड़ा व इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण के समय खालों का निर्माण किया गया था, जो अब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि उन खालों के जीर्णोद्धार के लिए 4 साल में कोई बजट जारी नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पड़ोसी क्षेत्र में तो सी ए डी के खालों का निर्माण किया जा रहा है, परन्तु हमारे क्षेत्र में सी ए डी के कोई खाले नहीं बनवाये जा रहे हैं। इसमें सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र सेमग्रस्त है, परन्तु सरकार द्वारा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सेमग्रस्त क्षेत्र में ध्वस्त खालों का पुन: निर्माण किया जाए।

आप द्वारा सड़कों के सुदृढ़ीकरण की बात की गई है, परन्तु 20-25 साल पहले जो सड़कें बनी थीं वे आज भी वैसी की वैसी पड़ी हैं और 40 ऐसी सड़कें हैं, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हैं, उनका कोई धणी धोरी नहीं है।

इसके अलावा सूरतगढ़-जाखड़ांवाली-रावतसर सड़क बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है तथा पूरे दिन उस पर बहुत वाहनों की आवाजाही रहती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सूरतगढ़-जाखड़ांवाली-रावतसर सड़क का जीर्णोद्धार कराया जाए तथा उसका चौड़ाईकरण किया जाए। चाइया से गंधेली सड़क का चौड़ाईकरण किया जाए और डिंगा भागसर 26 PBN सड़क का भी चौड़ाईकरण किया जाए।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 16 PBN नहर से लिखमीसर-खरलिया-सुरेवाली सड़क के आदेश हो चुके हैं। 16 PBN नहर से

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

गोलूवाला तक के आदेश हो चुके हैं, परन्तु राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना को रोक रखा है, उसकी स्वीकृति जारी करें ताकि वह सड़क सही हो और आम आदमी को चलने में उसका लाभ मिल सके।

इसके साथ-साथ प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आपने 10 करोड़ की मिसिंग लिंक व नॉन-पेचेबल सड़कें दी थीं, पर उसमें हमारे साथ भेदभाव किया गया है। अधिकारियों द्वारा मनमर्जी करके वे सड़कें ऐसे स्थानों पर बना दीं जिस पर अपना अधिकार जमाकर के हमारे साथ नाइंसाफी की है।

आपने पैरा संख्या 186 में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोल दिये, विद्यालय तो आपने खोल दिये परन्तु विद्यालय के अन्दर न तो टीचर हैं, न शौचालय है, न भवन है। ऐसे विद्यालय राम भरोसे चल रहे हैं और उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने प्राइमरी स्कूल एक भी नहीं खोला है, जबकि प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है। आपने प्रबन्ध किये पर प्राइमरी स्कूलों की जहां जरूरत है, वहां खोलने चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कई जगह हैं जहां पर प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है।

आपने पैरा संख्या 191 में प्रत्येक छात्र को दो सेट ड्रेस पर 200 रुपये प्रति छात्र सिलाई के लिए देने की बात कही है, परन्तु एक ड्रेस के 500 रुपये लगते हैं। उस गरीब के साथ मजाक मत करिये, उसे पूरे पैसे दीजिए। पीलीबंगा उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय नहीं है अत: आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पीलीबंगा, गोलूवाला व डबली कस्बे में महाविद्यालय स्थापित किया जाए, ताकि वहां के बच्चों को शिक्षा मिल सके।

इसी प्रकार आपने कहा, हमने उपखण्ड कार्यालय बहुत खोल दिये हैं, परन्तु जो पुराने कार्यालय हैं, उन उपखण्ड कार्यालयों में वहां के जो सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट हैं, वे खातेदारी अधिकार नहीं दे रहे हैं। जिसके कारण आम आदमियों के साथ कुठाराघात हो रहा है और लोग काफी वर्षों से अपनी खातेदारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा में एक भी नाम नहीं जोड़ा गया है, उनको जोड़ा जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): एक मिनट, साहब। पैरा संख्या 109 में नगर विकास की बात कही गई है, परन्तु शहरों में सफाई व्यवस्था बिलकुल नहीं है। रावतसर शहर में आठ दिन तक पानी भरा रहा, परन्तु पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है।

'प्रशासन शहरों के संग अभियान' में पीढ़ी दर पीढ़ी पट्टे बनाये गये थे, पर वे नहीं बने हैं। सरकार ने नगर मित्रों के नाम से दुकानें खोल दीं, जिसके कारण से नगर मित्र दलाली करने लग गये हैं। सरकार ने 501 रुपये में पट्टे बनाने की बात की थी पर पट्टे नहीं बन रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): पीलीबंगा नगरपालिका में ऑनलाइन टेंडर की बजाय ऑफलाइन टेंडर कर बन्दरबांट की जा रही है और खुला भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भीम।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस पवित्र सदन में सरकार ने माननीय राज्यपाल महोदय से अभिभाषण के रूप में असत्य का पुलिन्दा पढ़वाया है। मैं इसका विरोध करता हूं। पिछले चार सालों में आपकी सरकार ने चार बजट पेश किये हैं और उनमें खूब सारी बड़ी-बड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन धरातल पर कितनी उतरीं, यह आपको देखने की जरूरत है।

राइट-टू-हैल्थ बिल लाने की घोषणा की थी, प्राइवेट हास्पिटलों के दबाव में घोषणा धरी की धरी रह गयी। डिजिटल हैल्थ सर्वे कराने की घोषणा की थी। यहां बैठे माननीय बता दें कि उनका हो क्या गया है? हर विधान सभा क्षेत्र में सी.एच.सी. को मॉडल सी.एच.सी. बनाने की घोषणा की गई थी, उसका अता-पता नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक खोलने की घोषणा की थी, अभी तक केवल जयपुर में पांच या सात खुले हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में माननीय यहां बैठे हैं, बता दें कि किस-किस के विधान सभा क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं।

2018 के जन घोषणा पत्र में किसानों के सम्पूर्ण कर्ज माफी का वादा करके किसानों से वोट तो ले लिये थे, लेकिन 2 लाख 50 से ज्यादा किसान आज भी कर्ज माफी का इन्तजार कर रहे हैं। 28 हजार 817 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई हैं जबकि आप विधान सभा में बिल लेकर आये थे कि

(श्री हमीर सिंह भायल)

किसी भी किसान की जमीन कुर्क नहीं होगी। 2019 से पहले फसली ऋण किसानों को पचास हजार से लगाकर तीन लाख तक मिलता था। ऐसी जादूगरी की कि साख सीमा अब केवल दस हजार से लेकर साठ हजार तक ही है। वह भी किस्तों में, जो किसान के किसी काम नहीं आ सके।

यूरिया और डी.ए.पी. के लिए किसानों को कड़ाके की ठण्ड में रातों में लाइनें लगानी पड़ीं, ऊपर से पुलिसवालों के डण्डे भी खाने पड़े। तीन हजार कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने की घोषणा की थी, अब तक कितने खुल गये? जन घोषणा पत्र में, 2019 के बजट में किसानों को दिन में बिजली देने की घोषणा की थी। दिन में तो दूर अभी तो रात में भी 6 घण्टा क्या, 4 घण्टा भी नहीं मिल रही है। ब्लाक निर्धारित हैं, उनके अनुसार भी बिजली नहीं मिल रही है। केवल एक-डेढ़ घण्टा मिल रही है। कृषि कुओं के ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। उनमें माननीय सभापति महोदय, 15-20 दिन और महीना भी लग जाता है फसल बोयी हुई है फसल को अगर पांच दिन भी पानी नहीं दिया जाता है तो वह नष्ट हो जाती है।

21 जुलाई, 2022 तक की पैंडेंसी के कृषि कनेक्शनों के लम्बित आवेदन निपटाने की घोषणा की थी। अभी तक कितने कनेक्शन हुए? तीन-तीन, चार-चार साल लोगों को डिमाण्ड राशि जमा कराये हुए हो गये। सामान्य श्रेणी, बूंद-बूंद, बी.पी.एल. के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं।

जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 2 व 3 में वादा किया था कि पशुपालकों के पशुओं का मुफ्त बीमा किया जायेगा और बजट 2022-23 में बिन्दु संख्या 158 पर 6 लाख पशुओं का बीमा करने की घोषणा की थी। 2022 में पशुओं में लम्पी स्किन बीमारी फैली, जिससे पूरे प्रदेश में लाखों गायें मरीं और पशुपालकों का लाखों-करोड़ों का नुकसान हुआ। अभी कुछ दिन पहले अख़बार में पढ़ा था कि सरकार अब पशुओं का बीमा करेगी। प्रत्येक पशुपालक के अधिकतम पांच पशुओं का बीमा होगा। अगर आपने समय रहते पशु बीमा लागू कर दिया होता तो प्रदेश के पशुपालकों को कुछ लाभ भी मिलता। अभी भी राज्य सरकार अगर सच में पशुपालकों की मदद करना चाहती है तो बजट में मुख्य मंत्री जी घोषणा करें कि लम्पी स्किन बीमारी से मृत प्रति गाय के हिसाब से गोवंश पालकों को पचास हजार रुपयों का मुआवजा दिया जायेगा, तो पशुपालकों को कुछ राहत मिलेगी।

पांच हजार नये डेयरी बूथ खोलने की घोषणा की थी, कितने खोल दिये गये? 2019-20 में बजट घोषणा की थी 1,478 ग्राम पंचायतों पर नये पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोलने की, अब तक कितने खुल गये? 2019-20 में

(श्री हमीर सिंह भायल)

हर पंचायत मुख्यालय पर नन्दी गौशाला की घोषणा की। गौशाला के अध्यक्ष हमारे बाड़मेर जिले के मेवाराम जी जैन को बनाया गया है। एक भी जगह नन्दी गौशाला नहीं खोली और हर पंचायत पर खोलने की घोषणा कर दी गयी थी। जो पंजीकृत गौशालाएं चल रही हैं उनका भी अनुदान समय पर नहीं मिलना जबकि लम्पी स्किन बीमारी में प्रदेश की जनता ने गोमाता के लिए दिल खोलकर गोमाता की सेवा भी की, मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे भी दिये पर गौशालाओं को समय पर अनुदान नहीं दिया जा रहा है तो गायों को अनुदान कहां से देंगे?

आपने साठ साल इस देश पर राज किया। 1971 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था लेकिन लोगों की मूलभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वच्छता, पानी, बिजली, सड़क पर ध्यान नहीं दिया। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के स्वामी विवेकानन्द स्कूल चल रहे थे, उनको और बढ़ाया जा सकता था, लेकिन आपको शायद स्वामी विवेकानन्द जी का नाम पसन्द नहीं है, केन्द्र सरकार की योजना अच्छी नहीं लगती इसलिये महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोले गये।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की दृष्टि से मैं ईमानदारीपूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि स्कूलें सीनियर सैकण्डरी से लगाकर सारी खाली पड़ी हैं। कालेज खूब खोल दिये आपने, कालेज खोलने से क्या होगा? माननीय मंत्री महोदय, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मेरे बालोतरा से एक पूनियां जी प्रिंसिपल हैं, वो कह रहे थे कि सिणधरी से लगाकर, सिवाना से लगाकर गुढ़ामालानी और चौहटन तक परीक्षा के समय में अगर एक प्रिंसिपल उन कालेजों को सम्भालेंगे तो बच्चों की क्या दशा होगी।

पीने के पानी के लिए आपने देखा होगा पोकरण-फलसूंड योजना सिवाना विधान सभा क्षेत्र के टेल पर पड़ती है। सिणधरी के 70 से 80 गांव, सिवाना के 80 से 90 गांव इस सर्दी के अन्दर पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, तो गर्मी में क्या हाल होगा? 2018 में जो पोकरण-फलसूंड की योजना थी आज जो एक माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि एस पी एम एल कम्पनी द्वारा, उस पर 2008 से लगाकर आज दिन तक सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की और आज भी पानी की यह दशा है कि कई गांवों में दो-दो महीने में पानी का टैंकर नहीं पहुंच पा रहा है। आज भी हड़ताल कर रहे हैं लोग, पानी के लिए धरने पर बैठे हैं लोग। यह स्थिति बनी हुई है और आज भी कोई उसको देखने वाला नहीं है।

(श्री हमीर सिंह भायल)

देश के हर गरीब आदमी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले इसके लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू की, लेकिन आपको उससे भी दिक्कत हुई और आपने अलग ही महात्मा गांधी आयुष्मान भारत योजना का ड्रामा किया, फिर उसमें फेल हो गये तो चिरंजीवी योजना लागू की।

मैं यह कहूंगा कि ऊर्जा विभाग, पेयजल विभाग, चिकित्सा विभाग के माननीय मंत्री महोदय विराज रहे हैं, डाक्टरों की सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं करीब-करीब। मेहरबानी करके इनको शीघ्र भरने की कोशिश करें।

अपने यहां पेपर लीक कहते हैं, गुजरात में कहते हैं पेपर फूटा। 16-16 बार यहां पेपर फूट गया और कोई भी कार्रवाई आज दिन तक नहीं हुई। आज कितने दिनों से युवाओं के साथ में राज्य सभा सांसद आदरणीय किरोड़ी जी मीणा धरने पर बैठे हैं पर सरकार कोई सुध-बुध नहीं ले रही है। कल रात की बरसात में कितने ही हजारों की संख्या में युवा, वहां ओले गिरे, वहां भी मजबूती के साथ में बैठे।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन का कार्य भी, इस तरीके से हो रहा है। सरकार के पैसे खर्च हो रहे हैं पर इनका सदुपयोग जो होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। 2014 से एस.आर. बनी हुई है, आज दिन तक पानी नहीं पहुंचा। 2016 से एस.आर. बनी हुई है, पानी नहीं पहुंचा, उस एस.आर. की हालत क्या होगी, आगे जाकर क्या होगा?

सभापति महोदय, मैं, एक निवेदन करूंगा कि अभी जो ओलावृष्टि हुई है इसमें पूरे राजस्थान में नुकसान हुआ है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हमारे वहां ओले कम गिरे हैं, परन्तु किसानों के अरण्डी से लगा कर, जीरे से लगा कर फसलों का इतना नुकसान हुआ है, माननीय मंत्री जी ने आज घोषणा की कि मैं गिरदावरी कराऊंगा। गिरदावरी करा कर समय पर इनको लाभ दिया जाये और चार माह का बिजली का बिल माफ किया जाये तो किसानों को कुछ राहत मिलेगी।

राजस्थान में हर प्रान्त की अपनी भाषा है। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत इस बजट घोषणा में मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा लागू की जाये, इसके लिए घोषणा करवायें, लोगों की इच्छा है, युवाओं की इच्छा है। साथ ही समय पर पेयजल की व्यवस्था करायी जाये।

(श्री हमीर सिंह भायल)

कालेज शिक्षा में भी पद खाली हैं। चिकित्सा विभाग में खाली, ऊर्जा विभाग में भी यह हाल है। भ्रष्टाचार में तो आपने अभी देखा होगा, आज के पेपर डकैती, अपराधों की खबरों से भरे पड़े हैं। खुले आम चैलेंज के साथ में गोलियां चलानी और भयभीत करना, पुलिस हाथ पर हाथ धर कर बैठी है।

माननीय सभापति महोदय, आने वाले समय में यह राजस्थान अपराधी प्रदेश बन जायेगा। आपने देखा होगा जगह-जगह खुले आम सीकर से लगा कर आज जयपुर के अन्दर सुबह अख़बार में देखा, रात को कितनी गोलियां बरसा दीं और राजस्थान में बेहाल हो जायेंगे। भ्रष्टाचार पर तो अंकुश सरकार को लगाना चाहिये और नहीं लगेगा तो पूरे राजस्थान में क्या स्थिति होगी?

आदरणीय सभापति महोदय, समय रहते यह पानी की घोषणा नहीं की गयी तो आने वाले समय में बहुत बुरे हाल होंगे। यही मेरा निवेदन रहेगा। जय भारत। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। वैसे देखा जाये तो इस सरकार ने घोषणाओं के अलावा कोई काम नहीं किया है। कथनी और करनी में अन्तर है और धरातल पर कोई चीज नजर नहीं आ रही है। अगर किया भी है तो नौ दिन चले अढ़ाई कोस, ऐसी कहावत चरितार्थ हो रही है।

सभापति महोदय, चाहे पलायन का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सब में इन्होंने कछुआ चाल चली है। काम भी किया है तो कछुआ चाल जैसा किया है। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना की बात करता हूं तो वहां विकट समस्या पलायन की है। रीको द्वारा बजट में जमीन आबंटन करने के बाद भी छोटे-मोटे कुटीर उद्योग-धन्धे भी स्थापित नहीं कर पायी। मेरा विधान सभा क्षेत्र 65 ग्राम पंचायतों में बसा हुआ है। 65 ग्राम पंचायतों में से करीबन 38 ग्राम पंचायतें पठारी क्षेत्र में बसी हुई हैं, जो वर्षा पर निर्भर होती हैं, आवश्यकता है वहां डैम बनाने की, माइक्रो डैम बनाने की। ऐसी जातियां हैं तंवर, भील, मीणा, लोधा, गुर्जर जो हमेशा लावणी पर जाते हैं और उनको अपने जीवनयापन के लिए पलायन करना पड़ता है। दूसरे क्षेत्रों में मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। चार साल बीतने के

(श्री गोविन्द प्रसाद)

बाद भी इस सरकार ने एक भी कुटीर उद्योग स्थापित नहीं किया है इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां छोटे-मोटे कुटीर उद्योग लगाये जाएं ताकि इस पलायन को रोका जा सके।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में वहां आज की स्थिति यह है कि 65 ग्राम पंचायतों में 65 सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं और मेरा विधान सभा क्षेत्र तीन ब्लाकों में बसा हुआ है। मनोहर थाना ब्लाक की बात करता हूं तो 32 सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं, इन 32 में एक भी प्रिंसिपल नहीं है और 118 व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं, मात्र 17 व्याख्याता मौजूद हैं तो यह लोग क्या शिक्षा सुधारेंगे? यह हालत है इस सरकार की। मैं निवेदन करता हूं कि वहां 65 सीनियर सैकण्डरी स्कूल और पांच और मान लो तो करीब 70 स्कूल हैं और पूरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र दो प्रिंसिपल हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां इन पदों को भरा जाये।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में श्यामपुरा और बिशनखेड़ा में दो पी.एस. हैं। चार साल से उनके भवन बिलकुल जर्जर हो चुके हैं। वह आदिवासी क्षेत्र के पी.एस. हैं। आदिवासी बच्चों को पढ़ने के लिये छत नहीं मिल रही है, वे बाहर बैठते हैं। मैं राज्य सरकार से चार साल से बराबर मांग कर रहा हूं, लेकिन उनको एक भवन तक उपलब्ध नहीं करा सकी, ऐसी इनकी शिक्षा व्यवस्था है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया जाये।

वहां पर महाविद्यालय है, मनोहर थाना में महाविद्यालय दोनों फेज में स्वीकृत था। दोनों फेज स्वीकृत होने के बावजूद एक फेज का बन चुका है और दूसरे फेज के जो 60 लाख रुपये स्वीकृत थे, वह इस राज्य सरकार ने वहां से पैसा ट्रांसफर कर दिया पर पता नहीं वह पैसा कहां भेजा है और दूसरा फेज अभी भी अधूरा है। वहां कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता है।

मनोहर थाना में नगरपालिका की आवश्यकता है, वहां बस स्टैंड की आवश्यकता है। चार साल से मेरे बार-बार मांग करने के बाद भी इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इन रिक्त पदों को भरा जाये और बस स्टैंड, कन्या महाविद्यालय और नगरपालिका की स्थापना की जाये।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं। हां, आपने चिरंजीवी योजना लागू की, नि:शुल्क दवा योजना लागू की लेकिन आपके पास कर्मचारी कहां हैं? आपके पास काम करने वाले

(श्री गोविन्द प्रसाद)

कहां है? मैं निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन सी.एच.सी. हैं, एक मनोहर थाना सी.एच.सी. है जो बड़े कस्बे में बसी हुई है, उसमें मात्र 30 बैड हैं, मैं वहां 50 बैड की मांग कर रहा हूं लेकिन आज तक भी वहां 50 बैड की स्वीकृति नहीं दी गई है। दूसरी बात, जावर, भालता, गेहूंखेड़ी, चुरलिया और सलड़ा, ये 10-10, 15-15 साल से पी.एच.सी. हैं लेकिन आज तक सबसे पुरानी जावर, गेहूंखेडी पी.एच.सी. को सी एच सी में क्रमोन्नत नहीं किया गया। एक पी.एच.सी. से करीब 20 किलोमीटर और सी.एच.सी. से करीब 30 किलोमीटर दूर उप-स्वास्थ्य केन्द्र है जो पठारी क्षेत्र में बसा हुआ है। आदिवासी लोग आस-पास निवास करते हैं। कोलूखेड़ीकलां उप-स्वास्थ्य केन्द्र को आज तक पी.एच.सी. में क्रमोन्नत नहीं किया गया। मैं इसकी भी बराबर मांग उठा रहा हूं। ये हैं स्वास्थ्य के हाल।

दूसरी बात बिजली की, बिजली के क्षेत्र में देखा जाये तो मेरे क्षेत्र में एक भी जी.एस.एस. नहीं खोला गया। खाना बनाते समय बिजली जाती है, 8-8 घंटे तक लाइट गायब रहती है। जब एम.डी. साहब से फोन पर बात करते हैं या एस ई साहब से बात करते हैं तो वे कहते हैं, एल.डी. मैसेज, यह एल.डी. मैसेज क्या है? बिलकुल ही बंद हो जाती है। आप बराबर बिल लेते हो, बिजली नहीं देते हो, बिल उतना ही आता है जितना आ रहा है और बिजली का पता ही नहीं। आप दिन में किसानों को बिजली देने का वादा करते हो, किसानों को दिन में बिजली क्यों नहीं देते हो? जब आपकी 2-3 घंटे ट्रिपिंग हो जाती है तो उसके बदले भी किसानों को बिजली नहीं दी जाती है। यह हाल आपका बिजली का है।

सिंचाई के क्षेत्र में मेरा विधान सभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इसी कारण वहां के लोग पलायन करते हैं और इसी कारण पेयजल की समस्या है। सिंचाई के क्षेत्र में न तो आज तक इस सरकार ने कोई डैम बनाया, न माइक्रो डैम बनाया, न नदियों पर एनीकट बनाये। वसुन्धरा जी की पिछली सरकार के समय एक कालीखाड़ डैम बना, एक गुलेंडी डैम बना। गुलेंडी डैम से 77 गांव जोड़े और कालीखाड़ डैम से 72 गांव जोड़े। जब छापी डैम बना, छापी डैम से करीबन 38 गांव जोड़े। आज जो आपकी जल जीवन मिशन चल रही है, इस जल जीवन मिशन ने सत्यानाश करके रख दिया। चाहे वह हमारा गौरव पथ हो, चाहे ग्राम पंचायत का खरंजा हो, उन खरंजों का भी सही ढंग से मेंटीनेंस नहीं हो पा रहा है। जब केन्द्र सरकार ने जल जीवन मिशन का टोटल पैसा दे

(श्री गोविन्द प्रसाद)

दिया, उसके बाद भी मेरे झालावाड़ जिले में मात्र 15 प्रतिशत पैसा यह सरकार खर्च कर पाई है और दूसरा चरण लागू कर दिया। पहला चरण पूरा ही नहीं हुआ, दूसरा चरण लागू कर दिया है और उसमें भी कार्य बाधित हो रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन योजनाओं की क्रियान्विति कराएं ताकि वह धरातल पर नजर आये। यह बड़े-बड़े वादे करते हैं, वादे करके यह सरकार में आये और यह सरकार काम के नाम पर जीरो है।

सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा में भी यही हाल है। मेरे झालावाड़ के राजपुरा गांव में 8 माह से लोग मरे हुए के गेहूं उठा रहे हैं। यह हाल है इस सरकार के और कोई सुनने वाला नहीं है। अब इस पांचवें साल में आपने पोर्टल चालू किया है, उसमें नाम मात्र के नाम जोड़े हैं और फायदा वही उठा रहे हैं, गरीब लोगों तक तो आपकी योजना ही नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसकी जांच करायें ताकि ऐसे लोगों को कुछ सज़ा मिल सके और लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाये।

दूसरी बात पशुओं का मुआवजा, 2022 का आज तक मुआवजा नहीं मिला है। 2021 का भी कुछ ही किसानों को मिला है और 2022 का खरीफ का और रबी का आज तक मुआवजा नहीं मिला है, यह बड़ी विडम्बना है। यह सरकार केन्द्र सरकार की योजनाओं को भी सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर पा रही है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा हो, कोई भी योजना यह अपने क्षेत्र में लागू नहीं कर पा रही है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी क्रियान्विति सही तरीके से नहीं हो पा रही है। पिछली वसुन्धरा जी की सरकार के समय जो योजनाएं चलाई गई थीं, उनको बंद कर दिया गया है या उनका नाम बदल दिया गया है, लेकिन वे फिर भी धरातल पर हैं पर उनकी सही तरीके से क्रियान्विति नहीं हो रही है। मैं निवेदन करता हूं कि मैंने अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं बताईं उन पर ध्यान देने की कृपा करेंगे और इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। जय हिन्द, जय भारत, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): धन्यवाद सभापति महोदय। राज्यपाल महोदय आपणा सदन में पधार्या और सरकार री उपलब्धियां रा बारा म चर्चा करी, अभिभाषण पढ्यो। सरकार जो लिखन दियो, उन राज्यपाल महोदय

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

पढ्यो। मैं इजाजत चाहूंगा म राजस्थानी में बोल रहयो हूं और मने उम्मीद है आप एतराज नहीं करोला। इण अभिभाषण में शुरुआत में ही बात करी है राजस्थान दिवस रो अमृत महोत्सव आ ग्यो है। अब अमृत महोत्सव शब्द रो आपनै एतराज है तो आप उन म हिरब जयंती शब्द प्रयोग कर ल्यो, कोई बात नहीं। 30 मार्च न आपां राजस्थान दिवस क्यों मनावा, उन दिन राजस्थान री स्थापना हुई। मैं सदन की जानकारी मैं लावणी चाहूं कि राजस्थान री स्थापना 30 मार्च न नहीं हुई, राजस्थान री स्थापना हुई थी वर्ष प्रतिपदा चैत्र सुदी एकम न। व दिन इ वास्तर तय करयो थो कि उन दिन चैत्र सुदी एकम अति नवां साल रो दिन हेतो, चोखो दिन हेतो, बढ़िया दिन हेता। संयोग री उन दिन 30 मार्च हेती। 30 मार्च तो अपन न याद रह गयी और वर्ष प्रतिपदा भूल गया। म इण सदन रा सब सदस्या न अर्ज करनी चाहूं और पूरी सरकार न भी अर्ज करनी चाहूं और आसन न भी अर्ज करनी चाहूं कि राजस्थान दिवस मनाओ तो वर्ष प्रतिपदा र दिन मनाओ, 30 मार्च न भले और मना लो। पण मूल तारीख तो आपणी वर्ष प्रतिपदा है, चैत्र सुदी एकम् है। उण दिन न महत्व मिलनो चाहिए और मैं आपरे माध्यम सूं निवेदन करनी चाहू हूं।

अभिभाषण री शुरूआत में आयुष चिकित्सा री बात करी है। सुबह प्रश्न काल में भी बात आयी। इण राजस्थान सरकार में सबु बुरी हालत जो कोई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, नोट तो करें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, नोट नहीं कर रहे हैं। अनुवादक को कहें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आयुष चिकित्सा विभाग रो सबसो बुरो हाल इण राजस्थान में है। चिकित्सक कठे ही कोनी। न आयुर्वेद रा है, न होम्योपैथी रा, न यूनानी है, न योगा रा है। कठे ही कोनी है। चिकित्सक है तो कम्पाउन्डर कोनी है। कम्पाउंडर है तो चपरासी कोनी और कई हास्पिटल ऐसा पड़्या, जिनका ताड़ो खोलनवालों कोई नहीं है, धणी-धोरी नहीं है। उण री चिन्ता सरकार न करणी चाहिए। इण बात री आप शाबाशी लेणी चाहो, हास्पिटल बन्द पड़या है, तो मैं आपणे जरूरी देणी चाहू हूं।

इनमें आपणे चर्चा करी, चिरंजीवी स्वास्थ बीमा री। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना पहली बार देश री धरती म लागू हुई तो राजस्थान में लागू हुई। बहुत शानदार योजना आयी अच्छी योजना आयी। देश भर में तारीफ हुई। उण में लाखों लोगों रो इलाज हुयो और उण आधार माथे उण न

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मॉडल मान न भारत सरकार भी आयुष्मान भारत योजना लागू करी। पण, आयुष्मान भारत योजना पूरा देश में लागू, राजस्थान में लागू नहीं। चूंकि राजस्थान म भामाशाह योजना लागू कर तो वसुन्धरा जी रो नाम हो जाये। आयुष्मान भारत योजना लागू कर तो मोदी जी रो नाम हो जाये। इण वास्ते दो नाम सू बचवा र वास्ते चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, एक नवी योजना लायी। उण न फायदो तो अभी मिलण देख्यो थोड़ो बहुत, पण नुकसान अतरो भारी हुयो हो, प्रवासी राजस्थानी जितना बाहर है, जो राजस्थान रा मूल निवासी है, राजस्थान रा मतदाता है और कमाई, नौकरी और धन्धा र वास्ते बाहरे गयोड़ा है। कोई मद्रास में है, कोई बैंगलोर में है।

श्री अमीन खां (शिव): ऐसी भाषा कहां बोली जाती है। जालौर में बोली जाती है?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मैं राजस्थान री भाषा विधान सभा में बोल रह्यो हूं। आप विराजो। मैं राजस्थान री भाषा बोल रह्यो हूं। यह जालौर री बोली कोनी। वे बोल्या हैं, बाड़मेर री बोली अलग है, जालौर री अलग है, जैसलमेर री अलग है। मैं राजस्थानी बोल रह्यो हूं। राजस्थानी भाषा, सब बोल्यां को समेत बोल रहा हूं।

मैं अर्ज करनी चाहूं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सिर्फ राजस्थान में लागू है। जो प्रवासी बाहर बैठा है, उण न इण योजना रो लाभ मिल नहीं सके और आयुष्मान भारत आप दी कोनी तो उठे जो बैठड़यो, तमिलनाडु के कोई गांव में बैठड़यो मोट्य्यार बीमार पड़ जाये तो उ न इलाज नहीं मिणे, कोई फायदो नहीं मिणे। चिरंजीवी बीमा रो उठे लाभ नहीं और आयुष्मान भारत आप लागू नहीं करी। या एक भारी समस्या पैदा करी है। राजस्थान रा प्रवासियों र वास्ते इननो सुधार करना चाइजे और आयुष्मान भारत योजना न भी पूरी तरऊं राजस्थान में लागू करनी चाइजे।

मैं आपण निवेदन करनी चाहूं। ऋण माफी री घणी-घणी मोटी-मोटी बातां हो रही है। ऋण माफी कर्या आप। 'दो लाख रुपये का किसानों का बैंक का कर्जा माफ करेंगे' सभापति जी, मैं आपरे माध्यम सूं पूछनी चाहूं, राजस्थान री एक बैंक रो नाम बता दो, जिनम किसान रो कर्जा माफ हुय्यो है और राजस्थान रा एक किसान रो नाम बता दो, जिनणा दो लाख रुपया माफ हुआ है। सिर्फ ग्राम सेवा सहकारी समितियों रा पैसा माफ करिया है, 12 हजार, 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार और उण म भी चोट कांई हुई। मैं म्हारो उदाहरण

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

देऊ हूं। ऋण माफी र पहली म्हने केसीसी में 1 लाख 35 हजार मिलता। ऋण माफी योजना हुई। म्हाने तो नहीं मिल्यो लाभ, कोई बात नहीं। पण उन न बाद आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वापस शुरू करी। केसीसी रो रजिस्ट्रेशन वापस शुरू करियो। उण में ऋण सीमा तो तय करी 1 लाख 35 हजार, पण पहली बार में म्हने मिल्या 25 हजार, दूजी बार 10 परसेंट प्लस कर मिल्या साढ़े 27 हजार-28 हजार, तीजी बार में मुश्किल सूं 30-32 हजार मिल्या। आप काश्तकार र वास्ते मुसीबत क्यूं करी। जब डेढ़ लाख रुपयो ले बारे वास्ते एलिजिबल है, एंटाइटल्ड है, उण न 25 हजार, 30 हजार रूं शुरू कर रह्या हो। बाकी पइसो कठै सूं लावला? फिर कठै न कठै उधार लेबा जानो पड़ला। कोई गहणो गिरवी रखनो पड़ला। आज स्थिति आप जो पैदा करी है। इण र वास्ते भी म सरकार री निन्दा करनी चाहूं और इ म सुधार सरकार न करनो चाइजे। पूरी केसीसी में जितनो मिलनो चाइजे, उतनो मिलनो चाइये।

ग्राम सेवा सहकारी समितियां, कॉपरेटिव सेक्टर, मतलब गडबड़िया रो सेन्टर। राजस्थान रो सहकारी कानून इतरो लचर है कि भ्रष्टाचार करनो, बेईमानी करनी, गबन करनो, बहुत आसान और जो करले उन न पकड़नो बहुत मुश्किल, सज़ा देणी बहुत मुश्किल। इण बारा म सदन न विचार करनो चाइजे और कानून म बदलाव करनो चाइजे और सख्ती सूं लागू करनी चाइजे ताकि भ्रष्टाचार करने वाले और गबन करने वाले हिम्मत नहीं कर सके। म्हारे विधान सभा क्षेत्र में 5-7, 10-10 करोड़ रा गबन कर बैठी और उन रो चार साल म कांई नहीं बिगड़ रह्यो। मैं सदन र माध्यम सूं आपने निवेदन करनी चाहूं।

विद्युत/बिजली री बात करी कि राजस्थान विद्युत म आत्मनिर्भर है। 23 हजार 489 मेगावाट बिजली पैदा करयां हां। आत्म निर्भर है, सरप्लस है तो वह बिजली कठै गयी? किसाना न क्यूं नहीं मिल रही है? धरा में क्यूं नहीं मिल रही है, कटौती क्यूं करनी पड़ रही है? वे कारखाना बन्द क्यूं पड़या है? सरकार न इणो जवाब देणो चाइतो। बण अभिभाषण म आप कठै जिक्र नहीं करियो, चर्चा ही नहीं की। आप बहुत बड़ी बात राजस्थान री जनता र साथ करी है। कारखाना में कोयला क लिए कहियो आपण पैसा नहीं है, इणो ज्यादा शर्म री बात कांई हो सके?

अभी काल-परसों में जो बरसात हुई है। सभापति महोदय, आपरे माध्यम रू म निवेदन करनी चाहूं, म्हारे विधान सभा क्षेत्र में भी अरण्डी री

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

फसल खराब हुई है। इण नू जस्ट पहले ही पालो पड़ गयो हो, हिमपात पड़ गयो, उण नू नुकसान हुयो। अनाज खराब होय गयी। रायड़ो खराब हो गयो। जीरो खराब हो गयो, ईसबगोल खराब हो गयो। इण न बारां म सरकार न तुरन्त विचार करनो चाइजे और इण नी भारपाई री कोई व्यवस्था करनी चाइजे। फसल बीमा में कवर है तो अच्छी बात है, नहीं तो सरकार कोई व्यवस्था करे। लम्पी स्कीन की इतनी मोटी-मोटी बातां करी। आप गो-रक्षक बन रहिया हो, नवा-नवा, ताजा-ताजा गो-भक्त बन रह्या हो। नंदीशाला री खोलबा री घोषणा की है। जो पहली घोषणा करी, वह भी नहीं खुली। नयी घोषणा तो सिर्फ घोषणा ही है। चुनावी वर्ष में घोषणा करनी है, खुलनी-करनी है कोनी। लम्पी स्कीन में भी जो लापरवाही राजस्थान बरती है, उण में बिल्कुल निन्दा करवा लायक बात है। पूरा देश म सबसू ज्यादा गोवंश मरयो है तो राजस्थान मरयो है और उण न वास्ते राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। लम्पी स्कीन री बीमारी, मुख्य मंत्री जी घोषणा करी थी, चिकित्सक नहीं है, पशुधन सहायक नहीं हैं तो मैं अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस माथे भर्ती करा लां, वह अर्जेन्ट टेम्प्रेरी भर्ती आज तक नहीं हुई। 90 प्रतिशत पोस्टां आज भी खाली पड़ी है। हास्पिटल बन्द पड़या है। इण न वास्ते मैं भी धन्यवाद देबारी जगह सरकार नी निन्दा करणी चाहूं।

सामाजिक सुरक्षा में आप अभिभाषण के अनुच्छेद 73, 74, 75, 76, 77, 78 में मोटी-मोटी घोषणा करी है। पेंशन, छात्रवृत्ति री सबरी बात करी है, धरातल माथे पूग नहीं रही है, सिर्फ कागजा म मंजूर रही है। लोगों रा खाता में नहीं पूग रही है। इण बारा म भी सरकार न चिन्ता करनी चाइजे।

प्रधानमंत्री आवास योजना री आप न 100 नम्बर पर चर्चा करी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 लाख 80 हजार आवास हमने बनाकर दे दिये। आप खुद री पीठ थपथपा रहे हो। उण म आपरो योगदान काई है? राजस्थान सरकार रो एक रुपयो लाग्यो काई तो उण मैं प्रधान मंत्री रो नाम लिखता ना और भारत सरकार रो नाम लिखता ना जोर क्यूं पड़ रहियो है। पइसा भारत सरकार रा और शाबासी आप ले रहे हो, हमने 2 लाख 80 हजार आवास बनाकर दे दिये। पइसा तो भारत सरकार दिया, स्कीम तो भारत सरकारी बनायी, जद ही आप बनाया। पहला आप री इंदिरा आवास योजना थी। गांव में एक साल में एक-आध बनतो, आज गांव में एक साल म सौ-सौ मकान बन रह्या है। जो आदर्श योजना, श्रेष्ठ योजना भारत सरकार दी है। आदरणीय

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो दी है, उण ना नाम लिखता न आपने तकलीफ नहीं होनी चाइजे।

अभी कई सारा विधायक नरेगा री चर्चा करी। नरेगा नहीं होता तो मर जाते। मैं गणित बतानी चाहू हूं। आप राजस्थान म 125 दिन अलाउ कर रहिया है, बाकी जगह 100 दिन है, अठै 125 दिन। एवरेज जो कमाई आ रही है, दो सौ और सवा दो सौ एक दिन री मजदूरी पड़ी है। 12 महीनों को हिसाब लगा लो, 125 दिन रो हिसाब लगा लो, तो एक महीना में एक हजार या ग्यारह सौ रुपया पांती आवे। एक महीना में एक परिवार ने हजार - ग्यारह सौ रुपया पांती आवे। आप कह रहे हो नरेगा जी ना दिया। आप उण ने एक हजार रूपयो महीना रो दे रह्या हो। उण में आप शाबाशी लेणी चाहो, भले लो। इन्दिरा रसोई री घणी तारीफा हो रही है। 8 रुपया पब्लिक सू लो, पहले आप 12 रुपया देता, अब 17 रुपया कर दिया। 25 रूपया री थाली, इज्जत के साथ, कोई भूखा नहीं सोयेगा। अन्नपूर्णा योजना चालती, आठ रुपया पब्लिक देती और 32 रुपया सरकार देती, 40 रुपया री थाली मिलती। 40 रुपया में शानदार भोजन मिलतो, भरपेट भोजन मिलता। इण में आप आठ रुपया में गिणती री चार रोटियां दे रह्यो हो, चार री पांच करी है, पांच में भी पेट नहीं भरतो तो एक कूपन और कटाओ और उण म भी आप 25 रुपया री थाली दे रह्यो तो क्वालिटी कसी होगी? 40 रुपया री थाली म और 25 रुपया री थाली में कतरो फर्क रहे।

एक सवाल म और पूछनी चाहूं आपरो माध्यम सूं कि अन्नपूर्णा योजना कद बंद करी और इंदिरा रसाई योजना कद चालू करी, बीच म ज्यों डेढ़-दो साल रो गेप है, उनम ज्यो भूखा होई ज्या लोग उनरो जवाब कुन देवलो, यह सवाल मैं आपन पूछनी चाहूं।

पेपर लीक पर घणी चर्चा होई गई, म ज्यादा करणी नी चाहूं, परंतु पेपर लीक मामला म्ह जादूगर कुण है, जो स्ट्रांग रूम सूं पेपर बारै काढ्या, वो जादूगर हाळ पकड़ मैं न आ रह्यो है। मैं उण जादूगर न खोज रह्यो हूं। सरकार न ऊं जादूगर न पकडर बारै ल्यावणों चाहिजे।

जनता जल मिशन में, जेजेएम में, राजस्थान सरकार भी पैसा दे रही है, भारत सरकार भी दे रही है। भारत सरकार सूं पैसा खूब आ रह्या है। राजस्थान सरकार रो भाग, उनमै पूरो टाइम म्हानै नहीं मिल रह्यो है। उन कारण म्हारै जालौर जिला मांय, म्हारै विधान सभा क्षेत्र मांय एफआर प्रोजेक्ट

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

धीमी गति सूं चाल रह्यो है। ईआर प्रोजेक्टर माइन बहुत धीमी गति सूं काम हो रह्यो है और एफआर प्रोजेक्ट में जो पाणी आ रह्यो है, उण पाणी म रास्ता म चोरी भी होरी है और राजनीतिक शहूं चोरी होरी है। चोरी करवा बाळा रै खिलाफ डिपार्टमेंट वाळा कार्रवाई करबा जाय तो मारपीट कर् और मारपीट करै तो राजनेता बचावा म् आ रह्या है। एफआईआर तक दर्ज नहीं होवां दे रह्या है। इन बारा म्ह मैं सदन रा माध्यम सूं अर्ज करनी चाहूं।

सड़कां री बात करता, अनुच्छेद 177 और 180 आप सड़कां री चर्चा करया, नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, पुल, आरओबी, एमडीआर, ग्रामीण सड़क, ये सब पैसा भारत सरकार रा है, नाम लिखो कि भारत सरकार इत्ता पैसा दिया और म्है इत्ता घाल्या। आप इण म्ह लगभग 35 हजार करोड़ रुपयो खर्च करबाली बात कर रह्या हो। आपरा 35 करोड़ भी न होवैला। म्ह दावा री साथ कहूं और चौहटन रा आवाळा माननीय विधायक बिराज्या है, वह कैवता कि इण चार साल म प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितना पैसा आया? कितनी सड़क बनी? आपरो अभिभाषण कह रह्यो है, अनुच्छेद 177 और 180 माइन, 5,821 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना म्ह राजस्थान री धरती माथ बणी है, इण चार साल म। पढ़र बोल बो करो भाई, गपोडा मत मारो। आप कह रहया प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में एक किलोमीटर सड़क नहीं आयी। 5,821 किलोमीटर आपरी किताब म्ह लिखयोडी है, म म्हार कनु नहीं बोल रहयो।

अंग्रेजी स्कूलां जो ल्याई है जबरदस्ती, कोई मांगी नहीं कणै, कणै नहीं मांगी कि अंग्रेजी स्कूल खोळो। आप जबरदस्ती ही हर पंचायत म खोल रहया हो। हिन्दी स्कूल बंद करन खोल रहया हो। हिन्दी स्कूल जा रहया है। हिन्दी स्कूल रा टाबर भटक रहया है कठ जावै। इंग्लिश मीडियम रा अध्यापक मिळया कोनी और हिन्दी स्कूल रा टाबर भटकता फिर रहया है, अटी-उटी र, आ भी एक भारी मुसीबत होगी। भारत सरकार री नवी शिक्षा नीति कै री है मातृ भाषा में शिक्षा देवो। राजस्थान री मातृभाषा राजस्थानी है, राजस्थानी है, राजस्थानी है और आप शिक्षा अंग्रेजी में देणी चाहो। राजस्थानी म्ह देवो तो ज्यादा ठीक रहे। राजभाषा एक्ट आपणो बणेड़ो है। 1956 रो राजभाषा एक्ट, उण म्ह सिर्फ हिन्दी एक भाषा लिख्योड़ी है। उण म्ह संशोधन रो प्रस्ताव लावो और उण न पास करयो और उण म्ह राजस्थानी रो नाम जोड़ो, या म्ह आपरे माध्यम से अर्ज करणी चाहूं।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

अध्यापक रा पद खूब खाळी हैं। शिक्षक भर्ती आप कर रहया हो, कह तो रहया हो कि म्है करहया है, पण कठ जा रहया है वे शिक्षक। 81,000 मास्टर भर्ती कर दिया, गया कठ, म्हारी स्कूला तो खाली पडी हैं। म्हार एरिया म्ह गांव है सिराणा, 23 पद 7 अध्यापक लाग्योडा, 18 पद खाली, विज्ञान रो शिक्षक नहीं, अंग्रेजी रो शिक्षक नहीं, गणित रो शिक्षक नहीं, टाबर पढला कि कर। इण हालत म्ह स्कूला चाल री है। बीच म्ह आप घोषणा करी विद्या संबल योजना ल्याई। बच्चा न कहया भाई विद्यार्थी मित्र स्टाइल म्ह आपां बेरोजगार जो बच्चा बैठ्या हैं, वानै भर्ती करांला। लाखा री संख्या माइन राजस्थान में फार्म भरी ज्या, हार्डकापी जमा कराब वास्ते फोटोकापी कराबा म्ह् पीसा लगावला। ई मित्र म्ह अपलोड करबा न साफ्ट कापी बिण म्ह पीसा लगावला। पैसा तो टाबरा रा खर्च हो गया, तीन-तीन, चार-चार हजार रुपया एक-एक टाबर रा खर्च हो गया और जिण दिन लास्ट डेट निकली उण दिन सरकार कहदियो ये योजना स्थगित की जाती है तो टाबरा नूं बर्बाद क्यूं करया, दौडाया क्यूं, पैसा क्यूं खर्च कराया उणरा। आं भी एक बहुत भारी आफत करी है।

उच्च शिक्षा रा बारां म्ह बात करो तो सब कालेज खाली पड्या हैं और कृषि महाविद्यालय जो म्हारै केशवाणा म्ह म्हारै विधान सभा क्षेत्र म्ह खुल्यो है, उण री हालत तो या है कि एक भी शिक्षक पढावण वालो नहीं है और न उठ लायब्रेरी है, न उठै लैबोरेट्री है, न कृषि कार्य रै वास्ते जमीन है, खेत चाहिजे, बैरो चाहिजे, ट्यूबवैल चाहिजे, पम्पसैट चाहिजे, कांई नहीं है, रामभरोसे उण री पढ़ाई हो रही है। उण बारा म्ह भी थोड़ी चिंता करणी चाहिजे।

एक या डीपीसी है, साल म्ह दो बार डीपीसी कराळा, अनुच्छेद 211 म्ह आप घोषणा करी है। राज्यपाल महोदया सूं घोषणा कराई है। आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, 31 दिसम्बर न शामरा इंतजार कर म्हार प्रमोशन री लिस्ट आवला और हर साल आवै। 31 दिसम्बर रौ 01 जनवरी हो जाव तो हडकंप मच जावै। आईपीएस और आईएएस अफसरा री पदोन्नति नियम सूं 31 दिसम्बर न हर साल होवे है और नियम बनोड़्यो हैं, बिलकुल परम्परा बनयोड़ी है और इण परम्परा रो कदै ही उल्लंघन न होवतो। आईएएस और आईपीएस कांई ऊपर आसमान रू उतरोड़्या है और एलडीसी, यूडीसी कांई आपणा सौतेला बेटा है। उणा री डीपीसी टाइम माळ क्यों नहीं होवे। उणा री भी तारीख घोषित करनी चाहिजे, निश्चित करनी चाहिजे।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

खाद्य सुरक्षा योजना री बात करी। जो करोड़पति, अच्छा पैसा वाळा हैं, वै खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ार बैठ्या है और जो वास्तव म्ह गरीब है, जिण न वास्तव म्ह फायदो मिलणो चाहिजे, वह नाम जुड़योड़ा नहीं है। वै नाम राजनीतिक द्वैष से जोड़्या नहीं या जुड्योडा काट दिया आप लोग और उण र बाद पोर्टल बंद कर दियो है। इण बारा म्ह भी सरकार ने पाछो विचार करनो चाहिजे। ई मित्र जो चल रहया है, उण म्ह बहुत भारी भ्रष्टाचार है। सरकारी कानून माइन जितनो पैसो देनो चाहिजे, दस-दस जना पैस्या ले रहया है। सरकार रो कोई कंट्रोल नहीं, कोई धणी-धोरी नहीं, कोई कहनवाळो नहीं, कोई रोकनवाळो नहीं, इण माथ अंकुश लगाबा री व्यवस्था सरकार न करनी चाहिजे।

आरजीएचएस योजना, जो आप नवी लागू करी है, उण माइन बहुत समस्या आ रही हैं। सरकारी कर्मचारया न भी आ रही है, पेंशनर्स न भी आ रही है, विधायका न भी आ रही है। व्यवस्थित और ठीक नहीं चाल रहयो है। सिस्टम न स्मूथ चाल बा र वास्ते कोई व्यवस्था सरकार न करनी चाहिजे। संविदार्मियां न परमानेंट कर दिया। सरकार घोषणा कर दी। पर वे नियम पढ्या म्है, संविदाकर्मी न परमानेंट करबाला नियम पढ्या म्है, सभापति महोदय, वण नियम में जो प्रावधान, किंतु परंतु, इफ-बट सब लगायोडा है। पांच साल ऊं पहले कोई परमानेंट नहीं होवेला। एक भी परमानेंट नहीं होवेला पांच साल ऊं पहली। लालीपाप आज दे दियो और घोषणा आज कर दी कि हमने कर दिया। वाह भाई वाह, असत्य बोलबा म्ह तो मास्टरी है आपणी। फेंकबा म्ह मास्टरी है। महंगाई री बात बार-बार, उद्योग मंत्री जी बोलता महंगाई, महंगाई, भारत री धरती माथै पूरा जितरा भी स्टेट हैं, राज्य हैं, सबरो महंगो पेट्रोल-डीजल कोई बिके है तो राजस्थान री धरती म्ह बिकरयो है। सबरी महंगी गैस बिक है तो राजस्थान री धरती माथै, सबरी महंगी बिजली है तो राजस्थान री धरती माथै और आप महंगाई री चर्चा कर रहया हो। इतणी चिंता है तो भाव घटावणा चाहिजे आपण।

इण बार जो काश्तकारा न जो ट्रांसफार्मर बदलवा म्ह, बड़ा-बड़ा ट्रांसफार्मर बदलबा म्ह जो तकलीफ हुई है, वह इतिहास में 33 सालू म्है भी राजनीति म्ह हूं, इतिहास माइन म्है नहीं देखी। दो-दो महीना, ढाई-ढाई महीना, 72 घंटा रो कानून, आदेश और 72 दिन तक ट्रांसफार्मर बदळया कोनी। बळोड्यो ट्रांसफार्मर लेर बैठया रहया और रोज एईएन आफिस रा चक्कर काटता रहया। पण सरकार काई नहीं कर सकी। इण वास्त भी मैं धन्यवाद की

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

जगह सरकार री निंदा करनी चाहूं। किसान सम्मान निधि कै बारा म्ह आप बात करता अबार कि इतणी सै काई होवै। इतरो तो दे रहया है। आप भी दैवो। आप भी ऋण माफी जो थोड़ा-सा एक हजार करोड़ री बात कर रहया हो, दो लाख करोड़ रुपया तो भारत सरकार दे चुकी है और किता दैवला, वह तो आगे टाइम आव जद बतावै। पण आपनै उण री आलोचना करबा की जगह स्वागत करनो चाहिजे। शुभ शक्ति योजना जो गरीबान फायदो देबा वाली है, उण मैं एक पैसो सरकार नहीं दे रही है, एक पैसो नहीं मिल रहयो है और इण बारा म्ह भी सरकार न विचार करनो चाहिजे।

सभापति महोदय, कुल मिलार जो यो अभिभाषण है, राज्यपाल महोदय तो पढ़ग्या, जो आप लिखर दियो, वे पढ लियो, पण इणम मोटी-मोटी बातां, लंबी-लंबी बाता करी है, फेंकी हैं लंबी-लंबी, पाछै लिपेटनी भी चाहिजे। सिर्फ घोषणा ही न रह जावे। काम भी धरातल माथ आनो चाहिजे।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सरकार रो काम काज केड़ा है, लास्ट मिनट है, उनियारा रो आब वाला विधायक रो भाषण आप वापस सुन लीजौ, विण पूरी पोल खोल दी, चार साल में जितना काम सरकार न बताया, एक कोनी हुयो और जो घोषणा बजट माइन हुई वै एक भी लागू नहीं हुई। यो आपरो विधायक कह रहयो हैं, म्हारै कहबा री जरूरत नहीं है। इण वास्ते आपरी पूरी पोल खुलगी है, चार साल में। चार साल र बाद पांचवा साल म्ह आपरी सरकार रो अंतिम वर्ष, इण म्ह जो चुनाव आब वाला है, उण चुनाव म्ह असत्य री पोल खुलेला और सरकार बुरी तरह हारला। भारतीय जनता पार्टी सत्ता माइन आवला। इण साथ ही म्ह म्हारी बात समाप्त करूं। आप मनै समय दियो, आपरो बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 31 जनवरी 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.00 बजे मंगलवार, दिनांक 31 जनवरी 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सुजानगढ़ ब्लाक में भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र

44. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सुजानगढ़ ब्लाक में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने भवन विहीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भवन विहीन केन्द्रों पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सुजानगढ़ ब्लाक में वर्तमान में 110 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं तथा उनमें से 9 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित हैं। स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों, भूमि की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण किये जाने पर विचार किया जा सकेगा। सुजानगढ़ ब्लाक में भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नागौर में सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण की कार्ययोजना

48. श्री रामनिवास गावड़िया (परतबतसर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार के पास ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में जिला नागौर में ऐसे कितने गोदाम बनाये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समितियों में गोदामों के निर्माण के कितने प्रस्तावों की स्वीकृति हुई तथा कितने प्रस्ताव लम्बित हैं व अब उक्त गोदामों का निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों/क्रय-विक्रय

(सहकारिता मंत्री)

सहकारी समितियों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से मुख्य मंत्री बजट घोषणा एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गोदाम निर्माण करवाये जाने की योजना प्रभाव में है।

विगत 03 वर्षो में नागौर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 34 गोदाम स्वीकृत हुए हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) नागौर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण हेतु गत 3 वर्ष में कुल 34 प्रस्ताव, (9 बजट घोषणा तथा 25 आर.के.वी.वाई.) स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 7 निर्माणाधीन हैं। (परिशिष्ट-1) जिनका निर्माण मई 2023 तक पूर्ण करवा दिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

भापुरा (सांगानेर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

56. श्रीमती गंगा देवी (बगरू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत भापुरा में भामाशाहों द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2015 को 3160.44 वर्ग गज भूमि राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये नियमानुसार समर्पित कर सरकार को सूचित किया गया है?

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायत मुख्यालय भापुरा, तहसील सांगानेर में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम पंचायत भापुरा में भामाशाह द्वारा भूमि नहीं दी गई है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

पंचायत समिति, सांगानेर में ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्डानुसार 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति, सांगानेर में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मापदण्ड से अधिक स्वीकृत होने के कारण ग्राम पंचायत मुख्यालय भापुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

बीकानेर संभाग की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन के प्रकरण

60. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर संभाग में ग्राम सेवा सहकारी समितियों और अन्य सहकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार व गबन के कितने प्रकरणों की जांच कब से लम्बित है? सरकार द्वारा उक्त में से कितने प्रकरणों में गबन की गई राशि की वसूली कर ली गई है? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संभाग की ग्राम सेवा सहकारी समितियां व अन्य सहकारी संस्थाएं लंबे समय से अंकेक्षण नहीं करवा रही हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्देश जारी किये गये थे? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर संभाग में ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं अन्य सहकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार व गबन के प्रकरणों में लम्बित जांच एवं इनमें वसूल की गई राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) बीकानेर संभाग की कुछ ग्राम सेवा सहकारी समितियों और अन्य सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण शेष है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। अंकेक्षण शेष रहने के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं:-

1. समितियों का रिकार्ड अपूर्ण होना।

2. समितियों द्वारा आडिटर्स को रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराना।

(3) जी हां। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समितियों की नियमित आडिट करवाने हेतु परिपत्र क्रमांक फा. सविरा/आडिट/परिपत्र/जनरल/2013 दिनांक 17.04.2015 जारी किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 पर है। इसके साथ-साथ विभाग द्वारा आडिट हेतु समय-समय पर पत्र जारी कर दिशा-निर्देश दिये हैं।

(विवरण एवं प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

राशन डीलरों को मासिक वेतन व मानदेय देने की कार्ययोजना

61. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि उचित मूल्य की दुकान पर काम करने वाले राशन डीलर द्वारा सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना की सामग्री एक कार्मिक की तरह वितरित करने के उपरान्त भी उन्हें वेतन नहीं मिलता है? यदि हां, तो क्या सरकार उचित मूल्य दुकानदारों को मासिक वेतन, मानदेय देने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उचित मूल्य दुकानदार को आबंटित मात्रा के विरुद्ध उसके द्वारा वितरित मात्रा के आधार पर कमीशन का भुगतान किया जाता है।

उचित मूल्य दुकानदारों को मासिक मानदेय दिये जाने के क्रम में प्रकरण परीक्षणाधीन है।

देवली-उनियारा में छात्रावास खोलने की कार्ययोजना

62. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत चार वर्षों में कितने अल्पसंख्यक छात्रावास खोले गए हैं? विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत चार वर्षों में खोले गये राजकीय एवं अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावासों का विधान सभावार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में अल्पसंख्यक छात्रावास खोला जाना राज्य सरकार के संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की संचालित बसें

63. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जनवरी, 2014 में कितनी बसें संचालित कर रहा था एवं दिनांक 01 जनवरी, 2023 को कितनी बसें संचालित कर रहा है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निगम में माह जनवरी, 2014 में तथा माह दिसम्बर, 2022 में कितना यात्री भार था? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त निगम द्वारा वर्ष 2019 से 2022 के मध्य तक नयी बसें क्रय की गई हैं? यदि हां, तो कितनी तथा कितनी बसें जो चल रही थीं, वे चलने से बाहर हो गयीं? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जनवरी 2014 तथा 01 जनवरी, 2023 को संचालित की जा रही बसों की संख्या निम्न प्रकार है:

माह/वर्ष	**बसों की संख्या**
जनवरी, 2014	4209
01 जनवरी, 2023	3256

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का जनवरी, 2014 एवं दिसम्बर, 2022 का यात्री भार निम्न प्रकार है:

माह/वर्ष	**यात्री भार (प्रतिशत में)**
जनवरी, 2014	69
दिसम्बर, 2022	91

(3) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2019 से वर्ष 2022 के मध्य 875 बसें क्रय की गई हैं।

उक्त अवधि में निगम द्वारा नाकारा घोषित बसों का वर्षवार संख्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है:

(राज्य मंत्री, परिवहन)

वर्ष	नाकारा की गई बसों की संख्या
2019	646
2020	321
2021	742
2022	271

रेवदर में संचालित जनजाति बालिका छात्रावास

64. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर में कितने जनजाति बालिका छात्रवास कहां-कहां किन सुविधाओं के साथ कब से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में संचालित उक्त छात्रावासों में दी जा रही भोजन, चिकित्सा, अध्ययन-अध्यापन, खेलकूद, मनोरंजन आदि सुविधाओं में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार रेवदर उप-खण्ड मुख्यालय पर जनजाति बालिका छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर में कुल 04 छात्रावास संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	संचालन वर्ष	क्षमता
1	बालिका आश्रम छात्रावास, मानपुर	1996	150
2	बालिका आश्रम छात्रावास, ओर	1985	130
3	बालिका खेल अकादमी, सांतपुर	2011	75
4	बालिका कालेज छात्रावास, सिरोही	2022	50

उक्त आश्रम छात्रावासों में यथा- नि:शुल्क आवास, पोशाक, भोजन, चिकित्सा, खेल सामग्री, कोचिंग सुविधाएं देय है तथा कालेज छात्रावास में नि:शुल्क आवास, भोजन, चिकित्सा, खेल सामग्री की सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

(2) जी नहीं। वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित जनजाति बालिका आश्रम छात्रावासों में दी जा रही भोजन, चिकित्सा, अध्ययन-अध्यापन, खेलकूद, मनोरंजन आदि सुविधाओं में गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। छात्रावासों का समय-समय पर विभागीय एवं अन्य क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

(3) रेवदर उपखण्ड मुख्यालय पर जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास खोलने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर संसाधनों तथा बजट की उपलब्धता एवं अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रेवदर उपखण्ड मुख्यालय पर नवीन छात्रावास खोलने के प्रस्ताव पर निर्णय किया जायेगा।

ऊर्जा विभाग में कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों की पालना

65. श्री पृथ्वीराज (टोडाभीम): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विभाग में कार्मिक विभाग द्वारा जारी पदोन्नति के समस्त नियम लागू किये जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार विभाग में किसी संवर्ग के उच्चतम पद पर मेरिट एवं अन्य समस्त पदों पर वरिष्ठता सह-योग्यता के अनुसार पदोन्नति के नियम लागू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। राज्य के विद्युत निगमों में कार्मिक विभाग के नियमों के स्थान पर प्रत्येक विद्युत निगम द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बनाये गये विनियम लागू होते हैं यथा अभियंता संवर्ग के लिये संबंधित निगम द्वारा बनाये गये इंजीनियर्स सर्विस रेगुलेशन-2016, अधिकारी संवर्ग के संबंध में आफिसर्स सर्विस रेगुलेशन-2017, मंत्रालयिक संवर्ग के संबंध में मिनिस्ट्रियल स्टाफ सर्विस रेगुलेशन-2017 एवं तकनीकी कामगारों के लिए टेक्निकल वर्कमैन सर्विस रेगुलेशन-1975 लागू होते हैं। विभिन्न पदों पर पदोन्नति संबंधी प्रावधान संबंधित सेवा विनियमों में ही हैं।

विद्युत निगमों के विभिन्न सेवा विनियमों में दिये गये प्रावधानानुसार उच्चतम पदों पर मेरिट पर एवं अन्य पदों पर पदोन्नति हेतु वरिष्ठता-सह-योग्यता अथवा योग्यता-सह-वरिष्ठता अथवा ये दोनों ही मापदण्ड अपनाये जाते हैं। इन प्रावधानों में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

पाली के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में रिक्त पद

66. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली में किस-किस स्थान पर कितने तकनीकी शिक्षण संस्थान संचालित हैं व उक्त में किस-किस ट्रेड में कितनी-कितनी सीटें हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थानों में से किस-किस संस्थान में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं एवं इनमें से कितने पद कितने समय से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में इनमें से किस-किस संस्थान में कौन-कौनसा नया ट्रेड, कितनी-कितनी सीटों का स्वीकृत किया गया एवं किस-किस में पूर्व में संचालित ट्रेड में अतिरिक्त सीटें स्वीकृत की गईं? क्या सरकार नये ट्रेड खोलने एवं पूर्व में संचालित संस्थानों में सीटें बढ़ाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली में सत्र 2022-23 में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत कोई भी अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित नहीं है तथा 02 पॉलीटेक्निक महाविद्यालय जिसमें 01 राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, सुमेरपुर रोड, पाली में तथा 01 निजी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, चिमनपुरा, पाली में स्थित है।

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र पाली में 02 राजकीय एवं 03 प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) संचालित हैं।

विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) उक्त संस्थानों में से राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, पाली में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-3 एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाली एवं रोहट में अनुदेशकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संस्थानवार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

निजी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाली में रिक्त पदों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-5 एवं 6 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

(3) विगत चार वर्षों में सरकार द्वारा उक्त संस्थानों में ट्रेडवार/ ब्रांचवार सीटों का विवरण परिशिष्ट-7 एवं 8 पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र पाली के रोहट (पाली) में पूर्व में स्वीकृत टेक्निशियन पावर इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम के स्थान पर कोपा व्यवसाय की दो यूनिट खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 25.07.2022 द्वारा जारी की गई है। (परिशिष्ट-9)

संसाधनों एवं बजट की उपलब्धता तथा गुणावगुणों के आधार पर क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नये ट्रेड खोले जाने का निर्णय किया जाता है।

वर्तमान में पाली जिले में सत्र 2022-23 में 01 राजकीय एवं 01 निजी पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में प्रवेश क्षमता कमशः 100 एवं 162 है तथा इनमें प्रवेश क्रमशः 26 एवं 15 हुए हैं। प्रवेश कम होने के फलस्वरूप आगामी शिक्षा सत्र में नयी शाखाएं खोलने एवं अतिरिक्त सीटें बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में नयी ब्रांचेज खोलने एवं सीटों का निर्धारण ए.आई.सी.टी.ई., नई दिल्ली के नोर्म्स एवं आई.टी.आई. में व्यवसायों में सीटों की संख्या का निर्धारण भारत सरकार के डी.जी.टी. (Directorate General of Training) एवं एन.सी.वी.टी. (National council for vocational Training) नोर्म्स के अनुसार किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सांगानेर में संचालित पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी.

28. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में कहां-कहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र, पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी. संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पी.एच.सी., सी.एच.सी. एवं सिटी डिस्पेंसरी में नर्सिंग स्टाफ व टैक्निकल स्टाफ के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित सी.एच.सी., पी.एच.सी. एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। एन.एच.एम. के अधीन संचालित शहरी पी.एच.सी. का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन पी.एच.सी., सी.एच.सी. एवं सिटी डिस्पेंसरी में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

एन.एच.एम. के अधीन शहरी पी.एच.सी. में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) जी हां। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग आफिसर एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों से रिक्त पदों को भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा।

एन.एच.एम. के संविदा आधारित रिक्त पदों को समय-समय पर निर्धारित प्रक्रियानुसार भरने की कार्रवाई की जाती है।

(विवरण एवं सूचना पुस्तकालय में रखे गये)

चित्तौड़गढ़ में संचालित 108 एम्बुलेंस

29. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में कितनी 108 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं? उक्त की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस की स्थिति को सुधारने एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त नवीन 108 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में चार 108 आपातकालीन एम्बुलेंस उपलब्ध हैं। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन नं.**	**एम्बुलेंस का प्रकार**	**बेस लोकेशन**	**एम्बुलेंस की स्थिति**
1	RJ14-PE-8051	बीएलएस	सी.एच.सी., भदेसर	ऑनरोड
2	RJ14-PC-7278	बीएलएस	सी.एच.सी., विजयपुर	ऑनरोड
3	RJ14-PE-7818	बीएलएस	जिला अस्पताल, चित्तौड़गढ़	ऑनरोड
4	RJ14-PD-7118	एएलएस	जिला अस्पताल, चित्तौड़गढ़	ऑनरोड

(2) वर्तमान में बिन्दु संख्या 01 में वर्णित 108 आपातकालीन एम्बुलेंस द्वारा अपनी-अपनी लोकेशन के साथ आस-पास के क्षेत्र को शामिल करते हुए आमजन को आपातकालीन सेवायें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आबादी के आनुपातिक आधार पर एम्बुलेंस का अनुमोदन किया जाता है। तदानुसार एम्बुलेंस वाहनों का नवीन परिनियोजन किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पी.आई.पी. वित्तीय वर्ष 2022-24 में प्रति एक लाख की आबादी पर एक बी.एल.एस. और प्रति पांच लाख की आबादी पर एक ए.एल.एस. एम्बुलेंस का अनुमोदन प्राप्त है।

राजकीय अस्पतालों में रिक्त पद

30. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने राजकीय अस्पताल संचालित हैं? उक्त में किस-किस श्रेणी के कुल कितने पद स्वीकृत व कितने पद रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजकीय अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं राजमेस के अधीन चिकित्सा महाविद्यालों एवं सम्बद्ध चिकित्सालय कुल 61 (जोधपुर-10, जयपुर-13, अजमेर-04, कोटा-07, बीकानेर-07, उदयपुर-07, आर.यू.एच.एस.-02, राजमेस-11) संचालित है। उक्त चिकित्सालयों में श्रेणीवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पदों का नाम	स्वीकृत	रिक्त
चिकित्सक शिक्षक	6042	2336
नर्सिंग संवर्ग	12766	2319
पैरामेडिकल संवर्ग	3875	1717
अन्य संवर्ग	5781	3613

प्रदेश में स्वीकृत राजकीय चिकित्सालयों का संख्यावार विवरण निम्न प्रकार है:-

जिला चिकित्सालय-43, उप जिला चिकित्सालय-43, सैटेलाइट चिकित्सालय-11, अन्य चिकित्सालय-51, सी.एच.सी.-762, पी.एच.सी. (ग्रामीण)-2267, पी.एच.सी. (शहरी)-57, सिटी डिस्पेन्सरी-186

प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में संचालित चिकित्सा संस्थानों में राजपत्रित संवर्ग के चिकित्सक/विशेषज्ञों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में संचालित चिकित्सा संस्थानों में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

राज्य में एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत स्वीकृत संविदा पदों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 299 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 09 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। उक्त चिकित्सा संस्थानों में से 160 संस्थान पूर्व से ही विभाग द्वारा संचालित हैं जिन्हें एन.यू.एच.एम. के तहत सम्मिलित कर सुविधाओं का विस्तार किया गया है।

140 नवीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व 09 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पूर्णतया संविदा आधारित पद स्वीकृत हैं। विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में कुल 43 जनता क्लिनिक संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

प्रत्येक जनता क्लिनिक पर (चिकित्सक-01, जी.एन.एम.-02, एएनएम-01, फार्मासिस्ट-01, सपोर्ट स्टाफ-02) कुल 07 पद स्वीकृत हैं।

(2) चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं राजमेस के अधीन चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में समय-समय पर विभिन्न चिकित्सक श्रेणियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु जारी विज्ञप्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान 341 पदों (चिकित्सक शिक्षक) हेतु विज्ञापन जारी किया गया है जो कि वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।
2. राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के अधीन सीधे साक्षात्कार के माध्यम से वर्ष 2022 में 746 पदों के विरुद्ध 364 को नियुक्ति पत्र जारी किये गये हैं।

जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासम्भव शीघ्र लगाने के प्रयास किये जायेगे।

चिकित्सा अधिकारी के 1,765 पदों पर पदस्थापन की कार्रवाई

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

प्रक्रियाधीन है। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर यथासम्भव लगाने के प्रयास किये जायेंगे।

एन.एच.एम. के संविदा आधारित रिक्त पदों को समय-समय पर निर्धारित प्रक्रियानुसार भरने की कार्रवाई की जाती है।

जनता क्लिनिक पर जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा रिक्त पदों को भरा जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नवाचार हेतु कृषकों को प्रोत्साहन राशि

31. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में नवाचार हेतु कृषकों को इनाम की राशि वितरित की गई है? यदि हां, तो विगत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराडा, जयसमंद, गींगला, सेमारी व झल्लारा तहसील के किन-किन किसानों को कितनी-कितनी राशि कब-कब दी गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कृषकों को देय इनाम राशि में वृद्धि कर किसानों को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी राशि तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (NMAET) सबमिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन (आत्मा) हरित कृषोन्नति योजना के अन्तर्गत श्रेष्ठ कृषकों का चयन जिले की जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित आत्मा शाषी परिषद् द्वारा किया जाकर पंचायत समिति स्तर व जिला स्तर के कृषक पुरस्कार दिये जाते हैं। राज्य स्तरीय पुरस्कार का चयन राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा श्रेष्ठ कृषकों का चयन कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त दिया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराड़ा, जयसमंद, गींगला, सेमारी व झल्लारा तहसील के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक आत्मा योजना अन्तर्गत श्रेष्ठ कृषकों को कृषि नवाचार हेतु वितरित की गई कृषक पुरस्कार राशि का वर्षवार व लाभार्थीवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

(2) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (NMAET) सबमिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन (आत्मा) हरित कृषोन्नति योजना के दिशा-निर्देश भारत सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं। आत्मा योजनान्तर्गत केन्द्रीयांश एवं राज्यांश क्रमशः 60:40 प्रतिशत के रूप में वहन किया जाता है। अतः आत्मा योजना के किसी कैफेटेरिया में राशि की बढ़ोतरी भारत सरकार द्वारा ही निर्धारित की जा सकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर को जवाई बांध से पानी देने की योजना

32. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जवाई बांध निर्माण की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जालौर जिले के हक के लिए पानी नदी में छोड़ने के लिए निश्चित किया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जिले के हक का पानी नदी में छोड़ने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। जवाई बांध निर्माण की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जालौर जिले के लिये जवाई बांध से नदी में पानी छोड़ने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था। वर्तमान में जवाई बांध के स्थापित सिंचित क्षेत्र तथा पेयजल की मांग के कारण बांध के पूर्ण भराव से पूर्व जालौर जिले हेतु नदी में पानी छोड़ा जाना विचाराधीन नहीं है।

वल्लभनगर में जल जीवन मिशन की कार्ययोजना

33. श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के समस्त ग्रामों को जल जीवन मिशन में वर्ष 2023 में लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसकी क्या कार्ययोजना है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जाखम, माही परियोजना में भीण्डर, मावली एवं वल्लभनगर के सभी ग्रामों में पानी दिया जाना था? यदि हां, तो परियोजना हेतु सर्वे की स्वीकृति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

(3) जाखम परियोजना में शुरू में किन-किन ग्रामों हेतु कितना पानी आरक्षित किया गया था तथा योजना बनाने के दौरान जिन ग्रामों को योजना से बाहर किया गया उनका आरक्षित पानी किस काम में लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में कुल सम्मिलित 377 ग्रामों में से 308 ग्राम 02 वृहद् पेयजल परियोजनाओं एवं 68 ग्राम अन्य जल योजनाओं (वृहद् पेयजल परियोजना के अतिरिक्त) में सम्मिलित किये गये हैं तथा पंचायत समिति, कुराबड़ का 01 ग्राम हाथीधरा वर्तमान में गैर-आबाद है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति करने हेतु उक्त क्षेत्र के 376 ग्रामों हेतु दो वृहद् पेयजल परियोजनाओं एवं अन्य जल योजनाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) जाखम बांध (माही बांध से जल अपवर्तित) आधारित वृहद् पेयजल परियोजना में विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की पंचायत समिति, वल्लभनगर एवं भीण्डर के क्रमश: 79 एवं 179, कुल 258 ग्रामों सहित जिला उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ के कुल 1473 ग्राम सम्मिलित किये जाकर, परियोजना हेतु राशि रुपये 4674.13 करोड़ के सक्षम स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर निर्णय राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की आगामी समय में प्रस्तावित बैठक में लिया जा सकेगा।

(ख) सोम-कमला-अम्बा बांध आधारित वृहद् पेयजल परियोजना में विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की पंचायत समिति, कुराबड़ के 50 ग्रामों सहित उदयपुर जिले के 298 ग्राम सम्मिलित किये जाकर, परियोजना हेतु राशि रुपये 676.73 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 25.02.2022 को जारी की जा चुकी है तथा वित्त विभाग से सहमति वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(ग) अन्य जल योजनाएं:- विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की पंचायत समिति, वल्लभनगर, भीण्डर एवं कुराबड़ के क्रमश: 26, 17 एवं 19, कुल 62 ग्रामों में उक्त मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति करने हेतु इनकी भू-जल आधारित योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

उक्त स्वीकृति के विरुद्ध, 01 ग्राम हेतु 01 जल योजना कार्य पूर्ण हो

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

चुका है, 21 ग्रामों हेतु 13 जल योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं, 39 ग्रामों हेतु 14 जल योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु निविदाओं एवं 01 ग्राम की 01 जल योजना हेतु तकनीकी स्वीकृति संबंधी कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति, कुराबड़ के 06 ग्रामों हेतु सतही जल स्रोत जयसमंद झील से प्रस्तावित जल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर विचाराधीन है।

उक्तानुसार पेयजल परियोजनाओं एवं अन्य जल योजनाओं तथा इनमें विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के सम्मिलित ग्रामों सहित पूर्ण विवरण क्रमशः परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्तानुसार वर्णित वृहद् पेयजल परियोजनाओं एवं अन्य जल योजनाओं में विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के उक्त वर्णित 376 ग्रामों को हर घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा चरणबद्ध रूप से वर्ष 2024 तक पेयजल आपूर्ति करना प्रस्तावित है।

(2) जाखम बांध आधारित वृहद् पेयजल परियोजना में उदयपुर जिले की पंचायत समिति, भीण्डर, मावली एवं वल्लभनगर में कुल सम्मिलित क्रमशः 196, 180 एवं 105 ग्राम, इस प्रकार 481 ग्रामों सहित जिला उदयपुर, राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़ के कुल 1899 ग्राम प्रस्तावित किये जाकर, सर्वे एवं डी.पी.आर. तैयार करने हेतु राशि रुपये 1180.40 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 08.10.2021 को जारी की गई तथा सलाहकार फर्म को दिनांक 14.07.2022 को कार्यादेश जारी किया गया।

पंचायत समिति, भीण्डर, मावली एवं वल्लभनगर के क्रमशः 179, 117 एवं 79, इस प्रकार कुल 375 ग्रामों सहित जिला उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ के कुल 1473 ग्रामों हेतु राशि रुपये 4674.13 करोड़ की तैयार की गई डी.पी.आर. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर निर्णय राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की आगामी समय में प्रस्तावित बैठक में लिया जा सकेगा।

उक्त पेयजल परियोजना की डी.पी.आर. तैयार करने मय सर्वे एवं डिजाइन इत्यादि के कार्य हेतु जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा कार्यादेश की प्रतियां क्रमशः परिशिष्ट-स एवं परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) जाखम बांध आधारित परियोजना अंतर्गत जिला उदयपुर, राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़ के कुल 1899 ग्रामों की वर्ष 2054 की अभिकल्पित

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

जल मांग हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा कुल 2750 मिलियन घन फुट जल का आरक्षण किया गया है।

उक्तानुसार तैयार की गई डी.पी.आर. में जिला उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ के कुल सम्मिलित 1473 ग्राम तथा इसके अतिरिक्त जिला उदयपुर, राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़ के 08 कस्बों हेतु वर्ष 2054 की अभिकल्पित जल मांग 2318.32 मिलियन घन फुट रही है। डी.पी.आर. तैयार करने हेतु किये गये सर्वेक्षण के दौरान राजसमंद जिले के 95 ग्रामों को जोड़ना तकनीकी रूप से फिजिबल नहीं होने तथा शेष 331 ग्राम भू-जल आधारित योजनाओं में स्वीकृत होने के कारण, उक्त परियोजना अंतर्गत 431.68 मिलियन घन फुट जल आरक्षण की वर्तमान परिपेक्ष्य में बचत रही है।

(विवरण एवं प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

रामगंज मण्डी में पेयजल की कार्ययोजना

34. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की पेयजल की क्या कार्य योजनाएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र के रामगंज मण्डी नगर, कोटा शहर के आंवली-रोझडी, नयागांव, बन्धा, धर्मपुरा, रथकांकरा, दौलतगंज सहित ग्रामीण क्षेत्र के कई गांवों में पेयजल के गंभीर संकट से निपटने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है एवं कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रामगंज मण्डी, कुम्भकोट, लक्ष्मीपुरा व कुछ कालोनियों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पाइप लाइन नहीं डाली जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में 04 शहर/जनगणना कस्बे क्रमशः रामगंज मण्डी, सुकेत, साथलखेड़ी एवं उदपुरा तथा वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 178 आबाद राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। उक्त क्षेत्र के 07

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)
ग्राम कोटा नगरीय सीमा में आने के कारण 171 आबाद राजस्व ग्राम वर्तमान में रहे हैं।

उक्त विधान सभा क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मानक मात्रा एवं गुणवत्ता अनुरूप स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कस्बा रामगंजमण्डी हेतु अमृत 2.0 के तहत भारत सरकार द्वारा राशि रुपये 9.12 करोड़ की योजना की स्वीकृति दिनांक 24.01.2023 को जारी की गई है तथा तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त इसका क्रियान्वयन माह मई, 2023 तक प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र, रामगंज मण्डी के शहर कोटा की नगरीय सीमा में उक्त क्षेत्र के वर्णित एवं सम्मिलित 07 ग्राम आंवली, रोझड़ी, नयागांव, बन्धा, धर्मपुरा, रथकांकरा एवं दौलतगंज सम्मिलित हैं। अमृत 2.0 के तहत भारत सरकार द्वारा इन ग्रामों सहित कोटा शहर (दक्षिण) हेतु राशि रुपये 220.00 करोड़ की योजना की स्वीकृति दिनांक 24.01.2023 को जारी की गई है तथा लिये गये निर्णयानुसार इस योजना का क्रियान्वयन नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा प्रारम्भ कर पूर्ण किया जाना है।

इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र, रामगंज मण्डी के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक समाधान के लिये स्वीकृत पेयजल परियोजनाओं एवं अन्य जल योजनाओं की वर्तमान स्थिति एवं इनका पूर्णता संबंधी विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) विधान सभा क्षेत्र के कस्बा रामगंज मण्डी हेतु अमृत 2.0 के तहत भारत सरकार द्वारा राशि रुपये 9.12 करोड़ की योजना की स्वीकृति दिनांक 24.01.2023 को जारी की गई है तथा तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त इसका क्रियान्वयन माह मई, 2023 तक प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र के 150 ग्रामों सहित कुल 185 ग्राम एवं 07 ढाणियों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति करने हेतु राशि रुपये 169.51 करोड़ की स्वीकृत पेयजल परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु राशि रुपये 143.79 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 23.02.2022 को जारी किया जाकर परियोजना का कार्य वर्तमान में

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

प्रगति पर है तथा इस परियोजना के स्वीकृत प्रावधानों के अनुरूप ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु मुख्य एवं वितरण पाइप लाइनें बिछाने एवं जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र के प्रश्न में वर्णित ग्राम कुंभकोट एवं लक्ष्मीपुरा में भी उक्त परियोजना अंतर्गत पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने का कार्य किया जा रहा है परन्तु खनन लीज होल्डर द्वारा लीज क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने के कार्य हेतु अनुमति नहीं दिये जाने तथा माननीय सिविल न्यायालय, रामगंज मण्डी द्वारा खनन क्षेत्र ब्लाक नं. 1 सातलखेड़ी, लक्ष्मीपुरा एवं कुंभकोट में स्थित लीज क्षेत्र के विवादित भाग पर तथा स्वीकृत लीज के किसी भी हिस्से पर रामगंज मण्डी-पचपहाड़ पेयजल परियोजना के अंतर्गत पाइप लाइन नहीं बिछाने और न ही ऐसा कोई कार्य अपने किसी अधीनस्थ कर्मचारी व ठेकेदार से कराने बाबत निर्णय दिनांक 19.08.2014 को विवृत् न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा उक्तानुसार पारित निर्णय की अनुपालना में उक्त ग्रामों में स्थित लीज क्षेत्र के विवादित भाग तथा स्वीकृत लीज के किसी भी हिस्से पर उक्त परियोजना अंतर्गत पाइप लाइन बिछाने एवं जोड़ने का कार्य विभाग द्वारा नहीं किये जाने के कारण, प्रकरण में किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा में यूरिया खाद के कारखाने

35. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा में यूरिया खाद बनाने के कुल कितने कारखाने स्थापित हैं तथा उक्त के द्वारा प्रति वर्ष कितने यूरिया का उत्पादन किया जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि विभाग ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से यूरिया विक्रय करता है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों को निजी क्षेत्र से यूरिया आबंटन करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि यूरिया की कमी होने पर प्राइवेट डीलरों द्वारा खाद को अधिक दाम पर विक्रय किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर नियंत्रण हेतु सहकारी समितियों के माध्यम से यूरिया विक्रय

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में यूरिया खाद बनाने की 2 यूनिट स्थापित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

नाम	**वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता**
मैसर्स श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि., गढेपान, कोटा	3.60 लाख मै.टन
मैसर्स चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि., गढेपान, कोटा	33.13 लाख मै.टन

(2) जी हां। भारत सरकार से आबंटन उपरान्त निजी एवं सहकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा यूरिया की आपूर्ति की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आदान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजफैड द्वारा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को यूरिया एवं डी ए पी उपलब्ध करवाया जाता है। सहकारी क्षेत्र की कम्पनियां कृभको एवं इफको द्वारा क्रय विक्रय सहकारी समिति (के वी एस एस) एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति (जी एस एस) के माध्यम से कृषकों को यूरिया की आपूर्ति की जाती है। मैसर्स आई पी एल द्वारा निजी एवं सहकारी दोनों क्षेत्रों में यूरिया की आपूर्ति की जाती है तथा अन्य कम्पनियों द्वारा अधिकृत निजी वितरकों एवं विक्रेताओं के माध्यम से यूरिया की आपूर्ति की जाती है।

वर्तमान में क्रय विक्रय सहकारी समिति (के वी एस एस) एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति (जी एस एस) को निजी क्षेत्र की कम्पनियों से यूरिया आबंटन करने का प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(3) जी नहीं। कृषकों को अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने वाले विक्रेताओं पर कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षकों द्वारा सतत निगरानी रखी जाती है तथा यदि कोई विक्रेता अधिक मूल्य पर विक्रय करते हुए पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

अजमेर की उचित मूल्य की रिक्त दुकानों का आबंटन

36. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शंकर सिंह रावत)

(1) क्या यह सही है कि उचित मूल्य की दुकानों के रिक्त होने पर अस्थाई रूप से उक्त दुकानों के उपभोक्ताओं को अन्य दुकानों पर अटैच किया जाता है? यदि हां, तो जिला अजमेर में ऐसी कितनी दुकानें हैं, जिनको अन्य दुकानों से अटैच किया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उचित मूल्य की दुकानें अटैच होने से उपभोक्ताओं को दूर-दूर जाकर सामग्री लेने में परेशानियों का सामना करना पडता है? यदि हां, तो क्या सरकार उचित मूल्य की रिक्त दुकानों का आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय आदेश दिनांक 19.04.2022 के द्वारा उचित मूल्य दुकानों के अटैचमेंट संबंधित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

जिला अजमेर में कुल 167 दुकानें अन्य दुकानों से अटैच हैं।

(2) जी नहीं। विभागीय आदेश दिनांक 19.04.2022 में उचित मूल्य दुकान को 3 किलोमीटर से अधिक दूर वाली दुकान पर नहीं किये जाने एवं उसी पंचायत में किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी है आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राज्य में पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू है जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

जी हां। रिक्त उचित मूल्य दुकान का आबंटन एक सतत प्रकिया है। आम उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा का सुलभ लाभ दिलवाने हेतु दुकानों का यथाशीघ्र आबंटन करने की कार्रवाई की जा रही है

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पांचू में सहायक अभियंता कार्यालय की स्थापना

37. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार पंचायत समिति मुख्यालय पांचू में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बीकानेर जिले के पांचू पंचायत समिति मुख्यालय पर नवीन सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, जिसके मापदण्डों के अनुरूप पाये जाने पर स्वीकृति सम्बन्धी कार्रवाई के उपरान्त उक्त सहायक अभियन्ता कार्यालय का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।

खींवसर में फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम

38. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर में फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम हेतु वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक कितना बजट जारी किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जारी किये गये बजट में से कितना बजट व्यय हुआ एवं कितना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम का कार्य तय नोर्म्स से हुआ है? यदि नहीं, तो इसके जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम कार्य के तहत विधान सभा क्षेत्र खींवसर के लिये पृथक से बजट का प्रावधान नहीं होकर नागौर जिले के लिए कुल 96.14 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खींवसर में फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम कार्य के तहत वर्ष 2020-21 में 58.12 करोड़ रुपये, वर्ष 2021-22 में 4.82 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2022-23 में माह दिसम्बर-2022 तक में 2.42 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

(3) फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम का कार्य तय मापदण्ड के अनुसार ही पूर्ण किया गया है/किया जा रहा है।

राजसमन्द जिला आयुष चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पद

39. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

(1) राजसमंद जिला आयुष चिकित्सालय में विशेषज्ञ स्तर की क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? उक्त चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों के कौन-कौनसे व कितने पद सृजित तथा कितने पद भरे हुए हैं?

(2) क्या उक्त जिला चिकित्सालय में रोगों के निदान एवं जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित है? यदि हां, तो प्रयोगशाला में कौन-कौनसी जांचे की जा रही हैं?

(3) उक्त जिला चिकित्सालय में वर्तमान एवं विगत तीन वर्षों में कितने अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों का उपचार किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त चिकित्सालय में औषधियों के लिए उक्त अवधि में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई एवं वास्तविक व्यय कितना हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुष विभागान्तर्गत राजसमंद जिले में जिला आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित है।

आयुर्वेद चिकित्सालय राजसमंद में विशेषज्ञ स्तर की क्षारसूत्र की सुविधा उपलब्ध है।

विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद सृजित नहीं होने से उक्त चिकित्सालय में किसी भी प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद सृजित नहीं है।

उक्त चिकित्सालय में चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का पदवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) आयुर्वेद विभागान्तर्गत आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, राजसमन्द में रोगों के निदान एवं जांच के लिए कोई भी प्रयोगशाला स्थापित नहीं है।

(3) जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में वर्तमान एवं विगत तीन वर्षों में अंतरंग एवं बहिरंग से लाभांवित पंजीकृत रोगियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

वर्ष	**अंतरंग**	**बहिरंग**
2019-20	92	7509
2020-21	18	5411
2021-22	30	5093
2022-23 (दिसम्बर 2022 तक)	55	4213
कुल	**195**	**22226**

(4) उक्त चिकित्सालय में औषधियों के लिए स्वीकृत धनराशि का आबंटन व व्यय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

राशि लाख रुपये में

वर्ष	**आबंटन**	**व्यय**
2019-20	4.11	2.03
2020-21	5.37	3.75
2021-22	5.57	3.17
कुल	**15.05**	**8.95**

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर पॉलीटेक्निक कालेज में पेट्रोकेमिकल विषय प्रारम्भ करने की योजना

40. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2006 में बाड़मेर पॉलीटेक्निक कालेज में पेट्रोकेमिकल विषय प्रारम्भ किये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त में अब तक कितने छात्रों ने प्रवेश लिया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कालेज में उक्त विषय प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त विषय को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 में बाड़मेर पॉलीटेक्निक कालेज में पेट्रोकेमिकल विषय 40 प्रवेश क्षमता के साथ प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 2006 से वर्ष 2008 तक कुल 120 छात्रों ने प्रवेश लिया।

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

वर्ष 2009 में पेट्रोकेमिकल ब्रांच को केमिकल ब्रांच में परिवर्तित किया गया जो कुल प्रवेश क्षमता 40 के साथ संचालित है।

(2) जी नहीं। उक्त कालेज में वर्ष 2006 में यह विषय प्रारम्भ कर दिया गया।

वर्तमान में पेट्रोकेमिकल ब्रांच प्रारम्भ करने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।